

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



अप्रैल 2020

खंड 74 अंक 4

संपादन समिति
राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

सातवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20	1
मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2020	9

भाषण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और भावी दिशा शक्तिकांत दास	99
--	----

लेख

जलवायु परिवर्तन: समष्टि आर्थिक प्रभाव और जोखिमों को कम करने के नीतिगत विकल्प	105
केंद्रीय बजट 2020-21 का आकलन	127

वर्तमान सांख्यिकी	149
-------------------	-----

हाल के प्रकाशन	195
----------------	-----

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

सातवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

सातवां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति ने आज (27 मार्च 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि –

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.40 कर दिया जाए।
- तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.40 प्रतिशत से घटकर 4.65 प्रतिशत हो गई;
- इसके अलावा, विकासात्मक और विनियामक नीतियों में उल्लिखित किए अनुसार एलएएफ कॉरिडोर के विस्तार के परिणामस्वरूप एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 90 आधार अंक घटकर 4.0 प्रतिशत हो गया।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

* 27 मार्च 2020 को जारी किया गया।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. वैश्विक आर्थिक गतिविधि ठहराव की स्थिति में आ गई है क्योंकि सभी प्रभावित देशों में COVID-19 संबंधित लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग व्यापक स्तर पर लगाई गई है। 2019 के दशक में मंद वैश्विक विकास को 2020 में अल्प वसूली की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। महामारी की तीव्रता, प्रसार और अवधि की संभावनाएं अब काफी आकस्मिक है। इस बात की संभावना बढ़ रही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा।

3. COVID-19 के प्रकोप के कारण जनवरी से वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं। पैनिक सेल-ऑफ ने सम्पूर्ण उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी बाजारों में समान रूप से धन का नाश किया है। पूर्व में, सुरक्षा की ओर रुख के कारण हाल के दिनों में कुछ सख्ती के साथ सरकारी बांड प्रतिफल में कमी दर्ज की गई। उत्तरार्द्ध में, बाहर निकलने की जल्दबाज़ी ने नियत आय बाजारों को निरूपित किया है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिफल में वृद्धि हुई है। अत्यधिक जोखिम के कारण त्वरित बिक्री के वजह से उभरते और उन्नत अर्थव्यवस्था की मुद्राओं को दैनिक आधार पर गंभीर मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, केवल अमेरिकी डॉलर अत्यधिक अनिश्चित संभावनाओं में सुरक्षित बना हुआ है। मार्च के आरंभ तक अन्य दो-जापानी येन और सोना जो सुरक्षित थे, नकदी में बढ़ोत्तरी की ओर रुख किया। COVID-19 के प्रकोप के कारण मांग कमजोर पड़ने की आशंका में जनवरी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आरंभ में सौम्य भाव से कारोबार हुआ। हालांकि, प्रमुख तेल उत्पादकों के बीच उत्पादन में कटौती ने असहमति को बढ़ा दिया है, प्रतिशोधी सप्लाई स्केल-अप और मूल्य युद्ध के कारण 18 मार्च 2020 को अंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमतें 25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर आ गई हैं। इन घटनाओं से उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय बैंक और सरकार युद्ध मोड में हैं, चलनिधि के कारण मांग में गिरावट से बचने के लिए और वित्तीय बाजारों को बंद होने से बचाने के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए लक्षित कई पारंपरिक और अपारंपरिक उपायों के साथ स्थिति का जवाब दे रहे हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. फरवरी 2020 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2019-20 के चौथे तिमाही के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 4.7 प्रतिशत लगाया गया, जो कि पूरे वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के वार्षिक अनुमान के भीतर है। इस पर भी अब अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के कारण जोखिम मंडरा रहा है। उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि निजी अंतिम खपत व्यय को गहरा झटका लगा है, यहां तक कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण भी 2019-20 की दूसरी तिमाही के बाद से संकुचन में रहा है। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की संभावनाएं ही केवल एक उम्मीद की किरण है, जिसमें खाद्यान्न का उत्पादन 292 मिलियन टन है जो एक साल पहले की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है। निर्माण और बिजली उत्पादन में संवृद्धि ने पिछले पांच महीनों में अनिरंतर संकुचन और / या निष्प्रभाव गतिविधि के बाद जनवरी 2020 में औद्योगिक उत्पादन को सकारात्मक क्षेत्र में खींच लिया; हालांकि, यह जानने के लिए और अधिक डेटा को देखना होगा कि COVID-19 के सामने हाल का इजाफा टिकेगा के नहीं। इस बीच, जनवरी और फरवरी 2020 के लिए अधिकांश सेवा क्षेत्र के संकेतकों में मंदी या गिरावट आई। तब से वास्तविक साक्ष्य बताते हैं कि व्यापार, पर्यटन, एयरलाइंस, आतिथ्य क्षेत्र और निर्माण जैसी कई सेवाओं पर महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के विस्थापन के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी गतिविधि में कमी आएगी।

5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति, जनवरी 2020 में चरम पर पहुंच गई और फरवरी 2020 में पूर्ण प्रतिशत के स्तर से गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई, क्योंकि प्याज की कीमतों में गिरावट ने पूर्ववर्ती दो महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति को दोहरे अंक से नीचे ला दिया। हालांकि, मूल्य दबाव सभी प्रोटीन युक्त वस्तुओं, खाद्य तेलों और दालों के लिए स्थिर बने रहे; लेकिन COVID-19 से मांग में आने वाली गिरावट उन्हें आगे जाकर कमजोर कर सकता है। फरवरी में अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में देरी के घरेलू समायोजन के कारण ईंधन की मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई, मार्च में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत मिल सकती है। खाद्य और ईंधन को

छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल के सौम्य कीमतों के कारण कम हो गई। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2020 के दौर में एक वर्ष आगे के परिवारों की मुद्रास्फीति संभावनाएं 20 बीपीएस तक सौम्य हो गईं।

6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बड़े पैमाने पर अपविक्रय का सामना करने वाले इक्विटी बाजारों के साथ घरेलू वित्तीय स्थिति काफी हद तक मजबूत हुई है। बांड बाजार में भी प्रतिफल निरंतर एफपीआई की बिक्री पर बढ़ी है, जबकि मोचन दबाव, ट्रेडिंग गतिविधि में गिरावट और सामान्यीकृत जोखिम के फैलाव ने वाणिज्यिक पेपर, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य नियत आय वाले क्षेत्रों में ऊंचे स्तर तक प्रतिफल को बढ़ावा दिया है। विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (आईएनआर) निरंतर नीचे की ओर दबाव में रहा है। इन परिस्थितियों में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को तरल, स्थिर और कामकाज को सामान्य रूप से बनाए रखने का प्रयास किया है। एलएएफ के तहत निवल अवशोषण में परिलक्षित प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष मार्च में औसतन 2.86 लाख करोड़ (25 मार्च 2020 तक) था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने ₹ 11,724 करोड़ की संचयी निवल राशि उपलब्ध कराते हुए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों (₹ 28,276 करोड़) की समान बिक्री और दीर्घावधि प्रतिभूतियों (₹ 40,000 करोड़) की खरीद को शामिल करते हुए 'ट्रिस्ट ऑपरेशन' नामक नीलामी के रूप में अपरंपरागत परिचालन आरंभ किया। रिजर्व बैंक ने चलनिधि उपलब्ध कराने और मौद्रिक संचरण में सुधार करने के लिए अब तक 1.25 लाख करोड़ के संचयी राशि के 1 वर्ष और 3 वर्ष के कार्यकाल के पांच दीर्घकालिक रेपो नीलामी का भी आयोजन किया। रिजर्व बैंक ने 16 और 23 मार्च को 2.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा बाजार में संचयी रूप से अमेरिकी डॉलर चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए दो बिक्री-खरीद स्वैप नीलामी का भी संचालन किया। चलनिधि को मजबूत करने और वित्तीय स्थितियों को सरल बनाने के लिए 20 मार्च को ₹ 10,000 करोड़ और 24 मार्च तथा 26 मार्च दोनों को ₹ 15,000 करोड़ का खुला बाजार खरीद परिचालन आयोजित किया गया।

7. बाहरी क्षेत्र में, पण्य का निर्यात फरवरी 2020 में लगातार छह महीने के संकुचन के बाद विस्तारित हुआ। आठ महीने की

लगातार गिरावट के बाद आयात वृद्धि भी सकारात्मक दिखाई दी। फलस्वरूप, व्यापार घाटा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मामूली रूप से बढ़ा, हालांकि यह एक महीने पहले अपने स्तर से कम था। 12 मार्च को, रिजर्व बैंक ने भुगतान का संतुलन डाटा जारी किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि चालू खाता, जीडीपी के केवल 0.2 प्रतिशत की कमी के साथ क्यू3: 2019-20 में दर्शाए शेष के समीप था। वित्त पोषण के संबंध में, अप्रैल-जनवरी 2019-20 के दौरान 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफडीआई अंतर्वाह एक वर्ष पूर्व की तुलना में काफी अधिक था। संविभाग निवेश ने 2019-20 (25 मार्च तक) के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्गमन में गिरावट दर्ज की, जो एक वर्ष पहले 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 6 मार्च 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 487.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया – जो उनके मार्च 2019 के अंत के स्तर से 74.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक था।

आउटलुक

8. फरवरी 2020 के छठे द्विमासिक संकल्प में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यू4: 2019-20 के लिए 6.5 प्रतिशत पर अनुमानित की गई थी। जनवरी और फरवरी 2020 के प्रिंट्स से पता चलता है कि तिमाही के लिए वास्तविक परिणाम प्याज की कीमत को दर्शाते हुए, अनुमानों से 30 बीपीएस ऊपर चल रहे हैं। आगे, रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन के लाभकारी प्रभावों के तहत, कम से कम सामान्य गर्मियों की शुरुआत तक, खाद्य पदार्थों की कीमतें और भी नरम हो सकती हैं, इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ईंधन और मूल मुद्रास्फीति दोनों दबावों को कम कर सकेगा, जोकि खुदरा कीमतों के पास-थ्रू के स्तर पर निर्भर होगा। COVID-19 के परिणामस्वरूप, सकल मांग कमजोर हो सकती है और मूल मुद्रास्फीति को और कम कर सकती है। वित्तीय बाजारों में ऊँची अस्थिरता का असर मुद्रास्फीति पर भी पड़ सकता है।

9. विकास की ओर मुड़ते हुए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की निरंतर आघात-सहनीयता के अलावा, अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों पर महामारी द्वारा, इसकी तीव्रता, प्रसार और अवधि के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि COVID-19 लंबे समय तक रहा और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, तो

वैश्विक मंदी भारत के लिए प्रतिकूल प्रभाव के साथ गहरा सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, व्यापार लाभ के रूप में कुछ राहत प्रदान कर सकती है। COVID-19 और लंबे समय तक लॉकडाउन के प्रसार से विकास के लिए नकारात्मक जोखिम उत्पन्न होते हैं। मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य नीतिगत उपायों और COVID -19 के शुरुआती नियंत्रण से अधिक वृद्धि आवेग उत्पन्न होने की उम्मीद है।

10. एमपीसी का विचार है कि, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर, महामारी द्वारा लाए गए व्यापक आर्थिक जोखिम गंभीर हो सकते हैं। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि, घरेलू अर्थव्यवस्था को महामारी से बचाने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है, उसे करना चाहिए। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक और विनियामक उपाय - पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों किए हैं। दुनिया भर में सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए लक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थन सहित बड़े पैमाने पर राजकोषीय उपाय किए हैं। वायरस के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों सहित किसानों, प्रवासी श्रमिकों, शहरी और ग्रामीण गरीबों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण और अन्न सुरक्षा सहित ₹ 1.70 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज, की घोषणा की है। एमपीसी ने यह देखा है कि रिजर्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त तरलता को इंजेक्ट करने के लिए कई उपाय किए हैं। बहरहाल, महामारी के प्रतिकूल व्यापक आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई करने को प्राथमिकता देनी होगी। एमपीसी इस संदर्भ में सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर में भारी कमी के लिए वोट करता है, लेकिन कमी की मात्रा में कुछ असहमति के साथ। इसके अलावा, एमपीसी यह भी नोट करता है कि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में तरलता, मौद्रिक संचरण और ऋण प्रवाह को और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को शुरू करने का निर्णय लिया है और ऋण शोधन पर राहत प्रदान की है। यह सभी हितधारकों के लिए महामारी से लड़ने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को वायरस द्वारा लगाए गए अलगाव के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे आर्थिक एजेंटों को क्रेडिट प्रवाहित करने के

लिए जो संभव हो करना चाहिए। बाजार सहभागियों को भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे नियामकों के साथ काम करना चाहिए ताकि मूल्य खोज और वित्तीय मध्यस्थता की उनकी भूमिका में बाजारों के क्रमबद्ध कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। स्थिति से निपटने के लिए मजबूत राजकोषीय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

11. यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, सभी सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव

को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए वोट किया।

12. डॉ. रविन्द्र एच.ढोलाकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देबब्रता पात्र, श्री शक्तिकांता दास ने नीतिगत रेपो दर में 75 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया। डॉ. चेतन घाटे और डॉ.पमी दुआ ने नीतिगत रेपो दर में 50 बीपीएस कटौती के लिए वोट किया।

13. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 13 अप्रैल 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

इस वक्तव्य में अनेक प्रकार की विकासात्मक और विनियामकीय नीतियां शामिल की गई हैं, जो COVID-19 के कारण वित्तीय स्थितियों में उत्पन्न दबावों का सीधे-सीधे समाधान प्रस्तुत करती हैं। इनमें शामिल हैं (i) प्रणाली में काफी मात्रा में चलनिधि का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि COVID-19 संबंधी जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसके चलते वित्तीय बाजार और संस्थाएं सामान्य रूप से कार्य कर सकें (ii) मौद्रिक प्रसारण को बढ़ाना ताकि क्रेडिट का प्रवाह आसानी से हो सके और वे संस्थाएं स्वयं को बहाल रख सकें जो महामारी (पेंडेमिक) से प्रभावित हुई है। (iii) चुकौती संबंधी दबावों को रियायत बरतते हुए तथा कार्यशील पूंजी तक बेहतर एक्सेस प्रदान करते हुए COVID-19 की बाधाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय दबावों को कम करना तथा (iv) महामारी के चलते और उसके फैलने से बाजारों में उत्पन्न उच्च अस्थिरता को देखते हुए बाजारों की कार्यात्मकता को बेहतर बनाना इस भाग में दी गई नीतिगत पहल को मौद्रिक नीति कार्रवाई और समाधान स्वरूप उसके रुझान के संबंध में मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

I. चलनिधि प्रबंधन

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपायों की पहली खेप से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी प्रकार के घटकों को पर्याप्त मात्रा में चलनिधि उपलब्ध हो ताकि COVID-19 की वजह से पैदा चलनिधि बाधाएं सहज बन सकें।

1. लक्ष्य किए गए दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

भारत में COVID-19 के फैलने और तेजी से हुए उसके प्रसार ने घरेलू इक्विटी, बॉण्ड और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी बिक्री को और भी तीव्र कर दिया। शोधन के तीव्र दबाव के कारण लिखतों पर चलनिधि प्रक्रिया जैसे कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर और डिबेंचर पर प्रीमियम बढ़ते चले गए। इसके साथ, COVID-19 के फैलने से व्यापार संबंधी गतिविधियाँ कम हो जाने को मिलाकर देखा जाए तो इन लिखतों की वित्तीय स्थिति भी, अन्य बातों के साथ-साथ बैंक क्रेडिट की हालत मंद हो जाने की स्थिति में कार्यशील पूंजी को एक्सेस कर पाना भी कठिन हो गया। आर्थिक गतिविधियों पर इनके प्रतिकूल प्रभावों, जिससे नकदी प्रभावों पर दबाव पड़ता है, को कम करने के लिए यह निर्णय किया गया है

कि रिजर्व बैंक उपयुक्त आकार के लक्ष्य किए गए तीन वर्ष तक के सावधि रेपो की नीलामियाँ करेगा जिसकी कुल राशि 1,00,000 करोड़ रुपए होगी और जो नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर आधारित होगी।

बैंको द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई चलनिधि को निवेश श्रेणी के कॉर्पोरेट बॉण्ड, कमर्शियल पेपर तथा अपरिवर्तनीय डिबेंचर में लगाना होगा जो 27 मार्च 2020 को उनके द्वारा इन बॉण्डों में किए जाने वाले निवेश के बकाया स्तर के अतिरिक्त होगा। बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे पात्र लिखतों की अपनी वृद्धिशील धारिता का पचास प्रतिशत तक प्राथमिक बाजार के निर्गमों से प्राप्त करें और शेष पचास प्रतिशत म्यूचुअल फंड एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित द्वितीयक बाजार से प्राप्त करें। इस सुविधा के अंतर्गत बैंकों द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही एचटीएम पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कुल अनुमत निवेश 25 प्रतिशत से अधिक क्यों न हो। इस सुविधा के अंतर्गत किए गए एक्सपोजर की गणना बड़े एक्सपोजर प्रेमवर्क के अधीन नहीं की जाएगी।

टीएलटीआरओ की पहली नीलामी आज (27 मार्च 2020) को की जाएगी। इस नीलामी के परिणामों की समीक्षा के बाद आगामी टीएलटीआरओ नीलामियों की घोषणा की जाएगी।

इस सुविधा की जानकारी अलग से जारी की जा रही है।

2. नकदी प्रारक्षित अनुपात

ए. बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि प्रचूरता से बनी रहेगी जैसाकि 1 से 25 मार्च 2020 के दौरान दैनिक औसत आधार पर 2.86 लाख करोड़ रुपए एलएएफ रिवर्स रेपो परिचालन के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष को अवशोषित करने से परिलक्षित होता है। लेकिन यह पाया गया है कि चलनिधि का यह वितरण संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक असमान है और वह भी स्पष्टतया बैंकिंग प्रणाली के भीतर है।

COVID-19 से उत्पन्न बाधाओं के कारण तंगहाली में पड़े बैंकों की एकबारगी सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित निधि (सीआरआर) को 28 मार्च 2020 को प्रारंभ रिपोर्टिंग पखवाड़े से 100 आधार अंक कम कर के निवल माँग और मियादी देयताओं

(एनडीटीएल) का 3.0 प्रतिशत कर दिया जाए। सीआरआर में की गई इस कमी से संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में समान रूप से लगभग 1,37,000 करोड़ रुपए की प्राथमिक चलनिधि आ जाएगी जो घटकों की अतिरिक्त एसएलआर की धारिता के सापेक्ष न हो कर उनकी देयताओं के अनुपात में होगी। यह छूट 26 मार्च 2021 को समाप्त एक वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी।

बी. इसके अतिरिक्त, स्टाफ की सामाजिक दूरी की वजह से बैंकों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अपेक्षाओं पर जो दबाव पड़ रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2020 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले दिन से प्रभावी न्यूनतम दैनिक सीआरआर की अपेक्षा को घटाकर 90 से 80 प्रतिशत कर दिया जाए। यह छूट एकबारगी रूप में 26 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

3. सीमांत स्थायी सुविधा

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंक, अपने विवेक पर संविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में से 2 प्रतिशत तक ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। घरेलू वित्तीय बजार में अपवाद रूप से अत्यधिक अस्थिरता की हालत ने चलनिधि पर चरणबद्ध रूप से दबाव पैदा कर दिया है, बैंकिंग प्रणाली को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त सीमा को तत्काल प्रभाव से 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया जाए। यह उपाय 30 जून 2020 तक उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे मंशा यह है कि मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में घोषित एमएसएफ की घटी हुई दर पर दबाव की हालत में बैंकिंग प्रणाली को एलएएफ विंडो के अंतर्गत 1,37,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाएँ ताकि उसमें सहजता पैदा हो।

टीएलटीआरओ, सीआरआर और एमएसएफ इन तीनों उपायों से प्रणालियों में कुल 3.74 लाख करोड़ रुपए की चलनिधि आ जाएगी।

4. मौद्रिक नीति दर के कॉरिडॉर को बढ़ाना

यह निर्णय लिया गया है कि लगातार बनी हुई अधिशेष चलनिधि की स्थिति में वर्तमान नीतिगत कॉरिडॉर को 50 आधार अंक

से बढ़ा कर 65 आधार अंक कर दिया जाए। इस नए कॉरिडॉर के अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रतिवर्ती रेपो दर 40 आधार अंक होगी जो नीतिगत रेपो दर से कम होगी। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 25 आधार अंक पर नीतिगत रेपो दर से अधिक बनी रहेगी।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

चलनिधि संबंधी उपायों के साथ-साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि COVID-19 महामारी के संकट के कारण उत्पन्न बाधाओं की वजह से कर्ज चुकाने के बोझ को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस प्रकार के प्रयासों से वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के प्रसार पर रोक लगेगी और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कारोबार फायदेमंद तरीके से चलते रहें और ऐसी कठिन घड़ी में उधारकर्ताओं को राहत मिल सके।

5. मीयादी ऋणों का स्थगन

सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं तथा एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनी तथा माइक्रो वित्त कंपनी सहित) ("उधारदाता संस्थाएं") को अनुमति दी जाती है कि वे 1 मार्च 2020 को बकाया सभी मीयादी ऋणों पर किश्तों के भुगतान पर तीन महीने के स्थगन की अनुमति प्रदान करें। तदनुसार, चुकौती के सभी शैड्यूल तथा बाद की सभी देय तारीखें, तथा इस प्रकार के ऋणों की अवधि सभी स्तरों पर तीन महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी।

6. कार्यशील पूंजी सुविधा पर ब्याज आस्थगित करना

उधार देने वाली संस्थाओं को यह अनुमति दी जाती है कि कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में उनके द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट के संबंध में 1 मार्च 2020 को बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के लिए ब्याज के भुगतान की तारीख तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दें। इस अवधि के लिए संचित ब्याज का भुगतान आस्थगित अवधि की समाप्ति पर किया जाएगा।

उपर्युक्त पैरा 5 और 6 के संबंध में, स्थगन/ आस्थगन की सुविधा विशेष रूप से इसलिए प्रदान की जा रही है, ताकि उधारकर्ता COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपट सकें। अतः इसे उधारकर्ताओं की वित्तीय परेशानी के कारण ऋण हेतु किए गए

करार की शर्तों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का निम्न श्रेणी में वर्गीकरण नहीं करना होगा। उधारदाता संस्थाएं इस संबंध में तदनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कार्यान्वित कर सकते हैं।

7. कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण को आसान बनाना

कैश क्रेडिट / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधा के संबंध में उधारदाता संस्थाएं आहरण- शक्ति की पुनःगणना मार्जिन कम करते हुए और/ अथवा उधारकर्ता के लिए कार्यशील पूंजी के चक्र का पुनर्मूल्यांकन करते हुए करें। विशेष रूप से COVID-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए उधारकर्ताओं को क्रेडिट-शर्तों में बदलाव करने हेतु दी गई अनुमति को उनकी वित्तीय कठिनाई के कारण प्रदान की गई रियायत नहीं माना जाएगा और फलस्वरूप आस्तियों का वर्गीकरण निम्न श्रेणी में नहीं किया जाएगा।

पैरा 5, 6 और 7 के संबंध में भुगतान के पुनर्निर्धारण को पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के प्रयोजन से तथा (सीआईसी) उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग के प्रयोजन से चूक नहीं माना जाएगा। सीआईसी यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त घोषणा के अनुसरण में उधारदाता संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई का लाभार्थियों के क्रेडिट-इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

8. निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) के कार्यान्वयन को स्थगित करना

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में किए गए सुधारों के एक हिस्से के रूप में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसेल समिति (बीसीबीएस) ने निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की थी, जो भविष्य के वित्तपोषण तनाव के जोखिम को कम करने के लिए एक वर्ष के समय क्षितिज पर वित्तपोषण के पर्याप्त स्थायी स्रोतों से बैंकों के कार्यकलाप को वित्त पोषित कर बैंकों की आवश्यकता के हिसाब से जोखिम को कम करता है। निर्धारित समयावधि के अनुसार, भारत में बैंकों को 1 अप्रैल 2020 से एनएसएफआर को 100 प्रतिशत बनाए रखने की आवश्यकता थी। अब 1 अप्रैल 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक छह महीने तक एनएसएफआर के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

9. पूंजी संरक्षण बफर के अंतिम ट्रेंच का स्थगन

पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक सामान्य समय के दौरान (यानी, तनाव के समय के बाहर) पूंजीगत बफर का निर्माण करें, जिन्हें एक तनावग्रस्त अवधि के दौरान होने वाले नुकसान के लिए निकाला जा सकता है। बेसल मानकों के अनुसार, सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के ट्रेंच में लागू किया जाना था और 2.5 प्रतिशत के पूर्ण सीसीबी में परिवर्तन 31 मार्च 2019 तक पूरा होना तय था। बाद में 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। COVID-19 के कारण संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सीसीबी के 0.625 प्रतिशत के अंतिम ट्रेंच के कार्यान्वयन को 31 मार्च 2020 से आगे 30 सितंबर 2020 तक स्थगित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, अतिरिक्त टियर 1 लिखत (पीएनसीपीएस और पीडीआई) रूपांतरण / राइट-डाउन के माध्यम से हानि के अवशोषण के लिए पूर्व-निर्धारित ट्रिगर जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (आरडब्ल्यूए) के 5.5 प्रतिशत पर बना रहेगा और 30 सितंबर 2020 को आरडब्ल्यूए के 6.125 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

III. वित्तीय बाजार

वित्तीय बाजारों के संबंध में निर्णय अनिवार्य रूप से एक विकासात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य और ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच मध्यस्थता को कम करके विदेशी मुद्रा बाजार क्षेत्रों में गहनता और मूल्य खोज में सुधार करना है। यह उपाय मुद्रा बाजारों पर COVID-19 के प्रभाव के कारण रुपये की बढ़ी हुई अस्थिरता के संदर्भ में अधिक महत्व रखता है।

10. बैंकों को ऑफशोर गैर-सुपुर्द रुपया डेरिवेटिव बाजार (ऑफशोर एनडीएफ रुपया बाजार) में डील करने की अनुमति देना

ऑफशोर भारतीय रुपया (आईएनआर) डेरिवेटिव बाजार - गैर-सुपुर्द वायदा (एनडीएफ) बाजार हाल के दिनों में तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में, भारतीय बैंकों को इस बाजार में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि एनडीएफ बाजार में उनकी भागीदारी के लाभों को व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। मुद्दे के सभी पहलुओं

की विस्तार से जांच की गई है और आरबीआई में एक आम सहमति बन गई है कि यह समय ओनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच विभाजन को हटाने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के परामर्श से, 1 जून 2020 से एनडीएफ बाजार में भाग

लेने की अनुमति भारत में उन बैंकों को दी जाए जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) को परिचालित करते हैं। बैंक भारत में अपनी शाखाओं, अपनी विदेशी शाखाओं या अपने आईबीयू के माध्यम से भाग ले सकते हैं। आज अंतिम निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2020

I. समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण

इस समय वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, और वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति शृंखलाओं, व्यापार और पर्यटन में व्यापक विस्थापन हुए हैं। समूचे विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं, वैश्विक पण्यों की कीमतों, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। कोविड-19 भारत में लॉक-डाउन से प्रत्यक्ष रूप में और वैश्विक व्यापार और संवृद्धि के माध्यम से संचालित होने वाले द्वितीय दौर के प्रभावों के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करेगा। मुद्रास्फीति पर कोविड-19 का प्रभाव अनेकार्थी है, आपूर्ति व्यवधानों के कारण गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में संभावित लागत-दबाव से होने वाली बढ़ोतरी से खाद्य कीमतों में संभावित गिरावट प्रभावित हो सकती है।

यह मौद्रिक नीति रिपोर्ट जब घोषित की जा रही है तो उस समय वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य पर कोविड-19 नामक महामारी की छाया है। अप्रैल 7, 2020 को विश्व के 211 देशों में 12 लाख से भी अधिक लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि और 67,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी जिनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, यह सब देखें तो मानवता के लिए इस त्रासदी की मात्रा और गति भयावह है। प्रभावित देशों की बड़ी तादात ऐसी है जहां आर्थिक क्रियाकलापों में व्यवधान आया है, वैश्विक उत्पादन, आपूर्ति शृंखलाओं, व्यापार और पर्यटन में व्यापक विस्थापनों से विपरीत परिस्थितियों को और बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक उत्पाद सन 2020 में संकुचित होते दिखाई दे रहे हैं। समस्त विश्व के वित्तीय बाजार अत्यधिक परिवर्तनशीलता का अनुभव कर रहे हैं : इक्विटी बाजारों में तेज बिकवाली दर्ज हुई है, उतार-चढ़ाव ने वही स्तर छू लिया है जो वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान था, निरापदता की तरफ बढ़ने से सरकारी बान्डों से प्रतिलाभों में रिकार्ड गिरावट रही; जोखिम का दायरा बढ़ गया है; और वित्तीय स्थितियों में तंगहाली आ गई है। वैश्विक पण्यों की कीमतों, खासकर कच्चे तेल, में एक तरफ तो कमजोर पड़ रही वैश्विक मांग की प्रत्याशा और दूसरी तरफ पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और रूस के बीच वार्ताओं में विफलता के कारण, तेजी से गिरावट हुई।

बहुत से केन्द्रीय बैंकों ने मौद्रिक, चलनिधि और विनियामक नीतियों में ढील दी है ताकि घरेलू मांग को समर्थन दिया जा सके, इनमें आपातकालीन ऑफ-साइकल बैठकें भी शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान कुछ केन्द्रीय बैंकों के बीच निर्धारित द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्थाओं को इस समय सक्रिय कर दिया गया है। जी-7 वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने कहा है कि सामयिक और प्रभावी उपायों के लिए वे और भी सहयोग करने को तत्पर हैं। जी-20 वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने वचन दिया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए वे सब प्रकार के उपलब्ध नीतिगत उपायों का प्रयोग करेंगे। जी-20 लीडरों ने यह संकल्प लिया है कि इस विश्वव्यापी महामारी से जीतने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह सब किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (अमुको) और विश्व बैंक का समूह क्रमशः 50 बिलियन अमरीकी डॉलर और 14 बिलियन अमरीकी डॉलर की रकम देकर विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से अपने सदस्यों का वित्तपोषण कर रहे हैं ताकि इस संकट का प्रतिसाद किया जा सके।

घरेलू अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो भारत भी कोविड-19 के भयानक प्रकोप से अछूता नहीं रह सका है और 7 अप्रैल तक 4,700 से भी अधिक मामले रिपोर्ट किए जा चुके थे। यद्यपि इसके फैलाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि कोविड-19 का भारत में आर्थिक क्रियाकलापों पर और स्वदेशीय लॉकडाउन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। प्रभावों का दूसरा दौर वैश्विक व्यापार और संवृद्धि में भीषण मंदी से संचालित होगा। तत्काल प्रभाव देखेंगे तो वित्त और कॉन्फिडेंस चैनलों के माध्यम से स्वदेशी वित्तीय बाजार पर कुप्रभाव पड़ रहे हैं। इन कुप्रभावों और इनकी अन्तः क्रियाओं से संवृद्धि में गिरावट की गति का बढ़ना अपरिहार्य हो जाएगा, यह गिरावट 2018-19 की पहली तिमाही से ही आरंभ हो गई थी और 2019-20 की दूसरी छमाही में भी बनी रही। इसी बीच हेडलाइन मुद्रास्फीति दिसम्बर 2019-फरवरी 2020 के दौरान मुद्रास्फीति के लक्ष्यगत बैंड के ऊपरी सहनशीलता बैंड से अधिक ही बनी रही, इसमें सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही। यद्यपि यह शीर्ष पर है और सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही है, तथापि मुद्रास्फीति पर कोविड-19 का प्रभाव संवृद्धि के सापेक्षतया बहुअर्थी है, आपूर्ति व्यवधानों के कारण गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में संभावित लागत-दबाव में बढ़ोतरी से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में संभावित कमी पर प्रभाव पड़ेगा।

* 09 मार्च, 2020 को जारी किया गया।

मौद्रिक नीति समिति : अक्टूबर 2019-मार्च 2020

अक्टूबर 2019-मार्च 2020 के दौरान मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की चार बैठकें हुईं। समिति की जो बैठकें 31 मार्च, 1 अप्रैल और 3 अप्रैल 2020 को होनी थीं वे 24, 26, और 27 मार्च 2020 को ही कर ली गईं। अक्टूबर 2019 की अपनी बैठक में मौद्रिक नीति समिति ने यह उल्लेख किया था कि निरन्तर हो रही गिरावट के कारण गहन प्रयास अपेक्षित हैं ताकि संवृद्धि की बढ़ोतरी को बहाल किया जा सके। सन 2019-20 की शेष अवधि और 2020-21 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के लक्ष्य से कम रहने की प्रत्याशा में मौद्रिक नीति समिति का यह दृष्टिकोण रहा कि लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यबद्धता के व्यादेश के भीतर रहते हुए संवृद्धि की चिन्ताओं से निपटने के लिए नीतिगत अंतराल का प्रयोग किया जा सकता है। तदनुसार इसने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 5.15 प्रतिशत करने के पक्ष में वोट दिया (5 सदस्यों ने 25 आधार अंकों की कमी करने के लिए वोट दिया और एक सदस्य ने इसे 40 आधार अंक करने के लिए वोट दिया), और इसने यह सहमति दी कि संवृद्धि को बहाल करने के लिए जब तक जरूरी हो तब तक इस निभावकारी रुख को बनाए रखा जाए, जबकि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

एमपीसी ने अपनी दिसम्बर 2019 और फरवरी 2020 की बैठकों में यह निर्णय किया कि नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा जाए। इन बैठकों में चर्चाओं के दौरान यह पाया गया कि घरेलू मांग की स्थितियों में कमजोरी आई है, जबकि मुद्रास्फीति तेजी से ऊपर गई और इसने नवम्बर और दिसम्बर 2019 में अधिदेशित मुद्रा स्फीति बैंड के ऊपरी सहनशीलता स्तर को भी तोड़ दिया। संवृद्धि-मुद्रास्फीति के उद्विकसित हो रहे डायनामिक्स को देखते हुए, एमपीसी ने यह उचित समझा कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, यद्यपि इसने आगामी नीतिगत प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध दायरे को देखते हुए संवृद्धि की बहाली के लिए जब तक जरूरी हो तब तक निभावकारी रुख को बनाए रखने के लिए वोट दिया।

मार्च में अपनी निर्धारित समय से पहले आयोजित बैठक में एमपीसी ने यह उल्लेख किया कि इस विश्वव्यापी महामारी के कारण मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्षों पर आने वाले जोखिम बहुत गंभीर हो सकते हैं, और घरेलू अर्थव्यवस्था को इस महामारी से बचाने के लिए जो भी अनिवार्य हो उस पर जोर दिया। एमपीसी ने

नीतिगत रेपो दर को 75 आधार अंक घटाकर 4.4 प्रतिशत पर किया (4 सदस्यों ने 75 आधार अंकों की कमी करने के लिए वोट दिया और 2 सदस्यों ने इसे 50 आधार अंक करने के लिए वोट दिया)। फरवरी-मार्च 2020 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए ताकि अर्थव्यवस्था में चलनिधि, मौद्रिक पारेषण और क्रेडिट प्रवाह में और भी सुधार किया जा सके साथ ही ऋण-ब्याज चुकौती में राहत प्रदान की गई (अध्याय IV)।

एमपीसी की मतदान पद्धति से अलग-अलग सदस्यों के आकलन, प्रत्याशाएं और नीतिगत प्राथमिकताएं प्रकट होती हैं, जैसा कि अन्य केन्द्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति समितियों से भी प्रकट होता है (तालिका I.1)।

समष्टि आर्थिक परिदृश्य

अध्याय II और III में अक्टूबर 2019-मार्च 2020 के दौरान समष्टि आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है और मुद्रास्फीति विचलनों तथा प्रेक्षकों से प्राप्त संवृद्धि परिणामों को स्पष्ट किया गया है। परिदृश्य की तरफ देखते हुए विगत छह माह के दौरान महत्वपूर्ण समष्टि आर्थिक और वित्तीय चरों के उद्विकास से जरूरी हो जाता है कि बेसलाइन प्रत्याशाओं में संशोधन किया जाए (तालिका I.2)।

सर्वप्रथम तो यह कि अक्टूबर 2019 में हुई मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बाद से अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों (भारतीय बास्केट) में व्यापक उतार-चढ़ाव हुए हैं। दिसम्बर 2019 के अंत और

सारणी I.1: मौद्रिक नीति समिति तथा मतदान पैटर्न

देश	नीति बैठकें : अक्टूबर 2019 – मार्च 2020		
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति के साथ बैठक	असहमति के साथ बैठक
ब्राज़ील	4	4	0
चिली	5	4	1
कोलंबिया	4	4	0
चेक गणराज्य	5	2	3
हंगेरी	5	5	0
इजरायल	4	0	4
जापान	4	0	4
दक्षिण अफ्रीका	3	2	1
स्वीडन	3	2	1
थाईलैंड	5	3	2
यूके	6	3	3
यूएस	5	3	2

स्रोत: केन्द्रीय बैंक वेबसाइट।

सारणी 1.2: पूर्वानुमानों के लिए आधारभूत अनुमान

संकेतक	एमपीआर अक्टूबर 2019	एमपीआर अप्रैल 2020
कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान प्रति बैरल यूएस \$ 62.6	2020-21 के दौरान प्रति बैरल यूएस \$ 35
विनिमय दर	₹.71.3/यूएस\$	₹.75/यूएस\$
मानसून	2019 के लिए दीर्घावधि औसत के 10 प्रतिशत ऊपर	2020 के लिए सामान्य
वैश्विक संवृद्धि	2019 में 3.2 प्रतिशत 2020 में 3.5 प्रतिशत	2020 में संकुचन
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2019-20 के भीतर रहेगी केंद्र : 3.3 संयुक्त: 5.9	बीई 2020-21 के भीतर रहेगी केंद्र : 3.5 संयुक्त: 6.1
पूर्वानुमान की अवधि के दौरान घरेलू समष्टि आर्थिक / स्ट्रक्चरल नीतियां	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

- टिप्पणियाँ :**
1. कच्चे तेल का भारतीय बास्केट ऐसे व्युत्पन्न मूल्य मापन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सॉअर ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट) कच्चा तेल शामिल है।
 2. यहाँ अनुमानित विनिमय दर पथ आधारभूत अनुमान हासिल करने के उद्देश्य के लिए है तथा यह विनिमय दर के स्तर पर कोई "मत" प्रकट नहीं करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित है, न कि विनिमय दर के आसपास किसी भी विशिष्ट स्तर के और/या बैंड के उतार-चढ़ाव से।
 3. बीई : बजट अनुमान।
 4. संयुक्त राजकोषीय घाटे में केंद्र और राज्यों को एक साथ लिया है।

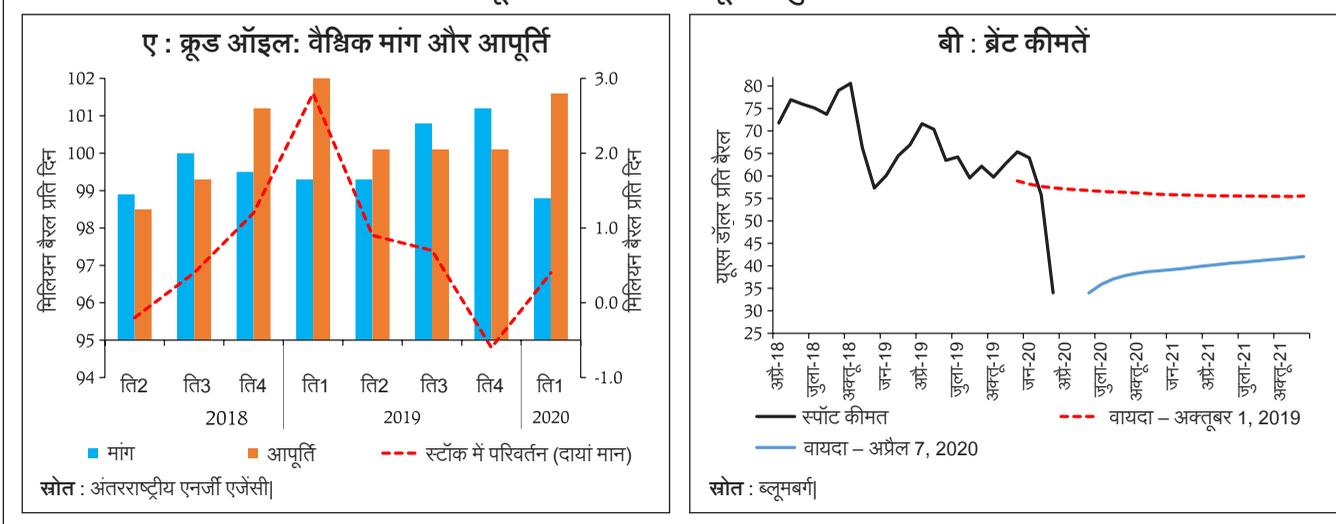
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान, बजट दस्तावेज़; और आईएमएफ।

जनवरी के आरंभ की अवधि के दौरान शुरुआत में इन कीमतों में प्रति बैरल लगभग 70 अमरीकी डॉलर की बढ़ोतरी हुई, जो कि

अमरीकी-ईरानी तनाव के कारण रही। बाद में इनमें नरमी आई, हालांकि कोविड-19 फैलने और इसके तीव्र भौगोलिक संक्रमण के बाद न्यूनतर वैश्विक मांग की प्रत्याशा में मार्च के शुरुआती दिनों में ये कीमतें 51 अमरीकी डॉलर पहुंच गईं। उत्पादन में कटौती के बारे में रूस के साथ सहमति होने में विफलता के कारण साउदी अरब द्वारा उत्पादन बढ़ाने और कीमतों में कटौती के निर्णय की वजह से 9 मार्च 2020 को ब्रेन्ट कीमतें गिरकर 32 अमरीकी डॉलर पर आ गईं। मार्च 30, 2020 को ब्रेन्ट और भी गिरकर 23 अमरीकी डॉलर पर आ गया जबकि 30 मार्च 2020 को अमरीकी कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय के लिए 20 अमरीकी डॉलर से नीचे रहीं। ब्रेन्ट अप्रैल 3 को फिर से उछल कर 34 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वर्तमान मांग-आपूर्ति के आकलन को देखते हुए, बेसलाइन परिदृश्य में प्रत्याशा है कि कच्चे तेल की कीमतें (भारतीय बास्केट) में 2020-21 के दौरान प्रति बैरल औसतन 35 अमरीकी डॉलर के आसपास रहेंगी (चार्ट 1.1)।

दूसरे यह कि सामान्य विनिमय दर (भारतीय रुपया या आइएनआर की तुलना में अमरीकी डॉलर) ने अक्टूबर-दिसम्बर 2019 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से द्वि-मार्गीय गतिविधि दिखाई है। जनवरी-मध्य के आरंभ से ही आइएनआर बहुत ही तीक्ष्ण और अनवरत मूल्यहास के दबावों में आ गया, जो कि सुरक्षित स्थलों की तलाश में उदीयमान बाजारों की मुद्राओं की सामान्यकृत कमजोरी को दिखाता है। तदनुसार हाल ही की इन गतिविधियों को दर्शाते हुए बेसलाइन में औसतन प्रति डालर 75 भारतीय रुपये होने की प्रत्याशा की गई है।

चार्ट 1.1: कूड ऑइल: मांग-आपूर्ति संतुलन और कीमतें

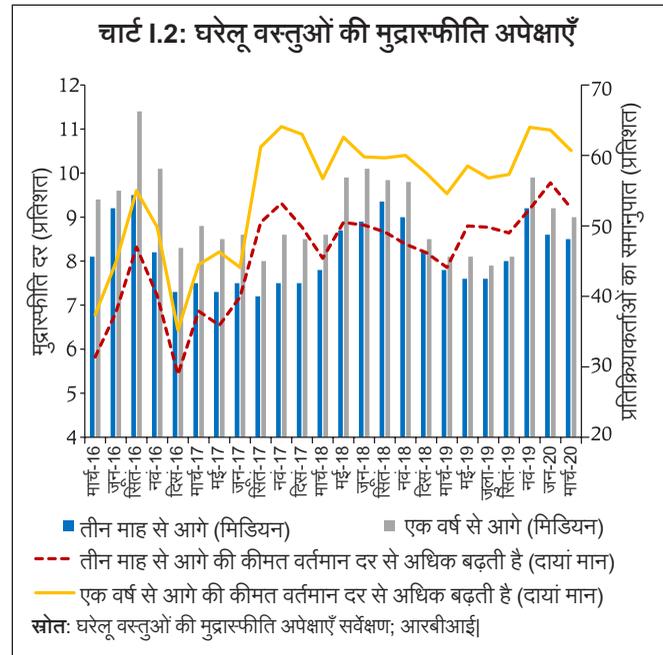


तीसरे यह कि, यद्यपि अमरीका-चीन संबंधों और ब्रेक्सिट से संबद्ध अनिश्चितताओं में कुछ कमी आई है, लेकिन अब कोविड-19 हावी हो गया है। इसकी छाया समष्टि आर्थिक परिदृश्य पर पड़ चुकी है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं, व्यापार, पर्यटन और होटल उद्योग प्रचंड रूप से प्रभावित हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के माल और सेवाओं संबंधी ट्रेड बैरोमीटर ने संकेत दिए हैं कि 2020 के आरंभ में विश्व व्यापार की मात्रा में होने वाली संवृद्धि कमजोर है; यह प्रत्याशित है कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से इसमें और भी कमजोरी आएगी। अमुको का अनुमान है कि 2020 में वैश्विक उत्पादन में होने वाला संकुचन 2009 के जितना या उससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। सन 2021 में मंदी की प्रवणता और बहाली की गति इस महामारी पर काबू पाने की गति और विभिन्न देशों द्वारा राजकोषीय नीति की प्रक्रियाओं की कुशलता पर निर्भर करेगी। कोविड-19 के लम्बे समय तक बने रहने के डरावने परिदृश्य में इस मंदी की दीर्घता और भी लम्बी हो सकती है। आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुमानों में कहा गया है कि जितने महीनों तक सख्त संरोधन उपाय लागू रहेंगे उनमें प्रत्येक माह हेतु वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि में 2 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। यदि यह बन्दी तीन माह तक चलती रही तो बिना किसी ऑफसेट घटक के यह उस स्तर से 4-6 प्रतिशत अंक नीचे रहेगी जो अन्यथा रहा होता।

1.1 मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण

हेडलाइन उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई) मंहगाई ने दिसम्बर 2019 में लक्ष्य के ऊपरी सहनशीलता बैंड को तोड़ा और जनवरी 2020 में यह शिखर पर रहा, फिर सब्जियों, फलों और पेट्रोलियम उत्पादों की गिरती हुई कीमतों से फरवरी के दौरान इसमें 100 आधार अंकों की गिरावट आई। निकट-अवधि में मुद्रास्फीति प्रक्षेप-पथ की दिशा सब्जियों की कीमतों में उछाल, अन्य खाद्यों की कीमतों पर स्फीतिकारी दबावों के प्रसार, प्रमुख स्फीति के विभिन्न तत्वों पर एकबारगी पड़ने वाले लागत-दबाव प्रभावों और खासकर कोविड-19 के प्रकोप के प्रसार से निर्धारित होगी।

तीन माह और एक वर्ष से आगे देखें तो शहरी हाउसहोल्ड में माध्यक स्फीति अनुमानों में क्रमशः 10 और 20 आधार

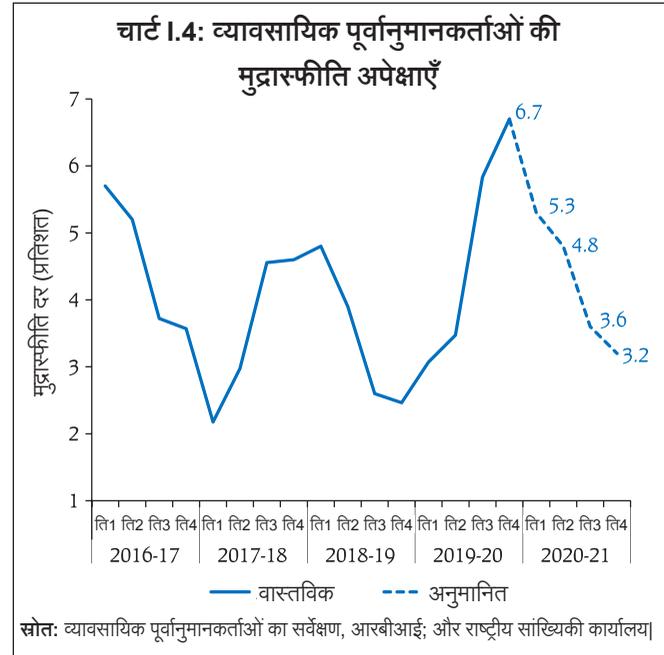
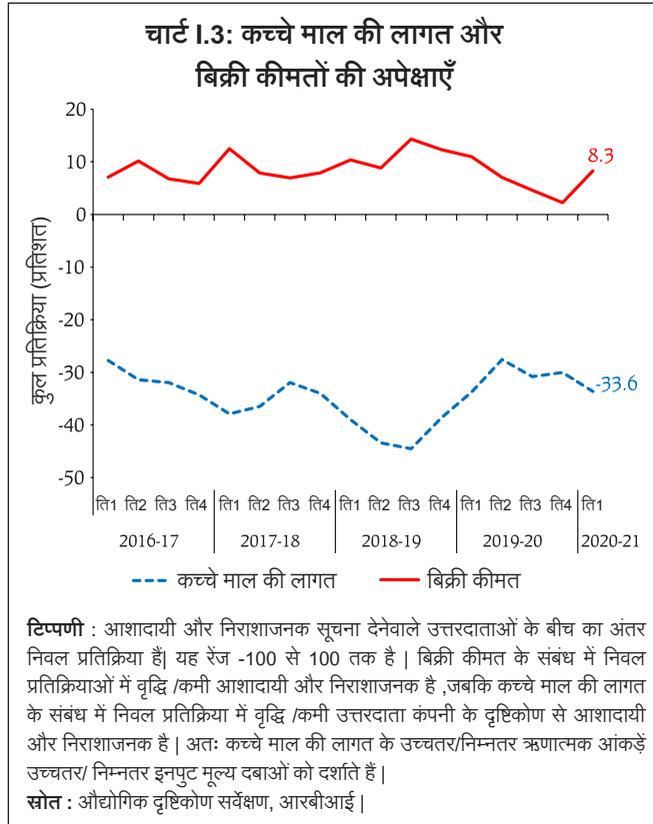


अंको की नरमी रहेगी, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित सर्वे के मार्च 2020 चक्र में बताया गया है।¹ सामान्य कीमत स्तर में वर्तमान दर से अधिक दर पर बढ़ोतरी की प्रत्याशा करने वाले प्रतिसादकर्ताओं का समानुपात भी जनवरी 2020 के चक्र की तुलना में तीन माह और एक वर्ष दोनों ही से आगे के परिप्रेक्ष्य में भी वर्तमान दर की तुलना में गिरावट रही है (चार्ट 1.2)। यद्यपि व्यापक रूप से अनुकूलनीय हाउसहोल्ड और फर्मों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं कीमत और मजदूरी निर्धारक व्यवहार के माध्यम से भावी मुद्रास्फीति को आकार दे सकते हैं। मार्च 2020 के लिए रिज़र्व बैंक ग्राहक कॉन्फिडेंस सर्वे के अनुसार विगत चक्र की तुलना में मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में संयमन रहा है।²

रिज़र्व बैंक के जनवरी-मार्च 2020 दौर के औद्योगिक परिदृश्य सर्वे में विनिर्माता फर्मों ने यह प्रत्याशा दर्शाई है कि 2020-21 की पहली तिमाही में बिक्री कीमतों के साथ-साथ कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी होगी; इसके बावजूद फर्मों की कीमत निर्धारण शक्ति कमजोर रहने का अनुमान है (चार्ट 1.3)³।

¹ रिज़र्व बैंक के हाउसहोल्ड हेतु मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वे 18 शहरों में संचालित किए जाते हैं और मार्च 2020 सर्वे के परिणाम 27 फरवरी – 7 मार्च 2020 के दौरान किए गए 5,912 हाउसहोल्डों से प्राप्त प्रतिसादों पर आधारित हैं।

² रिज़र्व बैंक के ग्राहक कॉन्फिडेंस सर्वे 13 प्रमुख शहरों में संचालित किए जाते हैं और मार्च 2020 चक्र के परिणाम 27 फरवरी – 7 मार्च 2020 के दौरान किए गए 5,365 हाउसहोल्डों से प्राप्त प्रतिसादों पर आधारित हैं।



विनिर्माताओं और सेवाओं के लिए खरीद प्रबंधकों के सर्वे में यह बताया गया कि मार्च 2020 के लिए इनपुट और आउटपुट कीमतों में बढ़ोतरी की दर में संयतता रहेगी।

मार्च 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए व्यावसायिक अनुमानकर्ताओं के सर्वे में यह अनुमान है कि फरवरी 2020 में सीपीआई मंहगाई 6.6 प्रतिशत से घटकर 2020-21 की पहली तिमाही में 5.3 प्रतिशत पर और 2020-21 की चौथी तिमाही तक 3.2 प्रतिशत पर आ जाएगी (चार्ट I.4)⁴।

इस प्रकार अग्र-दर्शी संकेतकों की श्रेणी कहीं अधिक नरम प्रक्षेपपथ की तरफ इशारा कर रही है। आगे चलकर मुद्रास्फीति जोखिम का संतुलन भी आगे तक नीचे की दिशा में झुका हुआ है। प्रथम, तो खाद्यान्नों और बागवानी के रिकार्ड उत्पादों के लाभदायक प्रभावों के तहत खाद्य वस्तुओं की कीमतें नरम हो सकती हैं, कम-से-कम सामान्य ग्रीष्म अपस्टिक की शुरुआत

होने तक तो रहेगा ही। द्वितीय, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति के दबावों को सहज बनाने की दिशा में काम करेगी, जो कि खुदरा कीमतों तक इनके पारगमन के स्तर पर निर्भर करेगा। ये सभी संकेत, हालांकि, पूरी तरह से कोविड-19 की गहनता, दायरे और अवधि से परिचालित होंगे और इस महामारी की इन विशिष्टताओं में किसी प्रकार के बदलाव इस परिदृश्य में भारी बदलाव पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में पूर्वानुमान बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इस महामारी के बारे में आने वाले प्रत्येक तथ्य के साथ इन पूर्वानुमानों में बड़े बदलाव करने होंगे। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को यह शक्ति देता है कि मौद्रिक नीति रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशन की तारीख के 6-18 माह के भीतर मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों को प्रकाशित करे और इनका विवरण दे। इसलिए, आरंभिक स्थितियों को, अग्रदर्शी सर्वेक्षणों के संकेतों और टाइम-सीरीज और संरचनागत प्रदर्शकों के पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए अंतरिम अनुमान है कि यह 2020-21 की पहली तिमाही के 4.8 प्रतिशत से कम होकर दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 2.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 2.4 प्रतिशत पर आ जाएगी, इसके साथ ही यह भी चेतावनी रहेगी कि वर्तमान की अत्यधिक अनिश्चितता के कारण जितना इस समय अनुमान लगाया गया है उसकी तुलना में सकल मांग और भी कमजोर पड़ सकती है और प्रमुख स्फीति में और भी राहत आ सकती है, जबकि आपूर्ति की बाधाएं प्रत्याशा

³ औद्योगिक परिदृश्य सर्वे के जनवरी-मार्च 2020 दौर के (30 जनवरी 2020 को आरंभ) परिणाम 18 मार्च 2020 तक प्राप्त 860 प्रतिसादों पर आधारित हैं।

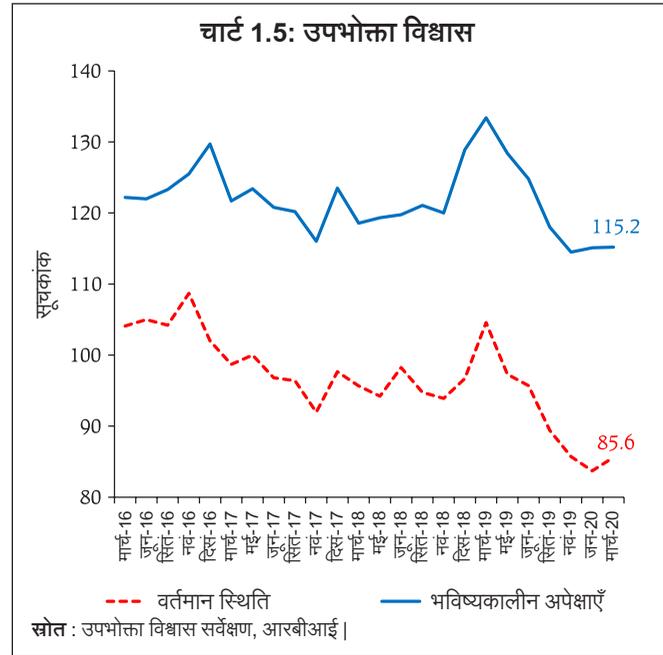
⁴ रिज़र्व बैंक द्वारा व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के लिए मार्च 2020 के दौर के 6-19 मार्च 2020 के दौरान किए गए सर्वे में 25 पैन्लिस्ट शामिल हुए थे।

से अधिक दबावों का सृजन कर सकती हैं। इसका उभयपक्ष यह भी है कि कोविड-19 पर तेजी से काबू तीव्र बहाली की तरफ ले जाएगा, और इसलिए स्फीति के दबाव मजबूत हो जाएंगे। इस लॉकडाउन को देखते हुए मार्च और आगामी कुछ माह के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के लिए सीपीआई का समेकन करना चुनौती भरा हो सकता है, ऐसे में संरचनागत प्रदर्श के अनुमानों से संकेत मिलते हैं कि स्फीति 3.6-3.8 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।

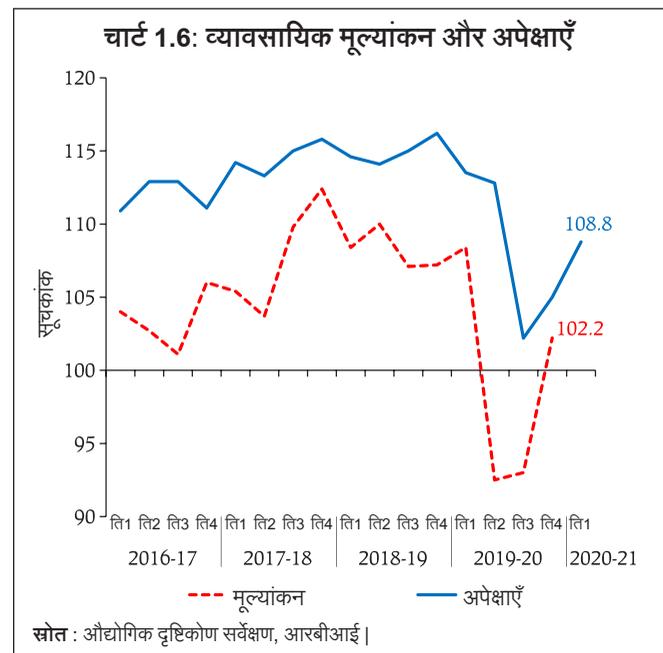
1.2 संवृद्धि के लिए दृष्टिकोण

कोविड-19 का प्रकोप आरंभ होने से पहले 2020-21 के लिए संवृद्धि का परिदृश्य ऊपर को जा रहा था। सर्वप्रथम तो 2019-20 के दौरान रबी की बम्पर फसल और खाद्यों की उच्चतर कीमतों ने ग्रामीण मांग में प्रबलता के लिए सहायक स्थितियां प्रदान कर दी थीं। दूसरे यह कि नीतिगत दरों में हुई कटौती का लाभ बैंकों द्वारा उधार देने की दरों में पारेषित करने में सुधार हो रहा है, इससे उपभोग और निवेश दोनों ही की मांग के लिए अनुकूल निहितार्थ रहेंगे। तीसरे यह कि सितम्बर में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती, कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती और ग्रामीण तथा अवसंरचनाओं पर होने वाले व्यय को बढ़ाने के उपायों का लक्ष्य यही था कि घरेलू मांग और भी सामान्य रूप से बढ़ती रहे। कोविड-19 महामारी ने इस परिदृश्य को बुरी तरह से बदल डाला है। अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में मंदी की चपेट में रहेगी, जैसा कि कोविड उपरांत के अनुमानों से संकेत मिल रहे हैं। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट, यदि बनी रही, तो देश की व्यापार शर्तों को सुधार सकती है, लेकिन इस चैनल से होने वाले अर्जनों से यह आशा नहीं है कि यह शटडाउन और बाहरी मांग में हुई गिरावट से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी।

भावी दृष्टि रखने वाले सर्वेक्षणों से मिलने वाले अहम संदेशों को देखा जाए तो पाते हैं कि रिजर्व बैंक सर्वे के मार्च 2020 दौर से ज्ञात होता है कि आगामी वर्ष के लिए ग्राहक कॉन्फिडेंस जनवरी 2020 के विगत सर्वे दौर में दर्ज स्तर के आसपास ही बना रहेगा (चार्ट 1.5)। हालांकि, इस खंड में भावी-दृष्टि वाले सर्वेक्षणों के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी यही है कि ये सब 25 मार्च को प्रभावी हुए देश-व्यापी लॉकडाउन से पहले ही पूरे कर लिए गए थे।



रिजर्व बैंक औद्योगिक सर्वे के जनवरी-मार्च 2020 दौर में आगामी तिमाही के लिए विनिर्माता क्षेत्र के लिए आशावादिता बढ़ी है जो कि उच्चतर उत्पादन, आर्डर बहियों, क्षमता उपभोग, रोजगार स्थितियों, आयातों और समग्र कारोबारी स्थिति की प्रत्याशाओं को दिखाता है (चार्ट 1.6)। कोविड-19 की प्रचंडता को देखते हुए चुनिंदा पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए 18-20 मार्च के दौरान विशेषरूप से त्वरित सर्वे किया गया ताकि कारोबारी

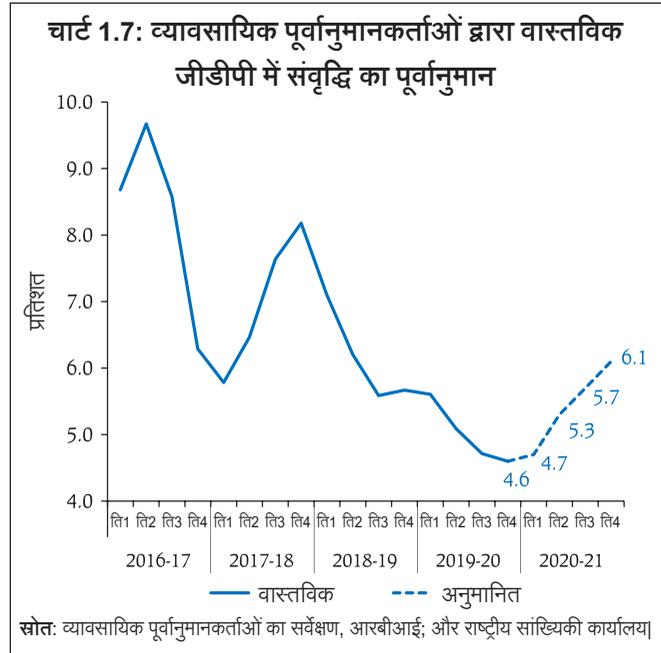


संवेदनाएं हासिल की जा सकें। प्राप्त हुए प्रतिसादों से 2020-21 की प्रथम तिमाही के परिदृश्य में मांग संकेतकों में महत्वपूर्ण विकृति दिखाई दे रही है।

अन्य एजेन्सियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों (कोविड-19 के प्रकोप से पहले किए गए) में भावी कारोबारी प्रत्याशाओं में काफी आशावादिता के संकेत मिले (तालिका 1.3)। मार्च 2020 के लिए परचेजिंग मैनेजरों के सर्वेक्षणों के अनुसार विनिर्माता फर्मों के एक वर्ष आगे के कारोबारी अनुमान सर्वाधिक कमजोर स्तर तक जा पहुंचे, जो कि कोविड-19 से हुए लम्बे व्यवधान के भय के कारण है। सेवा क्षेत्र की फर्मों में भी कारोबारी प्रत्याशाओं में गिरावट आई है।

मार्च 2020 दौर के लिए रिजर्व बैंक कि सर्वे (राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले मार्च 6-19 के दौरान किए गए) में व्यावसायिक पूर्वानुमाकर्ताओं ने बताया कि वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 2019-20 की चौथी तिमाही में 4.6 से बढ़कर 6.1 प्रतिशत पर आने का अनुमान है (चार्ट 1.7 और तालिका 1.4)।

समग्रतया कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों की सतत प्रतिकारिता के अलावा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी इस महामारी का, इसके प्रकोप, दायरे और समयावधि, पर निर्भर करते हुए, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य



नीतिगत उपायों और यदि कोविड-19 समय रहते काबू में आ जाता है तो इससे सापेक्षतया संयत बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसी अनिश्चितताएं मुद्रास्फीति और संवृद्धि को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना देती हैं (बॉक्स 1.1)।

सारणी 1.4: अनुमान - व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता

(प्रतिशत)

सारणी 1.3: कारोबारी प्रत्याशा सर्वे

मद	एनसीईईआर बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (फरवरी 2020)	फिक्की समग्र बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (जनवरी 2020)	दून और ब्रेडस्ट्रीट कम्पोजीट बिजनेस आइटिमिज्म इंडेक्स (मार्च 2020)	सीआईआई बिजनेस कांफिडेंस इंडेक्स (मार्च 2020)
सूचकांक का वर्तमान स्तर	111.2	59.0	63.0	53.4
पिछले सर्वे के अनुसार सूचकांक	103.1	55.0	56.4	49.4
% परिवर्तन (ति-दर-ति) क्रमिक	7.9	7.3	11.7	8.1
% परिवर्तन (वर्ष -दर-वर्ष)	-12.4	-2.2	-14.6	-18.1

टिप्पणी :

1. एनसीईईआर : नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च।
2. एफआईसीसीआई : फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
3. सीआईआई : कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।

व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के माध्यिका अनुमान	2019-20	2020-21
मुद्रास्फीति, चौथी तिमाही (वर्ष-दर-वर्ष)	6.7	3.2
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि	5.0	5.5
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	29.4	29.5
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	30.0	30.0
अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण में वृद्धि	7.2	9.3
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	6.8	6.5
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	3.8	3.6
रेपो रेट (समाप्त-अवधि)	5.15	4.65
91-दिवसीय खजाना बिल पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	4.9	4.7
10-वर्षीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.2	6.1
समग्र भुगतान शेष (यूएस \$ बिलियन)	49.8	40.0
पण्य निर्यात वृद्धि	-2.9	-0.6
पण्य आयात वृद्धि	-7.2	-2.9
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-1.0	-0.7

टिप्पणी : जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

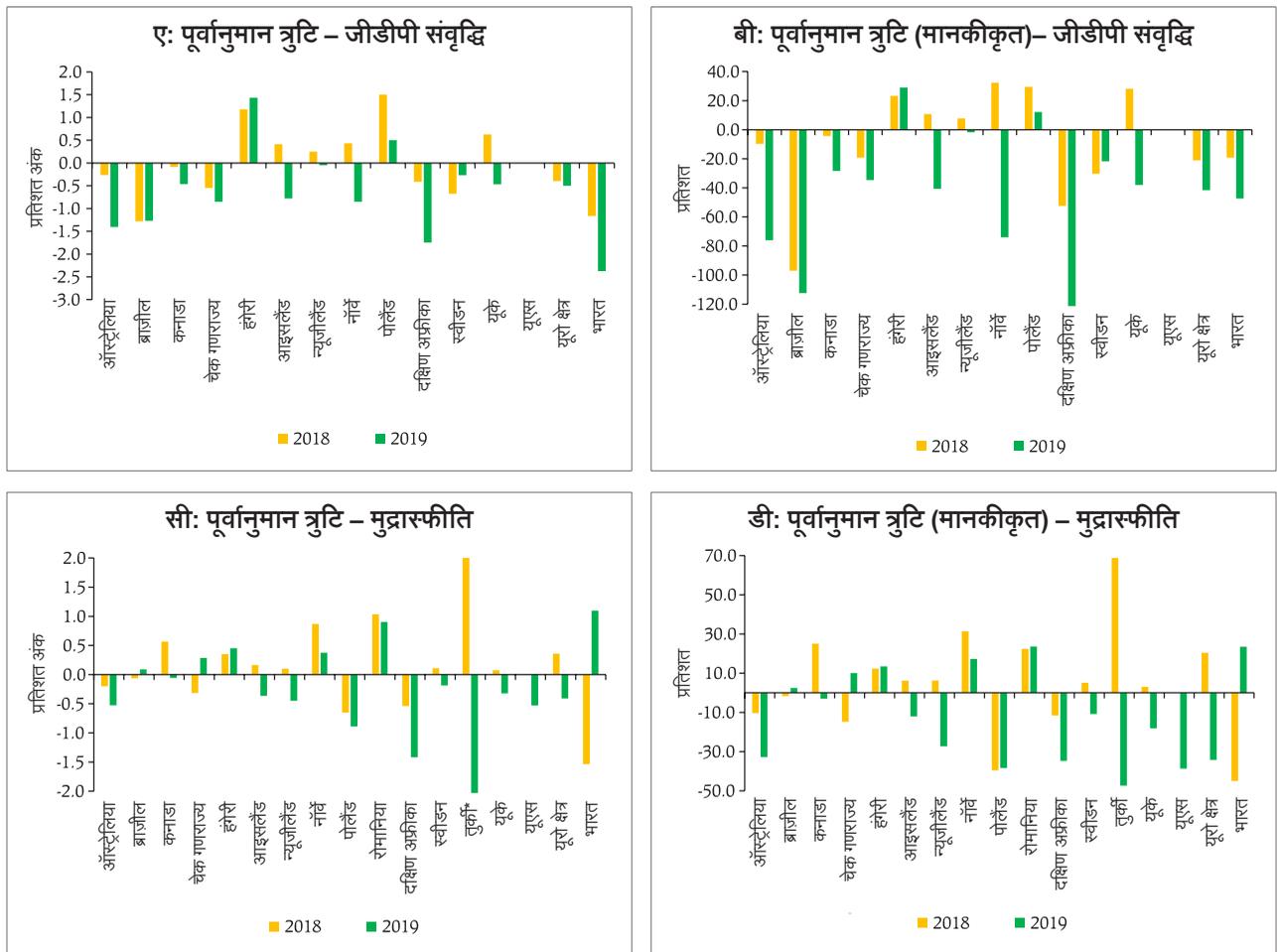
स्रोत : व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण(मार्च 2020 का दौर, मार्च 6-19, 2020 के दौरान किया गया)।

बाक्स I.1: चक्रीय अधोगति में होनेवाली अनिश्चितता में पूर्वानुमान

मौद्रिक नीति की संक्रियाओं से उत्पादन और मुद्रास्फीति दीर्घ और परिवर्तनशील अंशों में प्रभावित होते हैं। इसलिए उत्पादन और मुद्रास्फीति के बारे में समय रहते और विश्वसनीय पूर्वानुमान बहुत ही काम का महत्व रखते हैं। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों, वैश्विक व्यापार और संवृद्धि, विनिमय दर, मानसून का आगमन और आयनों पर उनके आने की बढ़ती हुई बारम्बारता जैसे महत्वपूर्ण कन्डीशनिंग चराकों पर घरेलू और वैश्विक आघातों से पूर्वानुमान लगाने का कार्य

चुनौतीपूर्ण हो जाता है, हालांकि यह क्रांतिकारी मोड़ों पर खास तौर पर होता है। चुनिंदा 17 केन्द्रीय बैंकों के लिए 2018 और 2019 के मुद्रास्फीति और जीडीपी संवृद्धि पूर्वानुमानों के विश्लेषण में, भारतीय रिजर्व बैंक सहित, अधिकांश आरंभ में आर्थिक क्रियाकलापों (अर्थात् ऋणात्मक पूर्वानुमान त्रुटियों) के बारे में आशावादी थो⁵ मानकीकृत पूर्वानुमान त्रुटियां (अर्थात् वास्तविक संवृद्धि दर/मुद्रास्फीति से विभाजित की गई त्रुटियां) तुलनीय थीं (चार्ट I.1.1)।

चार्ट I.1.1: संवृद्धि और मुद्रास्फीति पूर्वानुमान निष्पादन



टिप्पणी : पूर्वानुमान त्रुटि (मानकीकृत) वास्तविक किसी देश की जीडीपी संवृद्धि/मुद्रास्फीति की प्रतिशतता के रूप में पूर्वानुमान त्रुटि कहलाती है।

* वर्ष 2018 में 15.4 प्रतिशतता अंक और वर्ष 2019 में (-)4.9 प्रतिशतता अंक; #: वर्ष में (-)1145 प्रतिशत

स्रोत : संबंधित केन्द्रीय बैंकों की वेबसाइटें; और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा आकलन।

(जारी)

⁵ इस विश्लेषण में भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, हंगेरी, आइसलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, टर्की, यूके, यूएस और यूरो क्षेत्र के केन्द्रीय बैंकों को शामिल किया गया था। रोमानिया और टर्की के मामले में जीडीपी संवृद्धि पूर्वानुमानों के अभाव में यह विश्लेषण मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों तक ही सीमित है। इस विश्लेषण का फोकस एक वर्ष आगे की पूर्वानुमान त्रुटियों पर है (वास्तविक परिणाम को पूर्वानुमानों में से घटाते हुए); इसलिए वर्ष 2018 और 2019 के जिन पूर्वानुमानों पर विचार किया गया है उनको क्रमशः 2017 और 2018 की अंतिम में तैयार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के जो पूर्वानुमान लिए गए हैं, वे क्रमशः फरवरी 2018 और फरवरी 2019 के नीतिगत वक्तव्यों में उपलब्ध थे।

पैनल रीग्रेशन परिणामों से पता चलता है कि वैश्विक संवृद्धि के अप्रत्याशित तथ्य एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो घरेलू पूर्वानुमान त्रुटियों में अंतर्निहित रहते हैं; कच्चे तेल की कीमतों के अप्रत्याशित तथ्यों का ऋणात्मक प्रभाव होता है, यद्यपि यह सार्थक नहीं होता (समीकरण 1)। हालांकि देश-विशेष की विशेष प्रकृति वाले घटकों के कारण मुद्रास्फीति पूर्वानुमान त्रुटियां अधिक प्रतीत होती हैं – घरेलू संवृद्धि पूर्वानुमान त्रुटियों के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित तथ्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं होते (समीकरण 2)। दोनों ही रीग्रेशनों में अचल राशियां सार्थक नहीं होती, जिससे ज्ञात होता है कि वैश्विक संवृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों के अप्रत्याशित तथ्यों के नियंत्रित हो जाने के बाद पूर्वानुमान त्रुटियां निष्पक्ष रहीं।

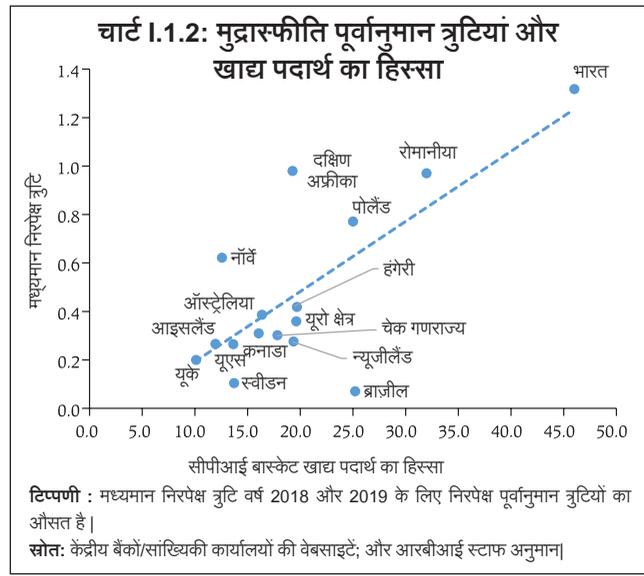
$$y_{fe_{it}} = 0.18 + 1.04 yw_{s_t} - 0.006 doil_{it} \dots\dots\dots (1)$$

(0.93) (4.91) (0.66)

$$\pi_{fe_{it}} = -0.12 + 0.09 y_{fe_{it}} + 0.002 doil_{it} \dots\dots\dots (2)$$

(1.27) (1.13) (0.14)

कोष्ठकों में दिए गए अंक t-सांख्यिकी; y_{fe} , π_{fe} , yw_s , $doil$ का क्रमशः आशय है संवृद्धि पूर्वानुमान त्रुटियां, मुद्रास्फीति पूर्वानुमान त्रुटियां, वैश्विक संवृद्धि के अप्रत्याशित तथ्य और स्थानीय मुद्रा के रूप में कच्चे तेल की कीमतों में परिवर्तना⁶



भारत में, सीपीआई (संयुक्त) में खाद्यों की बास्केट के उच्च अंश (45.9 प्रतिशत) (चार्ट 1.1.2) के साथ विगत जीडीपी संवृद्धि दरों में बड़े संशोधनों को देखते हुए, पूर्वानुमान की चुनौतियां कहीं अधिक तीक्ष्ण हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक भी अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह ही बेसलाइन प्रक्षेपणों के आसपास फैन चार्ट देता है ताकि भावी अनिश्चितता को बताया जा सके।

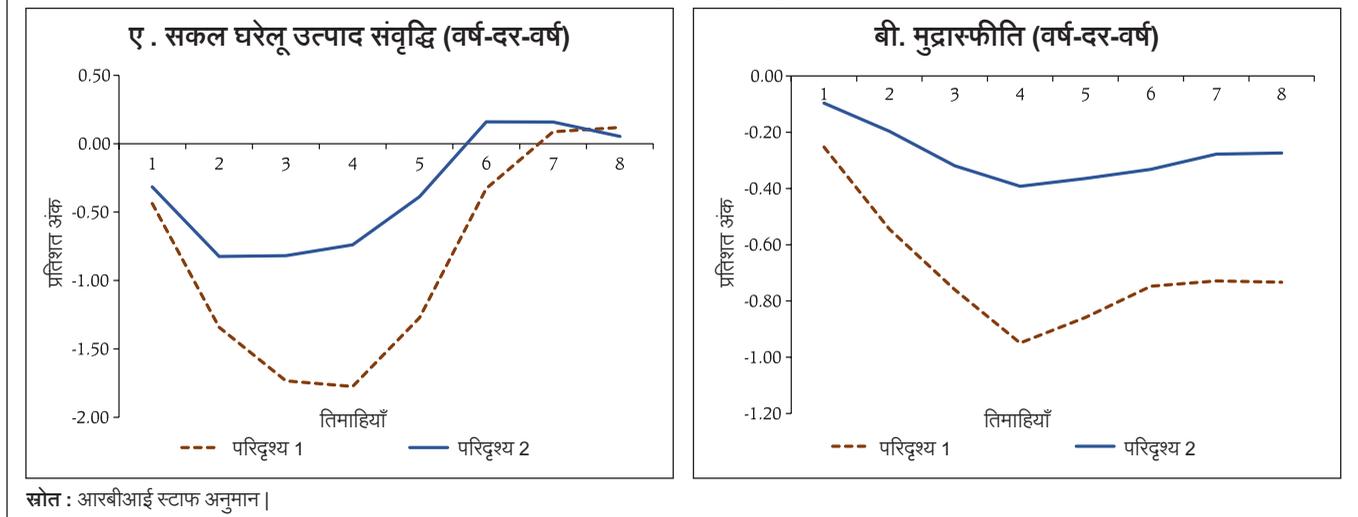
इस पृष्ठभूमि और खासकर जिन अत्यधिक अस्थिर परिस्थितियों में आंकड़े संवृद्धि परिदृश्य में दैनिक आधारों पर बदलाव पैदा करते हैं, उनमें भारत के जीडीपी संवृद्धि के पूर्वानुमानों को यहां नहीं दिया गया है, अभी कोविड-19 के तीक्ष्णता, दायरे और अवधि के बारे में स्पष्ट स्थिति की प्रतीक्षा की जा रही है। उदाहरण के लिए मार्च की शुरुआत में ओईसीडी ने 0.5-1.5 प्रतिशतता अंकों की श्रेणी में 2020 के लिए वैश्विक संवृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया था। अभी हाल ही में, 200 से भी अधिक देशों में कोविड-19 फैल जाने के कारण, अमुको का नवीनतम अनुमान यह है कि सन 2020 के दौरान वैश्विक संवृद्धि सन 2019 के दौरान 2.9 प्रतिशत (पूरे दशक के दौरान जो स्वयं ही न्यून थी) की संवृद्धि की तुलना में ऋणात्मक

हो सकती है। इस प्रकार से वैकल्पिक परिदृश्यों के तहत तिमाही प्रेक्षण प्रदर्श (क्यूपीएम)⁷ का प्रयोग करते हुए भारत की संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर वैश्विक मंदी के संभावित प्रभावों का आकलन किया जा सकता है। प्रथम परिदृश्य में प्रतिस्थापना है कि सन 2020 में वैश्विक संवृद्धि सन 2019 की तुलना में 3 प्रतिशतता अंक नीचे रहेगी। द्वितीय परिदृश्य में प्रतिस्थापना है कि इस प्रकोप पर तेजी से काबू पा लिया जाता है और वैश्विक उत्पाद संवृद्धि सन 2019 की तुलना में केवल 1.5 प्रतिशतता अंक का नुकसान होता है। न्यूनतर वैश्विक उत्पाद और मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को कई मार्गों से प्रभावित कर सकते हैं। प्रथम, यह निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, घरेलू मांग, संवृद्धि और स्फीति को नीचे ले जा सकता है। दूसरे, यह कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और अन्य पण्यों की कीमतें अत्यधिक उच्च परिवर्तनशीलता के बीच पहले ही काफी

⁶ वैश्विक संवृद्धि के अप्रत्याशित तथ्यों को हासिल करने के लिए वास्तविक वैश्विक संवृद्धि में से उन पूर्वानुमानों को घटा दिया गया है जो अमुको के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के पूर्ववर्ती वर्ष के अक्टूबर संस्करण में दिए गए थे। कच्चे तेल की कीमतों के अप्रत्याशित तथ्यों का आकलन पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम तिमाही में दिए गए स्तरों की तुलना में वर्ष के दौरान स्थानीय मुद्रा में व्यक्त कीमतों में परिवर्तन की प्रतिशतता के रूप में किया गया है।

⁷ नव केन्सीयन परम्परा में क्यूपीएम एक अर्ध-संरचनात्मक, अग्र-दर्शी, खुली अर्थव्यवस्था, अंशांकित, अंतराल प्रदर्श है और यह विभिन्न फीडबैक व्यवस्थाओं का आंतरिक रूप से संगत विश्लेषण प्रदान करता है।

चार्ट 1.8 : कोविड का प्रकोप : भारत की संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर वैश्विक मंदी का प्रभाव



तेजी से नरम हो चुकी है और निवल आयातक होने के कारण भारत को पण्यों की न्यूनतर कीमतों से लाभ हो सकता है। अंततः, वैश्विक वित्तीय बाजार की बढ़ी हुई परिवर्तनशीलता घरेलू वित्तीय बाजार में भी प्रविष्ट हो सकती है और संवृद्धि तथा स्फीति दोनों ही को प्रभावित कर सकती है। क्यूपीएम इन सभी चैनलों का अभिग्रहण करता है। इस प्रदर्श के अनुरूपणों से ज्ञात होता है कि वैश्विक घटकों के कारण घरेलू संवृद्धि, अपने शीर्ष पर, प्रथम परिदृश्य में 180 आधार अंक और द्वितीय परिदृश्य में 80 आधार अंक न्यूनतर हो सकती है। इन दोनो परिदृश्यों में स्फीति अपने शीर्ष पर 40-100 आधार अंक तक नीचे जा सकती है (चार्ट 1.8)।

1.3 जोखिमों का संतुलन

कोविड-19 महामारी ने बेसलाइन अनुमानों और आउटलुक के लिए अपसाइड और डाउनसाइड जोखिम पैदा कर दिए हैं।

(i) विनियम दर

अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की विनियम दर अभी हाल ही के महीनों में दोनों ही दिशाओं में गई है। कोविड-19 के समष्टि आर्थिक प्रभाव की अनिश्चितता के कारण, जैसा कि फरवरी-मार्च 2020 में रहा, वैश्विक वित्तीय बाजार की परिवर्तनशीलता के नए चक्रों से भारतीय रुपए पर दबाव पड़ सकता है। यदि भारतीय रुपया बेसलाइन से 5 प्रतिशत नीचे चला गया तो स्फीति में 20 आधार अंको के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है जबकि जीडीपी संवृद्धि बढ़े हुए निवल निर्यातों के कारण 15 आधार अंकों के आसपास उच्चतर हो सकती है। भारतीय

रुपये में 5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि मुद्रास्फीति में लगभग 20 आधार अंकों और बेसलाइन की तुलना में जीडीपी संवृद्धि लगभग 15 आधार अंक तक का संयमन ला सकती है।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रकोप और साउदी अरब द्वारा कीमतों में कटौती के कारण से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें अक्टूबर 2019 के अपने स्तर से तेजी से नीचे आई हैं। हालांकि, तेल का अल्प और मध्य अवधि का आउटलुक अत्यधिक अनिश्चित बना हुआ है। कोविड-19 पर समय रहते काबू पाने या नए प्रकार के भौगोलिक तनावों या उत्पादन में कटौती की सहमति के कारण V आकार लिए हुए वैश्विक बहाली की स्थिति कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों की दिशा तेजी से बदल सकती है। यदि कच्चे तेल की कीमतों की भारतीय बास्केट बेसलाइन अनुमानों से 10 प्रतिशत ऊपर जाती है तो मुद्रास्फीति 20 आधार अंक उच्चतर हो सकती है और संवृद्धि में 15 आधार अंकों के आसपास की कमजोरी आ सकती है। यदि कोविड-19 लम्बे समय तक बना रहा तो वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप और साउदी अरब द्वारा उत्पादन बढ़ाने के निर्णय के कारण सतत अति-आपूर्ति के परिवेश में कच्चे तेल की मांग में गिरावट आ सकती है। यदि भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बेसलाइन की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट आती है, तो मुद्रास्फीति 20 आधार अंकों की सहजता आ सकती है और संवृद्धि 15 आधार अंक उच्चतर हो जाएगा, लेकिन यह निर्भर करेगा कि घरेलू उत्पादों की कीमतों को इसे किस सीमा तक प्रभावित करने दिया गया है।

(iii) खाद्यों की कीमतें

काफी समय तक नियंत्रित रहने के बाद भारत में खाद्यों की मंहगाई में अक्टूबर 2019-जनवरी 2020 के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई, जो कि सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी से परिचालित हुई। बेसलाइन पथ में यह अनुमान रहा कि रबी फसल के आगमन और सन 2020 के दौरान दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के सामान्य रहने के साथ ही सब्जियों की कीमतों में तेजी से गिरावट हुई, जिसे संभावित एनसो (एल-नीनो-दक्षिणी स्पंदन) की उदासीन स्थितियों के बारे में समय रहते मिले संकेतों का भी समर्थन मिला। अनाज का पर्याप्त बफर भंडार और अच्छी रबी फसल (2019 का मौसम) खाद्यों की कीमतों को अनुमान से अधिक नरम कर सकता है और हेडलाइन मुद्रास्फीति को बेसलाइन से 50 आधार अंक नीचे ले जा सकता है। दूसरी तरफ अपर्याप्त या स्थानिक रूप से छितराए हुए दक्षिणी-पश्चिमी मानसून, और सब्जियों के अलावा अन्य खाद्यों की कीमतों में अनपेक्षित मजबूती के कारण 2020-21 में

हेडलाइन मुद्रास्फीति में बेसलाइन से ऊपर लगभग 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है।

1.4 निष्कर्ष

कोविड-19, इसके कारण हो रहे लॉकडाउन और 2020 में वैश्विक उत्पाद में अपेक्षित संकुचन से संवृद्धि आउटलुक पर बहुत भार पड़ने की संभावना है। इस महामारी पर जिस तेजी से काबू पाया जाएगा और आर्थिक क्रियाकलाप जिस तेजी से सामान्य स्थिति में लौटेंगे वास्तविक रूप में आगे निकलना उस पर ही निर्भर करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मौद्रिक और चलनिधि उपाय और सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय उपाय घरेलू मांग पर प्रतिकूल प्रभावों को निष्प्रभावी करेंगे और एक बार सामान्य स्थिति बहाल हो गई तो आर्थिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाएंगे। मुद्रास्फीति प्रेक्षकों के लिए जोखिम इस मुकाम पर तो संतुलित ही प्रतीत हो रहे हैं और हाल ही के इतिवृत्त को देखते हुए अनंतिम आउटलुक तो क्षुद्र है। लेकिन भविष्य पर तो पिशाच की तरह कोविड-19 छाया हुआ है।

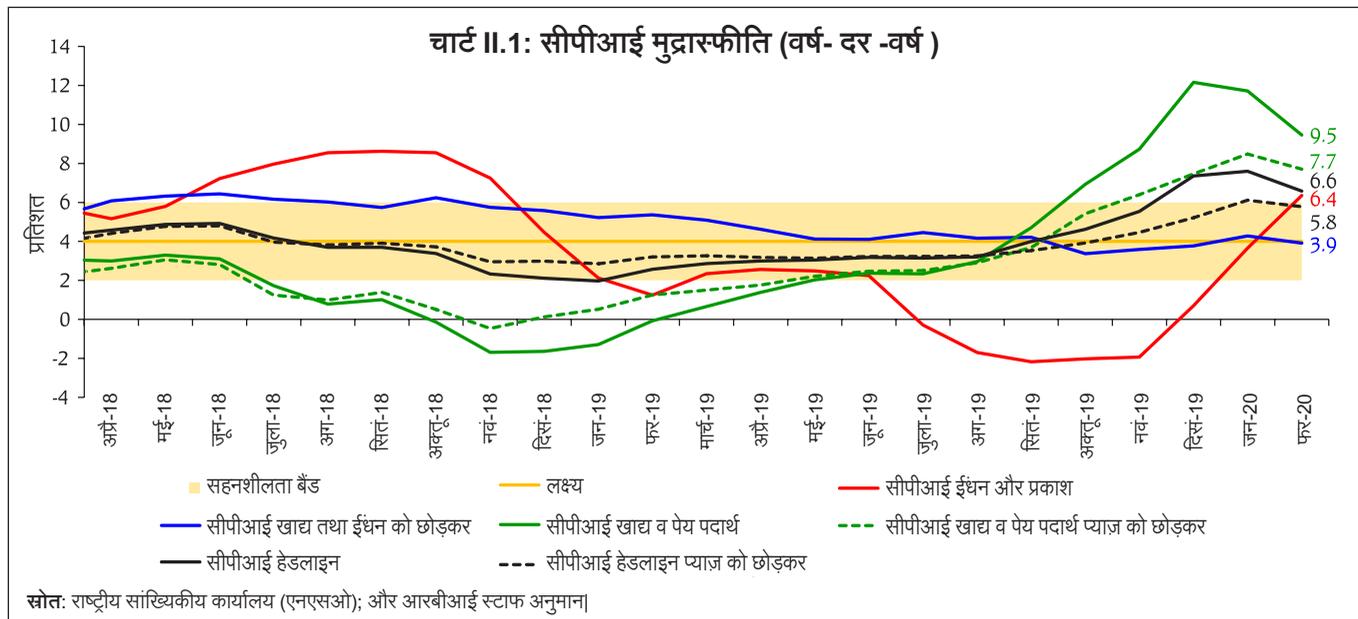
II. मूल्य और लागतें

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होने से बढ़ गई थी, विशेष रूप से प्याज की कीमतों के कारण और फरवरी में मंद होने से पहले दिसंबर में यह उच्चतम सहन-सीमा से भी पार कर गई थी। ईंधन की कीमतें दिसंबर में अपस्फीति की स्थिति से बाहर निकलीं। सीपीआई संबंधी मुद्रास्फीति, खाद्यान्न एवं ईंधन को छोड़कर अक्टूबर में ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी किंतु अतिलागत-जन्य कारकों (कास्ट-पुश फैक्टर्स) के कारण उसमें उभार पैदा हो गया। खेती के इनपुट, औद्योगिक इस्तेमाल के कच्चे माल, कृषि एवं कृषि से इतर कार्यों में लगे श्रमिकों की सांकेतिक मजदूरी तथा संगठित क्षेत्र के स्टाफ की लागतें शांत बनी रहीं।

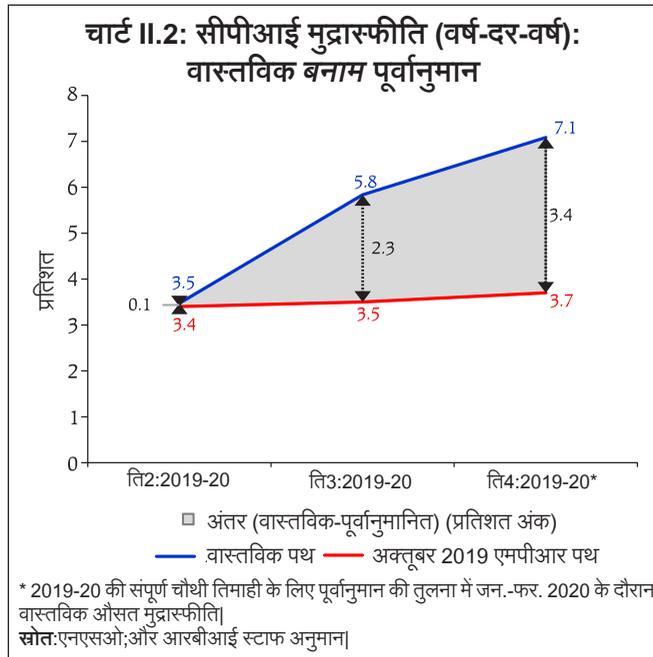
हेडलाइन मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से मापा जाता है,¹ जो वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही तक लगातार तेरह महीने तक लक्ष्य के नीचे बना हुआ था लेकिन, सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने- विशेष रूप से प्याज की बढ़ती कीमतों ने बने हुए मूल्य स्थिरता के वातावरण को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में हेडलाइन मुद्रास्फीति ने दिसंबर 2019 तक 6 प्रतिशत तक की उच्चतम सहन-सीमा

को पार कर लिया था और फरवरी 2020 में कम होकर 6.6 प्रतिशत पर आने से पहले जनवरी 2020 में 7.6 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई थी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के असामान्य रूप से लंबे समय तक बने रहने से तथा बिना मौसम के बरसात होने से खरीफ की बुवाई के आगे के समय को नष्ट कर दिया जिससे प्याज की कीमतें अप्रत्याशित तरीके से बढ़ गईं। वस्तुतः प्याज को छोड़कर यदि देखा जाए तो हेडलाइन मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही में 4.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.9 प्रतिशत (फरवरी तक) पर बनी रही, जो यह रेखांकित करता है कि प्याज की कीमतों का आघात कितना गहरा था। ईंधन की कीमतें भी पांच महीने तक अपस्फीति की स्थिति में बनी रहने के बाद दिसंबर 2019 में धनात्मक क्षेत्र में आ गईं और उसके बाद तो उनमें तेजी से वृद्धि हुई। खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति अथवा प्रमुख मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 के ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर 3.4 प्रतिशत से जनवरी 2020 तक लगातार बढ़ते हुए 4.3 प्रतिशत पर अनेक प्रकार की लागतों के धकेलने से आ गई थी जो बाद में फरवरी में थोड़ा सा नरम पड़ गई थी (चार्ट II.1)।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2016 में यथासंशोधित) भारिबैंक के लिए यह विधान किया गया है कि वह इस बात का निर्धारण करे कि अनुमानों से वास्तविक मुद्रास्फीति नतीजों में कितना विचलन हुआ है, यदि कोई हुआ



¹ हेडलाइन मुद्रास्फीति अखिल भारतीय स्तर पर सीपीआई संयुक्त (ग्रामीण एवं शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष हुए परिवर्तनों द्वारा मापी जाती है।



हो तो, तथा उसके निहित कारणों को बताए। अक्टूबर 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में सीपीआई मुद्रास्फीति के प्रति यह अनुमान दिया गया था कि वह 2019-20 की दूसरी तिमाही में दायरे के भीतर और 2019-20 की तीसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत एवं 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.7 प्रतिशत रहेगी। मुद्रास्फीति के वास्तविक नतीजों ने अनुमानों के मार्जिन को काफी बढ़ा दिया था – तीसरी तिमाही में 2.3 प्रतिशतता अंक और चौथी तिमाही में 3.4 प्रतिशतता अंक (चार्ट II.2)।

जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, प्याज की कीमतों में अप्रत्याशित एवं गैर-मामूली वृद्धि हेड लाइन मुद्रास्फीति में अनुमानों से विचलन का मुख्य स्रोत रही है। गैर-मौसमी बारिश के कारण सर्दी के मौसम में अन्य सब्जियों की कीमतों में होने वाली कमी में भी देरी हुई, खासतौर से आलू की कीमतों में। इसके अलावा, बेमौसम बारिश से खरीफ की फसल को होने वाले नुकसान के कारण अनाज और दूध की कीमतों में उम्मीद से कहीं ज्यादा वृद्धि होना, गेहूं का कम आयात किया जाना तथा पहले मामले में गेहूं के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बाद के मामले में इनपुट लागतों के बढ़ जाने ने मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दिया था। खाद्यान्न एवं ईंधन संबंधी मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई भी चौथी तिमाही के अनुमानों में त्रुटि का साधन बनी क्योंकि इसमें आघातों की एक पूरी श्रृंखला शामिल थी जैसे- मोबाइल फोन का उच्च टैरिफ,

बीएस-VI² कंपलेंट वाहन की ओर लगातार स्विचओवर होने से मोटर वाहन की कीमतें अधिक होना, स्वर्ण की ऊंची कीमतें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत के उतार-चढ़ाव को दर्शाती हैं, तथा सफाई, लांड्री, ब्यूटीशियंस की सर्विसेस की अधिक कीमतें, बस किराया बढ़ना – ये सब अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाता है कि यह खाद्यान्न और ईंधन की उच्च कीमतों से पड़ने वाले प्रभाव के कारण हुआ है। 2019-20 की चौथी तिमाही (जनवरी-फरवरी) में कच्चे तेल की कीमतें (इंडियन बास्केट) कम हुईं जो अक्टूबर की एमपीआर के समय 63 अमरीकी डालर प्रति बैरल से कम होकर फरवरी में 55 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गई थीं, जिसने बढ़ती लागतों के कारण कीमतें बढ़ने को रोकने में मदद की।

II.1 उपभोक्ता मूल्य

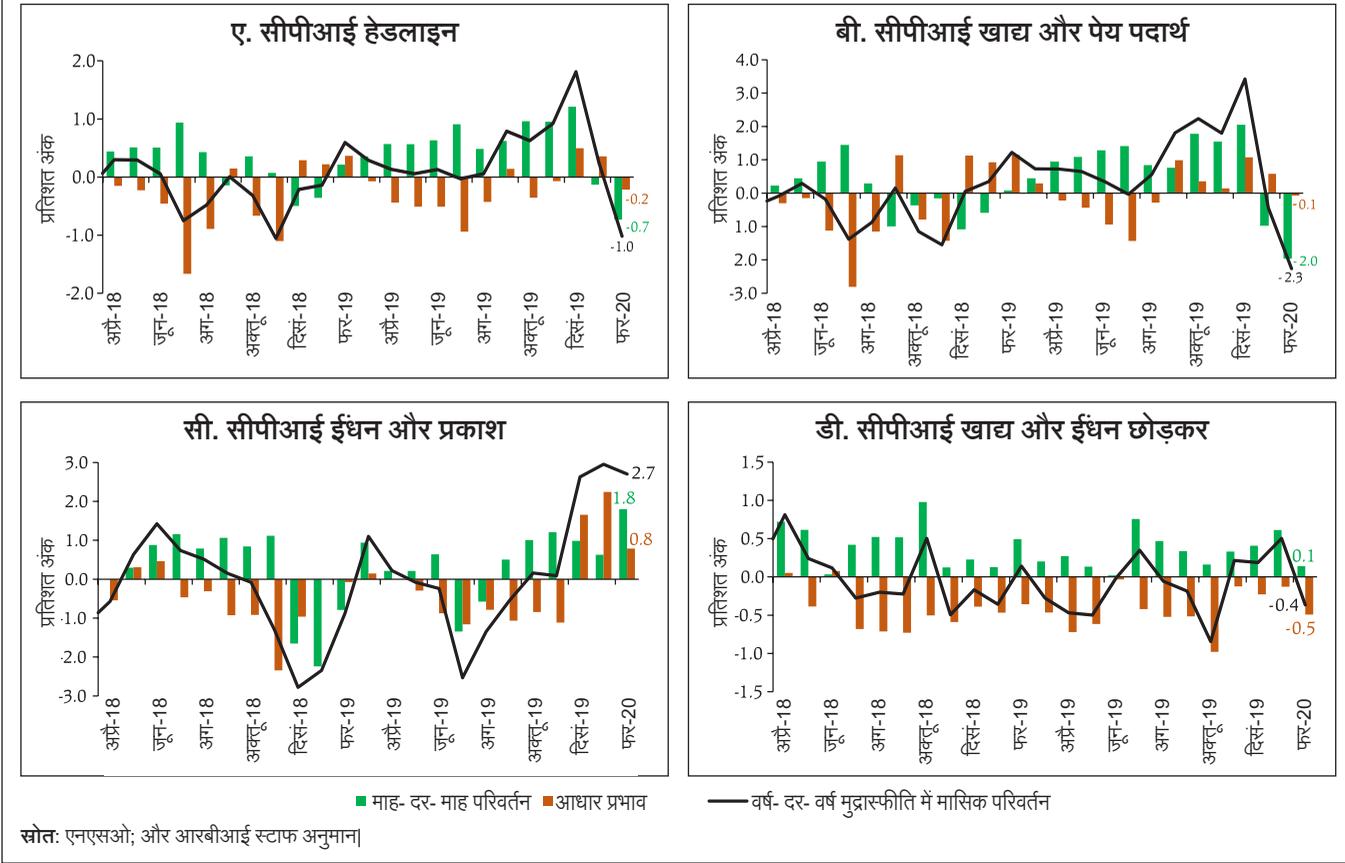
मुद्रास्फीति की स्थिति को वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग करके देखें तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में मूल्यों के उतार-चढ़ाव में तीव्र वृद्धि तथा प्रतिकूल आधारगत प्रभाव कार्य कर रहे थे³ तीसरी तिमाही के दौरान खाद्यान्न मूल्यों में सामान्य मौसमी गिरावट होने की तुलना में तीसरी तिमाही में मापी गई खाद्यान्न कीमतों में गति सकारात्मक थी जो सूचकांक के इतिहास में किसी भी तीसरी तिमाही में दर्ज की गई सर्वाधिक वृद्धि थी। फलस्वरूप खाद्यान्न मुद्रास्फीति तीसरी तिमाही के अंत तक बढ़ कर दो अंकों में हो गई। प्रतिकूल आधारगत प्रभाव ने भी ईंधन को और भी महंगा कर दिया। जनवरी में खाद्यान्न की कीमतें घटना शुरू हो गई थीं किंतु कोर-मुद्रास्फीति की गति में में बनी हुई दृढ़ता ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को जनवरी में शीर्ष स्तर पर पहुंचा दिया था। फरवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति मंद हुई क्योंकि खाद्यान्न के मूल्यों में तेज गिरावट आ गई थी तथा कोर-मुद्रास्फीति की गति थम गई थी (चार्ट II.3)।

वर्ष 2019-20 में सभी सीपीआई समूह में मुद्रास्फीति का संवितरण हाल के ऐतिहासिक अनुभवों से काफी हद तक भिन्न रहा है। मध्यमान मुद्रास्फीति दर पिछले तीन वर्ष के औसत की तुलना में कम बनी रही है। लेकिन, 2019-20 में इसमें सकारात्मक

² बीएस VI अथवा भारत चरण VI का आशय है ऐसे नये एमिशन मानक जिनका अनुपालन 01अप्रैल, 2020 को या उसके बाद निर्मित सभी हलके तथा भारी वाहनों, दुपहिया एवं तिपहिया वाहनों द्वारा आवश्यक है।

³ किसी दो महीनों के बीच सीपीआई वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन, मूल्य सूचकांक में होने वाले माह-दर-माह परिवर्तन (गति) तथा 12 महीने पूर्व (आधारगत प्रभाव) महीना-दर-महीना हुए मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर होता है। अधिक जानकारी के लिए सितंबर 2014 की एमपीआर का बॉक्स I.1 देखें।

चार्ट II.3 : सीपीआई मुद्रास्फीति – गति तथा आधार प्रभाव

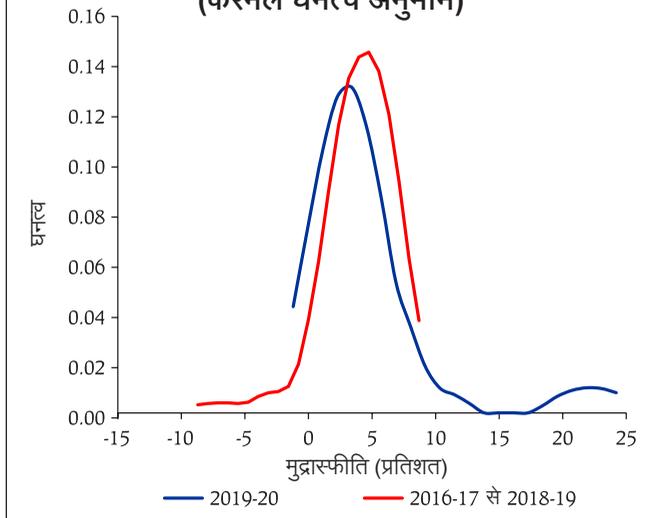


झुकाव दिखाई दिया है - क्योंकि ऐतिहासिक औसत के नकारात्मक झुकाव की तुलना में खाद्यान्न उप-समूहों जैसे सब्जियों में महंगाई दरें बहुत ज्यादा थीं। परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 के लिए माध्य मुद्रास्फीति दर काफी हद तक पिछले तीन वर्ष के औसत से कहीं अधिक थी (चार्ट II.4)। यहां तक कि वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति दरों पर चुनिंदा खाद्य मदों का ही प्रभाव रहा था, सीपीआई मदों में मूल्य परिवर्तन के डिफ्यूजन सूचकांक⁴ में मौसमी समायोजित आधार पर आई तेजी इस अवधि के दौरान—सभी वस्तुओं और सेवाओं में – भी सीपीआई बास्केट में मूल्य वृद्धि के आधार के बड़े होने की ओर संकेत करती है। चौथी तिमाही में अभी तक जहां लगभग सभी सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं

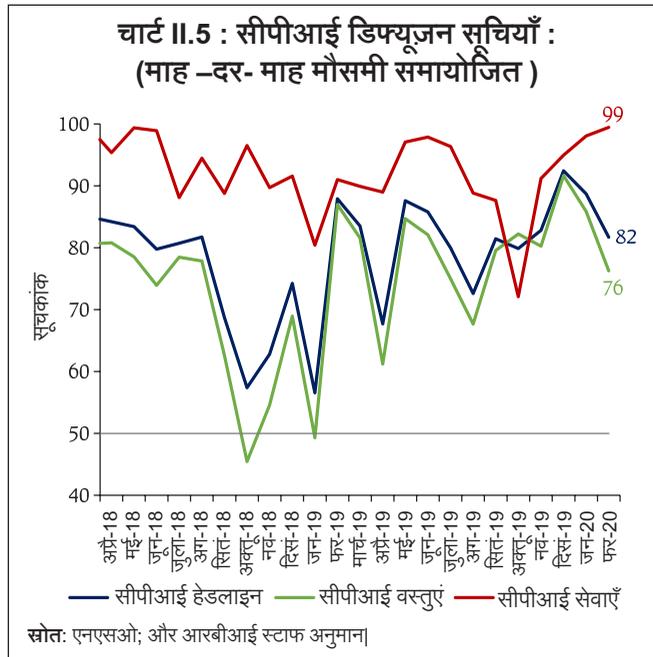
वस्तुओं, काफी हद तक खाद्यान्न की मदों में कीमतों में वृद्धि की घटनाएं कुछ कम हुई हैं (चार्ट II.5)।

⁴ सीपीआई डिफ्यूजन सूचकांक, मूल्य परिवर्तन के प्रसार की माप करता है, सीपीआई बास्केट की मदों में पिछले महीने में उनके मूल्यों में वृद्धि, अवृद्धि अथवा हुई गिरावट के अनुसार वर्गीकृत करता है। डिफ्यूजन सूचकांक की 50 से ऊपर की रीडिंग मूल्यों में अत्यधिक विस्तार अथवा सामान्यतया मूल्य वृद्धि होने का संकेत देता है तथा 50 से नीचे की रीडिंग बड़े पैमाने पर मूल्यों में गिरावट का संकेत देता है।

चार्ट II.4: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) (केरनेल घनत्व अनुमान)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



II.2 मुद्रास्फीति के संचालक

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के मुद्रास्फीति के नतीजों को ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग करके देखने से ज्ञात होता है कि प्रतिकूल आपूर्ति आघात ने किस प्रकार से शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर धीमी पड़ी हुई घरेलू मांग के अपस्फीतिकारी प्रभाव को दबा दिया है (चार्ट II.6ए)⁵ नश्वर वस्तुएं (7-दिन से ज्यादा न टिकने वाली वस्तुएं⁶) – खाद्यान्न वस्तुएं जैसे सब्जियां,

दूध और मांस उत्पाद – प्रमुख संचालक रहे हैं, जो अब तक दूसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति में 1.3 प्रतिशतता बिंदु, तीसरी तिमाही में 3.7 प्रतिशतता बिंदु एवं चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशतता बिंदु तक का योगदान कर रहे थे (चार्ट II.6बी)। अनाज, दालों तथा पेट्रोलियम उत्पादों के कारण कम नश्वर वस्तुओं (30 दिन से ज्यादा न टिकने वाली वस्तुएं) ने भी 2019-20 की तीसरी तिमाही से जोर पकड़ लिया था। टिकाऊ वस्तुओं का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान जो - औसतन 36 आधार अंक के साथ- सितंबर-दिसंबर के दौरान काफी हद तक स्थिर बना रहा था – उसमें स्वर्ण की कीमतें बढ़ने के कारण जनवरी-फरवरी में लगभग 40 आधार अंकों की तेजी पैदा हुई। सितंबर-नवंबर 2019 में आयातित वस्तुओं का समग्र मुद्रास्फीति में योगदान नकारात्मक रहा था, किंतु दिसंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान सकारात्मक बन गया – जिसका हेडलाइन मुद्रास्फीति में औसतन योगदान 60 आधार अंक हो गया था – ऐसा ऊर्जा और धातुओं के मूल्य बढ़ जाने के बाद हुआ था (चार्ट II.6सी)। सेवाओं का समग्र मुद्रास्फीति में योगदान बड़ा कठोर सा लगभग एक प्रतिशतता बिंदु पर बना रहा था क्योंकि दिसंबर-2019-जनवरी 2020 के दौरान मोबाइल टेलिकॉम प्रभार में इतनी तीव्र वृद्धि हो गई थी जो आवास किराया, अस्पताल सेवाओं एवं ट्यूशन शुल्क में हुई कमी द्वारा हुए समायोजन से भी अधिक थी (चार्ट II.6बी)।

सीपीआई खाद्यान्न समूह

अप्रैल 2019-फरवरी 2020 के दौरान समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में हुए परिवर्तनों पर अधिक भार खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ (भार: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) का था, साथ ही कुल मिलाकर दिसंबर में खाद्यान्न मूल्य आसमान पर थे जो ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक उच्च स्तर था (चार्ट II.7ए और II.7बी)।

परिणामस्वरूप, खाद्यान्न मुद्रास्फीति जो मार्च-सितंबर 2019 के दौरान 0.7 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत के दायरे में थी, उसके बाद दिसंबर में बढ़कर चोटी पर 12.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.8ए)। इस प्रकार की अधिकांश बढ़ोतरी बैमौसम बारिश की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाने के कारण हुई थी, लेकिन

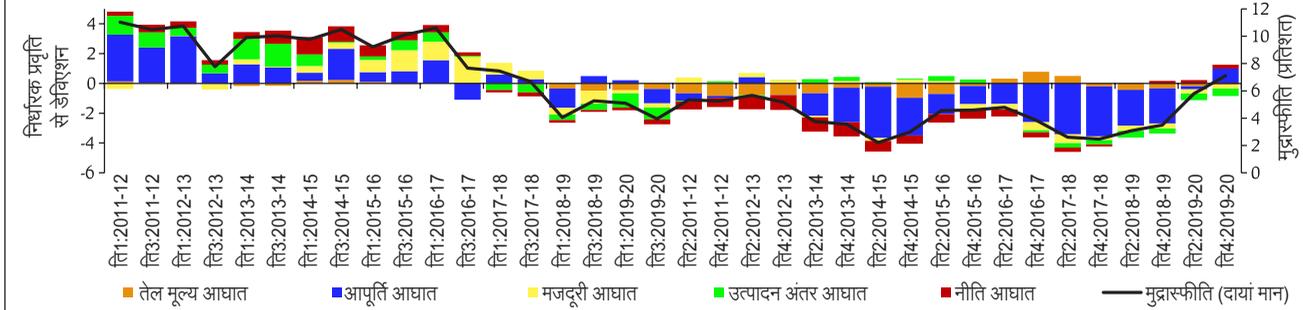
⁵ ऐतिहासिक पृथक्करण प्रक्रिया का इस्तेमाल नमूना अवधि में मुद्रास्फीति के घट-बढ़ के प्रति प्रत्येक आघात के योगदान का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो वेक्टर आटो रीग्रेशन (वीएआर) पर आधारित होता है जिसमें निम्नलिखित चर (जिसे वेक्टर Y_t से अभिहित किया गया है), जैसे कच्चे तेल की कीमतों में वार्षिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, उत्पादन-अंतराल, ग्रामीण मजदूरी में वार्षिक वृद्धि दर और नीतिगत रेपो दर होती हैं। वीएआर को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: $Y_t = c + A Y_{t-1} + e_t$ जिसमें e_t आघातों के वेक्टर को दर्शाता है [तेल मूल्य के आघात; आपूर्ति आघात (मुद्रास्फीति आघात); उत्पादन अंतराल आघात; मजदूरी आघात और नीतिगत आघात]। वोल्ड पृथक्करण का इस्तेमाल करते हुए Y_t को उसके निर्धारणात्मक प्रवृत्ति तथा समस्त e_t आघातों के योग के प्रकार्य को दर्शाता है। यह समीकरण विभिन्न आघातों के सकल योगदान में उसकी निर्धारक प्रवृत्ति से मुद्रास्फीति के विचलन के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाता है।

⁶ सीपीआई भार डायग्राम में संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) डाटा का उपयोग किया जाता है जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 2011-12 में किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है। एमएमआरपी के अंतर्गत बार-बार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के व्यय संबंधी आंकड़े संकलित किए जाते हैं जैसे पिछले सात वर्षों में खरीदे गए खाद्य तेल, अंडे, मछली, मांस, सब्जियां, फल, मसाले, पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्यान्न, पान, तंबाकू तथा नशीली सामग्रियां; पिछले 365 दिनों में खरीदे गए कपड़े, बिस्तर, जूते-चप्पल, शिक्षा व्यय, चिकित्सा व्यय (संस्थागत), टिकाऊ वस्तुएं और पिछले 30 दिनों में खरीदी गई समस्त खाद्यान्न सामग्री, ईंधन और बिजली व्यय, विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं तथा गैर-संस्थागत सेवाएं, किराया और कर शामिल हैं।

⁷ भारत के आयात में कच्चे पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद का वर्चस्व है (कुल आयात का लगभग 25.0 प्रतिशत)। आयात किए जाने वाले अन्य प्रमुख घटक हैं : इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (11.0 प्रतिशत), स्वर्ण और चांदी (8.0 प्रतिशत), रसायन और रसायन उत्पाद (6.0 प्रतिशत), धातु और धातु-उत्पाद (6.0 प्रतिशत), मोती एवं कीमती पत्थर (6.0 प्रतिशत) तथा वनस्पति तेल (2.0 प्रतिशत)। इसके साथ ही कुछ मदें जैसे कच्चे कपास का घरेलू मूल्य अंतरराष्ट्रीय मूल्य के समान बढ़ता है।

चार्ट II.6 : मुद्रास्फीति के संचालक

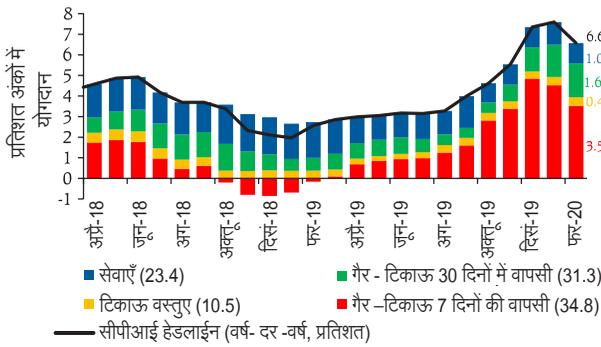
ए: सीपीआई मुद्रास्फीति का पृथक्करण*



*निर्धारक प्रवृत्ति से डेविएशन।

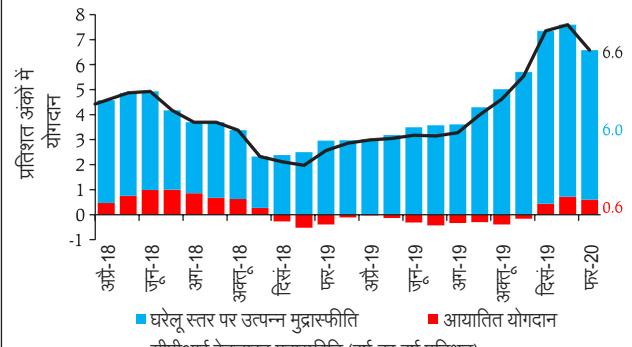
टिप्पणी : 2002-03 की पहली तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही तक के डाटा के उपयोग द्वारा भारतीय रु. में तेल की कीमतों के साथ वेक्टर आटो रिएगेशन(वीएआर) का उपयोग, सीपीआई मुद्रास्फीति, उत्पादन अंतर, ग्रामीण मजदूरी तथा नीति दर द्वारा अनुमानित।

बी: वस्तुओं तथा सेवाओं का योगदान



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

सी: आयातित मुद्रास्फीति का योगदान



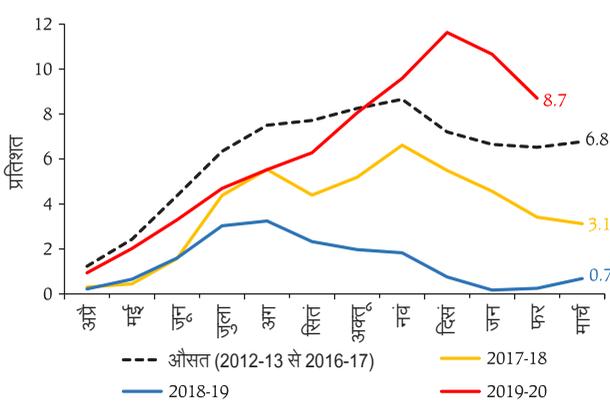
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

खाद्यान्न श्रेणी की वस्तुओं में मूल्य बढ़ने का बड़े पैमाने पर दबाव 2019-20 की दूसरी छमाही में देखा गया और मूल्य बढ़ने का ये

दबाव दालों, मांस और मछली, मसाले, अंडे, अनाज तथा दूध पर था (चार्ट II.8बी)। बाद में खाद्यान्न संबंधी मुद्रास्फीति जनवरी

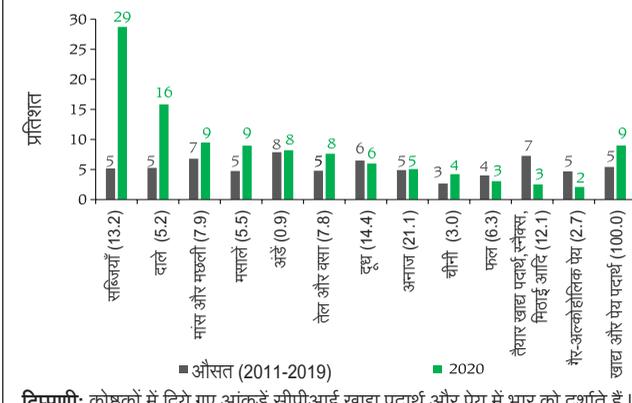
चार्ट II.7 : सीपीआई खाद्य कीमत बिल्ड –अप

ए: सीपीआई खाद्य – संचयी गति



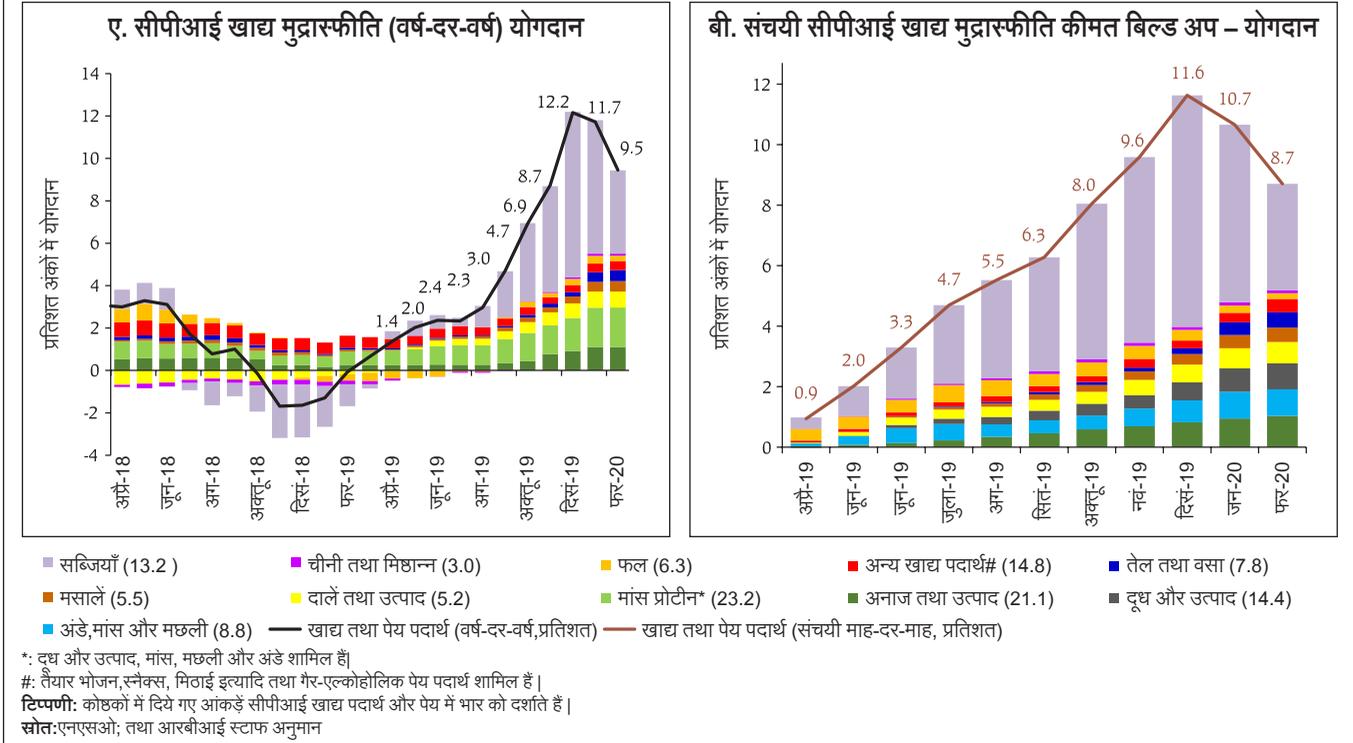
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बी: वित्तीय वर्ष की कीमत बिल्ड अप (फरवरी से मार्च)



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें सीपीआई खाद्य पदार्थ और पेय में भार को दर्शाते हैं।

चार्ट II.8 : सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति और कीमत बिल्ड अप



तथा फरवरी 2020 में क्रमशः कम होती गई, साथ ही थोड़ा देर से मौसमी सब्जियों की कीमतें भी सहज हो गई थीं।

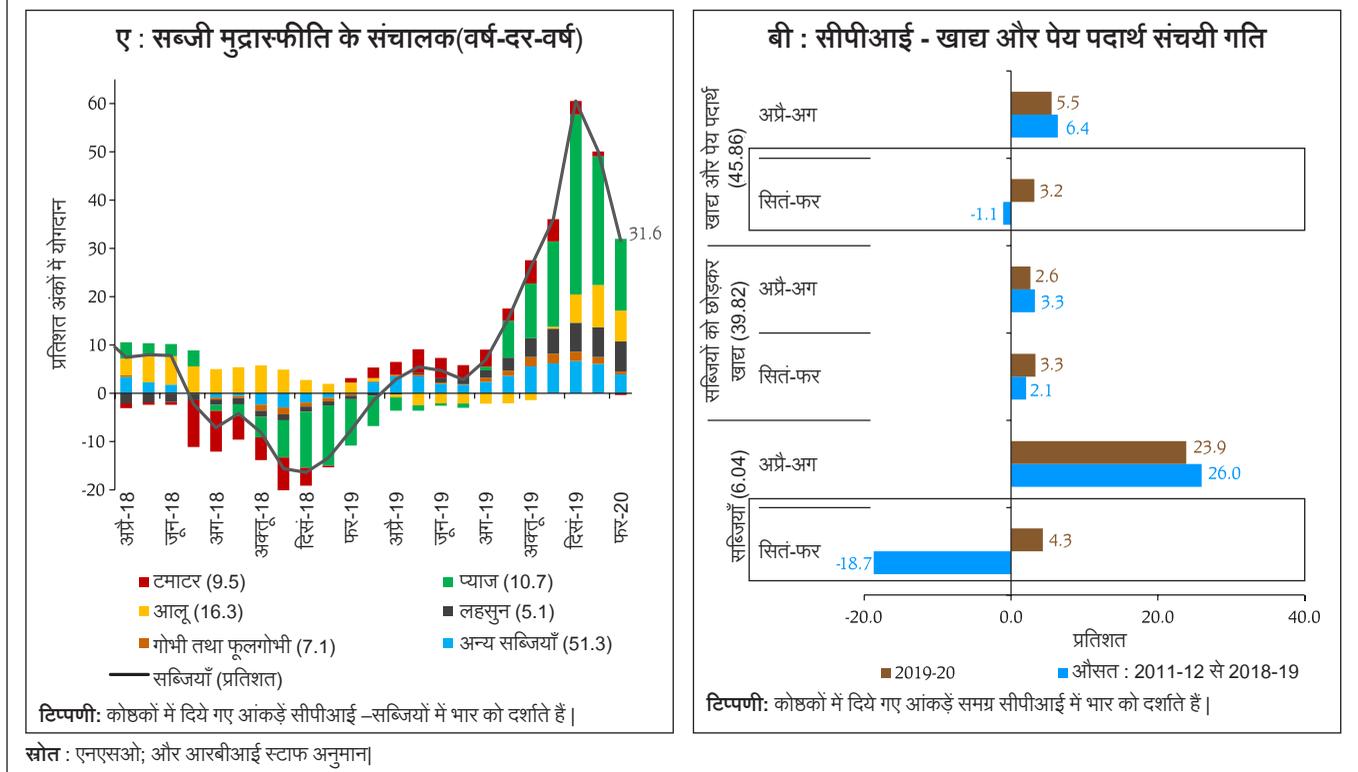
अनाजों के मामले में (सीपीआई में इसका भार 9.7 प्रतिशत और खाद्यान्न तथा पेय पदार्थ समूह में 21.1 प्रतिशत है) मूल्यों में 2019-20 की दूसरी छमाही में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। गेहूं की कीमतों का निर्धारण उच्च संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अत्यधिक सरकारी खरीद द्वारा हो रहा था और गेहूं का आयात बहुत कम हो रहा था [अप्रैल 2019-जनवरी 2020 के दौरान (-)39 प्रतिशत]। गैर-सरकारी वितरण प्रणाली (पीडीएस) में चावल की कीमतें 11 महीने अपस्फीति की स्थिति में रहने के बाद अक्टूबर 2019 में उभरीं तथा उसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2019 की शुरुआत में बेमौसम बारिश होने के कारण खरीफ फसल को हुए नुकसान की वजह से उसके मूल्यों ने जोर पकड़ा। इसके मूल्य फरवरी 2020 से कम होने शुरू हो गए क्योंकि बड़ी मात्रा में भंडारण को आगे ले जाया गया, साथ ही रबी की फसल अच्छी होने की संभावना थी और निर्यात कम किया गया था।

सब्जियों के मूल्यों की मुद्रास्फीति (सीपीआई में भार 6.0 प्रतिशत और खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ समूह में 13.2 प्रतिशत)

सितंबर से बढ़कर दो अंकों में हो गई तथा दिसंबर 2019 में शीर्ष पर 60.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे फसल को हुए नुकसान के प्रभाव एवं अत्यधिक तथा बेमौसम बारिश के कारण आपूर्ति में पड़े व्यवधान का पता चलता है (चार्ट II.9ए)। खरीफ की बुवाई का आगमन देर से हुआ, इसलिए सब्जियों के मूल्यों में कमी आना विलंब से जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ। सब्जियों के मूल्यों पे दबाव के मामले में वर्ष 2019-20 एक खास वर्ष रहने की संभावना है, क्योंकि आपूर्ति की कमी के अत्यधिक आघात ने सर्दियों में सब्जियों की कीमतों में होने वाली कमी के मौसमी पैटर्न को पूरी तरह से घेर लिया है, खासतौर से प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों को जो वर्ष के आगे आने वाले महीनों में कीमतों के बढ़ते जाने से राहत दिलाते हैं (चार्ट II.9बी)।

भारत में दो अंकीय मुद्रास्फीति के प्रति राजनीतिक चर्चा सहित सामाजिक असहिष्णुता बहुत ही मुखर रहती है। इसे प्याज की कीमतों की मुद्रास्फीति के समय व्यक्त होने वाली सामाजिक प्रतिक्रियाओं में भलीभांति देखा जा सकता है। वर्ष 2019-20 में सितंबर 2019 से प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ीं जिससे इस श्रेणी की मुद्रास्फीति में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई और वह दिसंबर 2019 में 327 प्रतिशत तक पहुंच गई जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में 4.7

चार्ट II.9 : सीपीआई सब्जियाँ और सीपीआई खाद्य कीमत गत्यात्मकता



प्रतिशत तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2.1 प्रतिशत अंकों की तीखी वृद्धि देखने में आई। मुद्रास्फीति की इस आश्चर्यजनक अप्रियकर स्थिति ने समय अंतराल और आपूर्ति पक्ष के अपर्याप्त उपायों को अनावृत किया, जैसे कि प्रति टन 850 अमेरिकी डालर का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय करना, प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और सितंबर 2019 में थोक एवं खुदरा व्यापारियों के भंडार धारण की सीमा पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही नवंबर-दिसंबर 2019 में टर्की, अफगानिस्तान व इजिप्त से 1.2 लाख टन प्याज के आयात की घोषणा करना। जनवरी 2020 में विलंबित खरीफ की आवक के बाद ही प्याज की कीमतों में नरमी आई। प्याज की कीमतों में उग्र उछाल और उसके अनुगामी प्रभाव आपूर्ति पक्ष से जुड़े सुधारों की तात्कालिकता को प्रकाशित करते हैं (बाक्स II.1)।

जहां तक मुद्रास्फीति-संवेदी सब्जियों का संबंध है, अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभावों की वजह से कीमतों के बढ़ने के बावजूद आलू की कीमतों में अवस्फीति रही। मोटे तौर पर अप्रैल 2019-

जनवरी 2020 के दौरान आलू की कीमतों की गति सकारात्मक रही, अक्टूबर-नवंबर 2019 के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक/बेमौसमी बरसात की वजह से फसल को हुए नुकसान और आपूर्ति में पहुंची बाधा, जिसे मंडी में कम आवक के रूप में देखा जा सकता है, से कीमतों में तेजी आई। वास्तविक तथ्य भी यह दर्शाते हैं कि बुलबुल नामक तूफान के चलते पश्चिम बंगाल में बुवाई में 20 दिनों की देरी हुई। परिणामस्वरूप, जनवरी 2020 में आलू की कीमतों की मुद्रास्फीति बढ़कर 62.9 प्रतिशत हो गई जो आगे चलकर फरवरी 2020 में घटकर 47.0 प्रतिशत पर आ गई और इसकी वजह थी 2019-20 में उत्पादन में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ आई नई उपज। वहीं दूसरी ओर, टमाटर की कीमतों की मुद्रास्फीति मई 2019 के सर्वाधिक स्तर से कम होकर अक्टूबर-दिसंबर 2019 के दौरान उच्च द्विअंकीय बनी रही, जो असमय बरसात और उससे जुड़ी आपूर्ति बाधाओं को प्रतिबिंबित करती है। जनवरी 2020 के आरंभ से टमाटर की कीमतों की मुद्रास्फीति सामान्य मौसमी उपज के च घटने लगी और फरवरी 2020 में (-) 4.3 प्रतिशत की अवस्फीति पर आ गई।

बाक्स II.1: प्याज की कीमतों का आघात- आपूर्ति प्रबंधन के मुद्दे

वर्ष 2019 में प्याज की कीमतों का आघात मात्रा एवं अवधि के हिसाब से हाल के समय का सबसे बड़ा आघात है (चार्ट II.1.1)। कई मायनों में इस अभूतपूर्व अनुभव को समझने के लिए, विभिन्न थोक बाजारों से अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य पर प्याज की कीमतों के आघात के फैलाव के डायनामिक्स का मूल्यांकन करने के लिए एक वेक्टर आटोरिग्रेसिव (वीएआर) मॉडल का सहारा लिया जाता है जिसमें निम्नांकित विशिष्ट विशिष्टताओं सहित थोक एवं खुदरा बाजार में प्याज की कीमतों का दैनिक डाटा शामिल होता है:

$$Y_t = c + A Y_{t-1} + e_t \dots\dots\dots(1)$$

जहां Y_t मुख्य थोक बाजारों, जैसे कि जोधपुर, कर्नूल, नासिक, पुणे एवं अन्य (अन्य बाजारों का औसत) में प्याज की दैनिक कीमतों के वेक्टर और अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है; e_t आपूर्ति एवं मांग आघातों के वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है – थोक बाजार कीमतों का आघात आपूर्ति आघात तो औसत खुदरा बाजार कीमतों का आघात मांग आघात का प्रतिनिधित्व करता है। यह आकलन उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए), भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 5 अगस्त 2019 से 28 फरवरी 2020 के बीच के थोक एवं खुदरा कीमतों के डाटा पर आधारित है।

चार्ट II.1.1: प्याज की मंडी कीमतें

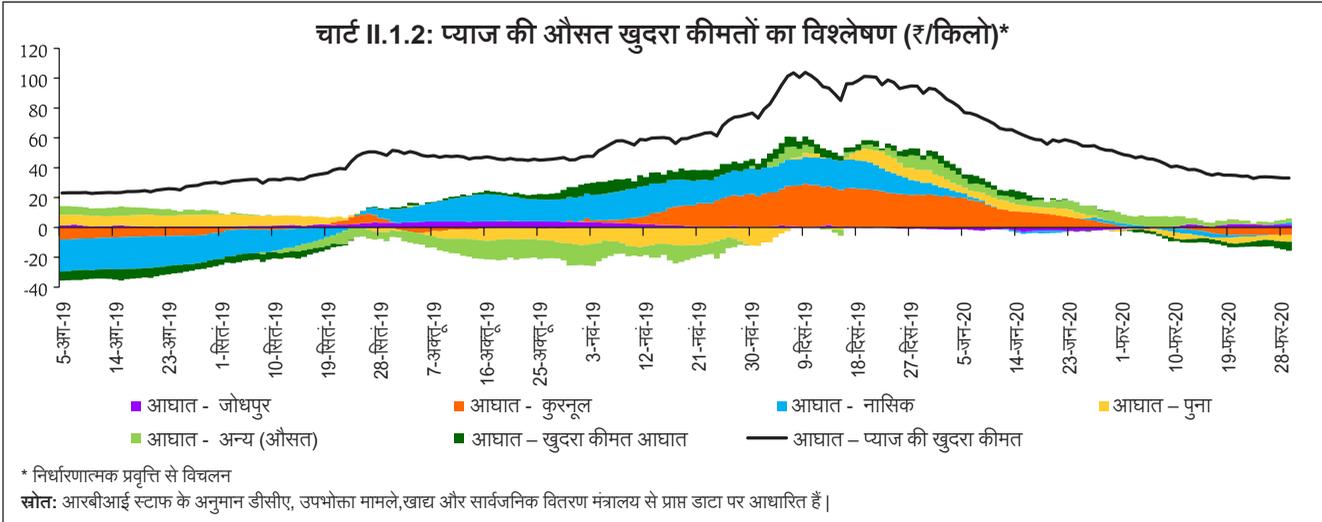


स्रोत: एगमार्केट

औसत खुदरा कीमतों का ऐतिहासिक विश्लेषण दर्शाता है कि कैसे थोक एवं खुदरा बाजारों के बीच कीमतों का बढ़ता मार्जिन बड़ा होता गया और अक्टूबर की शुरुआत में महाराष्ट्र के थोक बाजारों में प्याज की कीमतों का आघात नवंबर के

आरंभ में कर्नाटक तक और उसके तत्काल बाद अखिल भारतीय खुदरा कीमतों तक फैल गया। जनवरी के अंत तक प्याज की कीमतों का आघात पूरी तरह से पलट गया (चार्ट II.1.2)।

चार्ट II.1.2: प्याज की औसत खुदरा कीमतों का विश्लेषण (₹/किलो)*



* निर्धारणात्मक प्रवृत्ति से विचलन

स्रोत: आरबीआई स्टाफ के अनुमान डीसीए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त डाटा पर आधारित हैं।

(जारी)

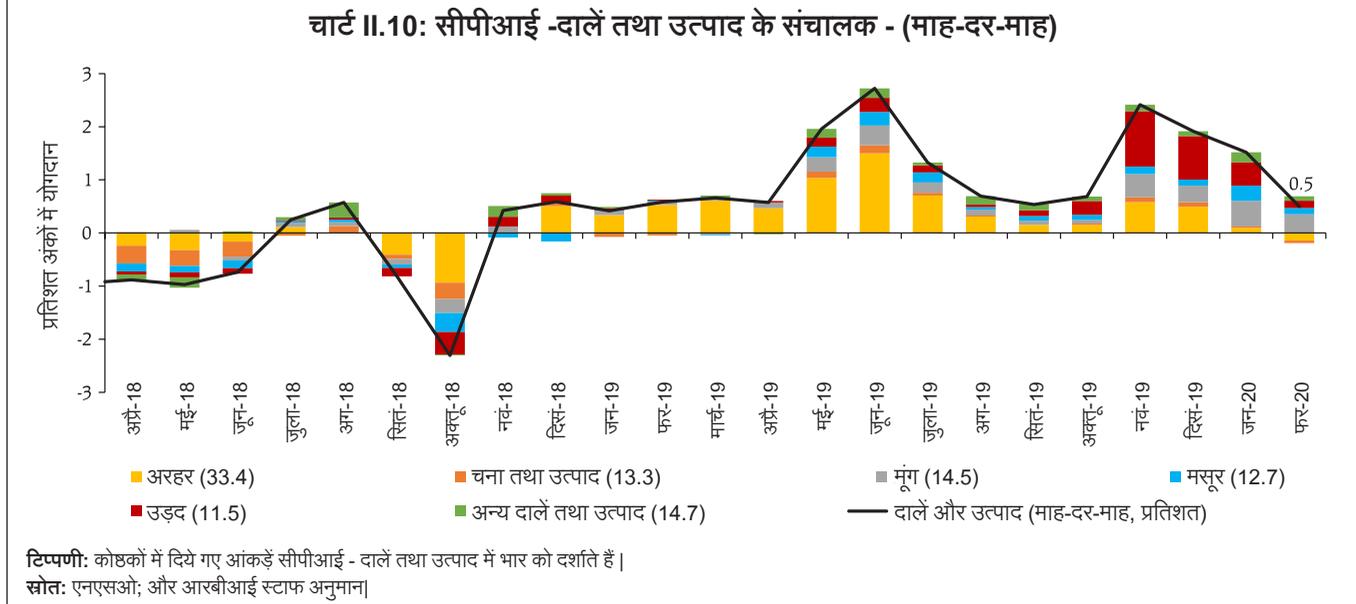
इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत में किसी भी वर्ष प्याज का उत्पादन मांग को आसानी से पूरा कर लेता है और साथ ही निर्यात के लिए अतिरिक्त उपज उपलब्ध रहती है, यह विश्लेषण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि प्याज की कीमतों के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति प्रबंधन की नीतियों में बदलाव किए जाने की जरूरत है। प्याज के प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन की रूपरेखा को निम्नांकित पर केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है: (1) मौसम और उत्पादन परिदृश्य के बारे में किसानों को बेहतर सूचना प्रणाली उपलब्ध कराना ताकि वे अगले वर्ष के लिए प्याज के उत्पादन की बेहतर योजना तैयार कर सकें, (2) किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों की सीधी बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विपणन प्रणाली में सुधारों को आरंभ करना, (3) बेहतर मूल्य

पता करने के लिए ई-नाम जैसी पहलों को मजबूत बनाना, (4) किसानों के लिए भंडारण की सुविधा को बेहतर बनाना ताकि अप्रियजनक बिक्री को टाला जा सके, (5) रबी उत्पादों का पर्याप्त बफर स्टॉक तैयार करना ताकि अत्यल्प और विलंबित खरीफ मौसम के समय आपूर्ति बाधाओं से निपटा जा सके, और (6) खाद्य प्रसंस्करण पहलों को बढ़ावा देना, जैसे कि प्याज को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर और पेस्ट तैयार करना जिसे उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। देखा जाए तो बीते समय में अधिकतर बार खरीफ और विलंबित खरीफ मौसम में प्याज की कीमतों में उछाल हुआ है जो इस तथ्य को साबित करता है कि प्याज की कीमतों में उछाल को कम करने में आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन की भूमिका कितना महत्व रखती है।

फलों की कीमतें (सीपीआई में 2.9 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 6.3 प्रतिशत का भारांक) सितंबर 2019 में 9 माह तक चली अवस्फीति से बाहर आ गईं और जनवरी 2020 में 5.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गईं जिसका मूल कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव था। फरवरी 2020 तक फलों की मुद्रास्फीति घटकर 4.0 प्रतिशत हो गई। केलों की कीमतों में नवंबर 2019 से सतत गिरावट रही। वहीं दूसरी ओर, सेव की कीमतें अगस्त 2019 से ही कम होने लगी थीं जिसका कारण था वर्ष 2019-20 में उत्पादन के 18.0 प्रतिशत अधिक रहने के चलते बाजार में सेवों की अधिक आमद का होना, तथापि जनवरी 2020 से कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ।

दालों की कीमतें (सीपीआई में 2.4 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 5.2 प्रतिशत का भारांक) मुद्रास्फीति कारक दबावों का एक और जरिया थीं, इस श्रेणी में मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 के (-) 0.8 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2020 में 16.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह 2018-19 के अंतिम आकलन की तुलना में 2019-20 के दूसरे अग्रिम आकलन (ईई) के अनुसार खरीफ दालों के उत्पादन में गिरावट को प्रतिबिंबित करता है, विशेष रूप से काफी कम खरीफ बुवाई और बेमौसम की बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान से प्रभावित हुआ उड़द का उत्पादन (27.1 प्रतिशत तक) (चार्ट II.10)। हालांकि अप्रैल 2019-जनवरी 2020 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आयात

चार्ट II.10: सीपीआई -दालें तथा उत्पाद के संचालक - (माह-दर-माह)



25 प्रतिशत तक बढ़ गया लेकिन वह दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने में सफल नहीं हो पाया।

सब्जियों और दालों के अलावा जानवर आधारित प्रोटीन युक्त वस्तुएं अन्य दबावकारी बिंदु थीं, 2019-20 में समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में जिनकी हिस्सेदारी 20.4 प्रतिशत थी। अप्रैल 2019-जनवरी 2020 के दौरान मांस और मछली से जुड़ी मुद्रास्फीति अधिक रही और जनवरी 2020 में 10.6 प्रतिशत (पिछले 72 माह में सर्वाधिक) पर पहुंच गई। वर्ष (अगस्त-अक्तूबर 2019 के कमजोर सीजन के अलावा) के दौरान मांस और मछली की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो चारे की ऊंची कीमतों (विशेषकर मक्का और सोयाबीन) को दर्शाती है और इसकी वजह थी बेमौसमी बरसात जिसने मौसमी कीमत दबाव को बढ़ा दिया। समन्वित रूप से अंडों की कीमतों की मुद्रास्फीति भी अप्रैल 2019 के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2020 में 10.5 प्रतिशत पर पहुंच गई लेकिन फिर उसमें फरवरी 2020 में नरमी देखने में आई और वह 7.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। फरवरी 2020 में कोविड-2019 के डर की वजह से चिकन और अंडों के उपभोग में आई कमी के कारण इनकी कीमतों में तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

उच्च खाद्य मुद्रास्फीति में दूध और दुग्ध उत्पादों (सीपीआई में 6.6 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 14.4 प्रतिशत का भारांक) का भी हाथ रहा। अमूल और मदर डेयरी जैसे सहकारी संस्थाओं ने दिसंबर 2019 में दूसरी बार (मई 2019 में पहला दौर) खुदरा दूध की कीमतों में प्रति लीटर रूपए 2-3 के दायरे में बढ़ोतरी की ऐसा खरीद की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से करना पड़ा। कई राज्य सहकारी संस्थाओं ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की जिससे वर्ष के दौरान दूध और उसके उत्पादों में तेजी बनी रही। उत्पादन की लागत के बढ़ने के प्रतिक्रियास्वरूप खरीद कीमतों में भी वृद्धि की गई। इसके अलावा, मलाई रहित दुग्ध उत्पादों की उच्च वैश्विक कीमतों ने भी घरेलू दूध की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। फरवरी 2020 में दूध की मुद्रास्फीति मजबूत होकर 56 महीनों के उच्चतम स्तर 6.0 प्रतिशत पर पहुंच गई।

शक्कर और मिठाई की कीमतें (सीपीआई में 1.4 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 3.0 प्रतिशत का भारांक) चार माह की सतत अवस्फीति के बाद अक्तूबर 2019 में उससे उबर पाई; अंशतः प्रतिकूल आधार प्रभाव की वजह से। घरेलू और वैश्विक उत्पादन में कमी के बावजूद पिछले वर्ष के शेष स्टॉक के कारण घरेलू उपलब्धता अपेक्षा से अधिक रही और इसके चलते

घरेलू कीमत दबावों को नियंत्रित रखा जा सका।

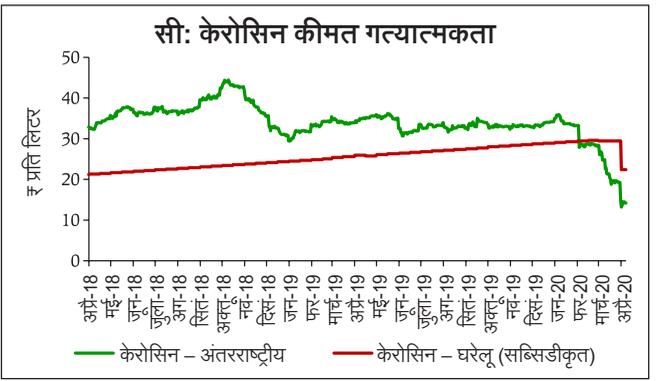
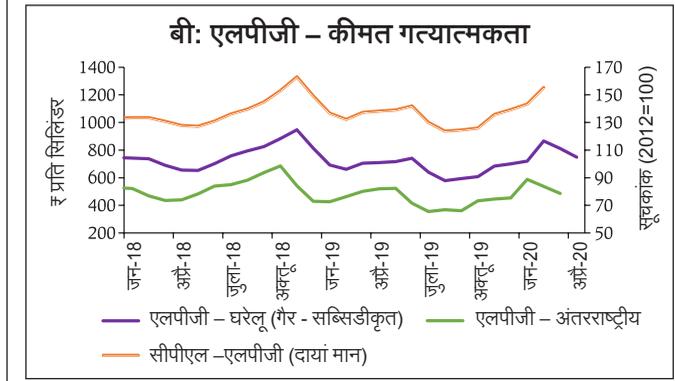
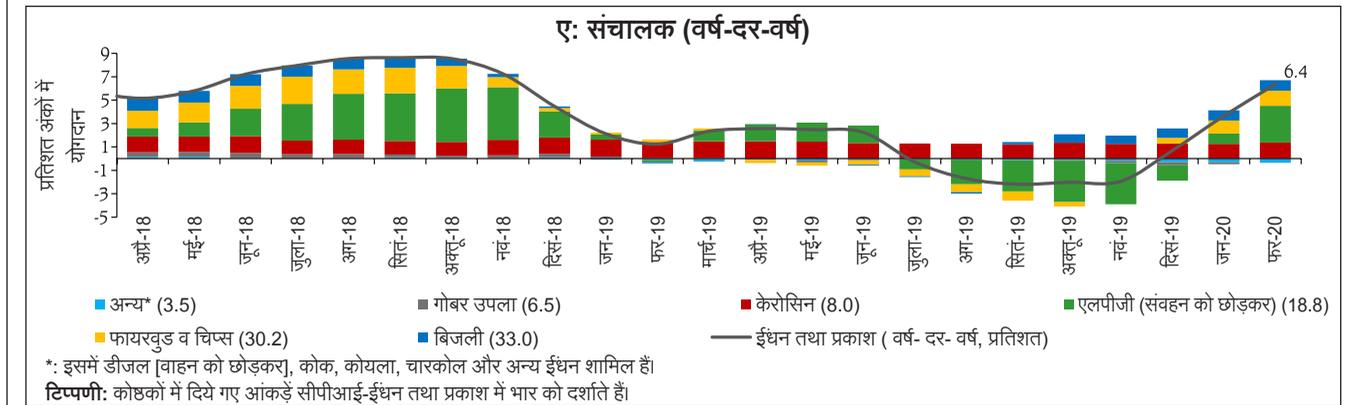
वर्ष के दौरान खाद्य तेलों और वसा की कीमतों की मुद्रास्फीति में तेजी आई और यह अप्रैल 2019 के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2020 में 7.6 प्रतिशत हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतों, रबी तिलहन की कम घरेलू पैदावार और प्रतिकूल आधार प्रभाव के मिले-जुले असर से उच्चतर खाद्य तेल मुद्रास्फीति सामने आई। दूध की उच्चतर कीमतों ने भी घी और मक्खन की कीमतों पर असर डाला।

मसालों में उल्लेखनीय कीमत दबाव देखने में आया और उसकी वजह से इस समूह में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से मजबूत होती चली गई और समग्र रूप से निम्नतर उत्पादन के चलते वह अप्रैल 2019 के 0.8 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2020 में 8.8 प्रतिशत पर पहुंच गई।

सीपीआई ईंधन समूह

सापीआई ईंधन समूह की कीमतें जो जुलाई में (-)0.3 प्रतिशत पर अवस्फीति में पहुंच गई थीं, वह नवंबर 2019 तक ऋणात्मक दायरे में बनी रहीं क्योंकि तरल पेट्रोलियम गैस, ईंधन की लकड़ी और गोबर के उपलों जैसी मुख्य ईंधन वस्तुओं की कीमतें गहरे अवस्फीति में पहुंच गईं। ईंधन समूह दिसंबर में अवस्फीति से बाहर निकल आया और उसके बाद इसमें तीखी बढ़ोतरी दर्ज की गई जिससे फरवरी तक इस श्रेणी की मुद्रास्फीति 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस तेजी में बिजली, एलपीजी और ईंधन की लकड़ी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी तथा मजबूत प्रतिकूल आधार प्रभावों की भूमिका रही (चार्ट II.11ए)। अंतरराष्ट्रीय प्रोपेन व बुटेन की कीमतें, जो 2019-20 की पहली छमाही में सतत गिरती जा रही थीं, उनमें अक्तूबर 2019-जनवरी 2020 के दौरान लगातार बढ़ोतरी देखी गई जिसका प्रमुख कारण था भूराजनैतिक तनावों के चलते आपूर्ति में पहुंच रही बाधा। फरवरी 2020 के अंतराल के साथ इन दबावों का असर घरेलू एलपीजी की कीमतों पर भी देखा गया (चार्ट II.11बी)। केरोसिन की प्रशासित कीमतें अस्थिर और ऊंची बनी रहीं जो ईंधन पर दी जानेवाली सब्सिडी को क्रमशः समाप्त करने के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा जाचं परखे गए ढंग से कीमतें बढ़ाने को प्रतिबिंबित करता है। तथापि, फरवरी के आरंभ में प्रशासित कीमतें बाजार दरों से ऊपर थीं, खासकर अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई अकस्मात् गिरावट की वजह से। इसके परिणामस्वरूप मार्च में पीडीएस में केरोसिन की कीमतों में कुछ गिरावट आई (चार्ट II.11सी)।

चार्ट II.11: सीपीआई ईंधन समूह मुद्रास्फीति



टिप्पणी : (1) एलपीजी के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य सऊदी ब्यूटेन और प्रोपेन के लिए ब्लूमबर्ग स्पॉट मूल्य पर आधारित है, जो क्रमशः 60:40 के अनुपात में संयुक्त है। ये अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्य संकेतक आयात मूल्य हैं। अधिक जानकारी www.ppac.org.in पर उपलब्ध है।
 (2) केरोसिन के लिए अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक मूल्य सिंगापुर जेट केरो स्पॉट मूल्य है।
 (3) एलपीजी और केरोसिन की घरेलू कीमतें इंडियन ऑइल कार्पोरेशन।

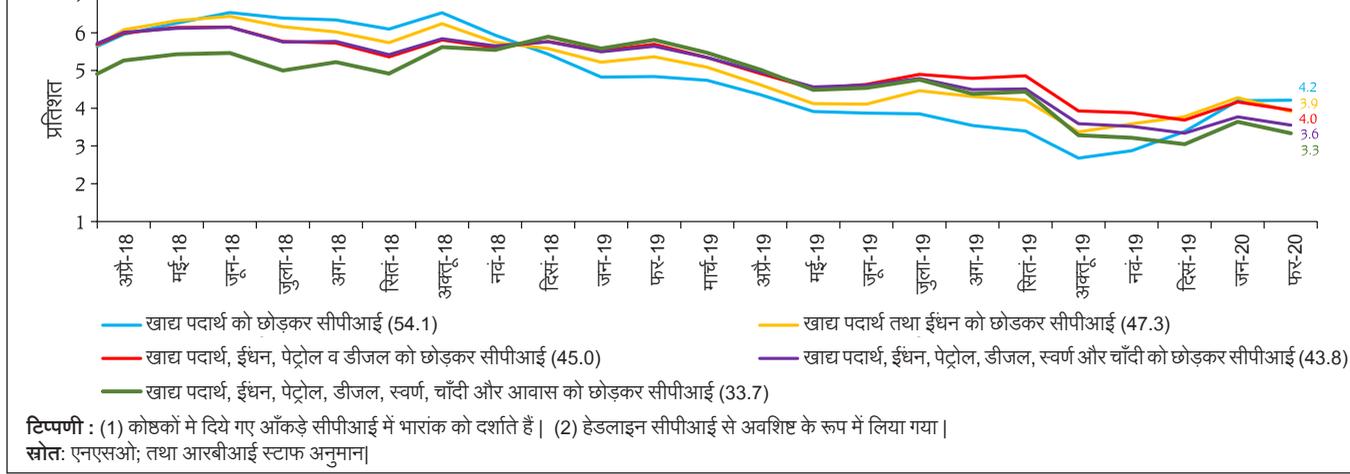
स्रोत: (i) चार्ट II.11ए के लिए एनएसओ और आरबीआई स्टाफ अनुमान।
 (ii) चार्ट II.11बी और 11सी के लिए ब्लूमबर्ग, इंडियन ऑइल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); एनएसओ।

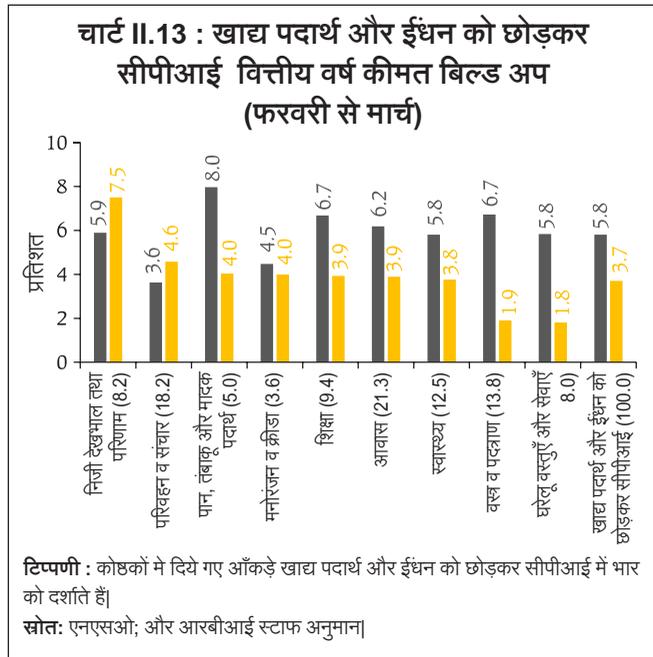
सीपीआई खाद्य और ईंधन को छोड़कर

खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई मुद्रास्फीति अथवा मूल मुद्रास्फीति में फरवरी 2020 में थोड़ी नरमी आने से पहले

क्रमशः तेजी रही और वह अक्टूबर 2019 के 3.4 प्रतिशत से जनवरी 2020 में 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गई (चार्ट II.12)। घटकों के हिसाब से, 2019-20 के दौरान कीमतों में चढ़ाव

चार्ट II.12: अपवाद-आधारित सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

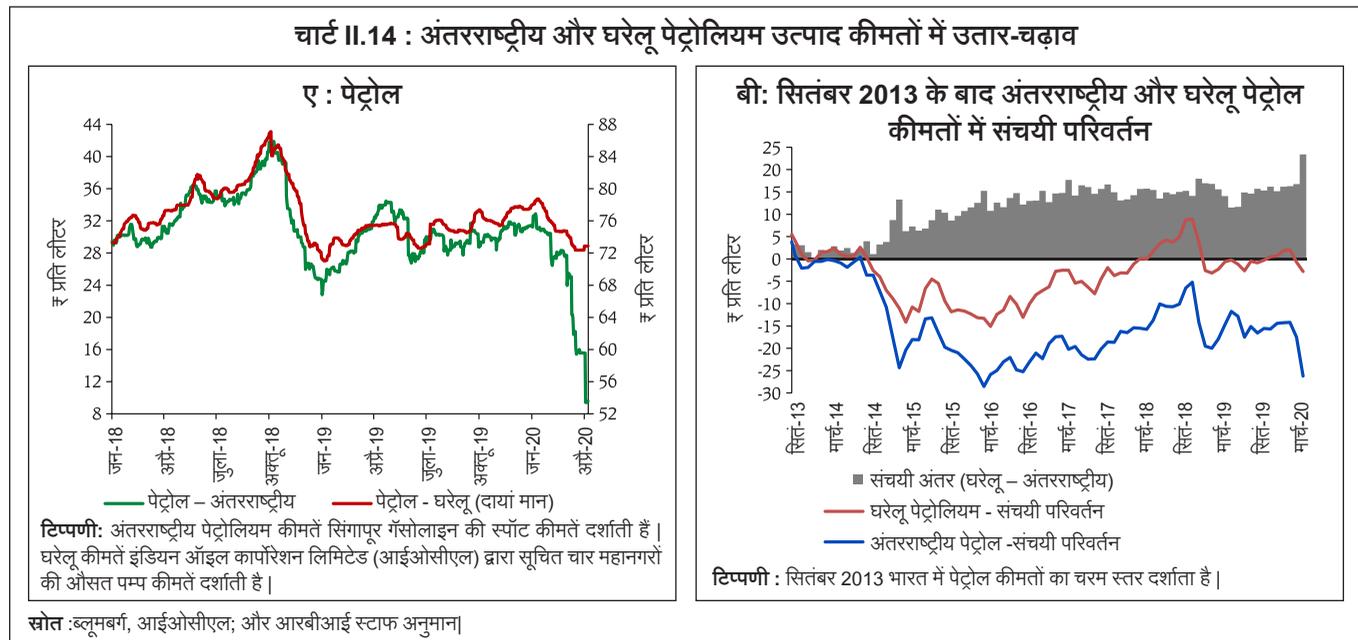




विगत औसतों से काफी कम रहा लेकिन परिवहन और संचार तथा व्यक्तिगत देखभाल व कपड़ा उप-समूह इसके अपवाद रहे (चार्ट II.13)।

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मची उथल-पुथल और उसके परिणामस्वरूप पेट्रोल की घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी ने जनवरी 2020 तक खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई के चढ़ाव और उसके बाद फरवरी में आई नरमी में मुख्य भूमिका

अदा की। नवंबर 2019 तक 11 माह के दौरान अवस्फीति में रही पेट्रोल और डीजल सीपीआई फरवरी में नरम पड़ने तक दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान तेजी से बढ़ी। 2019-20 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल कई घटनाक्रमों से उत्पन्न हुई जिसकी शुरुआत सितंबर के आरंभ में बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों के साथ हुई और उसके बाद दिसंबर में तेल उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) ने उत्पादन में कटौती कर दी तथा जनवरी में नए सिरे से भू-राजनैतिक तनावों की शुरुआत हुई। जनवरी मध्य से भू-राजनैतिक तनावों और ओपेक एवं रशिया के बीच कीमत युद्ध के घटने एवं कोविड-2019 की वजह से वैश्विक मंदी की आशंकाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतों में जनवरी के मध्य से तीव्र कमी देखने में आई। हालांकि, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का पेट्रोल की घरेलू कीमतों पर असर अभी दिखना बाकी है, तथापि पेट्रोल एवं डीजल के करों में बढ़ोतरी कर इसके प्रभाव को रोक दिया गया है (चार्ट II.14ए)। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के प्रति बैरल 40 अमेरिकी डालर से भी कम होते ही पेट्रोल एवं डीजल दोनों के उत्पाद शुल्क में 14 मार्च 2020 को प्रति लीटर 3 रु की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल एवं डीजल पर कुल उत्पाद शुल्क क्रमशः 22.98 रु एवं 18.83 रु बनता है। अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू पेट्रोल की कीमतों में यह अंतर हाल के समय में सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है (चार्ट II.14बी)।



चौथी तिमाही में अब तक (जनवरी-फरवरी) तीव्र वृद्धि दर्ज करने के पहले, खाद्य, ईंधन, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में दिसंबर में गिरावट आई। खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, स्वर्ण, चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति-जिसमें परिवर्तनशील स्वर्ण और चांदी के मूल्य प्रभावों को शामिल नहीं किया गया है- में भी इसी तरह का उतार-चढ़ाव दिखा (चार्ट II.12)।

खाद्य, ईंधन, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर सीपीआई के वस्तु और सेवाओं के घटकों का विवरण लागत-वृद्धि कारकों के प्रभाव को दर्शाता है जिसने इस वर्ग में मुद्रास्फीति के तीव्र मोडरेशन को प्रतिकूल बनाया और इसमें दिसंबर 2019 -जनवरी 2020 के दौरान बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.15)।

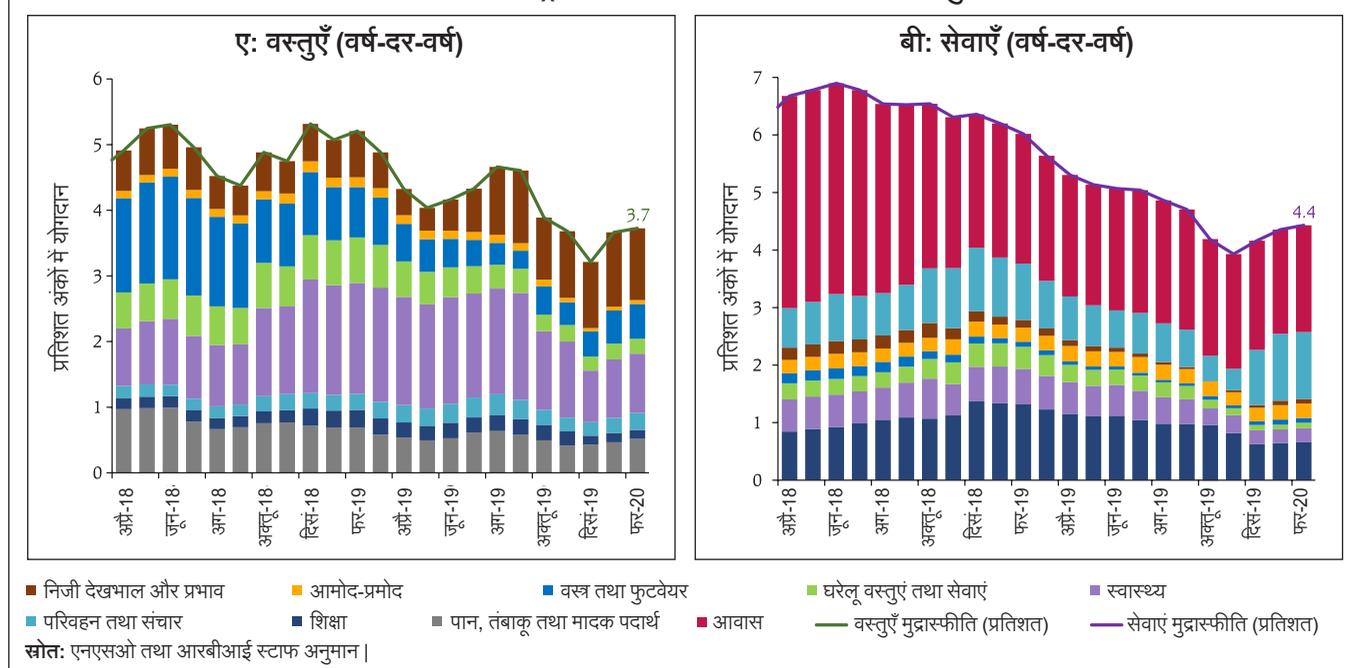
मूल वस्तुओं के मूल्यों की मुद्रास्फीति में दिसंबर 2019 तक क्रमिक रूप से कमी आई, जो माल मदों की मुद्रास्फीति विशेष रूप से बड़े और अनुकूल आधार प्रभाव के चलते स्वास्थ्य मुद्रास्फीति में व्यापक आधारित गिरावट के कारण थी। स्वास्थ्य उप समूह में वस्त्र, पान, तंबाकू, दवाओं के मूल्यों में वृद्धि के चलते जनवरी से माल मुद्रास्फीति ऊपर की ओर बढ़ रही है। तत्पश्चात, इनपुट लागत में वृद्धि और इमीशन मानदंड से बीएस-VI में स्विच-ओवर के कारण परिवहन तथा संचार उप समूह में आवश्यक दवाओं और ऑटोमोबाइल के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि हुई (चार्ट II.15ए)।

घरेलू नौकरानी/ रसोइए और अन्य घरेलू सेवाओं; शैक्षिक सेवाओं के शैक्षणिक शुल्क; गृह किराया, परिवहन और संचार सेवाओं के अंतर्गत परिवहन किराए और मोबाइल टेलीफोन प्रभारों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण अक्टूबर-नवंबर 2019 के दौरान मूल सेवाओं से संबन्धित मुद्रास्फीति में तेजी से कमी आई। दिसंबर के प्रारंभ में प्रमुख निजी मोबाइल परिचालकों द्वारा शुल्कों में वृद्धि के फलस्वरूप, मोबाइल टेलीफोन प्रभारों में वृद्धि हुई (नवंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच 12 प्रतिशत के आसपास)। इस अवधि के दौरान बस के किराए और प्रशासित रेलभाड़े में भी वृद्धि हुई। परिणामतः परिवहन और संचार सेवाओं से संबन्धित मुद्रास्फीति में काफी अधिक वृद्धि हुई, जिसने समग्र सेवा मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। कमजोर मांग की दशाओं को परिलक्षित करते हुए, 2019-20 की दूसरी छमाही में आवास मुद्रास्फीति में नरमी आई। दिसंबर 2019- फरवरी 2020 के दौरान शैक्षिक सेवाओं की मुद्रास्फीति भी नरम बनी रही (चार्ट II.15बी)।

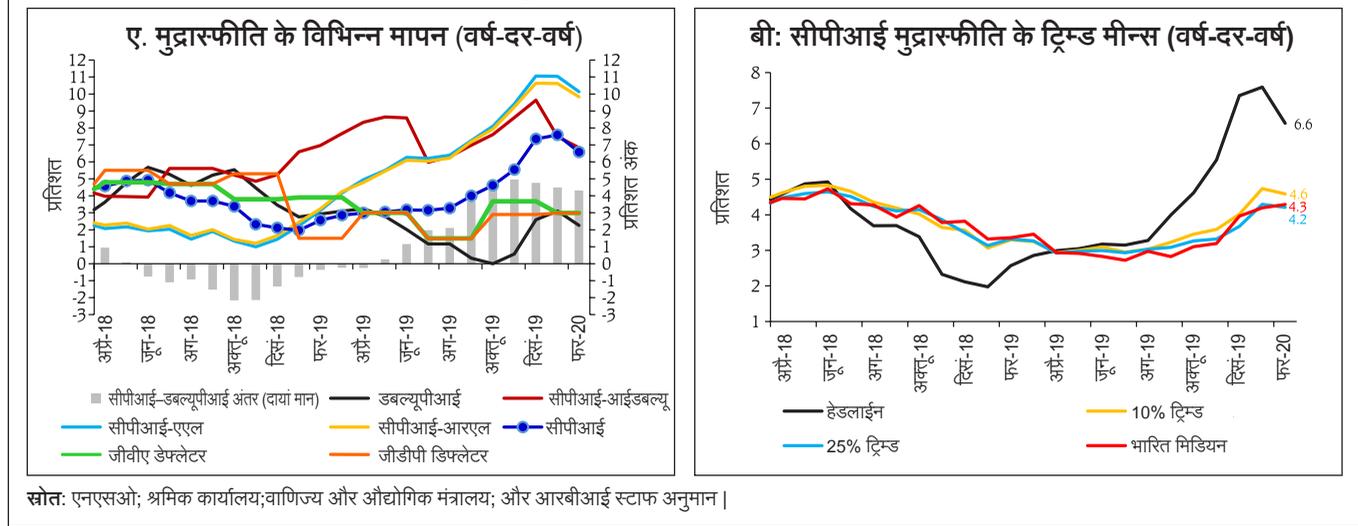
मुद्रास्फीति के अन्य उपाय

अगस्त-दिसंबर 2019 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू), कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई-आरएल) के लिए सेक्टरल सीपीआई मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई जो प्रमुख रूप से

चार्ट II.15 : खाद्य पदार्थ, ईंधन,पेट्रोल व डीजल को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान



चार्ट II.16: मुद्रास्फीति के वैकल्पिक मापन (वर्ष-दर-वर्ष)



खाद्य मूल्यों में गैर मौसमी वृद्धि के कारण थी। तथापि, खाद्य समूह में मूल्यों में स्थिरता के कारण जनवरी-फरवरी 2020 में इस गति में नरमी आई। सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के खाद्य और ईंधन घटक में मुद्रास्फीति हैडलाइन सीपीआई की तुलना में अधिक थी। खाद्य की एक बड़े भाग ने दिसंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान इन सूचकांकों द्वारा दहाई अंक तक मापित समग्र मुद्रास्फीति को और बढ़ा दिया।

जहां तक सीपीआई-आईडब्ल्यू की बात है, दिसंबर 2019 के पश्चात सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आवास किराया भत्ते के प्रभाव के पूरी तरह समाप्त होने के साथ, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट हुई, जिसने हैडलाइन सीपीआई के अंतराल को कम कर दिया। इस गिरावट के बावजूद, सीपीआई-आईडब्ल्यू के आवास सूचकांक, जिसे छह माह में एक बार अर्थात जनवरी और जुलाई में प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाता है, की गति में हाल की वृद्धि ने जनवरी 2020 के सीपीआई-आईडब्ल्यू में सर्वाधिक उर्ध्वगामी वृद्धि की (3.7 प्रतिशत अंक की माह दर माह वृद्धि)। खाद्य मूल्यों में 1.7 प्रतिशत अंक के तीव्र सुधार के कारण फरवरी 2020 में सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति में और कमी आई।

सेक्टरल सीपीआई के विरोधाभास में अगस्त- अक्टूबर 2019 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में गिरावट आई, जो वैश्विक पण्य मूल्यों में नरमी के चलते गैर खाद्य विनिर्मित उत्पादों के मूल्यों में कमी के कारण थी। तदुपरांत,

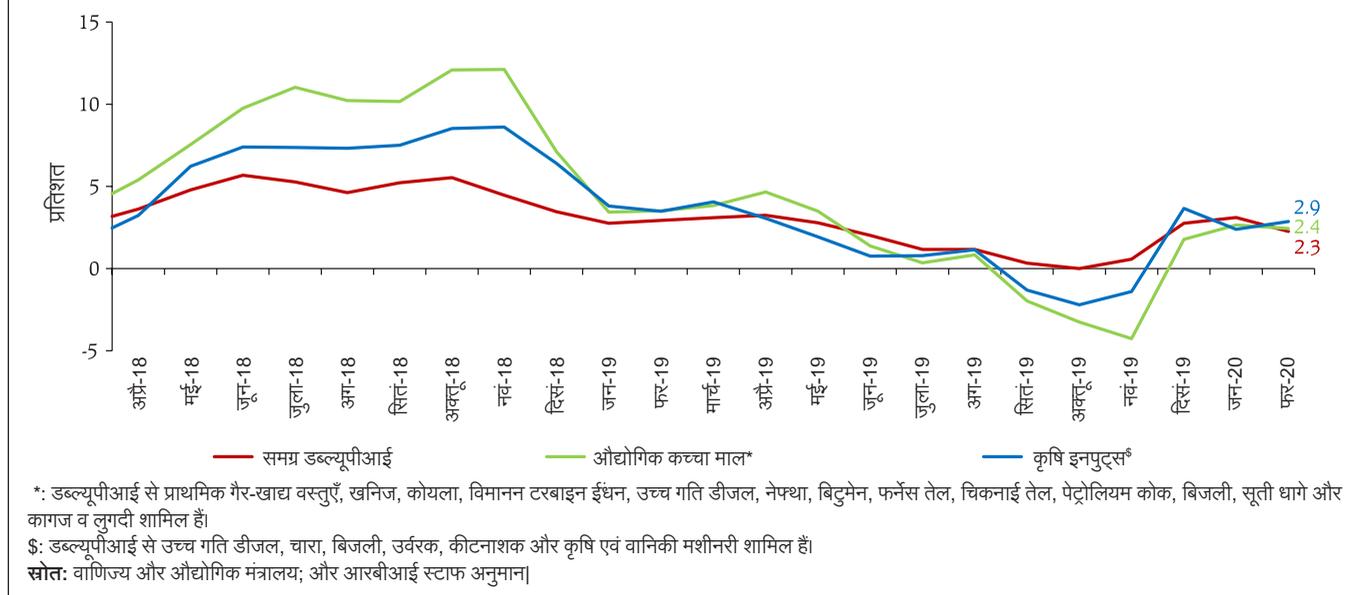
सेक्टरल सीपीआई के अनुरूप डबल्यूपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई क्योंकि खाद्य मूल्यों में सुगमता के चलते फरवरी में पुनः थोड़े सुधार के पहले दिसंबर 2019 - जनवरी 2020 में थोक खाद्य मूल्यों में बढ़ोतरी हुई, 2019-20 की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचने के पश्चात, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्ययोजित (जीवीए) अपस्फीतिकारकों में 2019-20 की तीसरी तिमाही में तीव्रता आई, जो सीपीआई के साथ स्पष्ट विपथन और डबल्यूपीआई के साथ व्यापक संरेखण को दर्शाता है (चार्ट II.16ए)।

मुद्रास्फीति का उत्तम मध्यमान मापदंड, जो आउटलाइर्स को सीधे तौर पर हटाकर और धनात्मक तथा ऋणात्मक स्क्वू को समाप्तकर निकाला गया है, अंतर्निहित मुद्रास्फीति के उतार-चढ़ाव का एक मापक उपलब्ध कराता है। सीपीआई के अपवर्जन आधारित मापदंडों में भी उन घटकों को हटाकर मुद्रास्फीति में प्रचलित रुझानों को शामिल किया गया है, जिन्हें कुछ विशेष प्रकृति का समझा जाता है। पिछले 6 महीनों के दौरान उत्तम मध्यमान और अपवर्जन आधारित मापदंडों में स्थिरता आई है (चार्ट II.12 और II.16बी)।

II.3 लागत

अंतर्निहित लागत दशाएं व्यापक तौर पर डबल्यूपीआई से संबंधित मुद्रास्फीति के अनुरूप रही हैं (चार्ट II.17)। फार्म आगतों और औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों (डबल्यूपीआई से उद्धृत) से संबंधित मुद्रास्फीति में अप्रैल 2019 के पश्चात काफी

चार्ट II.17 : कृषि कार्य तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



अधिक कमी आई और यह सितंबर-नवंबर 2019 के दौरान ऋणात्मक दायरे में बनी रही, किंतु, इसमें दिसंबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान वृद्धि दर्ज हुई। दिसंबर 2019-जनवरी 2020 के दौरान हुई वृद्धि आंशिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल के मूल्यों में सुधार तथा प्रतिकूल आधार प्रभावों को दर्शाती है। इसके अलावा, खनिजों और गैर खाद्य वस्तुओं की लागत ने भी गैर-फार्म आगतों की लागत की हालिया मूल्य संरचना को प्रभावित किया।

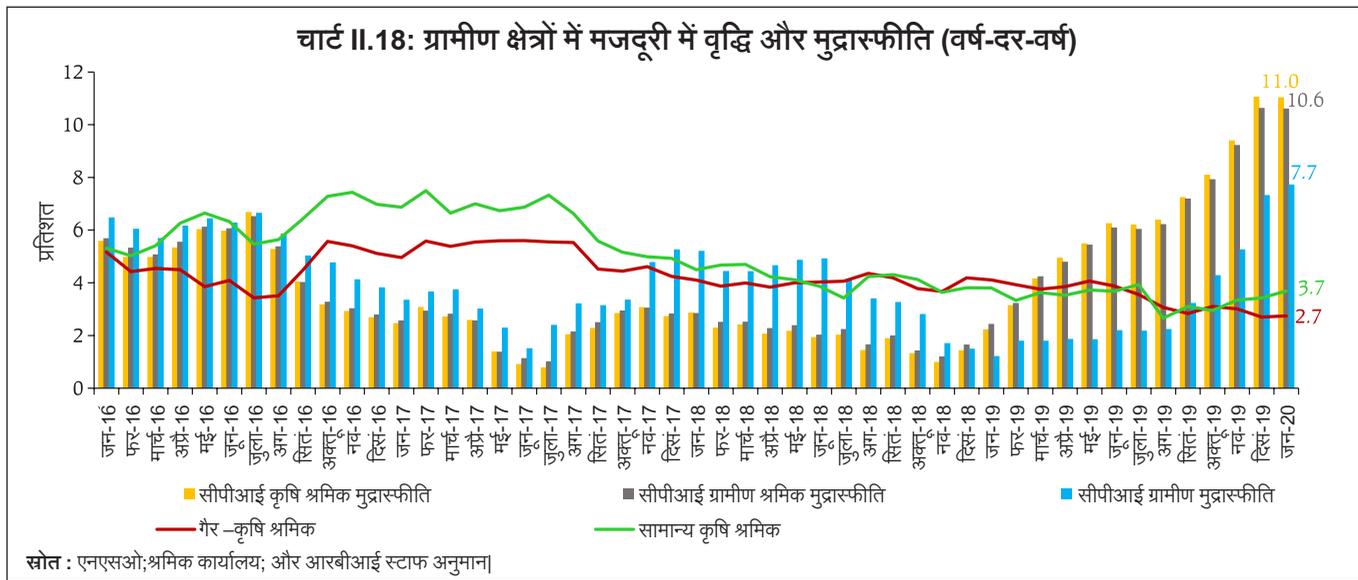
अन्य औद्योगिक कच्चे माल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय कोयला मूल्यों की वृद्धि के अनुरूप घरेलू कोयला मुद्रास्फीति अप्रैल 2019 के 0.4 प्रतिशत से अक्टूबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान बढ़कर 2.4 प्रतिशत हो गई। गूदासहित कच्चे माल की कम लागत के कारण जुलाई 2019-फरवरी 2020 के दौरान कागज और कागज उत्पादों के मूल्य अपस्फीतिकारक बने रहे। फाइबर की बात करें, कच्चे कपास और जूट फाइबर के मूल्यों में कमी के फलस्वरूप, अगस्त 2019-फरवरी 2020 के दौरान अपस्फीतिकारी स्थिति बनी रही, जो इसी अवधि में कपास धागे के मूल्यों की कमी में भी परिलक्षित हुई।

जहां तक फार्म क्षेत्र के आगतों की बात है, बिना मौसम की बारिश के कारण चारे के मामले में मुद्रास्फीति और बढ़ी, जबकि उर्वरकों और कीटनाशकों के मामले में कुछ नरमी देखी गई जो

सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय उर्वरक मूल्यों की कमजोर गति को दर्शाती है। बिजली के दामों में, जिसका औद्योगिक और फार्म आगत दोनों में उच्च भारांक है, वर्ष के दौरान मामूली वृद्धि हुई, जो कमजोर मांग की दशाओं को दर्शाती है। कृषि मशीनरी और उपस्कर लागतों से संबंधित मुद्रास्फीति भी वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान धीरे-धीरे नरम हुई।

कृषि और कृषेतर श्रमिक दोनों की नाममात्रेण ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि, 2019-20 के दौरान अब तक (जनवरी 2020 तक) औसतन लगभग 3.4 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत के आस-पास कमजोर स्थिति में बनी रही, जो प्रमुख रूप से विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर जारी स्लोडाउन को दर्शाती है (चार्ट II.18)। तथापि, फुटकर ग्रामीण मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि के कारण वास्तविक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि ऋणात्मक रही, जैसा कि मार्च 2019 से सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के मापदंडों तथा सितंबर 2019 से सीपीआई ग्रामीण मुद्रास्फीति से पता चलता है।

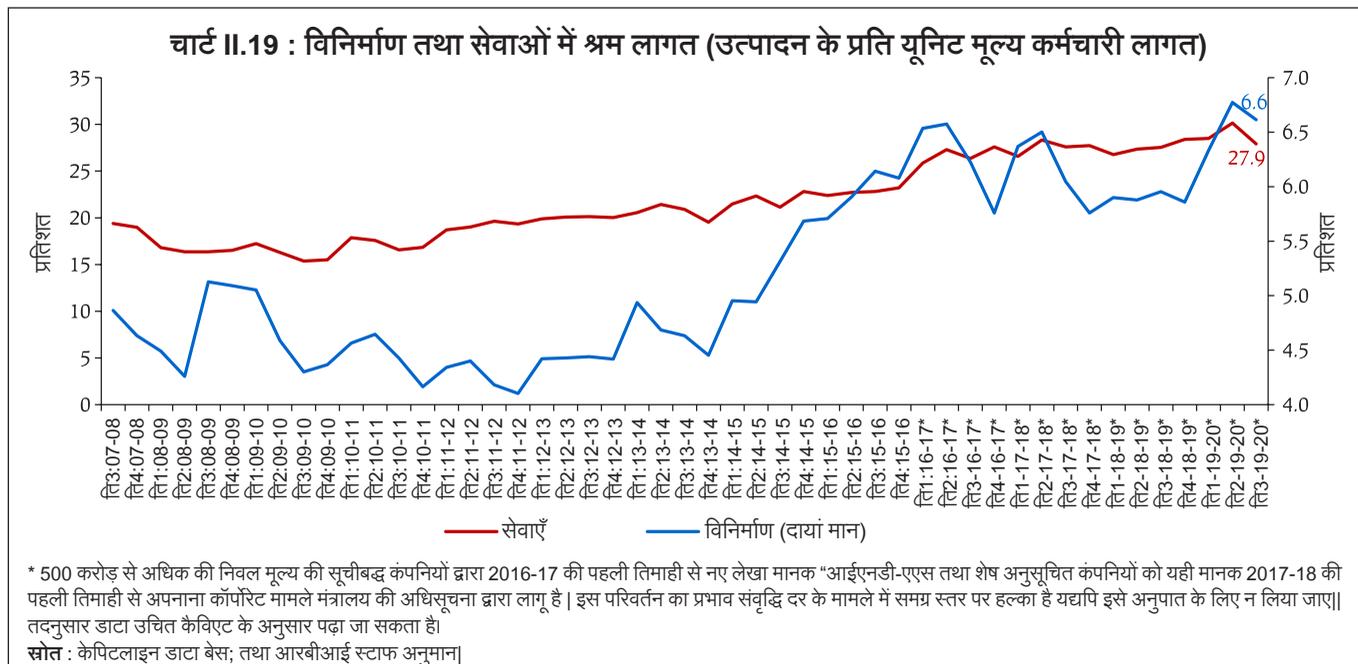
संगठित क्षेत्र के स्टाफ लागत में वृद्धि सेवा और विनिर्माण फर्मों के लिए विभिन्न उतार-चढ़ाव को दर्शाती है। जबकि पिछली तिमाही की तुलना में 2019-20 की तीसरी तिमाही में सेवा फर्मों की स्टाफ लागत वृद्धि में बढ़त हुई, विनिर्माण फर्मों के मामले में इसमें गिरावट आई। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों की इकाई श्रम



लागत (प्रतिशत में उत्पादन मूल्य की तुलना में स्टाफ लागत अनुपात) उत्पादन मूल्य में क्रमिक गिरावट और स्टाफ लागत में वृद्धि के कारण 2018- 19 की चौथी तिमाही के 5.9 प्रतिशत से 2019-20 की पहली तिमाही में 6.3 प्रतिशत और फिर दूसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत क्रमिक रूप से बढ़ी। 2019-20 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण के लिए इकाई श्रम लागत मामूली रूप से घटी। दूसरी तरफ, सेवा क्षेत्र की फर्मों के उत्पादन मूल्य में उच्चतर त्रैमासिक वृद्धि से इकाई श्रम लागत में 220 आधार अंक की गिरावट आई, जो 2019-20 की दूसरी तिमाही के

30.1 प्रतिशत से तीसरी तिमाही में 27.9 प्रतिशत रही जबकि स्टाफ लागत में कुछ वृद्धि हुई (चार्ट II.19)।

रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वे में शामिल होने वाली विनिर्माण फर्मों ने 2019-20 की तीसरी और चौथी तिमाही में कम लागत दबाव सूचित किए। इससे तीसरी तिमाही में फार्म और औद्योगिक कच्चे माल में मुद्रास्फीतिक नरमी और चौथी तिमाही में कमजोर धातु तथा अन्य पण्य मूल्य दबावों का पता चलता है। तीसरी और चौथी तिमाही के पोल में शामिल कंपनियों ने वित्त की लागत में भी गिरावट के बारे में सूचित किया। तीसरी



तिमाही में वेतन व्यय के कारण लागत दबाव में भी कमी आई और चौथी तिमाही में इसके कमजोर बने रहने की उम्मीद है। कमजोर मांग दशाओं और कमजोर आगत मूल्य दबावों ने बिक्री मूल्यों को नरम रखा, चौथी तिमाही में इसकी प्रत्याशा केवल कमजोर वृद्धि को दर्शाती है। जबकि उत्पादक मूल्य प्रत्याशाएं कमजोर रहीं, वहीं रिजर्व बैंक के सर्वे के मापन के अनुसार, घरेलू मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाएं भी नरम रहीं।

परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) में शामिल विनिर्माण फ़र्मों ने चौथी तिमाही में आगत मूल्यों में मामूली वृद्धि और स्थिर उत्पाद मूल्यों के बारे में सूचित किया। तथापि, चौथी तिमाही (फरवरी तक) में पीएमआई सेवा फ़र्मों से संबन्धित आगत मूल्यों में वृद्धि हुई, जो खाद्य और ईंधन के कम मूल्य और कमजोर मांग के चलते मार्च 2020 में तेजी से गिरने के पहले, खाद्य, श्रम और सामग्री की उच्च लागत से प्रेरित थे। सेवा फ़र्मों के द्वारा लिए गए मूल्य तीसरी और चौथी तिमाही में व्यापक तौर पर सीमांतगत रहे लेकिन फ़र्मों के द्वारा कमजोर मांग दशाओं के चलते अपनी फीस घटाने के कारण मार्च 2020 में इसमें नरमी आई।

II.4 निष्कर्ष

प्याज के दामों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीतिक परिदृश्य में नाटकीय तौर पर बदलाव आया। कोविड-19 गंभीर होने के पहले, 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए भावी मार्ग सर्वेक्षणों में कमजोर उपभोक्ता विश्वास और फ़र्मों की कमजोर मूल्य निर्धारण शक्ति के बारे में पहले ही संकेत दिया जा चुका है। मार्च 2020 से कोविड-19 के महामारी में बदलने के कारण मुद्रास्फीतिक दृष्टिकोण बहुत अधिक अनिश्चित हो गया है। कच्चे तेल के मूल्य अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं जो 2000 के दशक से नहीं देखे गए हैं। अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लॉकडाउन की स्थिति में होने के कारण, मांग की दशाएं तेजी से कमजोर हो सकती हैं। तदनुसार, विश्व भर के देश अपस्फीतिकारी शक्तियों का सामना कर रहे हैं। भारत महामारी जनित गंभीर निम्नगामी दबावों से अछूता नहीं रह सकता। सारे देश के लॉकडाउन में होने के कारण एनएसओ को उपभोक्ता मूल्यों के संकलन और मापन में बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

III. माँग और उत्पादन

वर्ष 2019-20 में सकल माँग में गिरावट की परिस्थितियाँ, दूसरी छमाही में निवेश में संकुचन और सरकारी व्यय में नरमी के कारण और बिगड़ती गईं आपूर्ति पक्ष में, कृषि और सहायक गतिविधियाँ, दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में बाद में आयी तेजी और प्रचुर उत्तर-पूर्व मानसून की सघनता से बल पाकर तेज हुईं तथापि, विनिर्माण गतिविधियों में गिरावट के कारण औद्योगिक गतिविधियाँ धीमी हुईं सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में भी निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं में मंदी आने के कारण सुस्ती आयी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) से जारी किए गए फरवरी 2020 के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमिक मंदी आने लगी थी। 2018-19 की दूसरी छमाही से 2019-20 की पहली छमाही तक वास्तविक जीडीपी संवृद्धि की गति और कम हुई और यह औसतन 5.5 प्रतिशत रही। 2019-20 की तीसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से नीचे के मान (4.7 प्रतिशत) ने इस परिदृश्य के बारे में अनिश्चताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। कृषि को छोड़कर, गतिविधियों के कमजोर या सुस्त उच्च आवृत्ति संकेतकों पर नॉवल कोरोना वाइरस (कोविड-19) महामारी का भारी दबाव यह संकेत देता है कि एनएसओ के आँकड़ों में 2019-20 की चौथी तिमाही में निहित वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अच्छे-खासे अंतर से कम हो जाएगी। वस्तुतः मार्च 2020 में और फैलती जा रही कोविड-19 की घटनाओं से चौथी तिमाही की जीडीपी में अधोगामी दबाव पड़ सकता है।

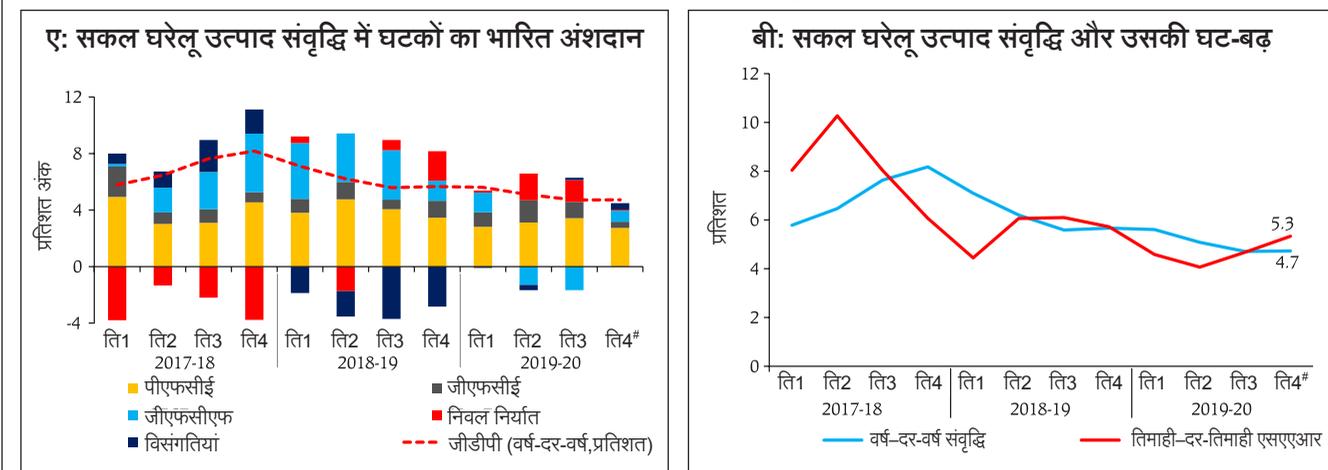
हाल के अनुभव के सापेक्ष, इस स्पष्ट गिरावट में अंतर्निहित है- 2019-20 की दूसरी तिमाही से सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में संकुचन। मुख्यतः सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में तीव्र उछाल के कारण उपभोग व्यय में तेजी आयी और सकल माँग बनी रही। निवल निर्यात ने भी सकल माँग में सकारात्मक योगदान दिया, लेकिन ऐसा अनिवार्यतः इसलिए हुआ क्योंकि आयातों में संकुचन की गति निर्यात में गिरावट से कहीं अधिक तेज रही। आपूर्ति पक्ष में, कृषि और सहायक गतिविधियों ने, खरीफ और फल उत्पादन में वृद्धि से

बल पाकर, दूसरी और तीसरी तिमाही में योजित सकल मूल्य (जीवीए) को गति प्रदान किया। उद्योग क्षेत्र, कमजोर माँग स्थितियों और इसलिए कमजोर कीमत-निर्धारण शक्ति के कारण, शिथिल बना रहा। सेवा क्षेत्र में, पीएमआई, सीमेंट उत्पादन और रेलवे माल ढुलाई को छोड़कर, जनवरी और फरवरी 2020 में उच्च आवृत्ति संकेतकों के सुस्त होने या गिरते जाने के साथ, 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान गतिविधियाँ कमजोर होती गईं। लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ (पीएडीओ) दूसरी और तीसरी तिमाही में मजबूत बनी रहीं। तथापि, ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर, केंद्र के राजस्व व्यय में आंशिक वृद्धि ही हुई। कोविड-19 के विस्फोट के मद्देनजर मार्च से ही लगे लॉकडाउन ने विनिर्माण गतिविधियों को एकदम ठप्प कर दिया है। उपाख्यानानात्मक साक्ष्य यह इंगित करता है कि विनिर्माण क्षेत्र में, श्रमिकों के विस्थापन ने ऑटोमोबिल, एलेक्ट्रॉनिक सामानों और उपकरणों और परिधान उद्योग पर प्रतिकूल असर डाला है। सेवाओं यथा- व्यापार, पर्यटन, विमानन, आतिथ्य क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र पर भी गहरी मार पड़ी है।

III.1 सकल माँग

2019-20 में सकल माँग स्थितियों में गिरावट सकल स्थिर पूंजी निर्माण में संकुचन (1.3 प्रतिशत) और दूसरी छमाही में सरकारी व्यय में सुस्ती के कारण और अधिक तेज हो गयी। यद्यपि निजी उपभोग क्रमिक रूप से बना रहा लेकिन यहाँ वर्षानुवर्ष आधार (चार्ट III.1ए और तालिका III.1) पर 2019-20 की दूसरी छमाही में अधिक धीमा रहा। समग्र रूप से, 2019-20 की दूसरी छमाही में जीडीपी संवृद्धि में ठहराव को प्रतिकूल आधारभूत प्रभावों में समझ जा सकता है, क्योंकि वर्षानुवर्ष मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दर (एसएएआर) द्वारा मापा गया आवेग दूसरी छमाही में त्वरित हुआ (चार्ट III.1बी)। फरवरी और खास तौर पर मार्च में कोविड-19 से हुई भारी क्षति के कारण यह आवेग वर्ष के समाप्त होने तक बना रह पाएगा होगा, इसकी संभावना कम ही है। तदनुसार, इस 2019-20 में पूरे वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि का एनएसओ द्वारा 5.0 प्रतिशत के अनुमान में जोखिम हो सकता है, क्योंकि यह 2018-19 के 6.1 प्रतिशत से पहले ही नीचे था।

चार्ट III.1: मौसमी समायोजित जीडीपी संवृद्धि और उसके घटक



टिप्पणी : 1.#.अंतर्निहित संवृद्धि | 2. एसएएआर – मौसमी समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दर
स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान |

अंतर्निहित गतिविधि पर पारंपरिक स्रोतों से मिलने वाले ठोस आँकड़ों के अभाव में, भारी मात्रा में- रूप और सामग्री में अलग-अलग और सुव्यवस्थित या अव्यवस्थित- उच्च आवृत्ति वाली सूचनाओं की उपलब्धता ने अर्थव्यवस्था के हालात पर अर्थपूर्ण संकेत निकालने के रास्ते खोल दिये हैं। प्रिंट मीडिया में

रोजाना आने वाली खबरों के आधार पर तैयार किया गया रुख सूचकांक (एसआई) भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से आँक सकता है। एसआई, 2019-20 की चौथी तिमाही में कमजोर गतिविधि का संकेत देता है (बॉक्स III.1)।

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

मद	2018-19 (एफआरई)	2019-20 (एसएई)	भारत योगदान*		2018-19 (एफआरई)				2019-20 (एसएई)			
			2018-19	2019-20	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
निजी अंतिम उपभोग व्यय	7.2	5.3	4.0	3.0	6.7	8.8	7.0	6.2	5.0	5.6	5.9	4.9
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	10.1	9.8	1.0	1.0	8.5	10.8	7.0	14.4	8.8	13.2	11.8	4.9
सकल फिक्स्ड पूंजी निर्माण	9.8	-0.6	3.0	-0.2	12.9	11.5	11.4	4.4	4.3	-4.1	-5.2	2.5
निर्यात	12.3	-1.9	2.4	-0.4	9.5	12.5	15.8	11.6	3.2	-2.1	-5.5	-2.8
आयात	8.6	-5.5	2.0	-1.3	5.9	18.7	10.0	0.8	2.1	-9.3	-11.2	-3.0
बाजार मूल्यों पर जीडीपी	6.1	5.0	6.1	5.0	7.1	6.2	5.6	5.7	5.6	5.1	4.7	4.7

एफआरई : पहला संशोधित अनुमान ; एसएई: दूसरा अग्रिम अनुमान : # अंतर्निहित संवृद्धि |

*: संवृद्धि के लिए घटक-वार योगदान को सारणी में जीडीपी संवृद्धि के साथ नहीं जोड़ा है क्योंकि स्टाक, कीमती वस्तुओं में परिवर्तन और विसंगतियों को शामिल नहीं किया है।
स्रोत: एनएसओ सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)|

बॉक्स III.1: आर्थिक संवृद्धि पर मीडिया रुख – एक मशीन शिक्षण दृष्टिकोण

बिग डेटा टूल और मशीन शिक्षण तकनीकों यथा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) और पाठ उत्खनन ने समाचार सामग्रियों (न्यूज टेक्स्ट) से अंकीय संकेतकों की निष्पत्ति और रचना को सुगम बना दिया है (शापिररो एवं अन्य, 2018)। रुचि की विभिन्न परिवर्तियों से संबन्धित दैनिक खबरों से रुख को समझना व्यापक दृष्टिकोण है (गोडबोले एवं अन्य, 2007)। खबरों में मौजूद शब्दों के आधार पर हरेक खबर को तीन रुख श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया जाता है, नामतः, सकारात्मक, नकारात्मक और निरपेक्ष। बिना किसी रुख वाली खबरों या असंगत खबरों को छंट दिया जाता है। रुख श्रेणी स्पष्टतः समान अर्थ-उन्मुखता वाले शब्दों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है (चार्ट III.1.1)।

चार्ट III.1.1: शब्दों का अर्थ-विन्यास



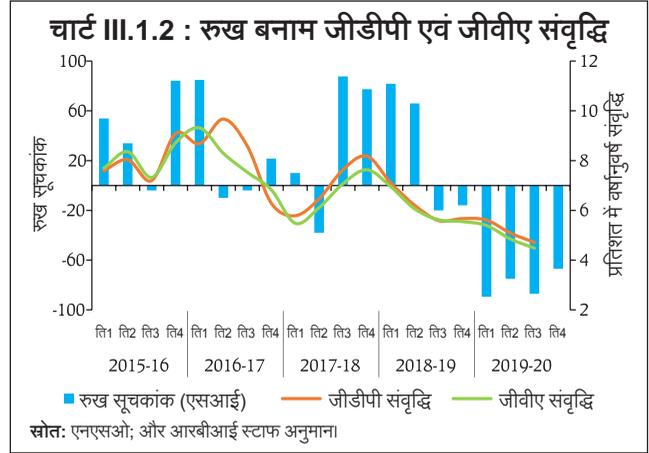
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान |

प्रासंगिक खबरों को सकारात्मक/ नकारात्मक/ निरपेक्ष रुख श्रेणी के अंतर्गत समेकित और सारांकित करके एक रुख सूचकांक (एसआई)¹ बनाया जाता है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

$$\text{एसआई} = \frac{\text{"सकारात्मक" रुख वाली खबरें (\%)} - \text{"नकारात्मक" रुख वाली खबरें (\%)}}{2}$$

इस विश्लेषण के लिए, अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि में आने वाली खबरों को मीडिया इंटेलिजेंस फ़र्म (मेल्टवॉटर) से जुटाया गया है और एक तिमाही रुख सूचकांक बनाने के लिए समेकित किया गया है ताकि वास्तविक जीडीपी और जीवीए में वर्षानुवर्ष संवृद्धि में उतार-चढ़ाव को देखा जा सके (चार्ट III.1.2)।

रुख सूचकांक और आर्थिक गतिविधि (जीडीपी या जीवीए संवृद्धि) को अंतर्संबंध के रूप में मापा जाता है। दिशात्मक सटीकता को एक चिन्ह सफलता अनुपात (एसएसआर)² के रूप में मापा जाता है, जो समय अवधियों का समानुपात है, जब एसआई द्वारा इंगित दिशा जीडीपी/जीवीए संवृद्धि के दिशात्मक परिवर्तन से मेल खाती है और इसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:



(क) IG_t को एक चरांक के रूप में निरूपित करें जो यह दर्शाए कि तिमाही t के लिए वर्षानुवर्ष संवृद्धि क्रमिक रूप से बढ़ी है/घटी है/समान रही है और इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाए

(जारी)

¹ SI का दायरा -100 से 100 तक है। SI का सकारात्मक (नकारात्मक) मान आशावाद/सुधार (निराशावाद/गिरावट) को दर्शाता है, वहीं शून्य मान निरपेक्ष रुख से सम्बद्ध है।
² SSR का उच्च मान, जो 0 से 100 के पैमाने पर 100 के नजदीक है, दर्शाता है कि मीडिया रुख, रुचियों के समष्टिआर्थिक चरांकों में दिशात्मक परिवर्तनों को आँकने में सक्षम है (बुओनो एवं अन्य, 2018)।

$$IG_t = \begin{cases} 1, & \text{if } G_t > G_{t-1} \\ 2, & \text{if } G_t < G_{t-1} \\ 3, & \text{if } G_t = G_{t-1} \end{cases} \dots (1)$$

जहाँ, G_t तिमाही t के लिए जीडीपी या जीवीए में वर्षानुवर्ष संवृद्धि है।
(ख) MS_t को एक चरकांक के रूप में निरूपित करें जो यह दर्शाए कि तिमाही t के लिए रुख सूचकांक सकारात्मक/नकारात्मक/निरपेक्ष रहा है और इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाए

$$MS_t = \begin{cases} 1, & \text{if } SI_t > 0 \\ 2, & \text{if } SI_t < 0 \\ 3, & \text{if } SI_t = 0 \end{cases} \dots (2)$$

(ग) I_t को एक संकेतक क्रिया के रूप में निरूपित करें जो तिमाही t के यह दर्शाए कि क्या जीडीपी/जीवीए संवृद्धि और इस तिमाही के रुख सूचकांक की क्रमिक दिशा मेल खा रही है या नहीं। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाए

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{if } MS_t = IG_t \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \dots (3)$$

उपर्युक्त स्थापना के अंतर्गत, संकेत सफलता अनुपात (SSR) को इस प्रकार परिभाषित किया जाए

$$SSR = \frac{\sum_{j=1}^n I_j}{n} * 100 \dots (4)$$

जहाँ n विचाराधीन तिमाहियों की कुल संख्या है (ति1: 2015-16 से ति3:2019-20 तक)।

रुख सूचकांक का जीडीपी और जीवीए संवृद्धि दोनों से मजबूत अंतर्संबंध पाया गया है और यह दिशात्मक परिवर्तन को आँकने में संतोषजनक रूप से सक्षम है (तालिका III.1.1)। 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए रुख सूचकांक कमजोर आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है।

तालिका III.1.1: रुख सूचकांक और जीडीपी/जीवीए संवृद्धि के बीच सांख्यिकीय संबंध

	जीडीपी संवृद्धि (वर्षानुवर्ष)	जीवीए संवृद्धि (वर्षानुवर्ष)
एसआई से अंतरसंबंध	0.62*	0.71*
एसआई का एसएसआर (%)	58	74

* 5 प्रतिशत के महत्ता स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अपारंपरिक बिग डेटा स्रोत, यथा ऑनलाइन प्रिंट मीडिया में खबरें जो उच्च आवृत्ति आधार पर उपलब्ध हैं, अर्थव्यवस्था की नब्ज के सर्वेक्षण-आधारित आकलनों का समर्थन करते हैं। तथापि मशीन शिक्षण तकनीकों से सामान्यतः समष्टिआर्थिक अंतर्संबंधों को समझना कठिन है और इन्हें आमतौर पर अतिरिक्त निगरानी तकनीकों के रूप में देखा जाता है।

संदर्भ:

बुओनो, डी., कैपेतानिओस, जी., मार्सेलीनो, एम., मज्जी, जी., और पपैलियस, एफ., (2018), "बिग डेटा एकोनोमेट्रिक्स : नाऊ कार्स्टिंग ऐंड अर्ली एस्टिमेट्स", मिलन, बोक्कोनी युनिवर्सिटी, बफफ्रीकरेफिन सेंटर वर्किंग पेपर 82

गोडबोले, एन., श्रीनवसैयाह, एम., और सकीना, एस. (2007), "लार्ज स्केल सेंटिमेंट अनालिसिस फॉर न्यूज ऐंड ब्लॉग्स", कॉन्फरेंस प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फरेंस ऑन वेबब्लॉग्स ऐंड सोशल मीडिया, जनवरी।

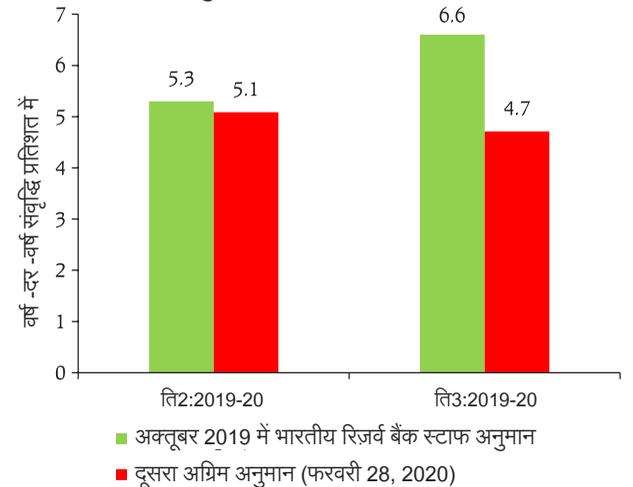
कुमारी, श्वेता और गिड्डी, गीता (2020), "इंफ्लेशन डिकोडेड थ्रू पावर ऑफ वर्ड्स", मीमओ।

शापिरो, एडम हाले, मोरिट्ज़ सुदफ, डेनियल विलसन (2018), "मेजरींग न्यूज सेंटिमेंट", फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सान फ्रान्सिस्को वर्किंग पेपर 2017-01

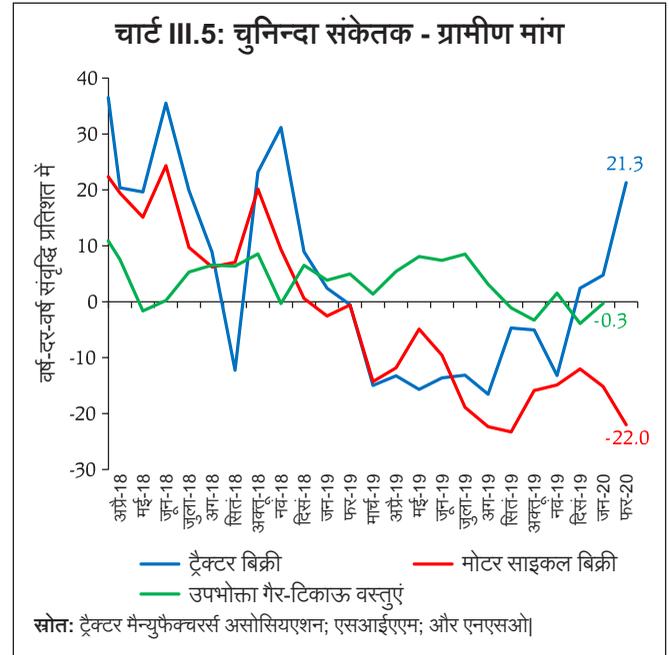
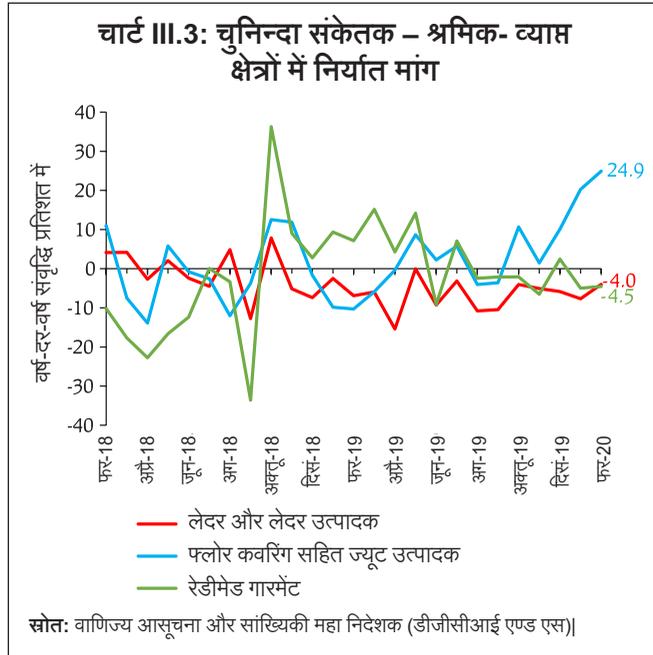
जीडीपी अनुमान के मुकाबले वास्तविक उत्पादन

अक्तूबर 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में जीडीपी संवृद्धि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें इस बेसलाइन पथ के इर्दगिर्द समान रूप से संतुलित जोखिम थे (चार्ट III.2)। एनएसओ के दूसरे अग्रिम पूर्वानुमान (एसआई) के अनुसार वास्तविक उत्पादन दूसरी और तीसरी तिमाही में इन पूर्वानुमानों से क्रमशः 20 और 190 आधार अंक नीचे रहे। दूसरी तिमाही में यह अधोगामी आघात सकल स्थिर पूंजी निर्माण में अपेक्षा से अधिक तीव्र गिरावट और निजी अंतिम उपभोग व्यय में आंशिक कमजोरी के कारण उत्पन्न हुआ। तीसरी तिमाही में, पूर्वानुमान त्रुटियाँ मुख्यतः सकल नियत पूंजी निर्माण में तीक्ष्ण अनपेक्षित संकुचन, जो जीडीपी की नई शृंखला में सबसे गहरा था, के कारण उत्पन्न हुई थीं।

चार्ट III.2: सकल देशी उत्पाद संवृद्धि: अनुमानित बनाम वास्तविक



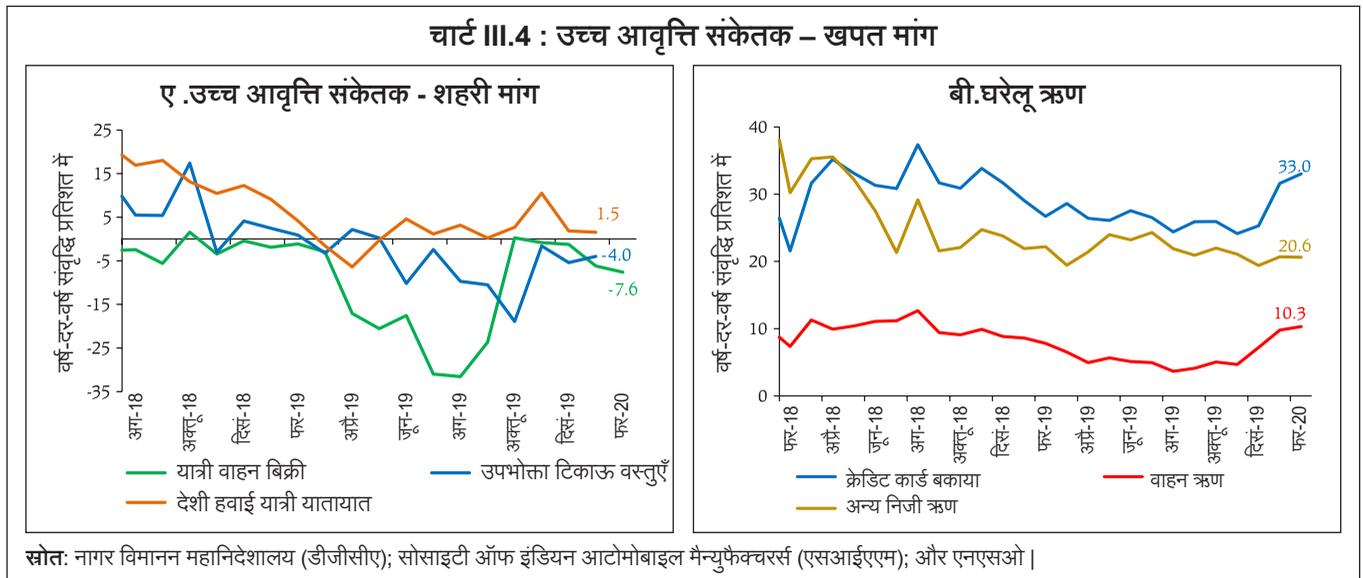
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



III.1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीडी) 2019-20 की दूसरी छमाही में 57.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सकल माँग का मुख्य आधार बना हुआ है। 2019-20 की दूसरी छमाही में पीएफसीडी में मंदी इकट्ठे कई कारकों के कारण आयी- पिछले दो वर्षों में दबी हुई खाद्य कीमतों/मुद्रास्फीति के कारण कमजोर ग्रामीण माँग; ग्रामीण दिहाड़ी में गिरावट; ग्रामीण उपभोग को प्रभावित करते श्रम-सघन निर्यातों में कमी; और गिरती आय के कारण शहरी उपभोग में मंदी (चार्ट III.3)।

शहरी उपभोग माँग के उच्च आवृत्ति संकेतक 2019-20 की चौथी तिमाही की सुस्त तस्वीर पेश करते हैं (चार्ट III.4a)। यात्री वाहनों की बिक्री में फरवरी 2020 में भी संकुचन जारी रहा। घरेलू टिकाऊ वस्तुओं की संवृद्धि जनवरी 2020 में मंद हुई। यद्यपि फरवरी 2020 में घरेलू वाहन ऋण संवृद्धि में थोड़ी तेजी और क्रेडिट कार्ड बकायों में वृद्धि हुई है, समग्र शहरी उपभोग, कोविड-19 के विस्फोट से और अधिक बुरी तरह प्रभावित होकर, चौथी तिमाही में अपनी गति खो चुका प्रतीत होता है (चार्ट III.4b)।



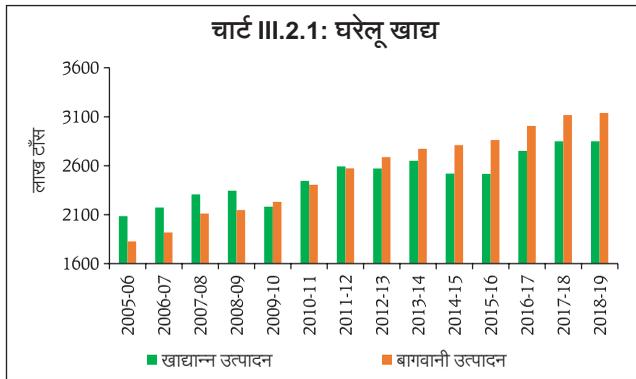
ग्रामीण उपभोग के संकेतकों में, मोटरसाइकल बिक्री में फरवरी 2020 में भी संकुचन रहा (चार्ट III.5)। यह क्षेत्र उत्सर्जन मानदंडों में किए गए उस परिवर्तन के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जो अप्रैल से लागू होने वाला था। हालाँकि

ट्रैक्टर बिक्री जनवरी में बढ़ी और फरवरी 2020 में इसमें और तेजी आयी, जो बेहतर रबी बुआई को दर्शाता है। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में संकुचन जारी रहा, जो कमजोर ग्रामीण माँग का परिचायक है (बॉक्स III.2)।

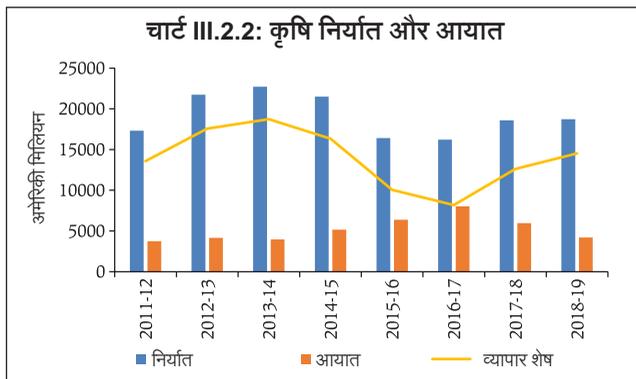
बॉक्स III.2: ग्रामीण मांग की व्याधि क्या है?

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन ग्रामीण माँग की स्थिति की कुंजी है। हाल के वर्षों में व्यापार की शर्तें (टीओटी) कृषि अर्थव्यवस्था से विमुख हुई हैं क्योंकि 2016, 2017 और 2018 के दौरान लगातार हुई बम्पर पैदावार ने कुछ खाद्य कीमतों/मुद्रास्फीति में गिरावट पैदा कर दी थी (चार्ट III.2.1)। वैश्विक खाद्य आपूर्ति की भरमार के सामने, भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात प्रभावित हुए और परिणामस्वरूप, वे अधिशेष आपूर्ति की अपनी सामान्य भूमिका की पूर्ति नहीं कर सके (चार्ट III.2.2)। अतिरिक्त आपूर्ति के फलस्वरूप जमा होते जा रहे स्टॉक ने कृषि पण्यों की कीमतों/मुद्रास्फीति को और कम कर दिया (चार्ट III.2.3)।

अंतर-क्षेत्रीय टीओटी, अर्थात् कृषि जीवीए अवस्फीतिकारक और गैर-कृषि जीवीए अवस्फीतिकारक के अनुपात में 2016-17 और 2018-19 के बीच गिरावट हुई (चार्ट III.2.4)। एक वैकल्पिक पैमाना

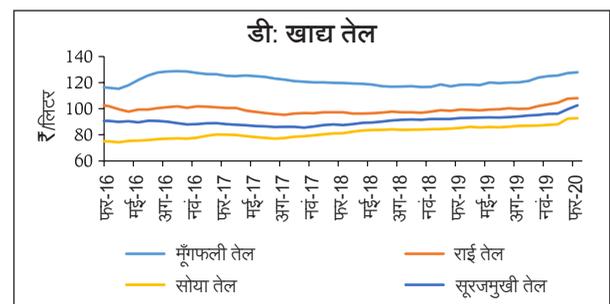
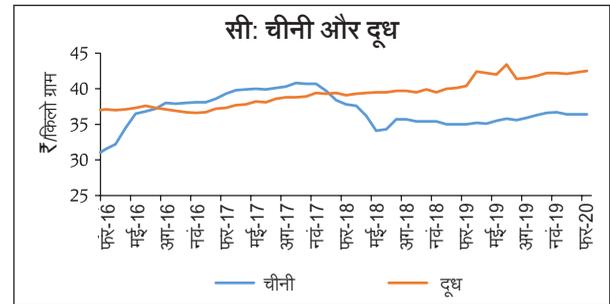
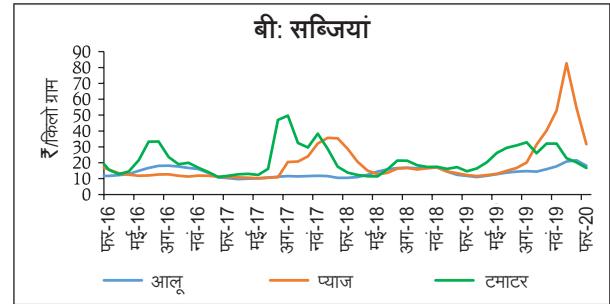
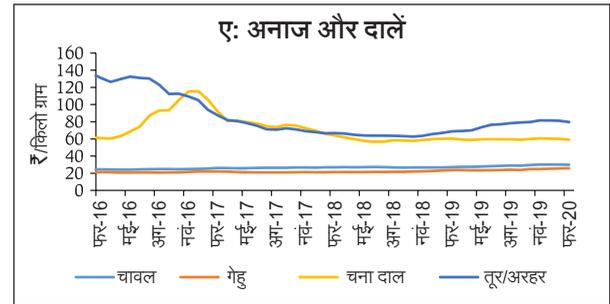


स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएफडब्ल्यू)।



स्रोत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण।

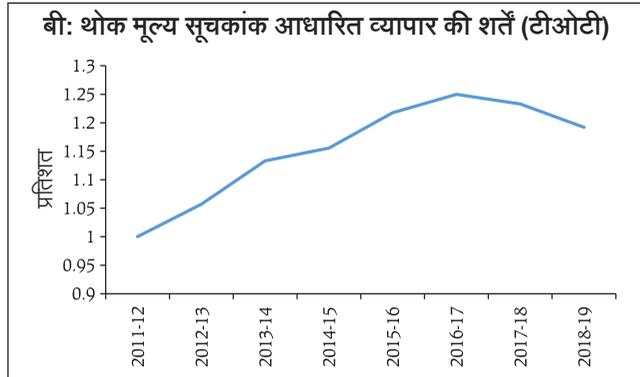
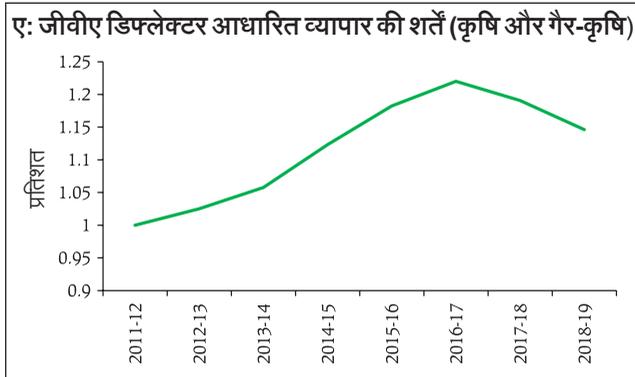
चार्ट III.2.3: प्रमुख आवश्यक कृषि माल के थोक मूल्य



स्रोत: उपभोक्ता मामलों कार्यालय, भारत सरकार।

(जारी)

चार्ट III.2.4: कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार के अंतर-क्षेत्रीय नियम



स्रोत: एनएसओ; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

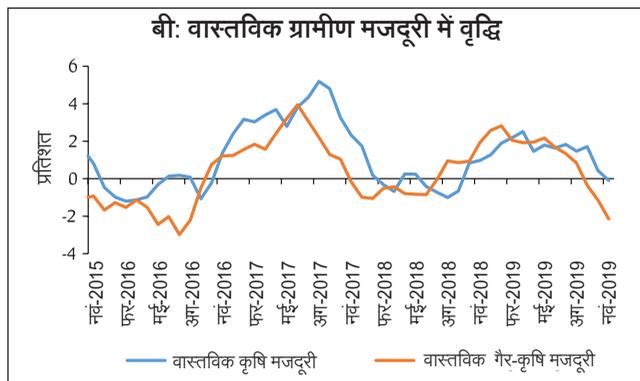
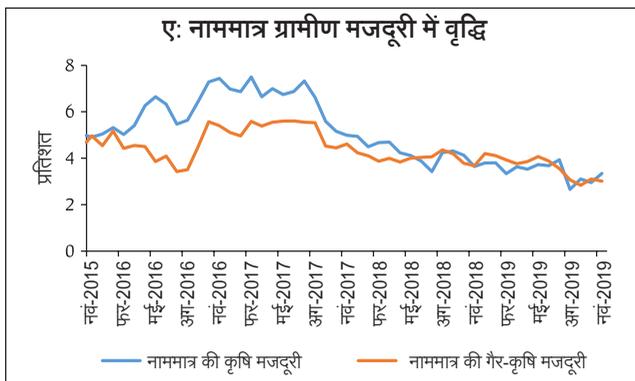
– कृषि और गैर-कृषि (सेवाओं को छोड़कर) के थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) का अनुपात टीओटी की इस हानि की पुष्टि करता है। इन बदलावों के अलावा, निर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण, ग्रामीण दिहाड़ी, खासकर कृषि दिहाड़ी में वृद्धि, मौद्रिक और वास्तविक रूप में सुस्त रही (चार्ट III.2.5)।

इसके अलावा, हाल के वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना से विलंब से दिहाड़ी भुगतान, कम दिहाड़ी और अपर्याप्त बजट आबंटन के कारण ग्रामीण आय को ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। एनएसओ द्वारा मई 2019 में जारी आवधिक दिहाड़ी बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट दर्शाती है कि मनरेगा कार्यों के अंतर्गत दी जाने वाली दिहाड़ी, गैर-सरकारी कार्यों के लिए बाजार की दिहाड़ी दर से ग्रामीण पुरुषों के मामले में 74 प्रतिशत और ग्रामीण महिलाओं के मामले में 21 प्रतिशत कम है।

कोविड-19 की हालिया महामारी और इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण ग्रामीण और शहरी- दोनों इलाकों में सकल माँग के और बुरी तरह गिरने की संभावना है। सरकार ने ग्रामीण माँग पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष नकदी अंतरण, मनरेगा योजना के अंतर्गत दिहाड़ी में बढ़ोतरी और निर्माण मजदूरों की कल्याण निधि के उपयोग जैसे कई उपाय किए हैं। तथापि, महामारी की गंभीरता को देखते हुए, ग्रामीण माँग कम से कम निकट भविष्य में और गिरने की संभावना है।

निष्कर्ष के रूप में, सामान्यतः कमतर कृषि कीमतों, निर्माण क्षेत्र में मंदी और मनरेगा जैसे अग्रणी कार्यक्रम में औसत से भी कमतर प्रदर्शन और तो और, कोविड-19 ने भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि आय में कमी, ग्रामीण दिहाड़ी में गिरावट और रोजगार अवसरों की हानि की है।

चार्ट III.2.5: नाममात्र और वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि



स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय; और भा.रि.बैं. स्टाफ अनुमान।

III.1.2 सकल स्थायी पूंजी निर्माण

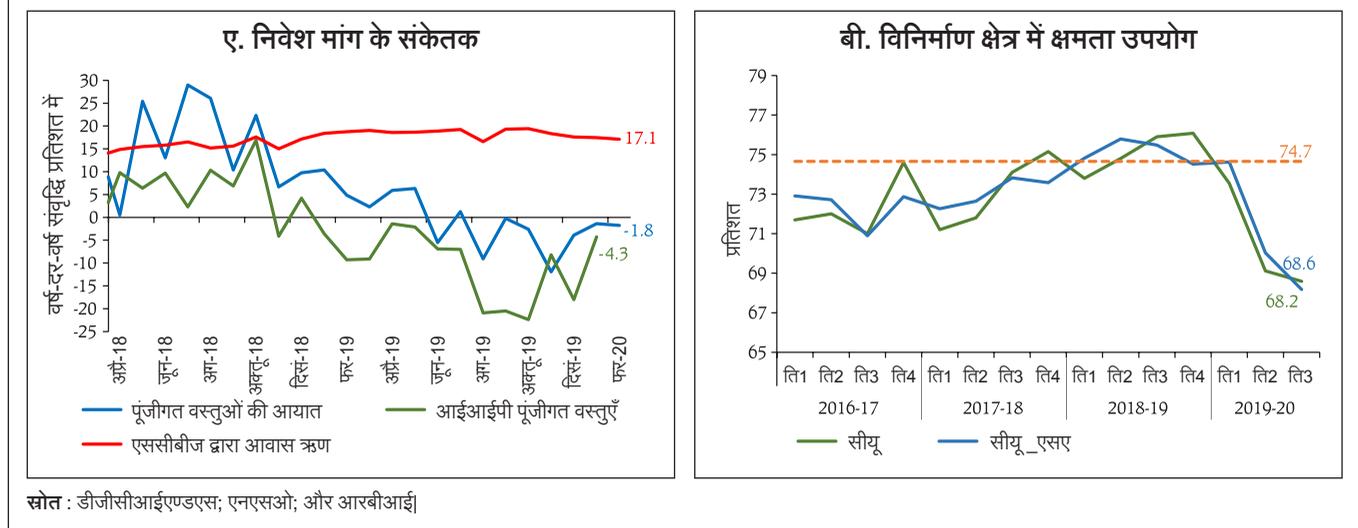
2019-20 की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की संवृद्धि ऋणात्मक हो गई। परिणामस्वरूप, 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जीएफसीएफ का योगदान एक वर्ष पूर्व के 31.9 प्रतिशत से घटकर 30.2 प्रतिशत रह गया। जनवरी/फरवरी 2020 में निवेश मांग के दो प्रमुख सूचकों, नामतः उत्पादन एवं पूंजीगत सामानों के आयात में भी कमी आई (चार्ट III.6ए)। जहां तक निर्माण गतिविधि का संबंध है, फरवरी में परिष्कृत स्टील की खपत में कमी आई, जबकि सीमेंट के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। नवीनतम वित्तीय परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि बौद्धिक संपदा के अंतर्गत उत्पादों में निवेश के प्रतिनिधि के रूप में सॉफ्टवेयर फर्मों का निष्पादन आघात-सह बना रहा। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में, विनिर्माण क्षेत्र का मौसम समायोजित क्षमता अनुप्रयोग (सीयू-एसए) दीर्घावधिक औसत से कम हो गया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि नए निवेश की जरूरत मंद है जिसे समायोजित गैर-खाद्य बैंक ऋण (एएनएफसी) में मंदी में भी देखा जा सकता है (चार्ट III.6बी)।

सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों के अर्द्ध-वार्षिक गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से यह पता चलता है कि मोटर-गाड़ी, सीमेंट, पेट्रोलियम, दूरसंचार एवं निर्माण जैसे सभी प्रमुख उद्योगों के कैपेक्स अनुपात³ में 2018-19 की

दूसरी छमाही की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में बढ़ोतरी हुई है। (चार्ट III.7)। वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के दौरान इन कॉर्पोरेटों द्वारा जुटाई गई निधियों का प्रयोग मुख्य रूप से स्थायी आस्तियों के निर्माण एवं डीलिवरेजिंग (उधारियों में कमी) के लिए किया गया। वित्तपोषण के प्रमुख माध्यमों द्वारा स्वीकृत/संविदाकृत परियोजनाओं की कुल लागत में भी 2019-20 की पहली छमाही में 2018-19 की पहली छमाही की तुलना में बढ़ोतरी हुई।

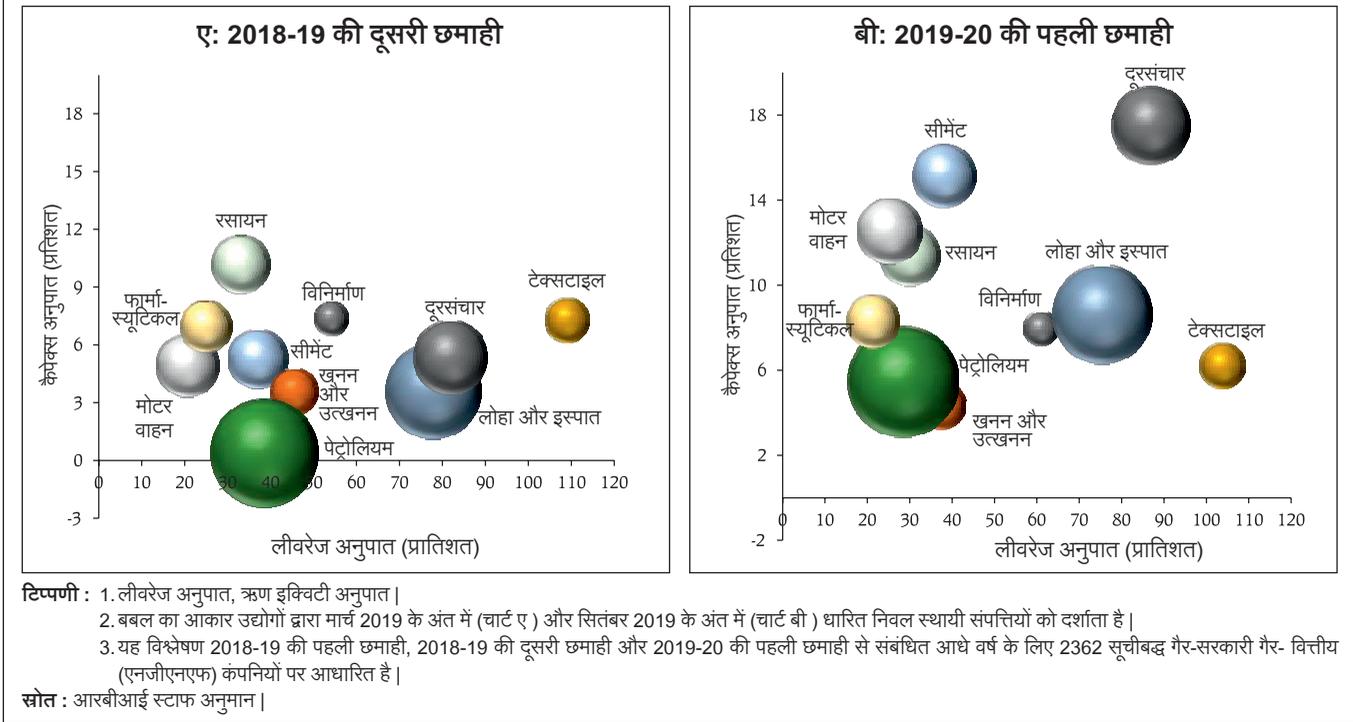
प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू बचत (जीडीएस) दर 2017-18 में जीडीपी के 32.4 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 30.1 प्रतिशत रह गई। अर्थव्यवस्था को निधियों की निवल आपूर्ति करनेवाले हाउसहोल्ड क्षेत्र की बचत दर 2011-12 में जीडीपी के 23.6 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 18.2 प्रतिशत रह गई। जबकि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने निवेश का वित्तपोषण प्रमुखतः अपनी स्वयं की बचत के माध्यम से करता है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का अपने घाटे के वित्तपोषण हेतु हाउसहोल्ड पर अत्यधिक निर्भरता बनी रही (चार्ट III.8)। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में हाउसहोल्ड की देयताओं में कमी उनकी (हाउसहोल्ड) जमा में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक रही जिसके कारण अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान हाउसहोल्ड की वित्तीय बचत में सुधार प्रतीत हुआ, जबकि बीमा और म्यूचुअल फंडों में उनका निवेश पिछले वर्ष के समान स्तर पर बना रहा।

चार्ट III.6: निवेश मांग



³ कैपेक्स अनुपात को [निवल अचल आस्तियों (वर्तमान छमाही) – निवल अचल आस्तियों (पूर्ववर्ती छमाही) + मूल्यहास (वर्तमान छमाही)] / निवल अचल आस्तियों (पूर्ववर्ती छमाही) के रूप में परिभाषित किया गया है।

चार्ट III.7: लीवरेज और निवेश गतिविधि

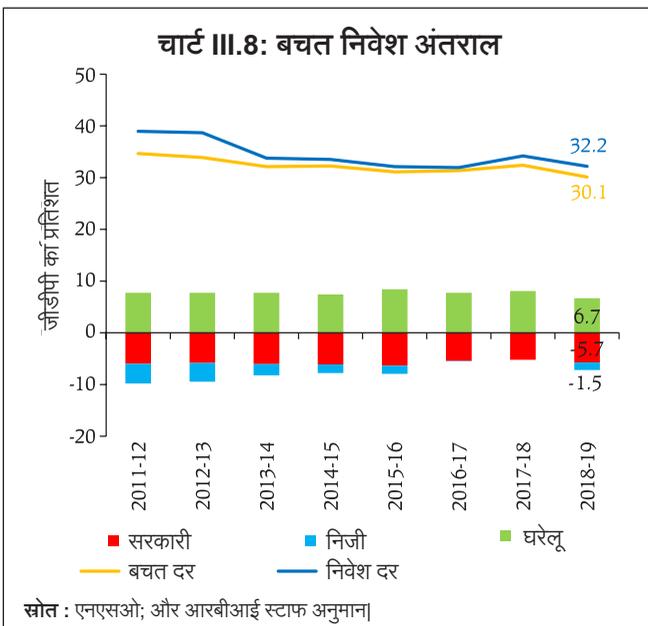


III.1.3 सरकारी व्यय

चौथी तिमाही में तीव्र मंदी के कारण 2019-20 की दूसरी छमाही में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में कमी आई, जो एनएसओ द्वारा जारी एसएई से भी स्पष्ट होता है। जनवरी-फरवरी 2020 के दौरान, केंद्र के राजस्व व्यय में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय के लिए

2019-20 के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में अधिक बजट प्रावधान किया गया है (सारणी III.2)।

2019-20 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति खराब हुई जिसका मुख्य कारण निगम कर के तहत सकल राजस्व में कमी होना रहा जो वर्ष के मध्य में कर दरों में कमी को दर्शाता है। 5.5 लाख करोड़ रूपए का जीएसटी संग्रह संशोधित अनुमान (आरई) का 89.5 प्रतिशत था, जो एक वर्ष पूर्व के संग्रह की तुलना में 4.5 प्रतिशत अधिक था। समग्र रूप से, वर्ष के प्रथम 11 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में 3.3 की कमी आई,

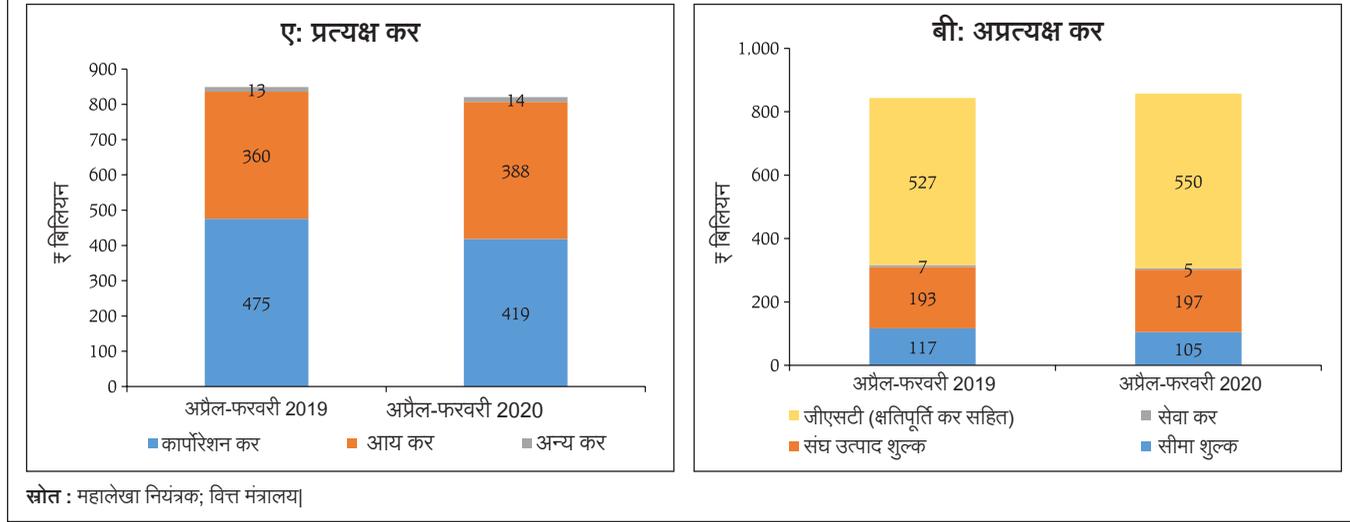


सारणी III.2: मुख्य राजकोषीय संकेतक – केंद्र सरकार वित्त
(जीडीपी का प्रतिशत)

संकेतक	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1. राजस्व प्राप्ति	9.3	9.1	9.0
अ. कर राजस्व (निवल)	7.8	7.4	7.3
ब. गैर-कर राजस्व	1.5	1.7	1.7
2. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्ति	0.6	0.4	1.0
3. राजस्व व्यय	11.6	11.5	11.7
4. पूंजी व्यय	1.6	1.7	1.8
5. कुल व्यय	13.2	13.2	13.5
6. सकल राजकोषीय घाटा	3.3	3.8	3.5
7. राजस्व घाटा	2.3	2.4	2.7
8. प्राथमिक घाटा	0.2	0.7	0.4

बीई : बजट अनुमान; आरई: संशोधित अनुमान |
स्रोत : संघीय बजट 2020-21।

चार्ट III.9: अप्रैल- फरवरी के दौरान कर वसूली



जबकि अप्रत्यक्ष करों में मात्र 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में कम है (चार्ट III.9 ए एवं बी)।

राजस्व व्यय संवृद्धि भी संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में कम रही, जिसका मुख्य कारण अपेक्षाकृत कम ब्याज भुगतान होना रहा। प्रमुख छूट के रूप में दी जाने वाली राशि में कमी आई और यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बजट अनुमान (बीई) से घटकर संशोधित अनुमान (आरई) में 1.1 प्रतिशत रह गई। इस कमी का कारण बजट में दी गई खाद्य छूट में की गई कटौती रही। इसके बावजूद, समग्र रूप से दी जाने वाली छूट में खाद्य छूट की प्रमुखता बनी हुई है। पूंजी व्यय की संवृद्धि भी संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में कम रही।

संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 (3) के प्रावधानों, जिसे विशिष्ट परिस्थितियों⁴ में लागू किया जा सकता है, के अधीन 2019-20 (आरई) में केंद्र के जीएफडी को 3.8 प्रतिशत तक संशोधित किया गया, जिसके लिए बजट में 3.3 प्रतिशत का प्रावधान किया गया था। कर राजस्व और विनिवेश से प्राप्त राशि में कमी होने के कारण यह संशोधन किया गया। इन उभरती परिस्थितियों के प्रभाव की जांच सामान्य साम्य फ्रेमवर्क में की जा सकती है (बॉक्स III.3)। बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2020-21 में जीएफडी कम होकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत रह सकता है और सुधार के साथ यह 2022-23 तक जीडीपी के 3.1 प्रतिशत तक लौट आएगा।

बॉक्स III.3: तिमाही पूर्वानुमान मॉडल (क्यूपीएम) का संवर्धन करना : राजकोषीय खंड

राजकोषीय नीतिगत उपाय उत्पादन, मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीतिगत निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है (भारत सरकार, 2017)। हालांकि, जरूरी नहीं है कि सभी राजकोषीय उपाय समष्टिगत आर्थिक चरों को एक ही प्रकार से प्रभावित करें। राजकोषीय-मौद्रिक इंटरफेस के विभिन्न वाहकों के संवृद्धि तथा मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तिमाही पूर्वानुमान मॉडल (क्यूपीएम)⁵ में राजकोषीय खंड को शामिल किया गया है।

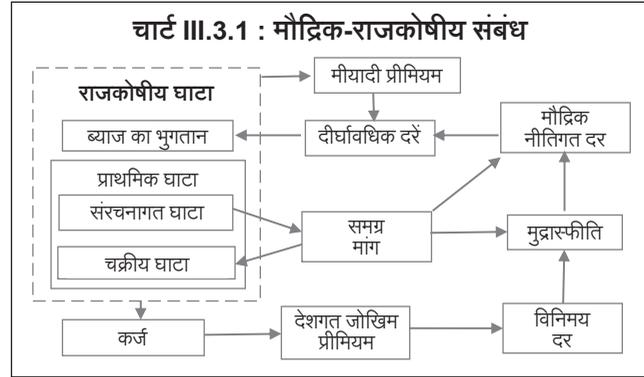
क्यूपीएम में समाहित राजकोषीय खंड की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : (क) मुख्य राजकोषीय घाटे को संरचनागत एवं चक्रीय प्राथमिक घाटों तथा ब्याज भुगतानों में विभक्त किया गया है; (ख) प्राथमिक घाटे का चक्रीय घटक अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है और उसमें यह माना जाता है कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में मंदी होने पर सरकारी कर राजस्व अपेक्षाकृत कम रहेगा तथा व्यय अपेक्षाकृत अधिक होगा जिसके कारण राजकोषीय घाटा अपेक्षाकृत अधिक होगा और इसके विपरीत घटना भी सत्य (जारी)

⁴ राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि के नष्ट होने के कारण कृषि उत्पाद और आय के बुरी तरह से प्रभावित होने, अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभावों सहित अर्थव्यवस्था में संरचनागत सुधार और किसी तिमाही की वास्तविक उत्पादन संवृद्धि में पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत की गिरावट होने पर (स्रोत : वित्त अधिनियम, 2018)।

⁵ क्यूपीएम नई कीनियन परंपरा के अंतर्गत अर्द्ध-संरचनागत, प्रगतिशील, खुली अर्थव्यवस्था, जांचा गया, अंतराल मॉडल है और यह विभिन्न प्रकार की फीड बैक प्रणालियों का आंतरिक रूप से सिलसिलेवार विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

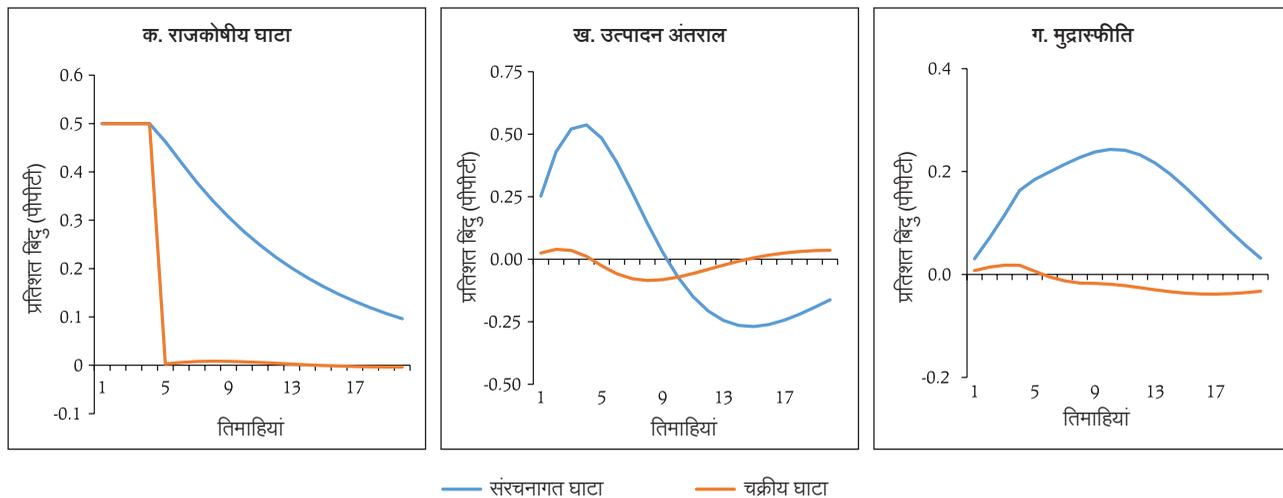
होगी ; (ग) राजकोषीय घाटे में घोषित राजकोषीय पथ से प्राथमिक घाटे के घटक को चक्रानुसार-समायोजित (अर्थात्, संरचनागत – राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जिसका संबंध अर्थव्यवस्था की स्थिति से नहीं होता) किए जाने पर विचलन होने पर राजकोषीय संवेग बढ़ता है, और यह समग्र मांग में योगदान करता है; (घ) स्टॉक-पलो निरंतरता के लिए कर्ज के निर्धारक तत्वों एवं राजकोषीय घाटे के बीच संबंध की पहचान की गई है (इस्कोलेनो, 2010); (ङ) राजकोषीय घाटे और कर्ज का प्रभाव देश के जोखिम प्रीमियम और विनिमय दर पर पड़ता है; और (च) राजकोषीय घाटे के साथ मौद्रिक नीति की परस्पर क्रिया का मापन ब्याज भुगतानों के माध्यम से किया जाता है (चार्ट III.3.1)।

इस मॉडल के निर्धारक यह दर्शाते हैं कि चक्रानुसार-समायोजित (संरचनागत) राजकोषीय घाटे पर पड़ने वाला आघात समग्र मांग को प्रभावित करता है। अपेक्षाकृत अधिक राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए कर्ज के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर होने पर देशगत जोखिम प्रीमियम बढ़ता है और विनिमय दर घटती है। इस प्रकार से, मुद्रास्फीति पर समग्र मांग और विनिमय दर माध्यमों, दोनों का प्रभाव पड़ता है। हालांकि, यदि मुख्य राजकोषीय स्थिति का घोषित पथ से विचलन चक्रीय घटकों के कारण होता है तो मुद्रास्फीति और उत्पाद का प्रभाव हल्का होगा (चार्ट III.3.2)।



2019-20 में, जीडीपी की वृद्धि मंद हुई है, जिसके कारण राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हुई, जिसके मुख्य कारण हैं – (क) अपेक्षाकृत कम समग्र मांग (हर), (ख) अपेक्षाकृत कम आर्थिक गतिविधि के कारण अपेक्षाकृत कम राजकोषीय राजस्व, और (ग) आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के कारण अपेक्षाकृत अधिक राजकोषीय व्यय। इस प्रकार, 2019-20 में हुए राजकोषीय घाटे में विचलन के महत्वपूर्ण हिस्से का कारण चक्रीय कारकों को माना जा सकता है। इस परिदृश्य में, इस विचलन का स्फीतिकारी प्रभाव व्यापक रूप से हल्का रहा।

चार्ट III.3.2: संरचनागत एवं चक्रीय राजकोषीय घाटा : उत्पादन एवं मुद्रास्फीति पर प्रभाव



स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ :

एस्कोलानो, एम.जे. (2010), “ए प्रैक्टिकल गाइड टू पब्लिक डेब्ट डायनैमिक्स, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, एवं साइक्लिकल एडजस्टमेंट ऑफ बजटरी एग्ग्रेस””, तकनीकी नोट्स एवं मैनुअल 10/02, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

भारत सरकार (2017), “फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी ” (अध्यक्ष : एन.के. सिंह)।

सारणी III.3: राज्य सरकार वित्त – प्रमुख घाटा संकेतक*

(जीएसडीपी के लिए प्रतिशत)

मद	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
राजस्व घाटा	0.1	0.1	0.7	0.0
सकल राजकोषीय घाटा	2.4	2.5	2.9	2.4

टिप्पणी : 1. ऋणात्मक (-) चिह्न अधिशेष को दर्शाता है।
2. डाटा 28 राज्यों में से 22 राज्यों से संबंधित हैं।
3. जीएसडीपी संबंधित 22 राज्यों के जीएसडीपी का योग है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर, 2019-20 (आरई) में 22 राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर उनके सकल राज्यीय घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.9 प्रतिशत हो गया, जिसके 2.5 प्रतिशत रहने का प्रावधान किया गया था (सारणी III.3)। यह अंतर आर्थिक गतिविधि में मंदी, मुख्यतः स्वयं और केंद्रीय अंतरण दोनों के राजस्व के अपेक्षाकृत कम रहने के कारण हुआ। इस कमी की प्रतिक्रिया में राज्यों को प्रतिकूल फीडबैक लूप के रूप में राजस्व और पूंजीगत व्यय, दोनों में कमी करना पड़ी, जिसके कारण समग्र मांग में और कमी आई। एक वर्ष पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक राजस्व और अपेक्षाकृत कम व्यय के अनुमान के साथ राज्यों ने वर्ष 2020-21 के लिए जीएसडीपी के 2.4 प्रतिशत समेकित जीएफडी का प्रावधान किया है।

2019-20 के दौरान, केंद्र के बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम, जिसका प्रबंधन रिजर्व बैंक करता है, के तहत सकल उधारियां 2018-19 की दूसरी छमाही के रु 2,83,000 करोड़ की तुलना में 2019-20 की दूसरी छमाही में रु 2,68,000 करोड़ रहीं, अर्थात् ये एक वर्ष पूर्व के स्तर से 5.3 प्रतिशत कम रहीं। वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान रु1,33,000 करोड़ की निवल बाजार उधारियां भी 43.2 प्रतिशत कम रहीं। सक्रिय कर्ज समेकन के हिस्से के रूप में, 2019-20 की दूसरी

छमाही के दौरान स्विफ्ट परिचालनों की शृंखला के तहत सात परिचालन किए गए, जिनका मूल्य रु1,24,694 करोड़ था, जिनका उद्देश्य विमोचनों का प्रबंधन करना और सरकारी प्रतिभूतियों की तरलता में वृद्धि करना था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष के ऋणात्मक होने के कारण बार-बार अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का सहारा लेना पड़ा जिसे नियंत्रित करने के लिए 2019-20 की दूसरी छमाही में नकदी प्रबंधन बिलों को सात बार जारी किया गया, जिनका मूल्य रु 2,50,000 करोड़ था। राज्यों ने वर्ष के दौरान कुल रु 6,34,521 करोड़ का उधार लिया (सारणी III.4)।

III.1.4 बाह्य मांग

2019-20 की दूसरी छमाही में समग्र मांग में निवल निर्यात का योगदान धनात्मक रहा, जिसके अंतर्गत निर्यात की तुलना में आयात संकुचन अधिक तेजी से हुआ (चार्ट 10)।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पण्य वस्तुओं के निर्यात में संकुचन, जो 2019-20 की पहली तिमाही में प्रारंभ हुआ, दूसरी तिमाही में और अधिक बढ़ा क्योंकि वैश्विक व्यापार और मांग में कमी लंबी अवधि तक बने रहने से अभियांत्रिकीय सामानों, रत्नों एवं आभूषणों, सूती और हथकरघा उत्पादों, तथा चावल के लदान में स्पष्ट रूप से गिरावट देखी गई। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान समग्र व्यापार संकुचन की गति धीमी हुई, और फरवरी में इसमें बदलाव आया जिसे पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट्स (पीओएल), अभियांत्रिकीय सामानों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों तथा रसायनों से सहारा मिला (चार्ट III.11ए)। समग्र रूप से, अप्रैल-फरवरी 2019-20 के दौरान निर्यात का 1.5 प्रतिशत संकुचन हुआ, यद्यपि वैश्विक आपूर्ति शृंखला और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव मार्च में निर्यात के निष्पादन को अधिक व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

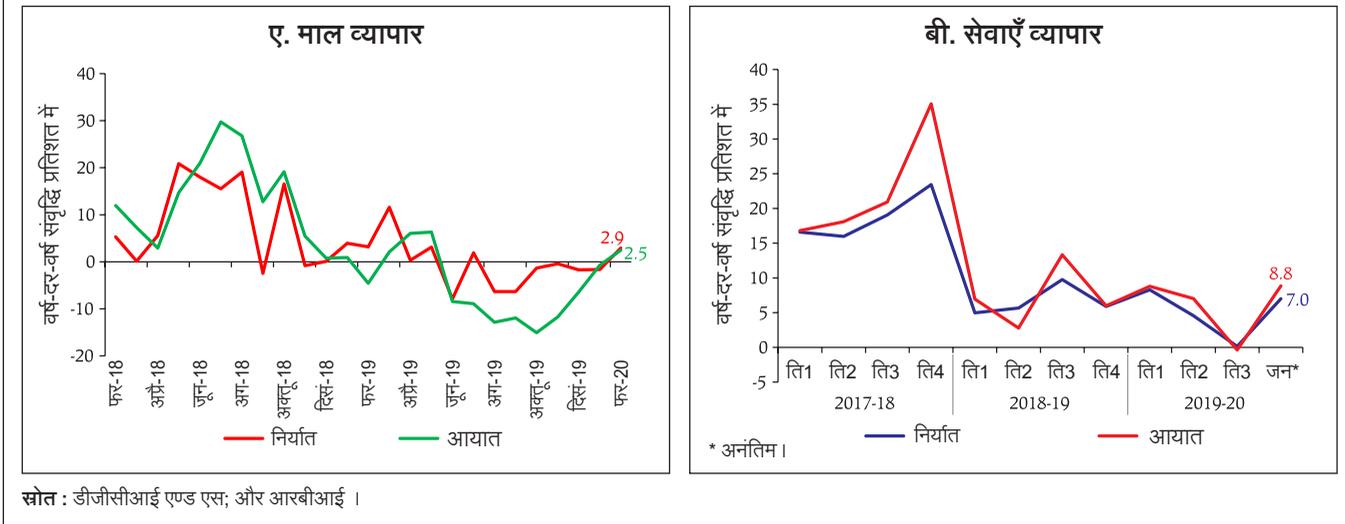
सारणी III.4: सरकारी बाजार उधार

(रु करोड़)

मद	2017-18			2018-19			2019-20		
	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
निवल उधार	4.48.410	3.40.281	7.88.691	4.22.737	3.48.643	7.71.380	4.73.972	4.87.454	9.61.426
सकल उधार	5.88.000	4.19.100	10.07.100	5.71.000	4.78.323	10.49.323	7.10.000	6.34.521	13.44.521

स्रोत : भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.10: व्यापार में संवृद्धि

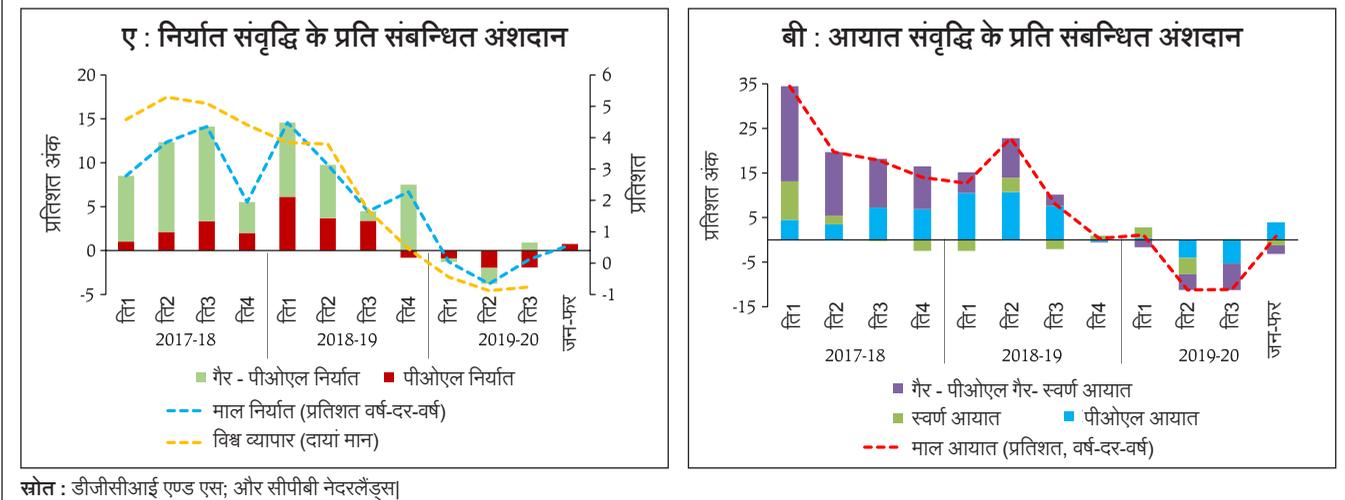


2019-20 की दूसरी तिमाही में निर्यात संकुचन हुआ, जिस पर स्वर्ण, पीओएल तथा गैर-पीओएल आयात का प्रतिकूल असर पड़ा (चार्ट III.11बी)। बाद वाले, अर्थात गैर-पीओएल आयात के अंतर्गत कमी का आधार बहुत व्यापक रहा तथा यातायात के उपकरण, मोती एवं कीमती पत्थर, कोल एवं रसायन जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत रहे। तीसरी तिमाही और जनवरी 2020 में भी आयात संकुचन हुआ, किंतु फरवरी में इसमें विस्तार हुआ, जिसकी अगुआई पीओएल, मोतियों तथा कीमती पत्थरों और मशीनरी ने की। अप्रैल-फरवरी 2019-20 के दौरान समग्र रूप से आयात में 7.3 प्रतिशत संकुचन हुआ। आयातों में निर्यातों की तुलना में अधिक कमी होने के कारण व्यापार घाटे में कमी आई

और यह अप्रैल-फरवरी 2018-19 के 173.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से स्तर से घटकर अप्रैल-फरवरी 2019-20 में 143.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी से गिरावट होने के साथ भारत के तेल आयात में मार्च में कमी आने की संभावना है और इसके कारण व्यापार घाटा आगे पूरे वर्ष के लिए घट सकता है।

चालू खाता घाटा (सीएडी) 2019-20 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत और एक वर्ष पूर्व की तीसरी तिमाही में रहे 2.7 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2019-20 की तीसरी तिमाही में 0.2 प्रतिशत रह गया। सीएडी में कमी प्राथमिक रूप से व्यापार घाटे के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रहने और निवल सेवाओं की

चार्ट III.11: निर्यात व आयात संवृद्धि के प्रति संबन्धित अंशदान



प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण हुई। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि सॉफ्टवेयर, यात्रा और वित्तीय सेवाओं से निवल कमाई में वृद्धि होने बाद हुई (चार्ट 10.बी)। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विप्रेषण में मजबूती रही, जबकि निवेश आय और कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति को मिलाकर होने वाले भुगतानों के बहिर्गमन पिछले वर्ष से व्यापक रूप से अपरिवर्तित रहे।

2019-20 की तीसरी तिमाही में निवल पूंजी प्रवाह सीएडी से अधिक हो गए। अप्रैल-जनवरी 2019-20 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर एक वर्ष पूर्व के स्तर से ऊपर रहा। एफडीआई में होने वाला प्रवाह मुख्य रूप से विनिर्माण, संचार, खुदरा एवं थोक व्यापार, वित्तीय एवं कंप्यूटर संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में हुआ। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वैश्विक मंदी के भय के चलते बढ़ती जोखिम विमुखता के बीच, 18 फरवरी 2020 से विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) निवल विक्रेता बन गए। सउदी अरब एवं रूस के बीच तेल मूल्य को लेकर मचे घमासान के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में नई उथलपुथल मच जाने से 6 मार्च 2020 से विदेशी संविभाग निवेश (एफपीआई) का बहिर्वाह अधिक तेज हो गया। समग्र रूप से, 2019-20 में (31 मार्च 2020 तक) एफपीआई का बहिर्वाह 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तुल्य था। हालांकि, स्वैच्छिक धारिता माध्यम से, 31 मार्च 2020 तक एफपीआई द्वारा होने वाला निवल निवेश 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के तहत भारतीय

संस्थानों द्वारा की गई निवल निकासी 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो एक वर्ष पूर्व हुई 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निकासी से अधिक थी। अंतरराष्ट्रीय निवल निवेश स्थिति (आईपीपी), अर्थात् देश की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का अंतराल, में 2019-20 की तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही की तुलना में सुधार हुआ। 27 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 475.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था, जो 11.8 महीनों के आयात के तुल्य था। इस कोष में मार्च 2019 के अंत में रहे स्तर में 62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई।

III.2 समग्र आपूर्ति

समग्र आपूर्ति की मात्रा में आधार मूल्य पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) की वृद्धि में गिरावट आई और यह 2018-19 की पहली छमाही के 5.1 प्रतिशत और दूसरी छमाही के 5.6 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2019-20 की दूसरी छमाही में 4.7 प्रतिशत रह गई (सारणी III.5)। आधार प्रभाव को इस गिरावट के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है क्योंकि तिमाही-दर-तिमाही एसएएआर के रूप में मापी गई इसकी गति में तेजी आई और यह पहली छमाही के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में 5.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.12ए)। चौथी तिमाही के अंतिम चरण में जीएवी पर कोविड-19 का जोरदार असर पड़ने के कारण वर्ष की समाप्ति होने तक इस गति के बने रहने की संभावना नहीं है।

जीवीए की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में मंदी से औद्योगिक और सेवा संबंधी गतिविधियों में कमी का पता चला। दूसरी तरफ, कृषि और

सारणी III.5: जीवीए में क्षेत्र वार संवृद्धि

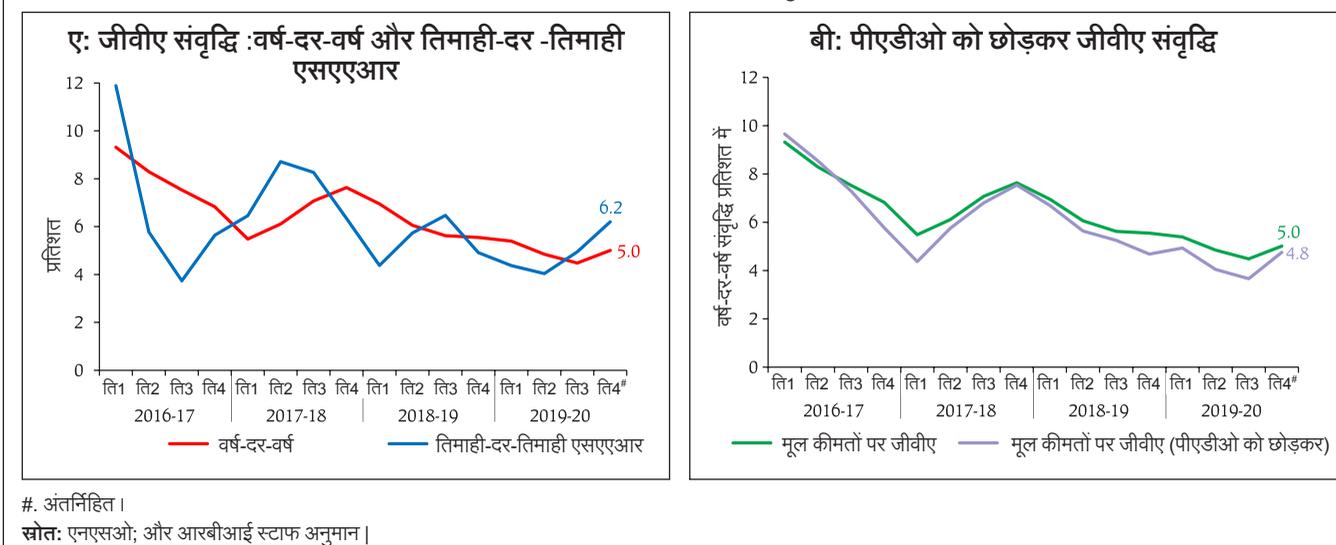
(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

क्षेत्र	2018-19 (एफआरई)	2019-20 (एसएई)	भारत योगदान 2019-20	2018-19 (एफआरई)				2019-20 (एसएई)			
				ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
कृषि, फोरेस्टरी और फिशिंग	2.4	3.7	0.5	3.8	2.5	2.0	1.6	2.8	3.1	3.5	5.0
उद्योग	4.5	1.5	0.3	7.8	4.7	4.4	1.4	3.2	0.1	0.1	2.3
खनन तथा उत्खनन	-5.8	2.8	0.1	-7.3	-7.0	-4.4	-4.8	4.7	0.2	3.2	2.6
विनिर्माण	5.7	0.9	0.2	10.7	5.6	5.2	2.1	2.2	-0.4	-0.2	1.8
विद्युत, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोग्यता	8.2	4.6	0.1	7.9	9.9	9.5	5.5	8.8	3.9	-0.7	6.5
सेवाएँ	7.5	6.5	4.1	7.3	7.2	7.3	8.3	6.7	6.8	6.4	6.1
निर्माण	6.1	3.0	0.2	6.4	5.2	6.6	6.0	5.5	2.9	0.3	3.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	7.7	5.6	1.1	8.5	7.8	7.8	6.9	5.7	5.8	5.9	5.1
वित्त, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ	6.8	7.3	1.6	6.0	6.5	6.5	8.7	6.9	7.1	7.3	8.0
लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ	9.4	8.8	1.1	8.8	8.9	8.1	11.6	8.7	10.1	9.7	6.7
मूल कीमतों पर जीवीए	6.0	4.9	4.9	6.9	6.1	5.6	5.6	5.4	4.8	4.5	5.0

एफआरई : पहला संशोधित अनुमान ; एसएई: दूसरा अग्रिम अनुमान ; # अंतर्निहित संवृद्धि

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ)

चार्ट III.12 : जीवीए संवृद्धि



संबद्ध गतिविधियों में हुई जीवीए वृद्धि में 2019-20 की दूसरी छमाही में 2019-20 की पहली छमाही और 2018-19 की दूसरी छमाही –दोनों की तुलना में मंदी देखी गई, जिसमें दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी बारिश के विलंब से आने और उत्तर-पूर्वी मानसून से प्रचुर मात्रा में बारिश होने के कारण तेजी आई। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के आधार पर, 2019-20 में उड़द और मूंग को छोड़कर सभी प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन विगत वर्ष के अंतिम अनुमानों की तुलना में अधिक था। समग्र आपूर्ति संबंधी परिस्थितियों को लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं (पीएडीओ) से मिलने वाला सहारा जारी रहा (चार्ट 12बी)।

III.2.1 कृषि

कृषि और अनुषंगी गतिविधियों में बुनियादी मूल्यों पर जीवीए वृद्धि 2019-20 की पहली छमाही में रही 3.0 प्रतिशत के मुकाबले 2019-20 की दूसरी छमाही में 4.2 प्रतिशत हो गई। अच्छे पूर्वोत्तर मानसून, पर्याप्त जलाशय स्तर, मिट्टी की नमी में सुधार और कृषि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की अनुकूलता के चलते रबी फसलों के रकबे में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019-20 के लिए फसल उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों में खरीफ और रबी खाद्यान्न के उत्पादन में क्रमशः 0.6 और 4.1 प्रतिशत की वृद्धि का होना आंका गया (तालिका III.6)। 2019-20 में बागबानी उत्पादन 3,133.5 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो 2018-19 के लिए किए गए अंतिम

सारणी III.6: 2019-20 में कृषि उत्पादन (दूसरा अग्रिम अनुमान)

(मिलियन टन्स में)

फसल	2018-19		2019-20		2019-20 परिवर्तन (प्रतिशत)		
	दूसरा ईई	अंतिम	लक्ष्य	दूसरा ईई	दूसरा ईई से ऊपर 2018-19	अंतिम से ऊपर 2018-19	लक्ष्य से ऊपर
खाद्यान्न	2814	2852	2911	2920	3.8	2.4	0.3
चावल	1156	1165	1160	1175	1.6	0.8	1.3
गेहूँ	991	1036	1005	1062	7.2	2.5	5.7
दालें	240	221	263	230	-4.2	4.3	-12.5
तेल के बीज	315	315	361	342	8.5	8.5	-5.3
गन्ना	3808	4054	3855	3538	-7.1	-12.7	-8.2
कपास#	301	280	358	349	16	24.4	-2.4
जूट और मेस्ता##	101	98	112	98	-2.6	-0.1	-12.4

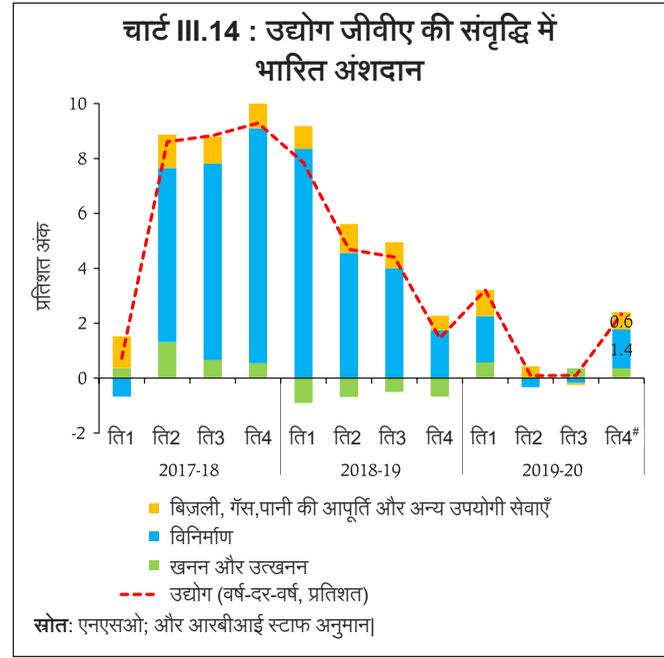
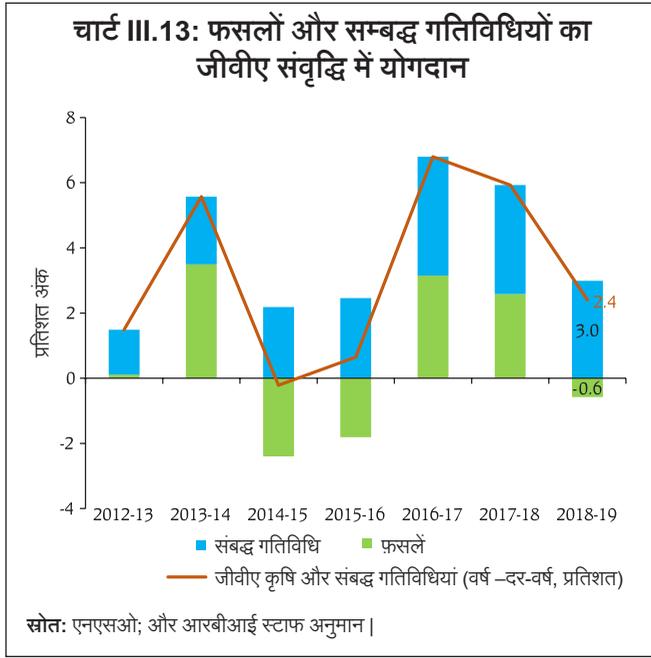
: प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठ।

##: प्रत्येक 180 किलोग्राम की मिलियन गांठ।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अनुमान से 0.8 प्रतिशत अधिक था और सामान्यतया सब्जियों के उत्पादन के कारण था।

अनुषंगी गतिविधियां जिसमें सम्मिलित हैं-पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ना-की कृषि और अनुषंगी क्षेत्र में हिस्सेदारी जीवीए का लगभग 40 प्रतिशत रही और 2012-19 (चार्ट III.13) के दौरान समग्र कृषि जीवीए वृद्धि में इसका योगदान चार बटे पांच था।



यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओए) के अनुसार, मार्च 2020 के दौरान भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह तापमान (एसएसटी) औसत से ऊपर के आस-पास था। वसंत ऋतु में ईएनएसओ⁶ के तटस्थ रहने की संभावना 65 प्रतिशत और 2020 की गर्मियों में 55 प्रतिशत है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो (बीओएम) ने संकेत दिया है कि ईएनएसओ आउटलुक तटस्थ है, जिसका अभिप्राय हुआ कि आने वाले महीनों में अल नीनो या ला नीना के विस्तार की संभावना क्षीण है या उसकी कोई संभावना नहीं है। स्काईमेट ने उम्मीद जाहिर की है कि मानसून के महीनों में 50 प्रतिशत से अधिक संभावना स्थितियों के सामान्य बने रहने की है। भारत के मौसम विभाग को भी उम्मीद है कि अप्रैल-जून 2020 के दौरान ईएनएसओ-तटस्थ स्थितियाँ रहेंगी।

III.2.2 औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र में मूल कीमतों में जीवीए वृद्धि 2019-20 की पहली तिमाही के 1.7 प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में 1.3

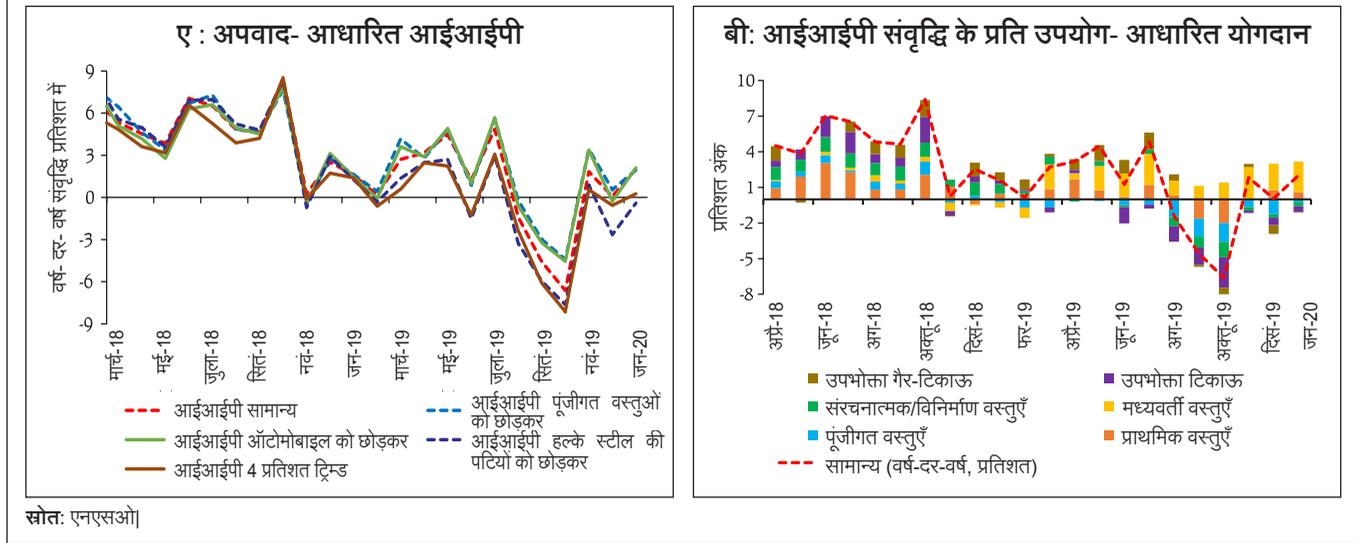
⁶ "ईएनएसओ" अल नीनो-दक्षिणी दोलन को संदर्भित करता है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत में वायुमंडल और महासागर के बीच परस्पर क्रियाओं के चलते सामान्य और सामान्य से ऊपर समुद्र की सतह के तापमान और कुछ वर्ष शुष्क और गीली स्थितियों के बीच कुछ हद तक भिन्नता होती है।"

प्रतिशत, और एक वर्ष पहले 2.8 प्रतिशत थी (चार्ट III.14)। विनिर्माण क्षेत्र, जो उद्योग का प्रमुखतम घटक है, में आई कमी ने मंदी को और भी विकराल बना दिया जिसके लिए घरेलू और कमजोर बाहरी मांग जिम्मेदार थे। खनन क्षेत्र में वृद्धि हुई, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी आई।

नवम्बर 2019 में संकुचन के चलते उच्च आवृत्ति संकेतकों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा और बाद के दो महीनों तक सकारात्मक क्षेत्र में रहा। जनवरी 2020 में ट्रैकेटेड आईआईपी, आईआईपी का 96 प्रतिशत रखकर अर्थात अति घट-बढ़ वाली मंदों के शीर्ष 2 प्रतिशत और तलहटी के 2 प्रतिशत को छोड़कर, में मामूली सुधार हुआ (चार्ट III.15ए)।

2019-20 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण आईआईपी में संकुचन हुआ जो मोटर वाहनों, मशीनरी और उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों, गढ़े हुए धातु उत्पादों, रबर और प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के कारण था। आईआईपी के गठन वाले 23 उद्योग समूहों में से तीसरी तिमाही में 17 में संकुचन हुआ, जबकि दूसरी तिमाही के दौरान 15 में संकुचन हुआ। उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में 2019-20 की तीसरी तिमाही में माध्यमिक वस्तु क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि हुई, जो हल्के

चाट III.15: आईआईपी और उपयोग- आधारित वर्गीकरण

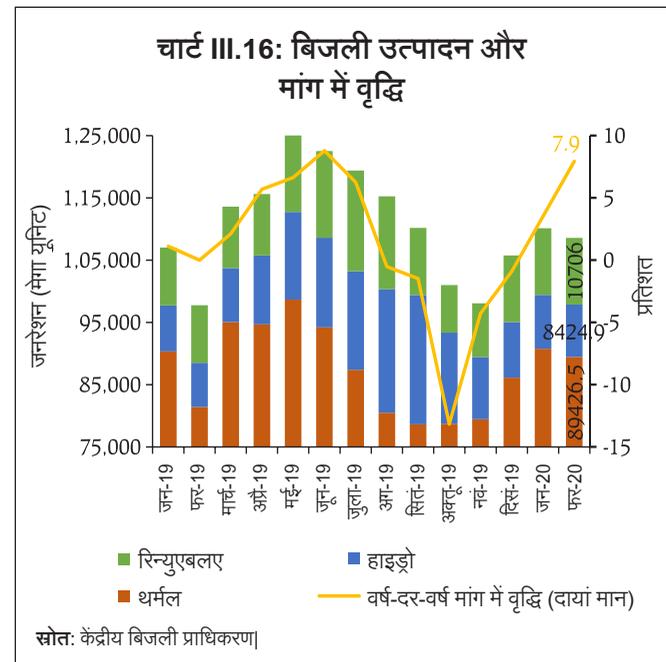


स्टील (एमएस) स्लैब में वृद्धि के कारण थी। दूसरी ओर, उपभोक्तायोग्य गैर-टिकाऊ वस्तुओं में संकुचन हुआ (चाट III.15 बी)। तीसरी तिमाही में प्राथमिक सामान, बुनियादी ढांचा और उपभोक्तायोग्य टिकाऊ वस्तुओं में संकुचन बना रहा। दो पहिया वाहन, टीवी सेट और ऑटो घटकों के उत्पादन में गिरावट के कारण 2019-20 की तीसरी तिमाही में उपभोक्ता टिकाऊ सेगमेंट में संकुचन हुआ। विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों और बिजली उत्पादन से संबंधित निवेश की कमजोर मांग के कारण तीसरी तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में भी संकुचन की स्थिति बनी रही।

जनवरी 2020 में, जबकि आईआईपी की वृद्धि 2.0 प्रतिशत होकर सकारात्मक थी बल्कि काफी व्यापक थी। तथापि, आनेवाले दिनों में इसकी निरंतरता कोविड-19 और कमजोर ऑटोमोबाइल बिक्री के कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने के मद्देनजर अनिश्चित प्रतीत होती है। माध्यमिक माल में दमदार वृद्धि दर्ज होना जारी रहा जो आमतौर पर हल्के स्टील स्लैब से प्रोड्यूस थी और जिसने जनवरी माह में हेडलाइन वृद्धि में 197 आधार अंकों का योगदान किया। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगातार तेरहवें महीने में क्रमिक गिरावट के साथ संकुचन जारी रहा।

पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में बिजली उत्पादन में गिरावट आई जो विस्तारित मानसून के मौसम में संगठित

विनिर्माण क्षेत्र में कम मांग को प्रतिबिंबित करता है। इस कमतर निष्पादन की वजह थी ताप विद्युत उत्पादन जो ऊर्जा आपूर्ति स्रोत का दो-तिहाई है। छह महीने के संकुचन के बाद दिसंबर-जनवरी 2020 में बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई (चाट III.16)। खनन क्षेत्र में, उत्पादन दूसरी छमाही में मामूली रूप से बढ़ा लेकिन कमजोर बना रहा। सरकार द्वारा हाल की घोषणाएँ जैसे



कोयला खनन में एन्ड यूजर प्रतिबंधों को खत्म करना, खनन पट्टों के लिए मंजूरी की वैधता का विस्तार करना और इस क्षेत्र को नए प्रतिभागियों के लिए खोलना क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देनेवाला है।

रिजर्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (IOS)⁷ के कारोबार मूल्यांकन में 2019-20 की चौथी तिमाही में सुधार दिखा जो रोजगार की स्थिति से जुड़ी भावनाओं में मामूली सुधार से था। कोविड-19 के तीव्र प्रसार के मद्देनजर, उद्यमों की अद्यतन भावनाओं को जानने के लिए चयनित मापदंडों के साथ एक त्वरित सर्वेक्षण 18-20 मार्च के दौरान विशेष रूप से करवाया गया। प्राप्त सीमित प्रत्युत्तरों से 2019-20 की चौथी तिमाही में प्रमुख मांग संकेतकों के काफी बिगड़ने का संकेत मिलता है और अगली तिमाही के लिए दृष्टिकोण में निराशावादिता साफ दिखाई दी। विनिर्माण पीएमआई फरवरी में रहे 54.5 से खिसककर मार्च में 51.8 हो गया जिसकी प्रमुख वजहें थीं नए कारोबार आर्डर (निर्यात) में आई बड़ी गिरावट ; सेक्टर में आपूर्ति पक्ष पर कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव जिसके चलते आपूर्तिकर्ताओं को पांच महीने में पहली बार आपूर्ति देने में लंबा समय लग रहा था। पीएमआई सेवा क्षेत्र का गमन संकुचन क्षेत्र में हो गया अर्थात फरवरी में सात साल के उच्च स्तर 57.5 पर रहने के बाद मार्च में

49.3 पर आ गया, जिसकी वजहें थी: नए निर्यात कारोबार में गिरावट और कारोबार की धूमिल संभावनाएं।

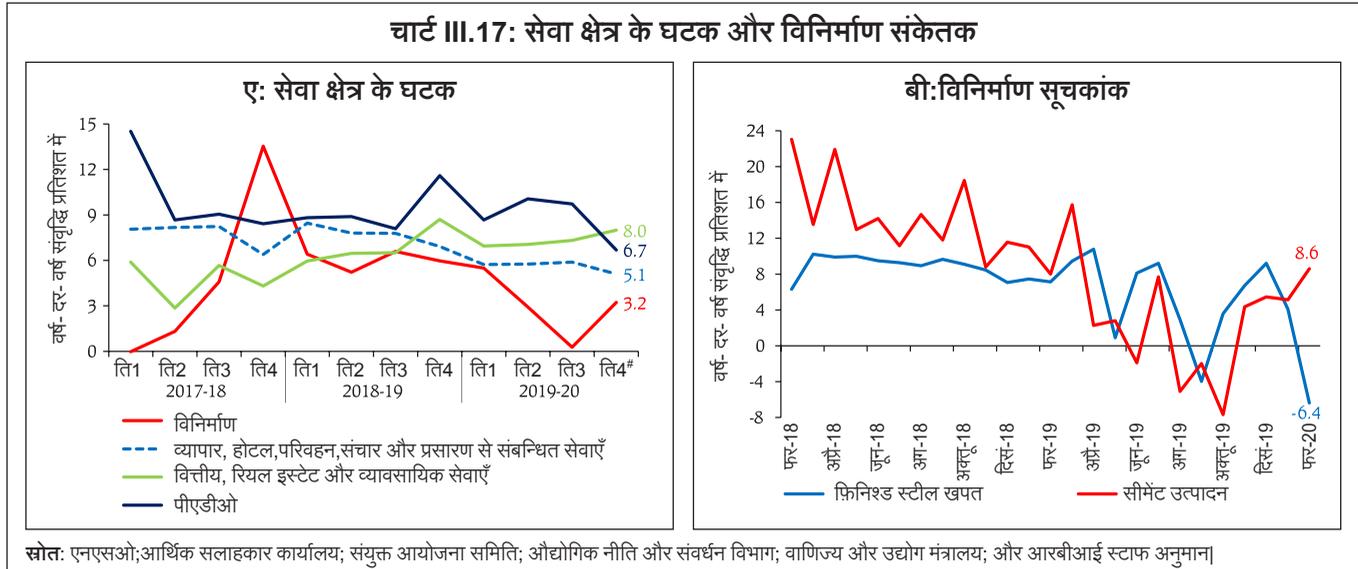
III.2.3 सेवाएँ

निर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार तथा रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) में गिरावट के कारण सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में 2019-20 की दूसरी तिमाही में कमी पाई गई (चार्ट III.17ए)। निर्माण क्षेत्र में आई मंदी का प्रतिबिंब इसके प्रमुख संकेतकों में से एक अर्थात, सीमेंट उत्पादन में गिरावट में लक्षित होता है (चार्ट III.17 बी)।

व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में वृद्धि स्थिर रही। वाणिज्यिक वाहन बिक्री, जो सड़क परिवहन के लिए एक प्रमुख संकेतक है, में जुलाई 2018 में एक्सल मानदंडों⁸ को बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप 2019-20 की दूसरी तिमाही में संकुचन जारी रहा (चार्ट III.18ए)। परिवहन सेगमेंट के अन्य घटक जैसे रेल, जल और वायुमार्ग द्वारा माल ढुलाई में दिसंबर-फरवरी 2019-20 में मामूली सुधार हुआ (चार्ट III.18.बी)।

वित्त, वास्तविक संपदा और व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि 2019-20 की दूसरी तिमाही में उत्तरोत्तर बढ़ी, जो व्यावसायिक

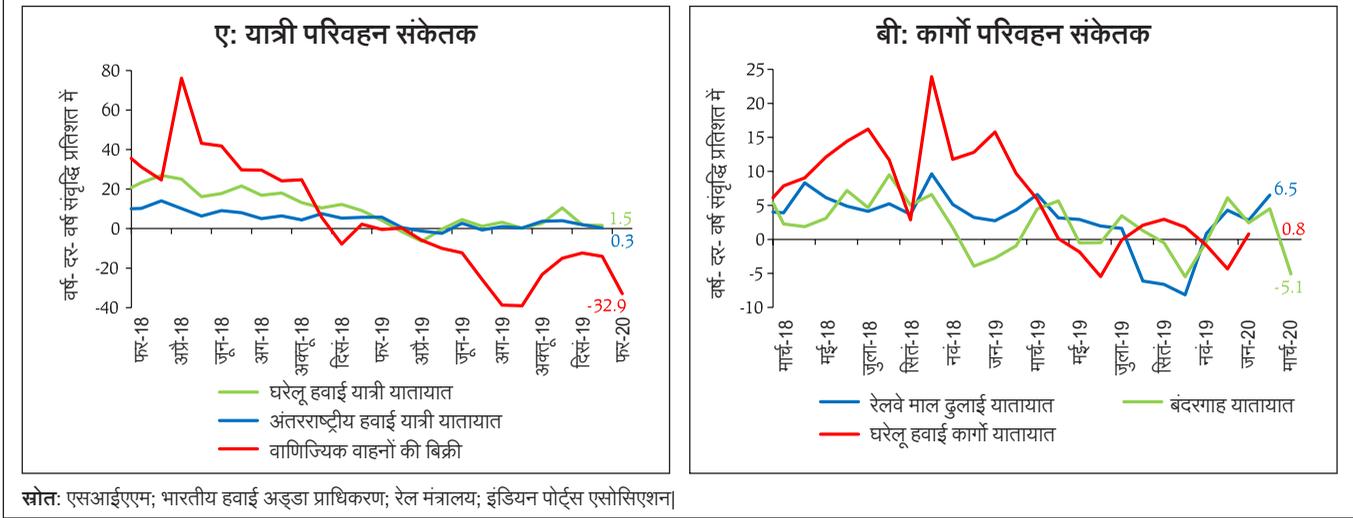
चार्ट III.17: सेवा क्षेत्र के घटक और विनिर्माण संकेतक



⁷ सर्वेक्षण का वर्तमान चक्र 30 जनवरी, 2020 को प्रारम्भ किया गया था और परिणाम 18 मार्च, 2020 तक प्राप्त 860 प्रत्युत्तरों पर आधारित हैं।

⁸ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2018 को भारी वाहनों के ट्रक एक्सल लोड माल वाहनों की वहन क्षमता में 20-25 प्रतिशत वृद्धि की और लोजिस्टिक लागत में लगभग 2 प्रतिशत की कमी को अधिसूचित किया।

चार्ट III.18: परिवहन क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

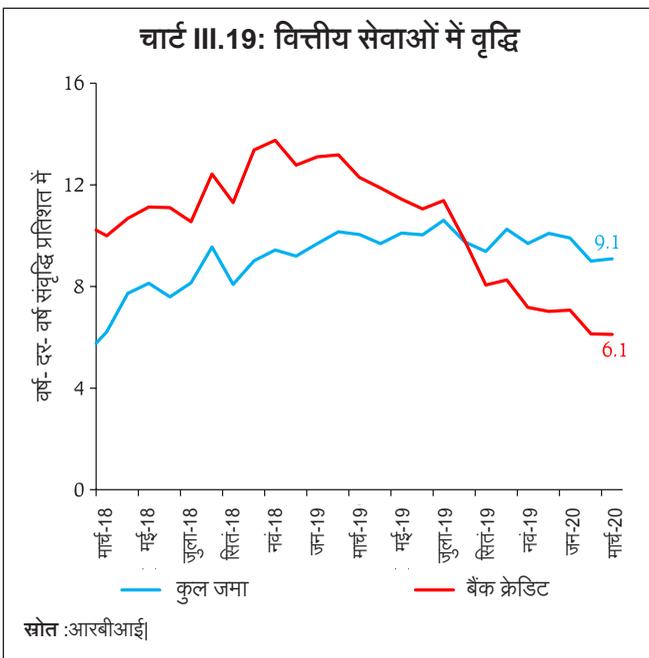


सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के दमदार निष्पादन को दर्शाती है। तथापि, कुल जमा और बैंक ऋण की वृद्धि स्थिर रही (चार्ट III.19)।

लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (PADO) की वृद्धि 2019-20 की तीसरी तिमाही में कम रही जो संघ और राज्य सरकारों के राजस्व व्ययों (ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर) में कमी को दर्शाती है। केंद्र और राज्यों की तंग वित्तीय स्थिति के मद्देनजर चौथी तिमाही में इस कमी के और

बढ़ने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अपने व्यय को बजट स्तर के भीतर सीमित रखने का निदेश दिया है।

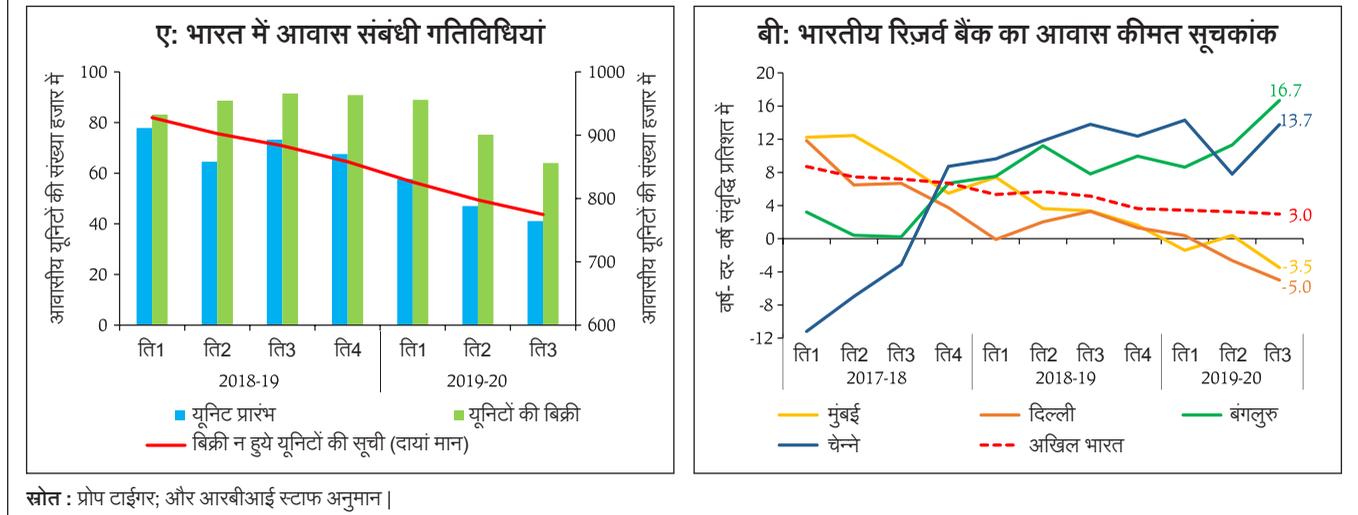
आवासीय वास्तविक संपदा क्षेत्र पर न्यून मांग और अनबिके भारी इन्वेंट्री की मार अभी भी जारी है। परिणामस्वरूप, 2019-20 की तीसरी तिमाही (चार्ट III.20 ए) में नए लॉन्च में गिरावट आई बड़ी मात्रा में अनबिके माल की इन्वेंट्री के कारण अखिल भारतीय स्तर पर आवास की कीमतों में कुछ हद तक नरमी आई है (चार्ट III.20 बी)।



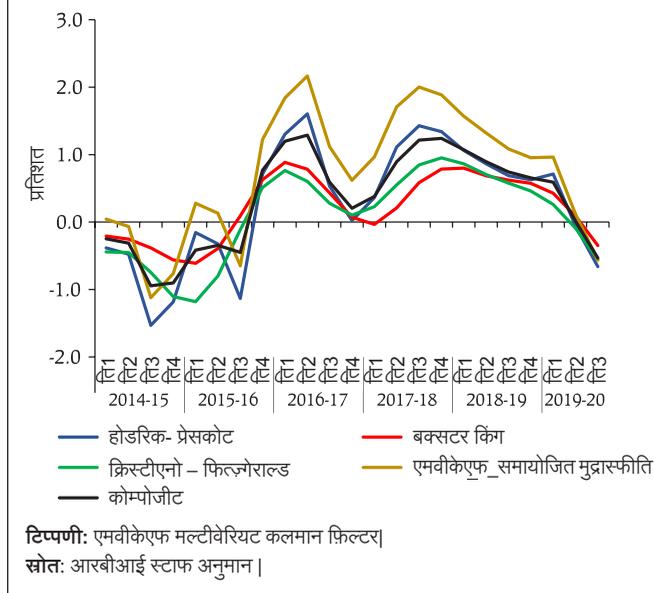
III.3 उत्पादन अंतर

उत्पादन अंतर - अपने संभावित स्तर से वास्तविक उत्पादन उसके संभाव्य स्तर से विचलन और जिसे संभावित उत्पादन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया है - अर्थव्यवस्था में मांग-आपूर्ति की स्थितियों का एक सारांशित उपाय और मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है, क्योंकि यह अंतर्निहित कारोबार चक्र के बरक्स अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक 'उपाय' प्रदान करता है। चूँकि संभावित उत्पादन अगोचर होता है, इसकी गणना का आकलन अनुभवजन्य रूप से किया जाना है, अतः यह गणनाविधि के चयन, समयवधि और डेटा में संशोधन के प्रति संवेदनशील है। विभिन्न प्रकार के उपाय - मुद्रास्फीति के चलन को ध्यान में रखते हुए यूनिवैरिएट फिल्टर यथा- होड्रिक-प्रेसकोट (एचपी) फिल्टर, बैक्सटर-किंग (बीके) फिल्टर और

चार्ट III.20 : आवास क्षेत्र – प्रारंभ,बिक्री और कीमतें



चार्ट III.21: आउटपुट अंतराल अनुमान



क्रिस्टियानो-फिट्जगेराल्ड (सीएफ) फिल्टर और मल्टीवेरिट कलमान फिल्टर (एमवीकेएफ) - को कारोबार चक्र की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन सभी उपायों

के संयोजन से प्राप्त समग्र अनुमान से पता चलता है कि उत्पादन अंतर 2019-20 की तीसरी तिमाही में नकारात्मक था (चार्ट III.21)।

III.4 निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में, अर्थव्यवस्था अधिकतर तिमाहियों में कमजोर रही और बाद में भी जोखिमों का झुकाव सामान्यतया नकारात्मक पक्ष की ओर है। रबी फसल की संभावनाओं में सुधार,खाद्यान मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि और केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यक्तिगत आयकर दरों का युक्तिकरण और साथ ही साथ ग्रामीण और बुनियादी ढांचा खर्च में वृद्धि के लिए किए गए उपायों के होते हुए भी कोविड-19 महामारी की वजह से विशेष रूप से निजी खपत बहुत जोखिम भरा है। सकल मांग पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिसकी वजहें हैं - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, यात्रा और पर्यटन का बेपटरी और कई अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन का होना। घरेलू उत्पादन भी देशव्यापी तालाबंदी से प्रभावित होगा। फिलहाल, कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कैसे कम किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है।

IV. वित्तीय बाजारों और चलनिधि की स्थितियाँ

बदलते घरेलू एवं वैश्विक घटनाक्रमों तथा जनवरी 2020 के अंत में भारत में कोविड-19 के प्रकोप से घरेलू वित्तीय बाजार अत्यधिक प्रभावित रहे। फरवरी के आरंभ से ही बाजार में काफी अस्थिरता बनी रही और ट्रेडिंग गतिविधि में तेज संकुचन ने मार्च में इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुरक्षित पनाह वाली आस्तियों की तलाश तथा बचाव की खोज के परिणामस्वरूप हुए बड़े पैमाने पर पूंजी पलायन ने इक्विटी बाजारों को गिरावट की गर्त में धकेल दिया तथा भारतीय रुपया के मूल्यहास पर तीखा असर डाला। अतरलता की बढ़ती आशंकाओं के मध्य बॉन्ड बाजारों में जोखिम प्रीमियम में तेज बढ़ोतरी हुई।

ईरान और अमरीका के बीच भू-राजनैतिक तनावों तथा कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि में वर्ष-2019-20 की दूसरी छमाही के उत्तरार्ध में वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल मच गई, अमरीका तथा चीन के मध्य व्यापारिक तनावों के कम होने से बाद की स्थिति पर काफी सकारात्मक प्रभाव रहा तथा ब्रिटेन का चुनाव परिणाम ब्रेकिजट के सौहार्दपूर्ण समाधान में सहायक रहा। फरवरी के अंत तथा मार्च की शुरुआत में वैश्विक बाजार में चरणबद्ध मंदी आई क्योंकि कोविड-19 ने चीन के बाहर के देशों में बड़ी तेजी से अपने पैर फैला दिए। संकट की गंभीरता ने अमरीकी फेडरल रिजर्व को 03 मार्च और 15 मार्च 2020 को दरों में आपातकालीन कटौती के लिए मजबूर किया। बाजार को निरावरोध रखने, पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने तथा वित्तीय हालात को सहज बनाए रखने हेतु कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कई अन्यो के केंद्रीय बैंकों ने एकसमान कदम उठाए जो पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक दोनों ही प्रकार के उपायों से समर्थित थे। अति अनिश्चितताओं के मध्य, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों ने वैश्विक आर्थिक संकट के पश्चात 9-16 मार्च 2020 के दौरान अपना सबसे खराब सप्ताह देखा। बॉन्ड प्रतिफल तेजी से गिरा, खासकर अमेरिका में जहां फेड द्वारा 3 मार्च और 15 मार्च को दर में की गई कटौती के दिन 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 1 प्रतिशत के नीचे आ गया। मुद्रा बाजार में,

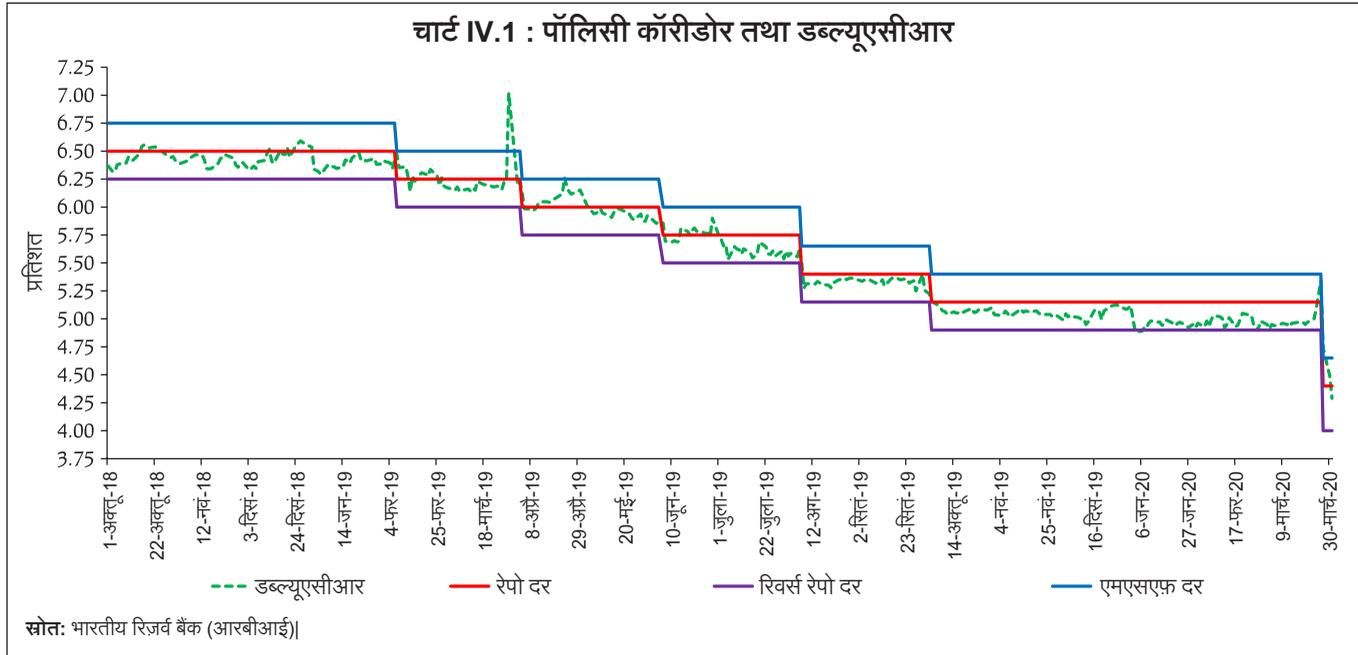
व्यापारिक तनाव कम होने के कारण दिसंबर में अमरीकी डॉलर मजबूत हुआ तथा कोविड-19 के प्रकोप के पश्चात सुरक्षित पनाह की मांग की वजह से यह और मजबूत हुआ। फरवरी के अंत तथा मार्च के शुरुआत में सुरक्षित पनाह की खोज में आई तेजी ने अधिकतर ईएमई मुद्राओं को तीव्र गति से कमजोर कर दिया।

IV.1 घरेलू वित्तीय बाजार

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान, घरेलू वित्तीय बाजार ने अलग-अलग रवैया दिखाया। अक्टूबर 2019 में दर में की गई कटौती तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालन ने बाजार धारणा को उत्साहित किया परंतु घरेलू आर्थिक मंदी की बढ़ती चिंताओं, राजकोषीय स्लिपेज, भू-राजनैतिक तनाव तथा कोविड-19 के तेजी से फैलने के कारण बढ़ती अनिश्चितताओं ने, विशेषकर चौथी तिमाही के अंत में, कठिन चुनौती खड़ी कर दी। 24, 26 तथा 27 मार्च को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की अनिर्धारित बैठक में नीतिगत रेपो दर में की गई अप्रत्याशित कटौती तथा विभिन्न चलनिधि-परिवर्धक उपायों ने बाजार की आशंकाओं को थोड़ा कम किया (बॉक्स IV.3 देखें)।

क्रेडिट बाजार में, प्रचुर चलनिधि अधिशेष, बैंकों की निधि लागत को कम करने के लिए लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ), खुला बाजार परिचालन (विशेष ओएमओ)¹ के तहत एक ही समय पर प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री तथा कतिपय क्षेत्रों में ऋण दिए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए नगद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) की आवश्यकताओं में छूट देकर मौद्रिक नीति अंतरण को सुगम बनाया गया। 14 जनवरी 2020 को शेयर बाजार ने एक नई ऊंचाई को पार किया लेकिन उसके पश्चात वैश्विक बाजारों के अनुरूप इसमें अत्यधिक अस्थिरता आ गई। महामारी फैलने तथा सुरक्षित पनाह की खोज से उत्पन्न

¹ दीर्घावधि ब्याज दर कम करने तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवसायों, उद्योगों एवं अन्य उधारकर्ताओं को सस्ता ऋण देने के लिए 1961 और 2011 में अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा किए गए ऐसे ही दो परिचालनों से अनुभव लेते हुए वित्तीय मीडिया द्वारा आमतौर पर इन परिचालनों को "परिचालन ट्विस्ट" कहा गया है।



आशंकाओं के कारण भारतीय रुपया (आईएनआर) दबाव में आ गया। तथापि, ऐसे में भी अन्य समकक्ष ईएमई मुद्राओं की तुलना में आईएनआर में मूल्यहास काफी कम था।

IV.1.1 मुद्रा बाजार

मुद्रा बाजार ने आघातों को काफी हद तक सहन किया जो आरबीआई के अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालन को दर्शाता है। दूसरी छमाही में, अरक्षित एकदिवसीय मुद्रा बाजार का भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूईआर) अविरत चलनिधि अधिशेष को दर्शाते हुए अधोगामी ढाल (औसत आधार पर रेपो दर से 13 आधार अंक नीचे) बनाते हुए नीति दायरे में रहा (चार्ट IV.1)। डब्ल्यूएसीआर में वर्षात की परंपरा के अनुरूप उछाल रहा, जो कोविड-19 जनित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से घटी हुई बाजार भागीदारी से संयोजित था।

एक दिवसीय मांग मुद्रा खंड में, कारोबारी लेन-देन का भारित औसत दर रिपोर्ट किए गए लेन-देन की तुलना में अधिक बना रहा² कारोबारी लेन-देन का हिस्सा (मात्रा के अनुसार) भी रिपोर्ट किए लेन-देन की तुलना में अधिक था, हालांकि इसमें पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में तेजी आई जिसके

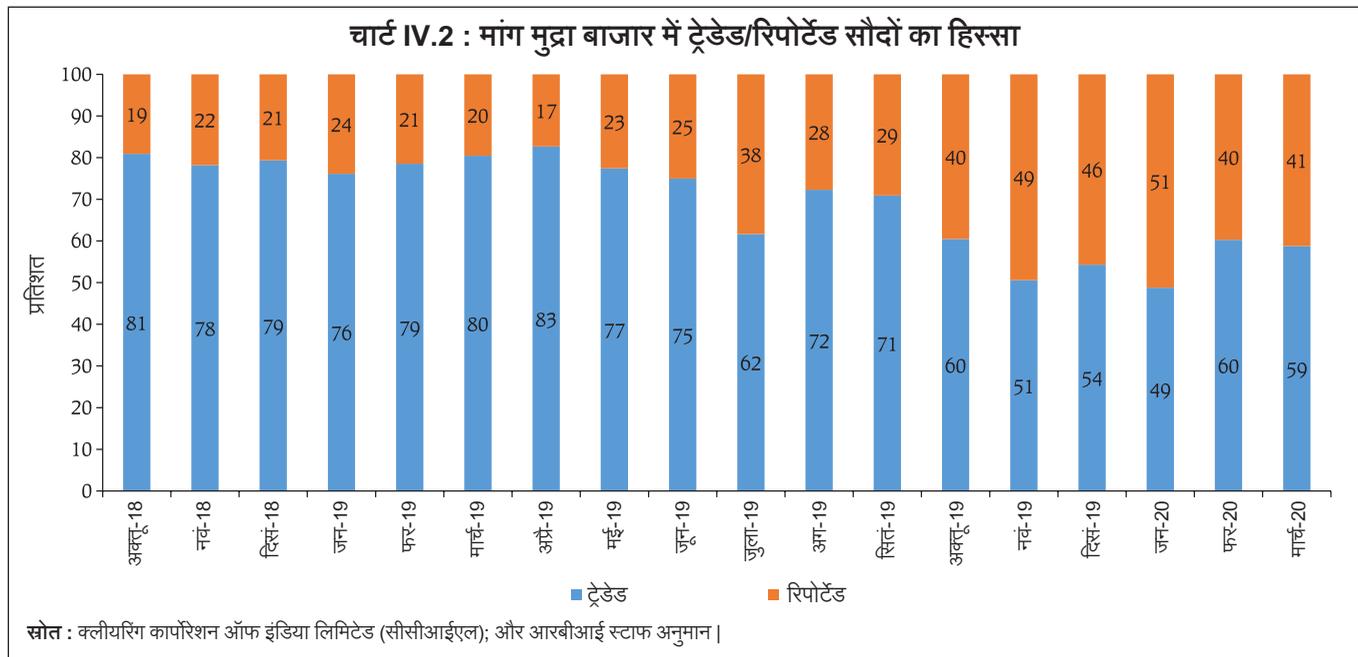
² 'कारोबारी लेन-देन' सीधे एनडीएस-मांग पटल पर पूरा किया गया लेन-देन है जबकि 'रिपोर्ट किया गया लेन-देन' काउंटर पर (ओटीसी) किया गया लेन-देन है जिसे लेन-देन पूरा होने के पश्चात एनडीएस-मांग पटल पर रिपोर्ट किया जाता है।

जिम्मेदार कारक थे- (i) सहकारी बैंकों द्वारा उधार देने में बढ़ोतरी; तथा (ii) वर्ष के उत्तरार्ध में चलनिधि अधिशेष का उच्च स्तर (चार्ट IV.2)।

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में एक दिवसीय मुद्रा बाजार की मात्रा में संपार्श्विकीकृत मुद्रा बाजार (त्रि-पक्षीय रेपो तथा बाजार रेपो) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई (चार्ट IV.3)। तथापि, मांग मुद्रा बाजार पर बैंकों की निर्भरता में बढ़ोतरी हुई (कुल एक दिवसीय लेन-देन में मांग मुद्रा की हिस्सेदारी जनवरी के 4 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी-मार्च 2020 के दौरान 6 प्रतिशत हो गई), जो अंशतः 14 फरवरी 2020 से दैनिक नियत रेपो परिचालन के बंद होने को दर्शाता है जो कि 6 फरवरी 2020 को घोषित संशोधितचलनिधि प्रबंधन ढांचा का हिस्सा है (बॉक्स IV.2 देखें)।

विशेषकर, म्यूच्यूल फंडों (एमएफ) द्वारा दिए जानेवाले उधार में अक्टूबर 2019 से बढ़ोतरी होने के कारण एक दिवसीय मुद्रा बाजार मात्रा में त्रि-पक्षीय रेपो की बेहतर हिस्सेदारी रही। चलनिधि और एक दिवसीय निधि में निवेश करने पर निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुप्रयोजन की समय सीमा³ में हुए

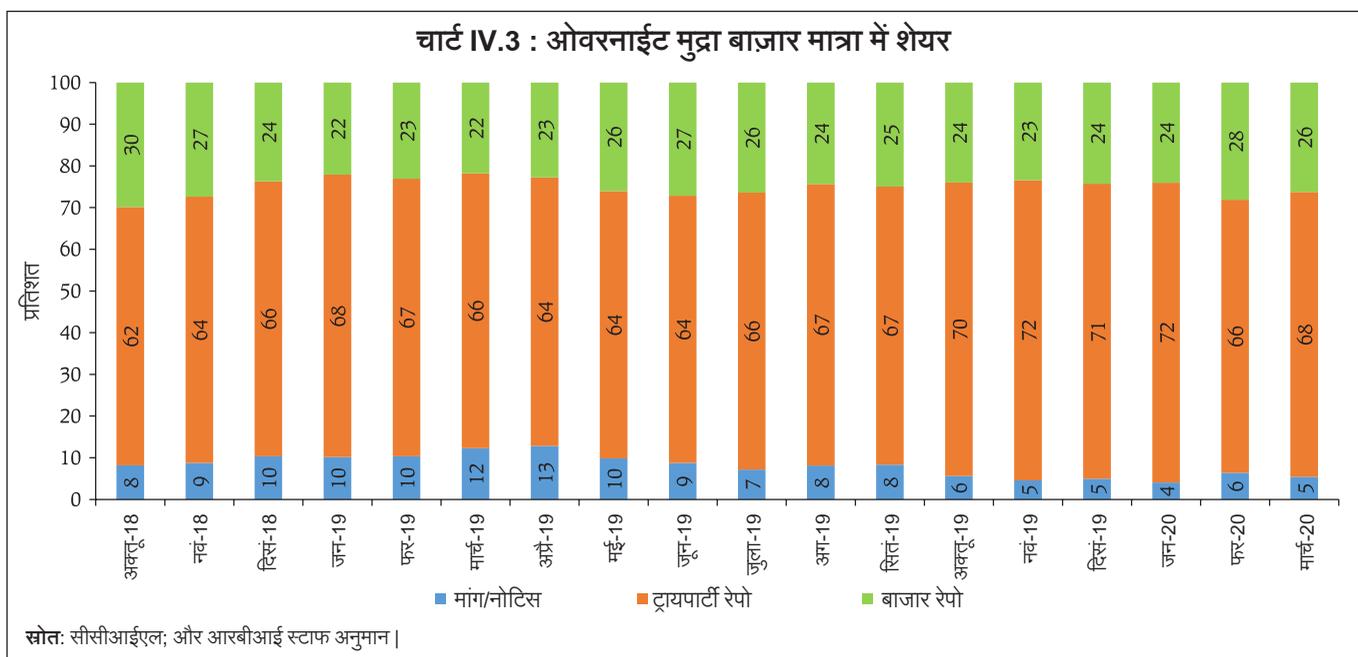
³ 20 सितंबर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने एनएवी गणना की समय-सीमा को अपराह्न 2:00 बजे से पहले अपराह्न 1:30 बजे कर दिया।



बदलाव ने आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एमसी) को त्रि-पक्षीय रेपो खंड में निवेश करने भी अधिक स्वतंत्रता दी है। तदनुसार, त्रि-पक्षीय रेपो में एमएफ द्वारा उधार हिस्सेदारी सितंबर 2019 के 60.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 64.7 प्रतिशत तथा मार्च में 72.1 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई। इसी के साथ, एमएफ द्वारा लेनदारी सितंबर 2019 के 9.8 प्रतिशत से तेजी से घटकर

अक्टूबर में 2.4 प्रतिशत रह गई जो बाद के महीनों में औसतन केवल 2.2 प्रतिशत ही थी।

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान, संपार्श्विकीकृत एक दिवसीय मुद्रा बाजार खंड में ब्याज दर डब्ल्यूएसीआर के अनुरूप नरम रही, हालांकि 06 जनवरी 2020 को विशेष ओएमओ की तीसरी नीलामी के समय यह नरमी अधिक स्पष्ट थी। मार्च

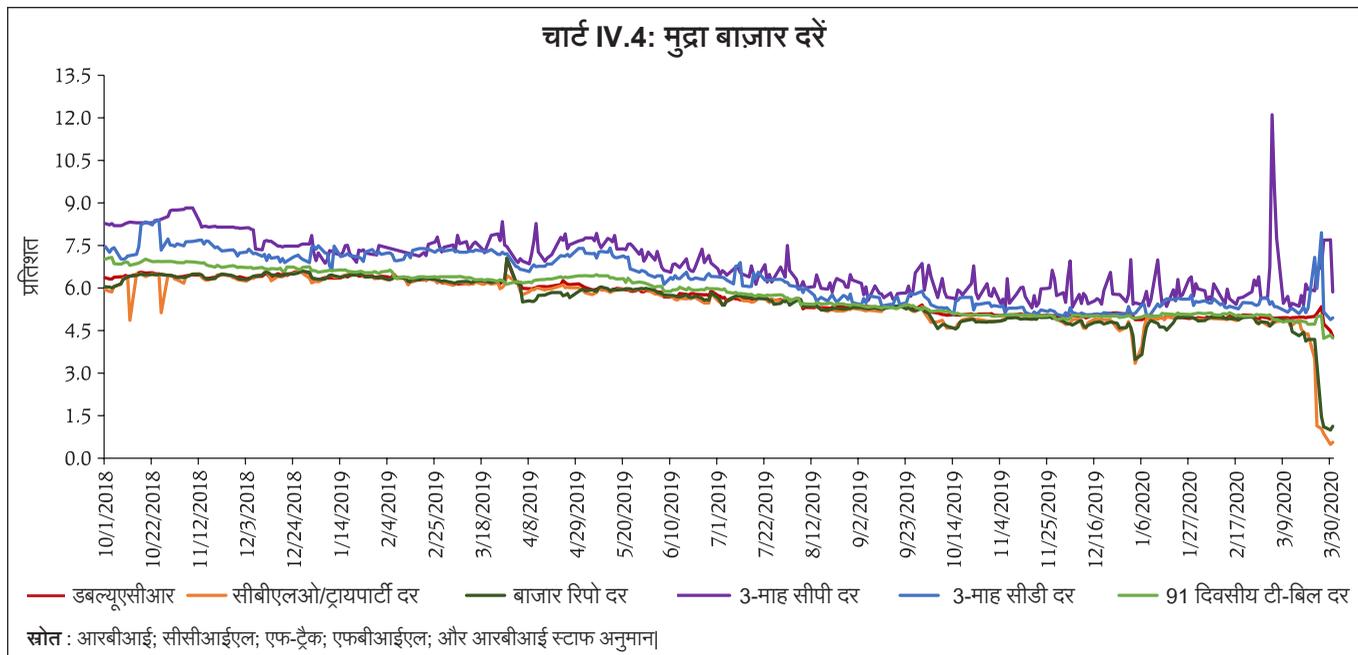


2020 के अंत तक त्रि-पक्षीय रेपो तथा बाजार रेपो खंड में एक दिवसीय दर तेजी से घटा, इसमें पहले में तो चलनिधि अधिशेष बढ़ गया क्योंकि कॉरपोरेट और गैर-बैंकों सहित अत्यंत जोखिम विमुखता वाले निवेशकों के चलते शून्य के आस-पास कारोबार हुआ। दूसरी छमाही में, त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो में क्रमशः डब्ल्यूएसीआर (औसतन) से 36 आधार अंक एवं 37 आधार अंक नीचे कारोबार हुआ। अक्टूबर में नीतिगत दरों में की गई कटौती तथा चलनिधि अधिशेष इकट्ठा हो जाने की अनुक्रिया में दीर्घावधि मुद्रा बाजार लिखतों जैसे जमा प्रमाणपत्र (सीडी), वाणिज्यिक पत्र (सीपी) तथा 3-माह परिपक्वता अवधि वाले खजाना बिलों की ब्याज दरों में भिन्नता दिखी (चार्ट IV.4)। फरवरी के आखिर तथा मार्च 2020 के आरंभ में मजबूती हासिल करने से पहले सीपी दरें अत्यधिक अस्थिरता के दौर से गुजरीं।

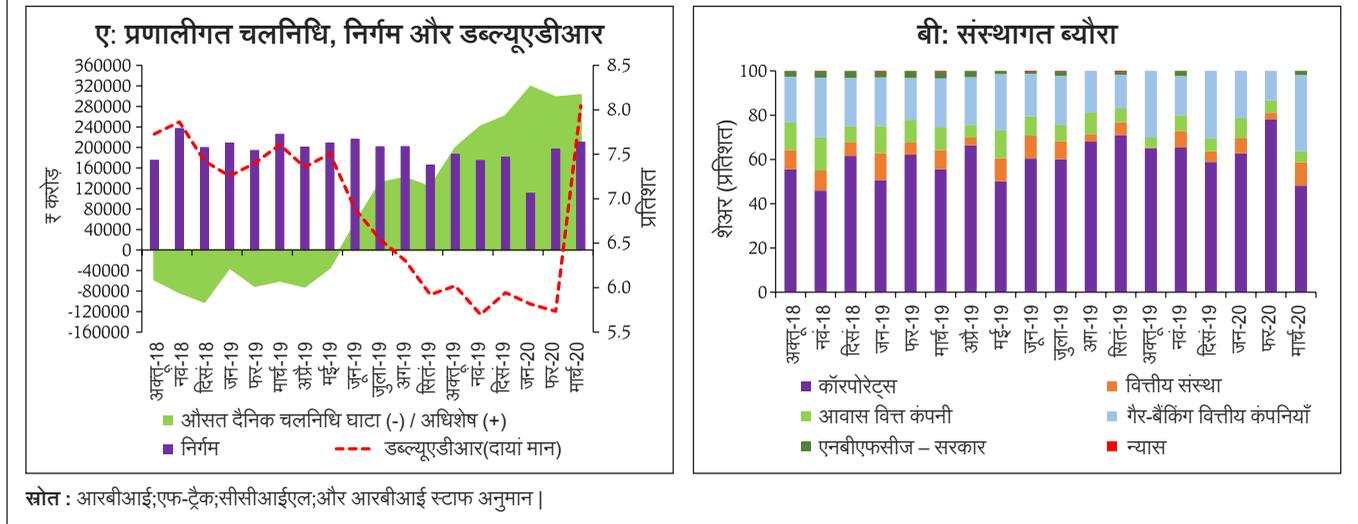
सुदृढ़ चलनिधि अधिशेष को देखते हुए, बैंकों ने सीडी के माध्यम से अपने संसाधन जुटाने कम कर दिए यथा पहली छमाही के दौरान रु 2,01,302 करोड़ से घटकर 2019-20 की दूसरी छमाही में नया निर्गमन रु 1,86,954 करोड़ रहा। सीपी का निर्गमन भी वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के रु 12,38,324 करोड़ से घटकर दूसरी छमाही में रु 10,02,667 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से जोखिम विमुखता को दर्शाता है। प्राथमिक बाजार में (i) चलनिधि अधिशेष इकट्ठा हो जाने के तदनुरूप तथा (ii)

अपेक्षाकृत अधिक मजबूत मूल कंपनियों से समर्थित शीर्ष दर्जा प्राप्त जारीकर्ता के निर्गमनों पर अधिप्रभुत्व के कारण सामान्य रूप से फरवरी तक सीपी का भारित औसत बढ़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) थोड़ा कम रहा। डब्ल्यूएडीआर, जो कि साख श्रेणी निर्धारण संबंधी चिंताओं के कारण दिसंबर 2019 में 24 आधार अंक बढ़ गया था, (i) कोविड-19 जनित वित्तीय दबाव; तथा (ii) निजी क्षेत्र के एक बैंक में आए दबाव का बैंकिंग प्रणाली से अंतर्संबंधता के कारण उत्पन्न संक्रमण की आशंका में मार्च में तेजी से 229 आधार अंक और बढ़ गया (चार्ट IV.5ए)। सीपी के प्राथमिक निर्गमन में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भागीदारी जो कि आईएल एंड एफएस संकट के तुरंत बाद से ही घट गयी थी, वह अक्टूबर में बढ़ी और फिर 08 मार्च 2020 को लगभग 35 प्रतिशत के सर्वोच्च पर पहुंच गई (चार्ट IV.5 बी)।

पहले की गई चर्चा के अनुसार कुछ हद तक वर्षांत की अवधारणा तथा 2019-20 की दूसरी छमाही में चलनिधि अधिशेष की स्थिति के फलस्वरूप त्रि-पक्षीय रेपो और बाजार रेपो खंड में मौद्रिक नीति अंतरण अनुपात से अधिक रहा (सारणी IV.1)। तथापि, वैश्विक तथा घरेलू वित्तीय बाजार में कोविड-19 जनित हलचल के बाद बाजार शिथिल हो जाने तथा अतरलता से उत्पन्न आशंकाओं के कारण मुद्रा बाजार में (91 दिवसीय खजाना बिलों की तुलना में 3 माह का सीपी) जोखिम प्रीमियम (औसतन) पहली



चार्ट IV.5 : वाणिज्यिक पत्र का प्राथमिक निर्गम



छमाही के 87 आधार अंक से बढ़कर दूसरी छमाही में 97 आधार अंक हो गया।

IV.1.2. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही की शुरुआत में, बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में (i) मौद्रिक नीति में ढील देने को लेकर बाज़ार प्रत्याशाओं; (ii) नए 10-वर्षीय पेपर की नीलामी की घोषणा करने संबंधी केंद्र सरकार के निर्णय; तथा (iii) मुद्रास्फीति की अनुकूल चाल के कारण, 4 बीपीएस की नरमी आई। तथापि, 4 अक्टूबर 2019 को की गई मौद्रिक नीति घोषणा के बाद प्रतिफलों में 8 बीपीएस की मजबूती आई, क्योंकि नीतिगत दर में 25 बीपीएस की कटौती बाज़ार की अपेक्षाओं से कम थी। उसके बाद केंद्रीय सरकार के वित्त के मामले में लगातार चिंताओं, मुद्रास्फीति प्रिंट्स में वृद्धि की प्रत्याशा तथा सरकारी पेपर के प्रति कम रुचि के कारण प्रतिफलों में संकुचन जारी रहा। तथापि, ये (1) एक दिवसीय सूचकांक स्वैप में गिरावट, (2) कच्चे तेल की वैश्विक

कीमतों में गिरावट तथा (3) अमेरिकी खजाना प्रतिफलों में नरमी से संकेत लेते हुए अक्टूबर के अंत में नरम पड़ गया। समग्र रूप से, अक्टूबर 2019 के दौरान बेंचमार्क प्रतिफल में 5 बीपीएस तक की गिरावट आई।

5 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार नए बेंचमार्क (6.45 प्रतिशत जीएस 2029) और पुराने बेंचमार्क (7.26 प्रतिशत जीएस 2029) दोनों के प्रतिफलों में 7 बीपीएस की वृद्धि हुई, जो राजकोषीय गिरावट के प्रति चिंता तथा यूएस के राजकोषीय प्रतिफलों में बढ़ोतरी को दर्शाता है। दिसंबर की शुरुआत में, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति के प्रति बाज़ार का रुख तनावपूर्ण हो जाने के कारण दोनों बेंचमार्क प्रतिफलों में वृद्धि हुई। 5 दिसंबर को मौद्रिक नीति घोषणा के दिन, (i) मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले जोखिमों के होने के बावजूद नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने संबंधी एमपीसी के निर्णय; तथा (ii) वृद्धि संबंधी निराशावादी दृष्टिकोण के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा भारी मात्रा में बिक्री के परिणामस्वरूप नए बेंचमार्क पर 14

सारणी IV.1: मुद्रा बाज़ार में नीति संचरण

(आधार अंक)

2019-20	दरों में परिवर्तन						
	रेपो	(कॉल/नोटिस) डब्ल्यूएसीआर	ट्राय-पार्टी रेपो	बाज़ार रेपो	3-माह सीडी	91-दिवसीय टी-बिल	3-माह सीपी
एच1:(अप्रैल 02 से सितंबर 30)	-85	-162	-111	-178	-132	-90	-59
एच 2:(अक्टूबर 01 से मार्च 31)	-100	-111	-477	-416	-94	-100	-100

टिप्पणी: इजिंग(-)/हार्डनिंग(+)

स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; एफ-ट्रेड; एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान |

बीपीएस और पुराने बेंचमार्क पर 18 बीपीएस तक प्रतिफलों में बढ़ोतरी हुई। तथापि, बाजार सहभागियों ने 19 दिसंबर को विशेष ओएमओ के संचालन के रिज़र्व बैंक के फैसले का स्वागत किया, जिसके परिणामस्वरूप नए और पुराने बेंचमार्क प्रतिफलों में क्रमशः 15 बीपीएस और 13 बीपीएस की गिरावट आई।⁴

दीर्घकालिक प्रतिफलों में नरमी आयी, जबकि अल्पावधि प्रतिफलों में मजबूती रही, जिससे दीर्घकालिक प्रीमियम में कमी आई (बॉक्स IV.1)। कुल मिलाकर, दिसंबर में नए और पुराने बेंचमार्क प्रतिफलों में क्रमशः 9 बीपीएस और 15 बीपीएस की वृद्धि हुई।

बॉक्स IV.1 : दीर्घकालिक प्रीमियम और इसके निर्धारक तत्वों का आकलन

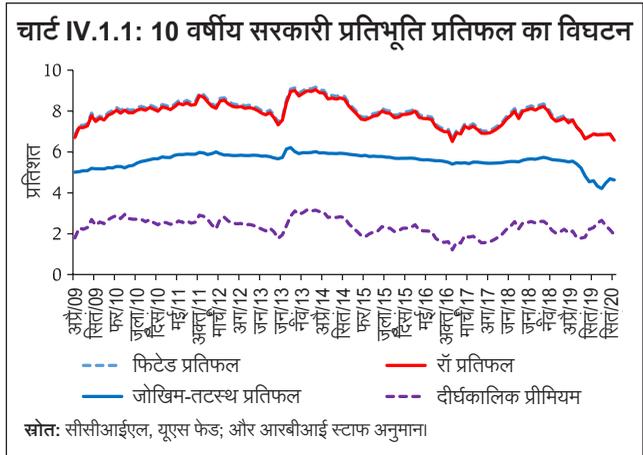
अल्पकालिक बॉण्ड की तुलना में दीर्घकालिक बॉण्ड के प्रतिफल में अंतर ही दीर्घकालिक प्रीमियम है तथा बॉण्ड को लंबी परिपक्वता अवधि के लिए रखने के बदले निवेशकों द्वारा अधिक ब्याज की मांग को दर्शाता है (स्वानसन, 2007)। भविष्य में अल्पकालिक ब्याज दरों की अपेक्षित चाल को देखते हुए किसी भी परिपक्वता पर दीर्घकालिक ब्याज को दो घटकों में विघटित किया जा सकता है: (i) जोखिम-तटस्थ दर, जो भविष्य की अल्पकालिक दरों की अपेक्षाओं को दर्शाती है; और (ii) दीर्घकालिक प्रीमियम, जो केंद्रीय बैंक की भावी नीति, मुद्रास्फीति और वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण से संबंधित निवेशकों की प्रत्याशाओं को इंगित करता है।

एड्रियन, क्रम्प और मोनेच (एसीएम) दृष्टिकोण, जो प्रतिफल को जोखिम-तटस्थ घटक और दीर्घकालिक प्रीमियम में विभाजित करने की स्वीकृति देता है, डायनेमिक टर्म स्ट्रक्चर मॉडल (एड्रियन एट अल., 2013) के नियमित श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये मॉडल नो-आरबिट्रेज वाली स्थिति में शामिल किए गए हैं।⁵ एसीएम दृष्टिकोण कीमत निर्धारक कारकों के रूप में बॉण्ड प्रतिफलों के प्रमुख घटकों का उपयोग करता है। जोखिम-तटस्थ दर का मॉडल इन कीमत निर्धारक कारकों के लीनियर फंक्शन के रूप में बनाया गया है। दीर्घकालिक प्रतिफलों को कीमत निर्धारक कारकों के लीनियर फंक्शन, जिसमें नो-आरबिट्रेज की मान्यता को शामिल करने के लिए मापदंडों पर उचित प्रतिबंध शामिल है, के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। यह दीर्घकालिक-स्ट्रक्चर मॉडलों को जोड़ता है। अलग-अलग समयावधि का दीर्घकालिक प्रीमियम, मॉडल-फिटेड प्रतिफल और जोखिम-तटस्थ प्रतिफल के बीच का अंतर है।

विघटन

भारत के संदर्भ में अनुभवजन्य विश्लेषण में अप्रैल 2009 से फरवरी 2020 तक के 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफलों के मासिक आंकड़ों के आधार पर एसीएम पद्धति (दिलीप, 2019) का अनुसरण करते हुए 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल के अपघटन को प्रत्याशा तथा दीर्घकालिक प्रीमियम घटकों में बदलना शामिल है। यह दर्शाता है कि 10-वर्षीय प्रतिफल ने व्यापक रूप से दीर्घकालिक प्रीमियम में ट्रैक किया है (चार्ट IV.1.1)।

सरकारी प्रतिभूति प्रतिफलों, जिन्हें $\frac{\Delta \text{टर्म प्रीमियम}^2}{\Delta \text{टर्म प्रीमियम}^2 + \Delta \text{रिस्क} - \text{न्यूट्रल यील्ड}^2}$ के रूप में अनुमानित किया गया है, में दीर्घकालिक प्रीमियम का योगदान यह इंगित करता है कि संपूर्ण दीर्घकालिक ढांचा में दीर्घकालिक प्रीमियम



धीमे से बढ़ता है, जो 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफलों में कुल उतार-चढ़ाव का 84 प्रतिशत है (सारणी IV.1.1)। जबकि अल्पकालिक प्रतिफलों (1 से 2 वर्षीय) में कुल उतार-चढ़ाव में से केवल 27-39 प्रतिशत के लिए दीर्घकालिक प्रीमियम जिम्मेदार है, लगभग 73-61 प्रतिशत परिवर्तन के लिए अल्पकालिक दरों संबंधी प्रत्याशाओं में बदलाव जिम्मेदार है। इसके विपरीत, यूएस दीर्घकालिक प्रीमियम अल्पकालिक प्रतिफलों में परिवर्तन के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात को स्पष्ट करता है।

सारणी IV.1.1: बॉण्ड प्रतिफल परिवर्तनों में दीर्घकालिक प्रीमियम का हिस्सा

(प्रतिशत)

अवधि	भारत	यूएस
1 वर्षीय	26.7	41.4
2 वर्षीय	38.8	45.0
3 वर्षीय	50.4	49.8
4 वर्षीय	58.5	53.3
5 वर्षीय	64.1	55.9
6 वर्षीय	70.2	58.1
7 वर्षीय	74.7	60.1
8 वर्षीय	78.1	61.9
9 वर्षीय	81.6	63.7
10 वर्षीय	84.4	65.4

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

(जारी)

⁴ इन गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 19 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के बीच 61 बीपीएस तक नरम होता गया तथापि, इस अवधि के दौरान प्रतिफलों में 69 बीपीएस तक की गिरावट आई।

⁵ भविष्य में समान नकद का प्रवाह उपलब्ध कराने वाली तथा समान स्तर की जोखिम वाली दो प्रतिभूतियों की बिक्री समान कीमत पर होगी।

भारत में दीर्घकालिक प्रीमियम का अभिनिर्धारण करने के प्रयोजन से, 10-वर्षीय दीर्घकालिक प्रीमियम को इसके स्वयं के लैंग पर रीग्रेस किया गया है, सरकारी प्रतिभूति बाजार की पैठ की प्रॉक्सी जीडीपी के समानुपात के रूप में दैनिक औसत प्रतिलाभ, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, आइएनआर-यूएसडी की हाजिर विनिमय दर, जीडीपी के समानुपात के तौर पर चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत बकाया शेष से आकलित प्रणालीगत चलनिधि, और वैश्विक आर्थिक नीतिगत

सारणी IV.1.2: दीर्घकालिक प्रीमियम के निर्धारक तत्व

चर	गुणांक
दीर्घकालिक_प्रीमियम (-1)	0.83 *** (9.60)
Δऔसत_कारोबार	-5.35*** (-5.57)
Δ(कच्चे_तेल_की_कीमत)	0.02*** (6.65)
Δ(आइएनआर/यूएसडी)	0.08*** (3.33)
Δ(प्रणालीगत_चलनिधि)	-0.89** (-2.14)
Δ(वैश्विक_अनिश्चितता) (-1)	0.003 (0.77)
Δ(नीतिगत_अनिश्चितता)	0.001 (0.81)
सी	0.29* (1.76)
आर-बार ²	0.82
डर्बिन वॉटसन	1.64
एलबी-क्यू (पी-वैल्यू)	0.59

***, **, * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाते हैं

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े टी-स्टैटिस्टिक्स हैं जो हेट्रोस्केडास्टीसीटी और ऑटोकॉरिलेशन कंसिस्टेंट (एचएसी)-करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स पर आधारित हैं; एलबी-क्यू बॉक्स-पियर्स-जंगका पी-वैल्यू है तथा 4 लैंग तक नो कोरिलेशन के नल्ल हायपोथेसिस के लिए क्यू-स्टैटिस्टिक्स हैं; तथा Δ डिफरेंस ऑपरेटर है।

औसत-कारोबार = दैनिक औसत कारोबार (जीडीपी का प्रतिशत), कच्चे_तेल_की_कीमत = यूएसडी प्रति बैरल ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत, आइएनआर/यूएसडी = स्पॉट रुपया-यूएस डॉलर विनिमय दर, प्रणालीगत_चलनिधि = बकाया एलएएफ शेष (जीडीपी का प्रतिशत), वैश्विक_अनिश्चितता = ग्लोबल इकॉनॉमिक पॉलिंसी अनसर्टेटी इंडेक्स (गेपु), पॉलिंसी_अनसर्टेटी = इकॉनॉमिक पॉलिंसी अनसर्टेटी (एपु), भारत के लिए।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अनिश्चितता सूचकांक (जीईपीयू) और भारत के लिए आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता (ईपीयू) दोनों द्वारा क्रमशः प्रतिव्यक्त वैश्विक और भारत-संबद्ध नीतिगत अनिश्चितता से की गई है। सभी व्याख्यात्मक चरांकों की विभेदीकृत श्रेणियों को सुस्थिर पाया गया और इस समीकरण का प्राक्कलन एक सामान्य लघुत्तम वर्गफल (ओएलएस) पद्धति से किया गया है। अपेक्षित चिह्नों के साथ अधिकांश अनुमानित गुणांक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं (तालिका IV.1.2)। लैंग टर्म के उच्च गुणांक से मीयादी प्रीमियम के सातत्य के संकेत मिलते हैं। प्रतिलाभ और प्रणालीगत चलनिधि के चरांकों के महत्व बॉण्डों के लिए उच्चतर मांग में चलनिधि की अहम भूमिका और इसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक प्रीमियम में कमी के संकेतक हैं। तेल की कीमतों और भारतीय रुपये (आइएनआर) की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव प्रतिलाभों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं – तेल की कीमतों में उछाल और आइएनआर के मूल्यहास के कारण निवेशक निरापद आस्तियों की तलाश में लग जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे निरापद की तरफ भागते (घबराहट में बिकवाली) हैं और दीर्घकालिक प्रीमियम में वृद्धि होती है। वैश्विक अनिश्चितता (लैंग्ड) और भारतीय नीतिगत अनिश्चितता, यद्यपि इसका प्रभाव धनात्मक है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं।

संदर्भ:

एड्रियन, टी., क्रम्प, आर. के., और मोएंच, ई. (2013), "प्राइसिंग द टर्म स्ट्रक्चर विद लिनीयर रिग्रेसन्स", जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकॉनॉमिक्स, 110 (1), 110-138।

दिलीप, ए. (2019), "टर्म प्रीमियम स्पिलओवर फ्राम द यूएस टू इंडियन मार्केट्स", आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, डब्ल्यूपीएस (डीईपीआर): 05/2019, दिसंबर।

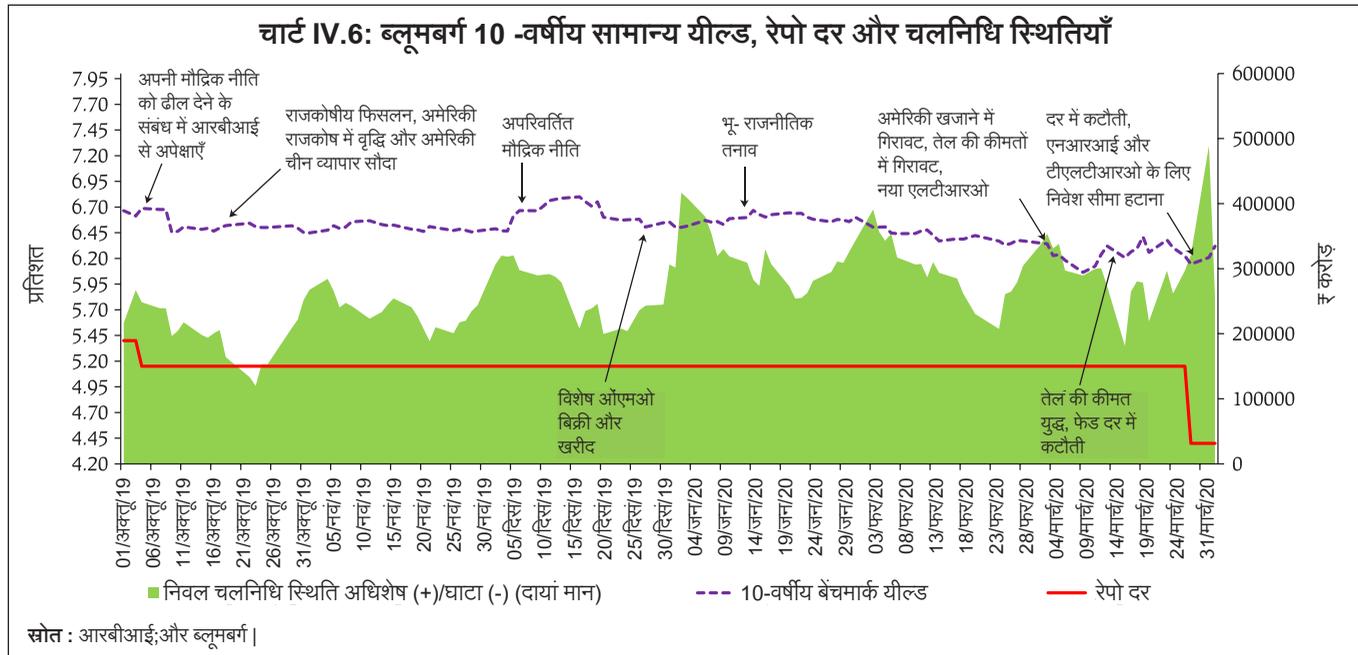
स्वानसन, ई. टी. (2007), "व्हाट वी डू एंड डोंट नो अबाउट द टर्म प्रीमियम", एफआरबीएसएफ इकॉनॉमिक लेटर, नंबर 2007-21, जुलाई।

जनवरी की शुरुआत में, रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक बॉण्डों की खुली बाज़ार खरीद करने से संबंधित प्रत्याशाओं के कारण 10-14 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले खंड में अधिकांश सरकारी पेपर मजबूत हुए। तथापि, बॉण्ड की कीमतें विशेष ओएमओ में अपेक्षा से कम कटौती के कारण बाद में गिर गईं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा जनवरी 2020 में मुद्रास्फीति प्रिंट के अपेक्षा से अधिक होने की प्रत्याशा के कारण प्रतिफलों में उछाल जारी रहा। समग्र रूप से, जनवरी 2020 के दौरान नए और पुराने बेंचमार्क में क्रमशः 4 बीपीएस और 7 बीपीएस तक की वृद्धि हुई।

केंद्रीय बजट के बाद, सरकार द्वारा अनुमानित राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी वाला संशोधन किए जाने के बावजूद वर्ष

2019-20 के लिए बाज़ार से अतिरिक्त उधार लेने से परहेज करने के कारण बाज़ार को सुखद आश्चर्य हुआ। परिणामस्वरूप, फरवरी की शुरुआत में नए और पुराने बेंचमार्क प्रतिफलों में क्रमशः 10 बीपीएस और 14 बीपीएस तक की गिरावट आई। नीतिगत दर पर अतिरिक्त चलनिधि प्रवाहित करने के लिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) की घोषणा करने पर प्रतिफलों में काफी कमी आई (चार्ट IV.6)⁶ कुल मिलाकर, फरवरी 2020 के दौरान नए और पुराने बेंचमार्क दोनों में क्रमशः 23 बीपीएस और 26 बीपीएस तक की गिरावट आई।

⁶ 6 फरवरी को एलटीआरओ की घोषणा के बाद से 1-वर्षीय, 3-वर्षीय, 5-वर्षीय तथा बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पेपर में मार्च, 2020 के अंत तक क्रमशः 62 बीपीएस, 71 बीपीएस, 31 बीपीएस तथा 37 बीपीएस तक की गिरावट आई।



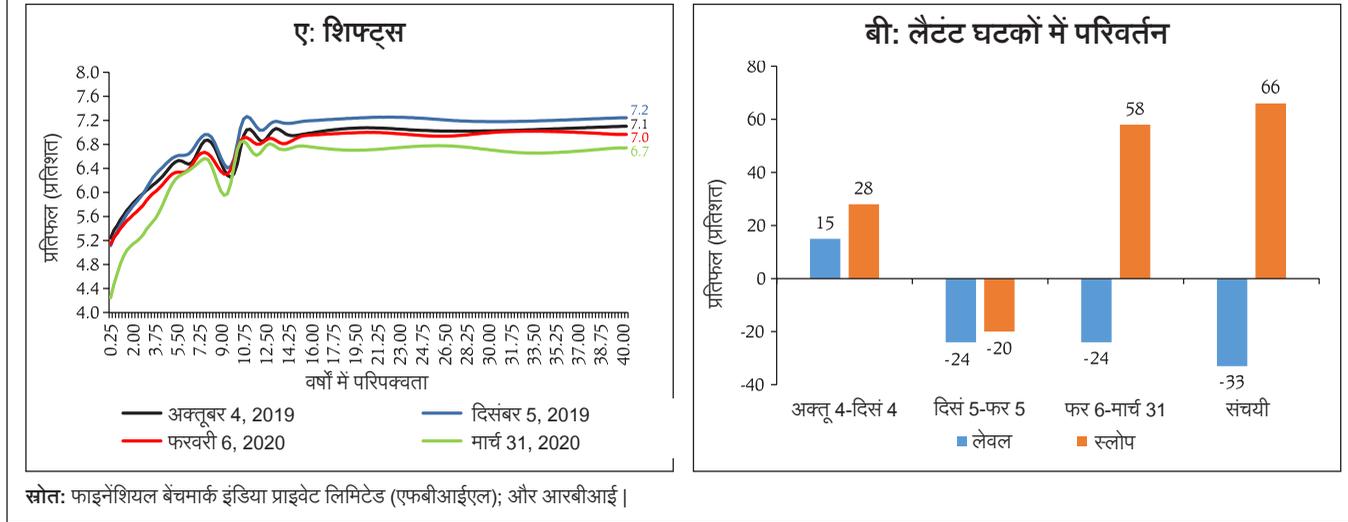
मार्च की शुरुआत में, (i) फेड द्वारा अपने नीतिगत दर में 150 बीपीएस (दो चरणों में) तक की कमी, जो पहले से निर्धारित नहीं थी; तथा (ii) सऊदी अरब द्वारा अपनी आपूर्ति बढ़ाने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के परिणामस्वरूप नए तथा पुराने बेंचमार्क प्रतिफल क्रमशः 19 बीपीएस एवं 13 बीपीएस की नरमी वाले रुख के साथ शुरू हुए। तथापि, इसके बाद (i) महामारी पर काबू पाने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने संबंधी यूएस के संकल्प के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी; (ii) कोविड-19 के कारण एफपीआई द्वारा घबराहट में की गई बिक्री के परिणामस्वरूप भारतीय रुपए में तेज गिरावट; तथा (iii) वैश्विक डॉलर चलनिधि में गिरावट के चलते वैश्विक मंदी के भय के कारण प्रतिफलों में वृद्धि हुई। तथापि, 20 मार्च को ओएमओ खरीद की घोषणा के साथ नए बेंचमार्क प्रतिफल में 15 बीपीएस तक की गिरावट आई। हालांकि, (i) रुपये द्वारा नए न्यूनतम का कीर्तिमान स्थापित करने; तथा (ii) सरकारी प्रतिभूति की मात्रा में कमी से कीमतों में गिरावट को बढ़ावा मिलने के कारण प्रतिफलों में गिरावट अस्थायी थी। कोविड-19 से संबंधित चिंता की पृष्ठभूमि में रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 को अनेक उपायों की घोषणा की गई। इस परिवेश में, जब सरकार द्वारा अपेक्षा से अधिक उधार लेने की संभावना पर बाजार व्यग्र था, इसने रिजर्व बैंक द्वारा चुनिंदा दिनांकित प्रतिभूतियों में अनिवासियों के लिए निवेश सीमा को हटाने की नीतिगत घोषणा का स्वागत किया। समग्र रूप से, मार्च में नए बेंचमार्क में 23 बीपीएस की गिरावट आई।

प्रतिफल वक्र में वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही में प्रासंगिक परिवर्तन हुए जैसा कि इसके स्तर और ढाल से अभिलक्षित होता है (चार्ट IV.7 ए)⁷। अक्टूबर की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद प्रतिफल के औसत स्तर में 33 आधार अंकों की नरमी आई जबकि 66 आधार अंकों की तीक्ष्ण ढाल रही। फरवरी की नीतिगत घोषणा (31 मार्च 2020 तक) के बाद प्रतिफल के औसत स्तर में 24 आधार अंकों की नरमी आई जबकि 58 आधार अंकों के साथ ढलान तीक्ष्ण हुई (चार्ट IV.7बी)। सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेशक

अक्टूबर 2019 में मुद्रास्फीति नियत सीमा में रहने के साथ विदेशी संविभाग निवेशक (पीएफआई) ऋण बाजार में निवल खरीदार बने रहे। हालांकि, सरकारी वित्तपोषण के साथ-साथ मूडी द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग ("स्थिर" से "नकारात्मक") डाउनग्रेड करने की आशंका और एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग द्वारा राष्ट्रिक रेटिंग डाउनग्रेड करने के भय के कारण वे जनवरी 2020 तक निवल बिकवाल बन गए। वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में निम्न राजकोषीय घाटे के प्रस्ताव के कारण बाजार में उछाल आया जिससे एफपीआई फरवरी में निवल खरीदार बन गए। वैश्विक वित्तीय बाजारों में आई मंदी के बाद घरेलू बाजारों में हुई जबरदस्त

⁷ जहां यह स्तर परिपक्वताओं में सभी प्रतिफलों का औसत है, वहीं, ढाल को दीर्घवधि व अल्पावधि परिपक्वता (टर्म स्प्रेड) के बीच प्रतिफल के अंतर से दर्शाया जाता है।

चार्ट IV.7: जी-सेक प्रतिफल वक्र



उथल-पुथल से एफपीआई फिर से मार्च में निवल बिकवाल बन गए (चार्ट IV.8)।

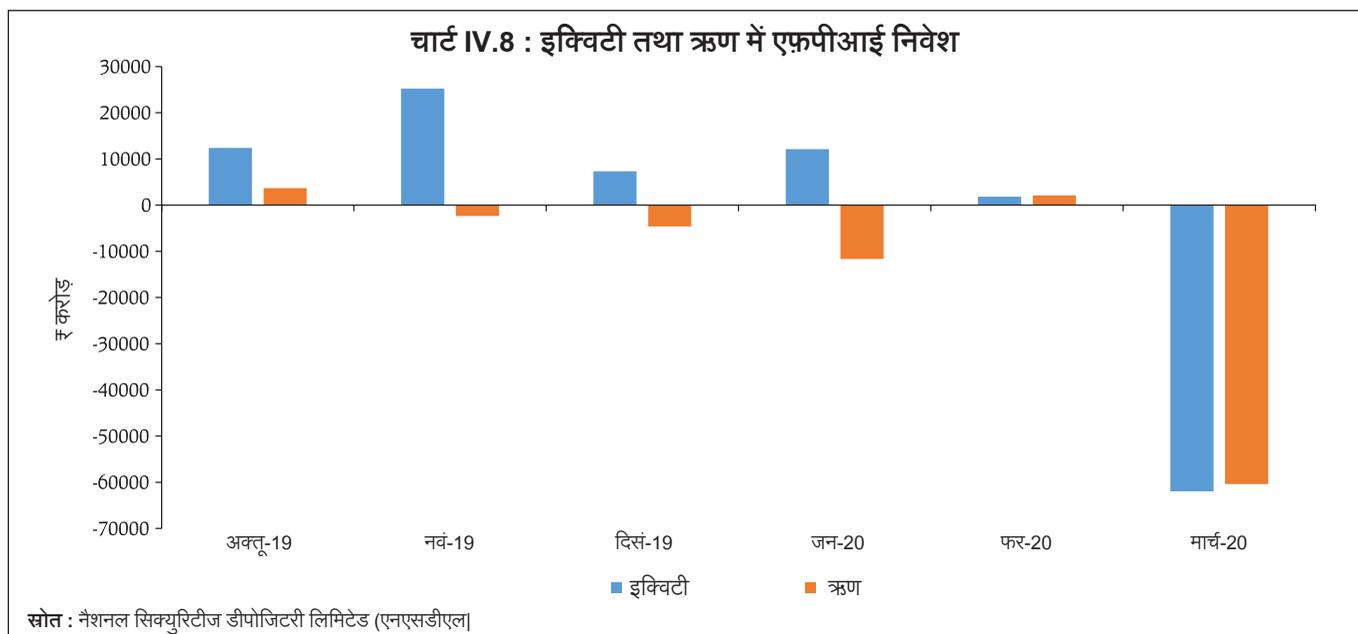
खजाना बिल

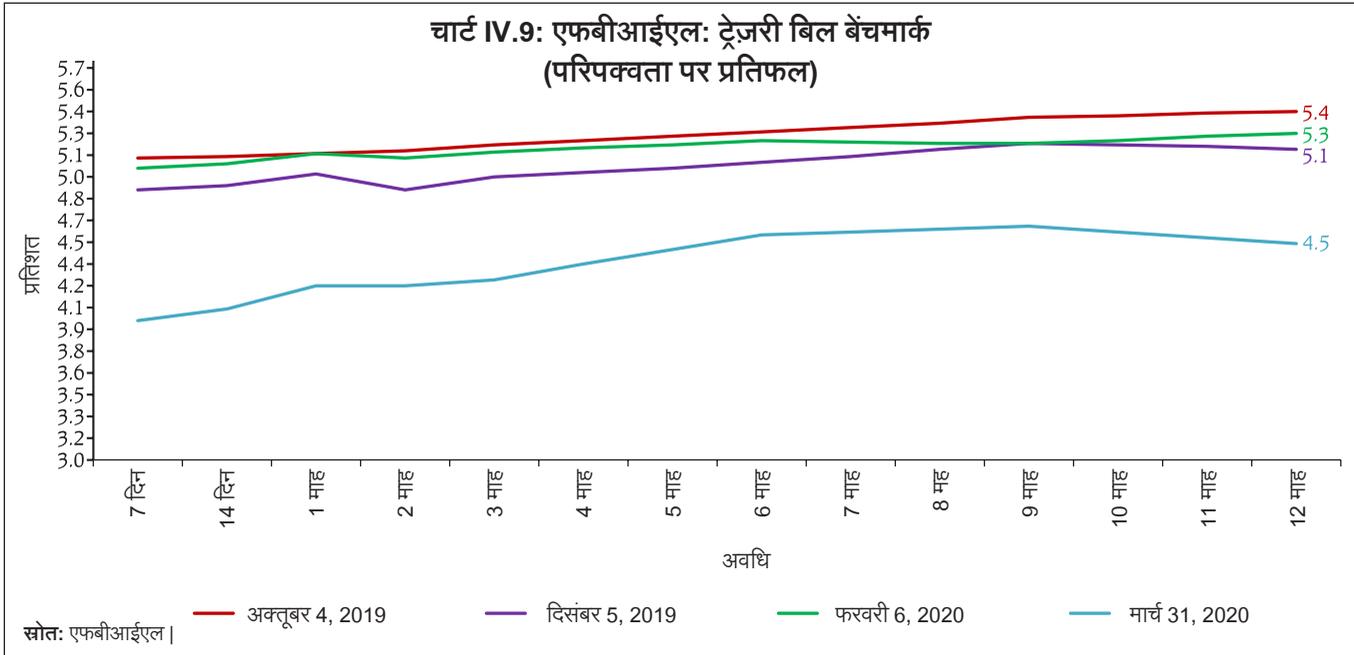
प्राथमिक खंड के लघु सिरे से पता चलता है कि बेंचमार्क पेपर का अनुसरण करने व बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि के कारण कतिपय परिपक्वताओं में रिवर्स रेपो दर से कम पर कारोबार करने से खजाना बिलों के प्रतिफलों में 2019-20 की दूसरी छमाही में नरमी आई (चार्ट IV.9)।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) का भारत औसत स्प्रेड का कट-ऑफ संबंधित जी-सेक प्रतिफलों के लिए दूसरी छमाही में बढ़कर 55 आधार अंक हो गया जो 2019-20 की पहली छमाही में 52 आधार अंक था (चार्ट IV.10)। 10 वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर - राज्य स्प्रेड पहली छमाही के 3.2 आधार अंक की तुलना में बढ़कर 7.2 आधार अंक हो गया। प्रतिभूतियों की अदला-बदली (स्विचिंग)

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान रिजर्व बैंक ने सक्रिय कर्ज समेकन के लिए ₹1,24,694 राशि के सात स्विच

चार्ट IV.8 : इक्विटी तथा ऋण में एफपीआई निवेश

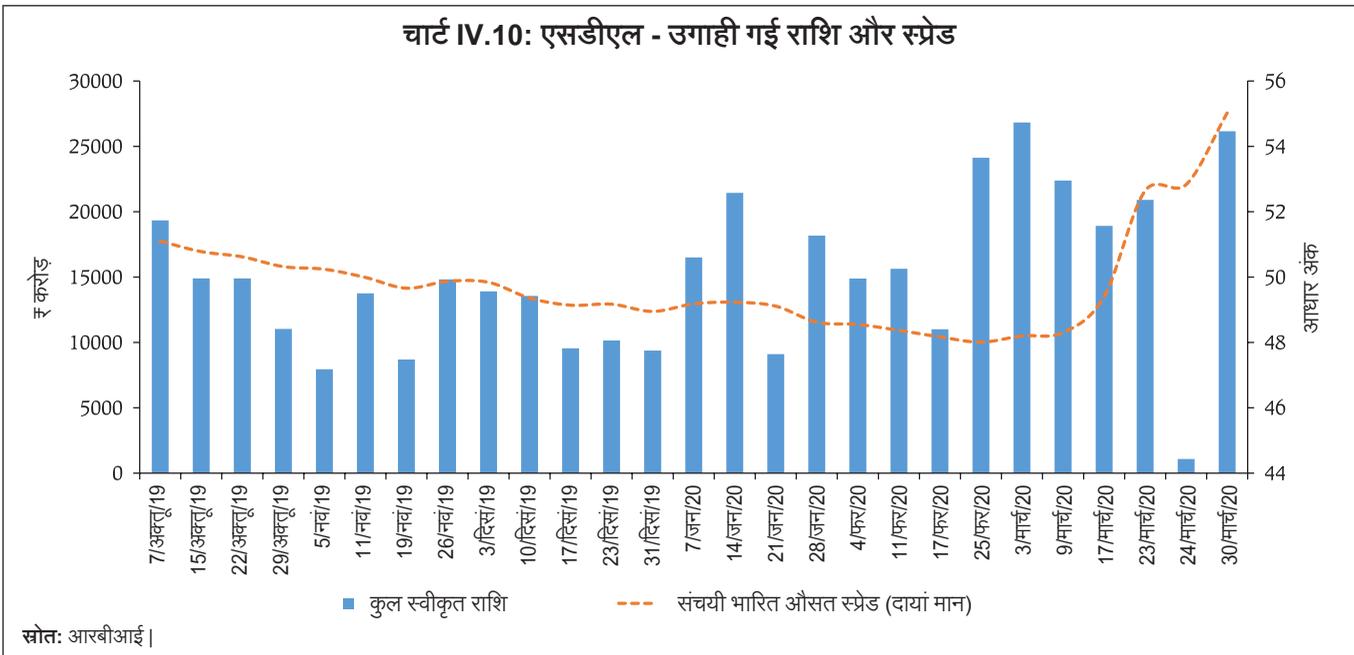




परिचालन किए। इसने सरकारी प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएम) में आंशिक योगदान दिया जिससे यह औसत जो 30 सितंबर 2019 में 10.02 वर्ष की तुलना में बढ़कर 31 मार्च 2020 को 10.54 वर्ष हो गया। 31 मार्च 2020 को भारत औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) 7.69 प्रतिशत था जो सितंबर 2019 के अंत में 7.77 प्रतिशत से कम था।

केंद्र सरकार के पास नकदी शेष

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के प्रारंभ से ही सरकार का नकदी शेष ऋणात्मक था और वह लगातार मार्च 2020 के अंत तक अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएम/ओडी) लेती रही। वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) सात बार जारी किए गए जिनकी परिपक्वता 42-84



दिनों⁸ की व संचयी राशि ₹ 2,50,000 करोड़ या वर्ष 2019-20 के सीएमबी के लिए ₹ 2,40,000 करोड़ के संशोधित अनुमान का 104.2 प्रतिशत थी।

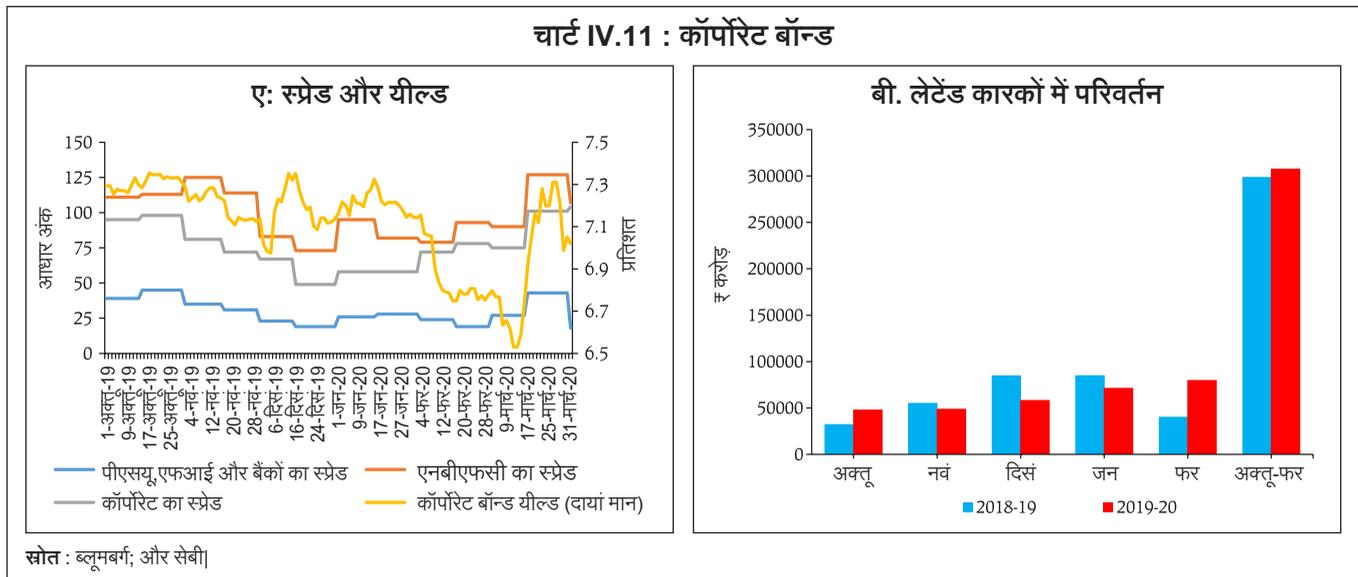
IV.1.3 कार्पोरेट बॉन्ड बाजार

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान कार्पोरेट बॉन्ड प्रतिफलों में नरमी आई जो जी-सेक प्रतिफलों के अनुसरण और अधिशेष प्रणालीगत चलनिधि स्थितियों को दर्शाती है (चार्ट IV.11ए)। एए पांच-वर्षीय कार्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल सितंबर 2019 की समाप्ति पर 7.44 प्रतिशत से 42 आधार अंक नरम होते हुए मार्च 2020 के अंत तक 7.02 प्रतिशत हो गया। समग्र रूप से एए 5- वर्षीय प्रतिफलों में वर्ष 2019-20 के दौरान 108 आधार अंकों की कमी आई जो कार्पोरेट बॉन्ड बाजार में मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के संचरण और दिसंबर 2019- मार्च 2020 के दौरान विशेष ओएमओ और एलटीआरओ नीलामियों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थाओं (एफआई) और बैंकों द्वारा जारी किए गए बॉन्डों (5- वर्षीय जी-सेक की तुलना में 5- वर्षीय एए कार्पोरेट बॉन्ड) की जोखिम प्रीमिया 26 आधार अंक कम हो गईं जबकि एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए बॉन्डों की 14 आधार अंक कम हो गईं। इसके विपरीत कार्पोरेटों द्वारा जारी किए गए बॉन्डों पर रिस्क प्रीमिया 5 आधार अंक बढ़ा दी गईं। वर्ष 2019-20 की

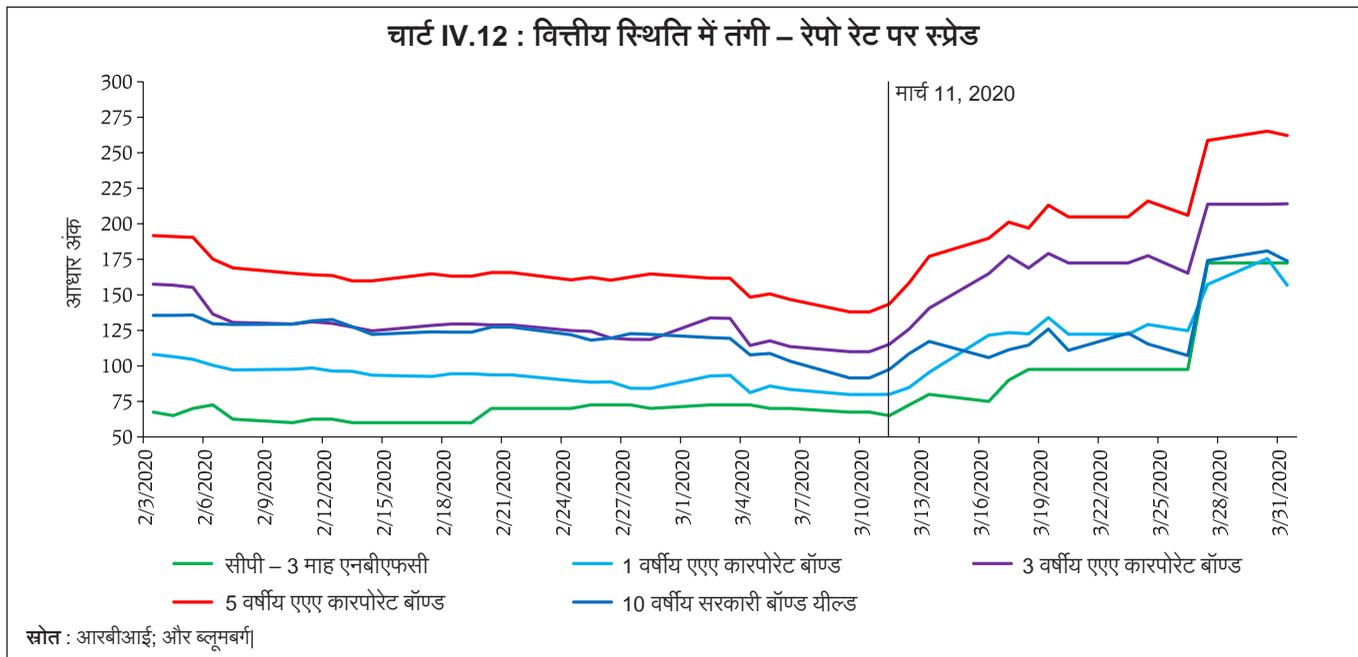
दूसरी छमाही में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का 5 - वर्षीय ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) लाभांतर क्रमशः 174 और 163 आधार अंक बढ़ गया जो एक प्रमुख निजी बैंक से बैंकिंग क्षेत्र में आए दबाव और महामारी की घोषणा को दर्शाता है।

प्राथमिक बाजार में कारपोरेट बॉन्डों के निर्गम के जरिए अक्टूबर 2019 - फरवरी 2020 के दौरान ₹ 3.1 लाख करोड़ के संसाधन जुटाए गए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए ₹ 3.0 लाख करोड़ की तुलना में 3.0 प्रतिशत अधिक था (चार्ट IV.11बी)। कार्पोरेट बॉन्ड बाजार (97.9 प्रतिशत) में लगभग सभी संसाधन जुटाना प्राइवेट प्लेसमेंट रूट के जरिए होता रहा। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को कम लागत पर वित्तपोषण का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने और खुदरा भागीदारी बढ़ाने के साथ निवेशक आधार में विविधता लाकर बॉन्ड बाजार को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का आरंभ किया। यह भारत में कारपोरेट बॉन्ड है जिसने ₹ 12,395 करोड़ जुटाए। कारपोरेट बॉन्ड में एफपीआई का निवेश सितंबर 2019 की समाप्ति पर ₹ 2.03 लाख करोड़ था जो 14.8 प्रतिशत गिरकर मार्च 2020 के अंत तक ₹ 1.73 लाख करोड़ हो गया। परिणाम स्वरूप कार्पोरेट बॉन्ड में निवेश के लिए एफपीआई की अनुमोदित सीमा का

चार्ट IV.11 : कार्पोरेट बॉन्ड



⁸ मार्च 2020 के दूसरे मध्य में अग्रिम कर के बहिर्वाह से उत्पन्न हुई चलनिधि की कमी को दूर करने के लिए सीएमबी की परिपक्वता डिजाइन की गई थी।



उपयोग सितंबर 2019 की समाप्ति पर 66.9 प्रतिशत के मुकाबले घटकर मार्च 2020 के अंत तक 54.5 प्रतिशत रह गया। कारपोरेट बाजार में औसत दैनिक टर्नओवर वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही (6 मार्च 2020 तक) में बढ़कर ₹ 8,460 करोड़ हो गया जबकि वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही की समान अवधि में यह ₹ 7,097 करोड़ था।

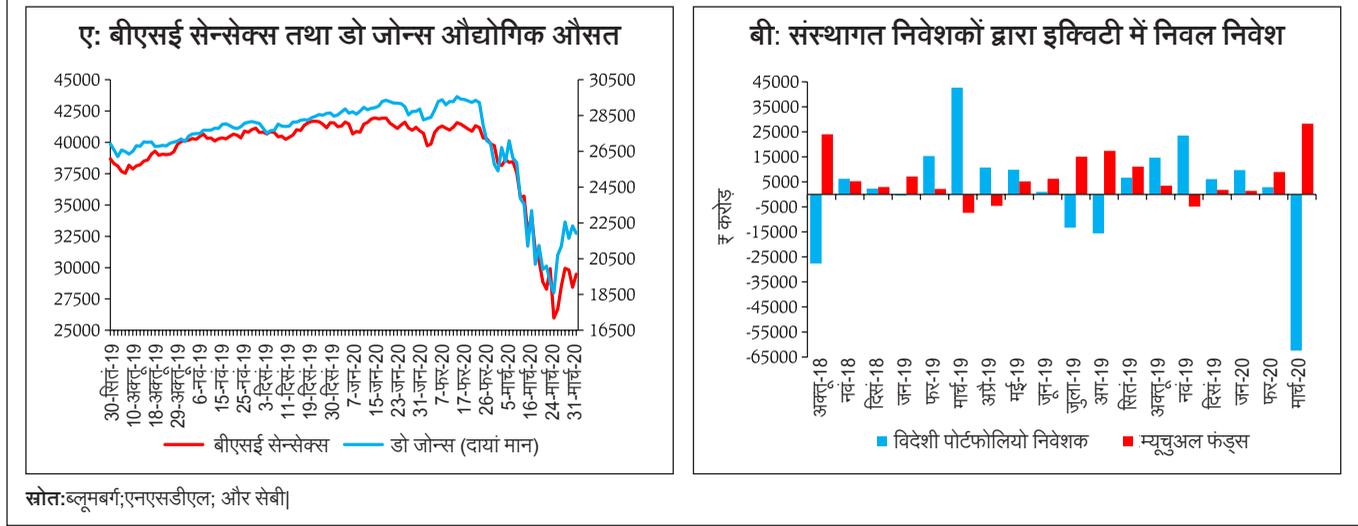
11 मार्च को कोविड-19 की महामारी के रूप में घोषणा के बाद वैश्विक वित्तीय बाजार मंदी की चपेट में आ गए। भारी वैश्विक उथल-पुथल के कारण 11 मार्च 2020 से भारत की वित्तीय स्थिति अत्यंत तंग हो गई (चार्ट IV.12)। 11-31 मार्च के दौरान द्वितीयक बाजार का स्प्रेड, जो नीतिगत रेपो दर पर एनबीएफसी के 3 माह की सीपी दर होता है, 108 आधार अंक बढ़ गया जबकि 1- वर्षीय 3-वर्षीय और 5- वर्षीय एए कारपोरेट बॉण्ड की परिपक्वता क्रमशः 77, 99 व 119 आधार अंक बढ़ गई। इसी अवधि में नीतिगत रेपो दर पर 10 वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क स्प्रेड 76 आधार अंक बढ़ गया। बिगड़ती वित्तीय स्थिति के लिए बाहरी और घरेलू दोनों ही कारक जिम्मेदार हैं। वैश्विक बाजार में उथल-पुथल के कारण एफपीआई ने अपनी आस्तियों को सुरक्षित करने के लिए घबराहट में बिकवाली की, जबकि म्यूचुअल फंडों के निवेशकों द्वारा मोचन दबावों की प्रत्याशा में चलनिधि बफर का निर्माण करने के लिए अपनी चलनिधि स्थिति को मजबूत बनाया।

IV.1.4 इक्विटी बाजार

भारतीय इक्विटी बाजार, जिसने जनवरी 2020 मध्य तक बड़े पैमाने पर लाभ कमाया, में कोविड-19 के कारण वैश्विक बाजार में आई मंदी का अनुसरण करने से 2019-20 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में गिरावट दर्ज हुई। बीएसई सूचकांक ने 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान 40,000 के स्तर को छुआ था परंतु 2019-20 की चौथी तिमाही में जबरदस्त दबाव में आ गया। सकल रूप से 2019-20 की दूसरी छमाही में सूचकांक में 23.8 प्रतिशत की गिरावट हुई (चार्ट IV.13 ए)।

अमेरिका- चीन के बीच व्यापार समझौते और यूके व यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट समझौते के करार से उत्पन्न नए आशावाद से वैश्विक बाजार में सकारात्मक वातावरण निर्माण के कारण बीएसई सूचकांक ने फिर से 40,000 के स्तर को प्राप्त कर लिया। यह बढ़त नवंबर और दिसंबर में भी जारी रही जो भारत सरकार द्वारा वृद्धि के उपायों को बढ़ावा देने से समर्थित थी। इन उपायों में शामिल थे - दीवाला और शोधन अक्षमता कोड में संशोधन को समर्थन और सरकारी बैंकों के लिए एनबीएफसी से पूल्ड आस्तियां क्रय करने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना का अनुमोदन। इसके अलावा, यूएस फेडरल के शिथिल परिदृश्य, यूएस-चीन के बीच व्यापार समझौतों का पहला चरण और यूके के चुनाव में ब्रेक्जिट के समर्थन से निकले सकारात्मक वैश्विक संकेतों से बाजार को गति मिली।

चार्ट IV.13: स्टॉक मार्किट सूचियाँ और निवेश



इस पृष्ठभूमि में कि विश्व में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थीं, नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ था, अधिकतम जीएसटी वसूली हुई थी तथा दिसंबर में क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में विस्तार हुआ था जिससे सेंसेक्स 14 जनवरी, 2020 को 41953 की रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था, इक्विटी बाज़ार में जनवरी 2020 के मध्य तक तेज़ी लगातार बनी रही थी। लेकिन, अमरीका और ईरान के बीच भू-राजनैतिक तनाव बढ़ जाने के चलते, घरेलू स्तर पर जीडीपी वृद्धि की धीमी संभावनाएं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 2019-20 के लिए भारत की संवृद्धि के बारे में दिए गए निम्नगामी अनुमान से बाज़ार की स्थिति मुरझा सी गई थी।

इस गिरावट के दबाव से सेंसेक्स 1 फरवरी, 2020 को 988 अंक (2.4 प्रतिशत) गिर गया क्योंकि संघीय बजट 2020-21 में किए गए प्रस्ताव बाज़ार की अपेक्षाओं पर पूरे नहीं लग रहे थे। लेकिन, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, जनवरी 2020 के लिए तीव्र पीएमआई डाटा प्रकाशित होने तथा 6 फरवरी, 2020 को क्रेडिट एवं चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा के चलते बाज़ार में वी-आकार की बहाली देखी गई है। बाद में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विश्व बाज़ार की प्रतिक्रिया के अनुसार ही भारतीय इक्विटी बाज़ार ने भी अपने हाथ खींच लिए थे।

मार्च, 2020 के दौरान भारत सहित विश्व में सभी स्थानों पर बढ़ती हुई जोखिम विमुखता से इक्विटी बाज़ारों में अपविक्रय होने लगा था। 12 मार्च, 2020 को बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2919 अंक (8.2 प्रतिशत) लुढ़क गया था। बाज़ार की भावनाओं ने अगले दिन

की स्थिति और बदतर कर दी क्योंकि बाज़ार कारोबार के प्रारंभिक समय में ही 10 प्रतिशत गिर गया, जिसके कारण कारोबार की सर्किट रोकनी पड़ी और कारोबार को 45 मिनट तक स्थगित रखना पड़ा। ऐसा सेबी द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद हुआ जिसमें सेबी ने यह संकेत दिए कि भारतीय स्टॉक सूचकांक में होने वाली गिरावट बहुत से अन्य देशों की गिरावट से कहीं कम थी तथा बाज़ार के सहभागियों को आश्चस्त किया था कि यदि आवश्यक हुआ तो उपयुक्त एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। बाज़ार, दिन की समाप्ति पर दुबारा बहाल हुआ पूरे 1325 (4.0 प्रतिशत) अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, यह किसी एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी बहाली थी। लेकिन, बाद में मंदी का रुख वापस छा गया जिसके कारण इस प्रकार हैं (i) विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट; (ii) भारत में कोविड-19 मामलों के बढ़ने की रिपोर्ट; (iii) एक निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा उत्पन्न किए गए संकट के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव बनना; और (iv) पूरे विश्व में मंदी छा जाने के प्रति बढ़ती चिंताएं। परिणामस्वरूप, भारतीय इक्विटी बाज़ार ने मार्च 2020 में दूसरी बार न्यूनतम सर्किट का अतिक्रमण कर लिया और साथ ही बीएसई सूचकांक में 23 मार्च, 2020 को 3,935 अंकों (13.2 प्रतिशत) की सबसे भारी गिरावट दर्ज की गई। सरकार द्वारा कारपोरेट्स एवं करदाताओं के लिए विनियामकीय अंतिम तारीखों को बढ़ाने और मानदंडों में रियायत देने की घोषणा के बाद सरकार से राजकोषीय उपायों की उम्मीदों के बीच बाज़ार में बहाली लौटी। उसके बाद, और अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षाओं ने बाज़ार की भावनाओं

में तेज़ी पैदा कर दी। रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में काफी कमी किए जाने के साथ-व्यापक स्तर पर चलनिधि उपायों की घोषणा किए जाने के बावजूद 27 मार्च को बीएसई सेंसेक्स में मामूली गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स में मार्च 2020 के दौरान 23.0 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई।

दूसरी छमाही में, भारतीय इक्विटी बाज़ार में म्यूचुअल फंड में 38,989 करोड़ रुपए (30 मार्च तक) तक के निवल क्रेता थे, जबकि एफपीआई में 5,599 करोड़ रुपए के निवल विक्रेता थे (चार्ट IV.13 बी)। विशेष रूप से निवल विक्रेताओं ने अत्यधिक बिक्री की और मार्च 2020 में निवल बिक्री 62,433 करोड़ रुपए की थी।

इक्विटी बाज़ार के प्राइमरी खंड में इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम (प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और राइट्स निर्गम) के माध्यम से अक्टूबर 2019-फरवरी 2020 के दौरान 6,176 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए गए जो धीमे बने रहे थे (हालांकि यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 3,429 करोड़ रुपए से अधिक था)।

IV.1.5 विदेशी मुद्रा बाज़ार

भारतीय रुपया अनेक कारकों की वजह से 2019-20 की दूसरी छमाही में अस्थिर बना रहा जिसका संदर्भ आगे के भागों में प्रस्तुत किया गया है तथा इक्विटी बाज़ार में अत्यधिक अस्थिरता

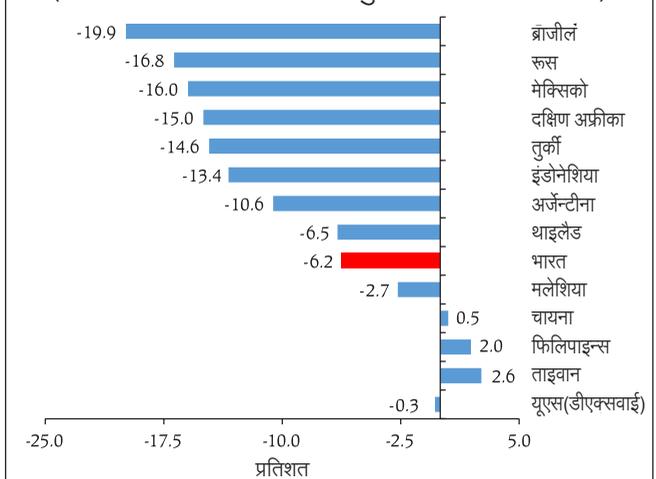
रही है। पोर्टफोलियों निवेश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फलस्वरूप, ईएमई करेंसियां भारतीय रुपया सहित मार्च में तेज़ी से कमज़ोर हो गईं, जिनमें रुपया का मूल्यहास हुआ और 24 मार्च 2020 को 76.15 रुपए के न्यूनतम स्तर पर आ गया। जहां वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही (सितंबर 2019 के अंत की तुलना में मार्च 2020 के अंत में) में अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपया का मूल्यहास 6.2 प्रतिशत हुआ वहीं यह गिरावट अनेक ईएमई समकक्ष समूह जैसे थाई बेहत, अर्जेंटीना पेसो, इंडोनेशियाई रुपियह, तुर्की लीरा, दक्षिण अफ्रीका रैंड, मेसक्को पेसो, रूस का रूबल तथा ब्राजील के रीयल की तुलना में कम रही थी (चार्ट IV.14ए)।

36-करेंसीय सांकेतिक प्रभावी विनमय दर (नीयर) के अनुसार भारतीय रुपया में मूल्यहास 2.9 प्रतिशत (सितंबर 2019 के औसत की तुलना में मार्च 2020 के अंत में) हुआ था। भारतीय रुपए का इसी अवधि में 36-करेंसीय वास्तविक प्रभावी विनमय दर (रीयर) के अनुसार मूल्यहास 1.3 प्रतिशत हुआ था (सारणी IV.2)।

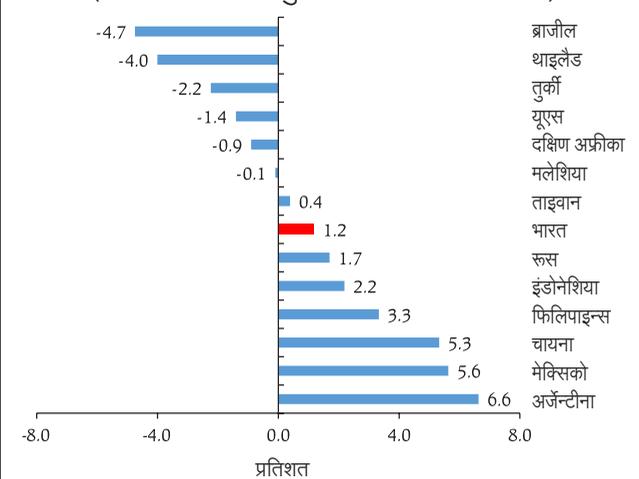
सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान रीयर के अनुसार भारतीय रुपए में मूल्यवर्धन रूस के रूबल, इंडोनेशिया के रुपियह, फिलीपीन के पेसो, चीन के युआन, मेक्सिको के पेसो तथा अर्जेंटीना के पेसो की तुलना में कम हुआ था (चार्ट IV.14 बी)।

चार्ट IV.14 : विभिन्न मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव

ए : यूएस डॉलर की तुलना में प्रमुख ईएमई मुद्राओं में उतार-चढ़ाव (30 सितंबर, 2019 के अंत की तुलना में मार्च 2020 को)



बी: आरईईआर में उतार-चढ़ाव (सितंबर 2019 की तुलना में फरवरी, 2020 को)



स्रोत: आरबीआई; एफबीआईएल; आईएमएफ; ब्लूमबर्ग; थॉमसन रूटर्स; और बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)।

सारणी IV.2: नाममात्र तथा वास्तविक प्रभावी विनिमय दरें – व्यापार-आधारित भार

(आधार : 2004-05=100)

मद	सूचकांक : मार्च, 2020 अंत को (पी)	वृद्धि (+) / कमी (-) (प्रतिशत)
		सितंबर (औसत) 2019 की तुलना में मार्च 2020 अंत को
36-करेंसी आरईईआर	114.6	-1.3
36-करेंसी एनईईआर	71.1	-2.9
6- करेंसी आरईईआर	120.3	-4.5
6- करेंसी एनईईआर	60.3	-5.5
₹/यूएस \$	75.4	-5.4

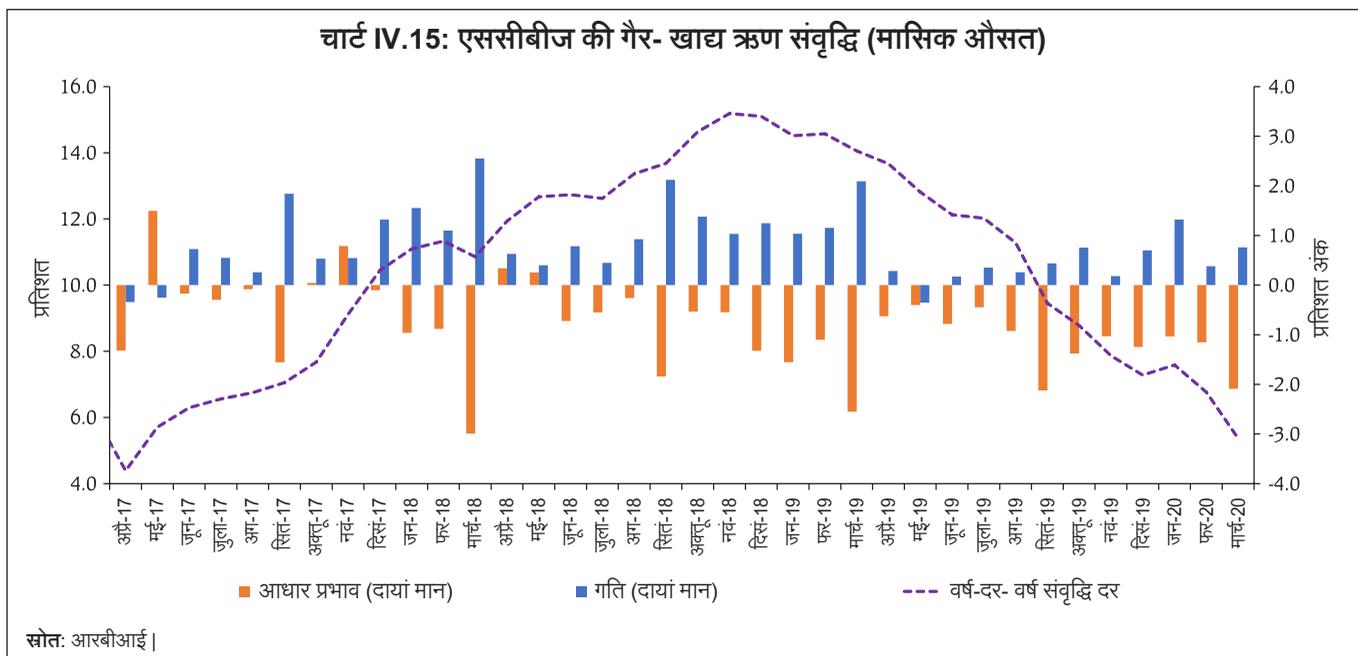
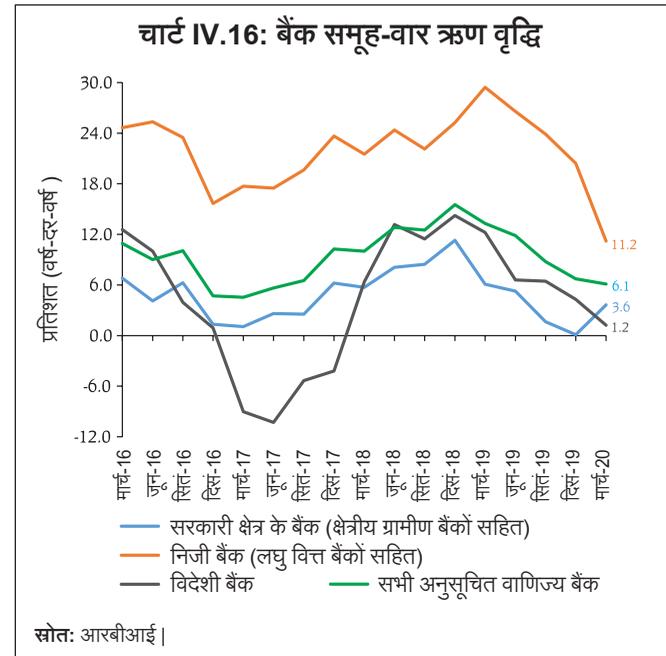
पी: अन्तिम

स्रोत: आरबीआई; और एफबीआईएल |

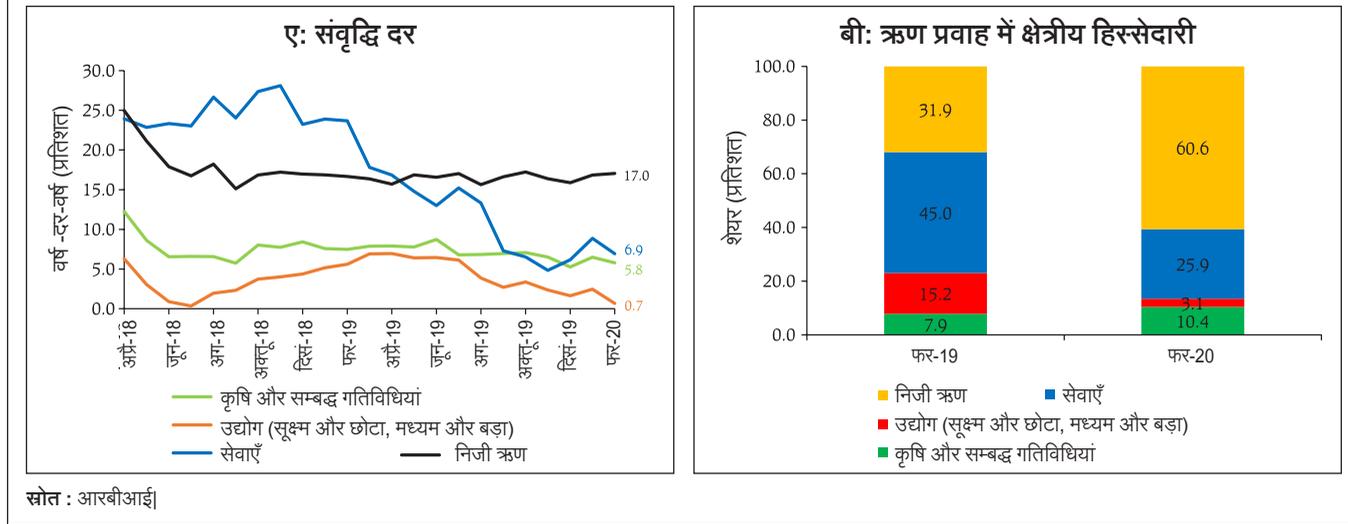
IV.1.6 क्रेडिट बजार

2019-20 (13 मार्च, 2020 तक) में क्रेडिट उठाव शांत रहा था जिसमें खाद्येतर क्रेडिट वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 14.4 प्रतिशत की वृद्धि के आधे से भी कम थी। इसमें एक तो धीमी गति तथा प्रतिकूल आधारगत प्रभाव दोनों कार्य कर रहे थे (चार्ट IV.15)। 2019-20 की तीसरी तिमाही में मौसमी गिरावट एक वर्ष पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी, जबकि 2019-20 की चौथी तिमाही (13 मार्च तक) में उठाव पिछले दो वर्ष की इसी अवधि के उठाव की तुलना में धीमा था।

क्रेडिट वृद्धि में धीमापन सभी बैंक समूहों में, खासतौर से निजी क्षेत्र के बैंकों में पाया जा रहा था। सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में क्रेडिट वृद्धि मंद ही बनी रही, हालांकि हाल के समय में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रेडिट में थोड़ा सा उभार दिखाई दिया था (चार्ट IV.16)। वर्ष के दौरान (15 मार्च 2019 से 13 मार्च, 2020 तक) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए वृद्धिशील क्रेडिट में 62.6 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा,



चार्ट IV.17: क्रेडिट का क्षेत्रीय परिनियोजन



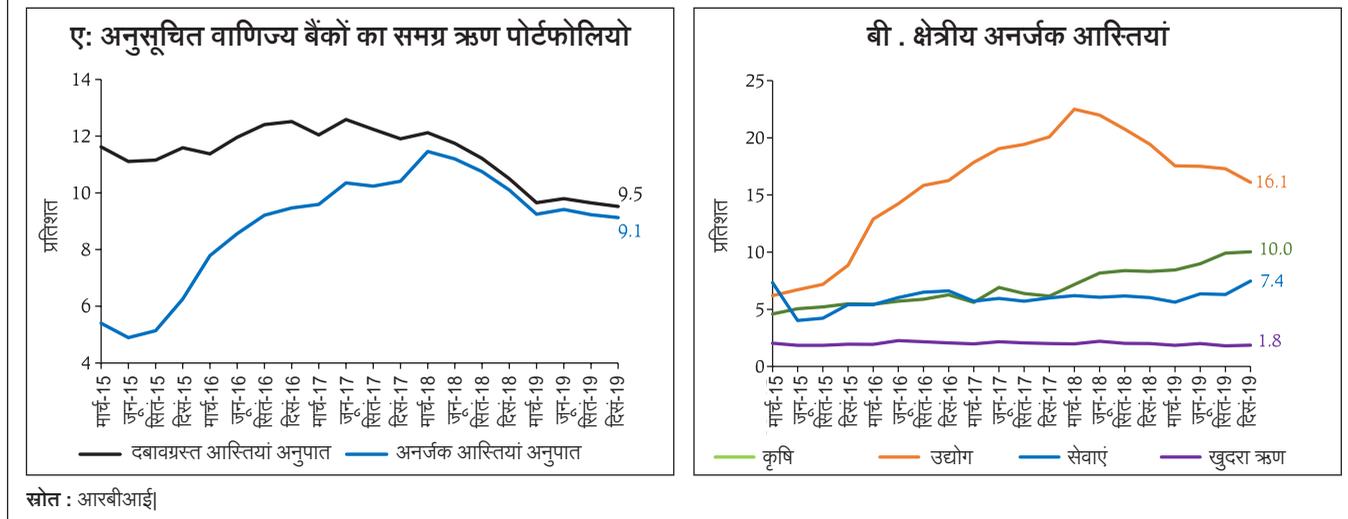
36.6 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा और 0.8 प्रतिशत विदेशी बैंकों द्वारा क्रेडिट दिए गए थे।

जहां वैयक्तिक ऋण में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) फरवरी 2019 के 16.7 प्रतिशत की तुलना में फरवरी 2020 में मामूली सी वृद्धि के साथ 17.0 प्रतिशत थी, वहीं कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में क्रेडिट में वृद्धि पिछले पांच वर्ष में धीमी रही है। हालांकि सेवा क्षेत्र में जनवरी 2020 में क्रेडिट में वृद्धि दिखाई दी थी, लेकिन फरवरी 2020 में वह दुबारा कमजोर पड़ गई (चार्ट IV.17ए)। वैयक्तिक ऋण खंड में क्रेडिट के उठाव का हिस्सा सबसे अधिक था (चार्ट IV.17बी)। वैयक्तिक ऋण खंड में क्रेडिट मुख्यतया आवास

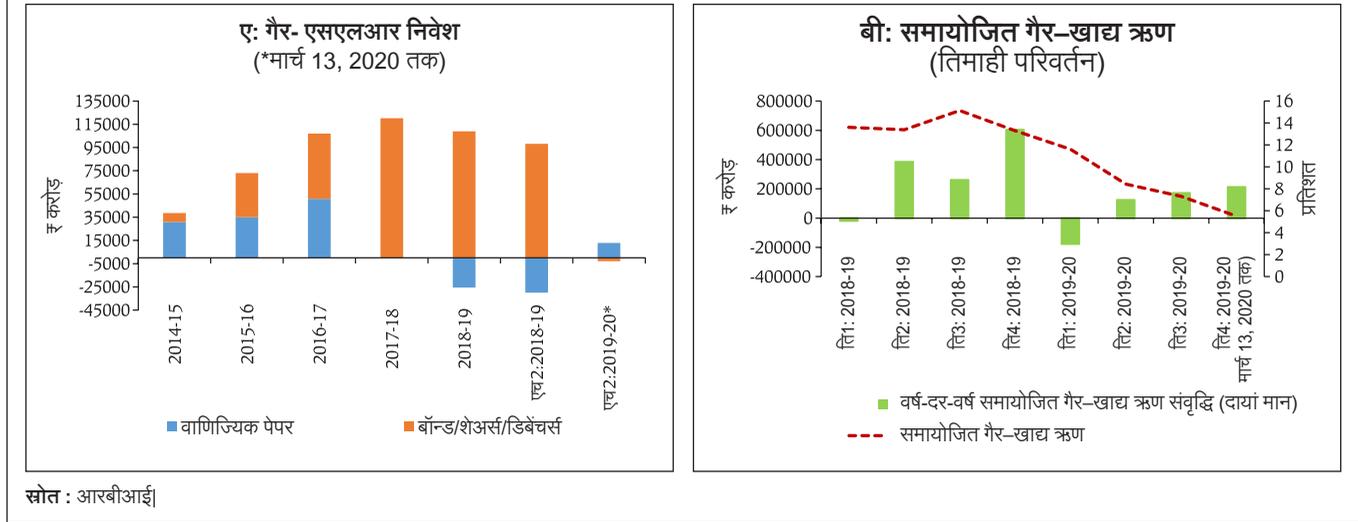
एवं क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए उठाया गया था। उद्योग के भीतर, पेय पदार्थों एवं तंबाकू के लिए क्रेडिट में वृद्धि तेज हुई थी, लेकिन रसायन और रसायन उत्पाद, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, निर्माण एवं अवसंरचना में क्रेडिट का प्रवाह कम हुआ था। सामान्य धातु एवं धातु उत्पाद, सूती वस्त्र, खाद्यान्न प्रसंस्करण तथा समस्त अभियांत्रिकी में क्रेडिट फरवरी 2020 में घट गयी थी।

जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के अनुपात मार्च 2019 के अंत से दिसंबर 2019 (चार्ट IV.18ए) तक अपरिवर्तित रहे, वहीं उद्योगों के संबंध में एनपीए अनुपात में गिरावट हुई (चार्ट IV.18बी)।

चार्ट IV.18 : दबावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां



चार्ट IV.19: गैर- एसएलआर निवेश और समायोजित गैर-खाद्य ऋण



सीपी, बॉन्ड, डिबेंचर और सरकारी तथा निजी कॉरपोरेट के शेयरों में बैंकों के – गैर-एसएलआर में परिलक्षित - वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान (13 मार्च तक) किए गए निवेश एक वर्ष पहले की तुलना में कम रहा जो कि प्रमुख रूप से बॉन्डों / शेयरों तथा डिबेंचरों में कम निवेश के कारण था (चार्ट IV.19ए)। परिणामस्वरूप, समायोजित गैर-खाद्य ऋण वृद्धि 2019-20 की तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही (13 मार्च तक) में कम रही (चार्ट IV.19 बी)।

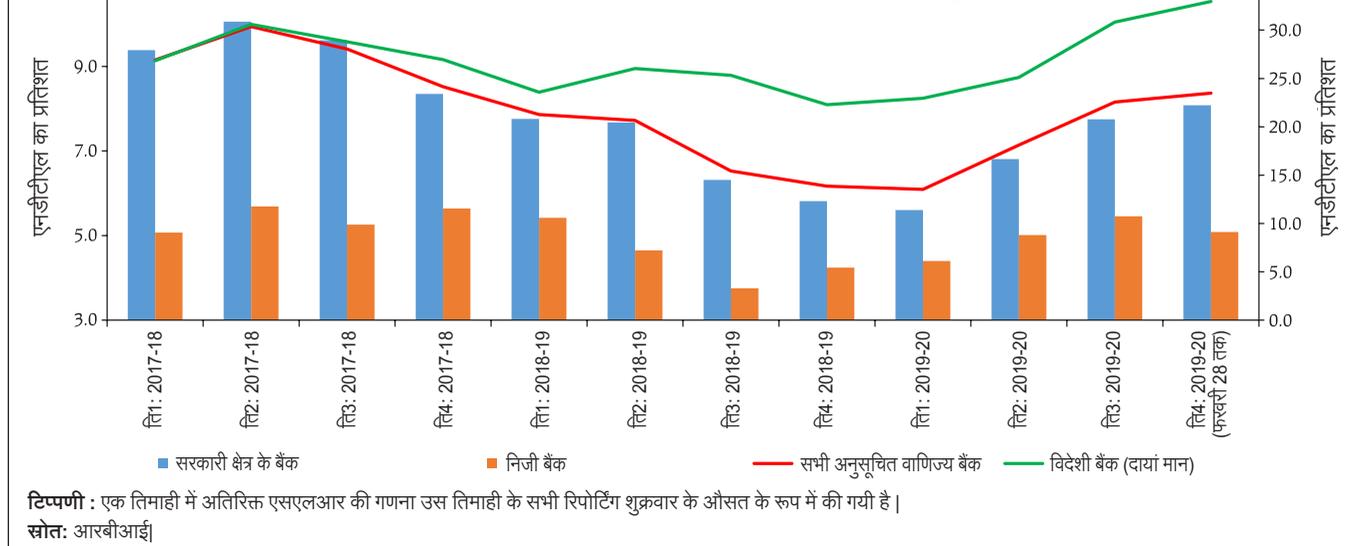
ऋण प्रसार (ऑफ टेक) के कम रहने तथा गैर-एसएलआर निवेशों में गिरावट के कारण बैंकों ने अपने एसएलआर पोर्टफोलियो

को संवर्धित किया। बैंकों ने मार्च 2019 के अंतिम में एनडीटीएल के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 28 फरवरी 2020 को निवल मांग और समयबद्ध देयता (एनडीटीएल) के 8.4 प्रतिशत का अतिरिक्त एसएलआर रखा (चार्ट IV.20)।

IV.2 मौद्रिक नीति संचरण

अक्तूबर 2019 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट के बाद से, बैंकों की सावधि जमाराशियों और उधारों पर ब्याज दरों में मौद्रिक नीति संचरण सुधरा है (सारणी IV.3)। बकाया रुपया जमाराशियों पर भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) के लिए नीतिगत दर में की गई कटौती के पास-श्रुं में पिछले आठ

चार्ट IV.20: बैंकों का अतिरिक्त सांविधिक चलनिधि अनुपात



सारणी IV.3: जमा तथा उधार दरों की ओर संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मियादी जमा दरें		उधार दरें		
		माध्यिका मियादी जमा दर	डब्ल्यूएडी-टीडीआर	1-वर्षीय माध्यिका एमसी-एलआर	डब्ल्यूए-एलआर - बकाया रुपए ऋण	डब्ल्यूए-एलआर - नए रुपए ऋण
फरवरी – सितंबर 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टूबर 2019 – मार्च 2020*	-100	-29	-39	-30	-18	-31
फरवरी 2019 – मार्च 2020*	-210	-48	-46	-60	-16	-71

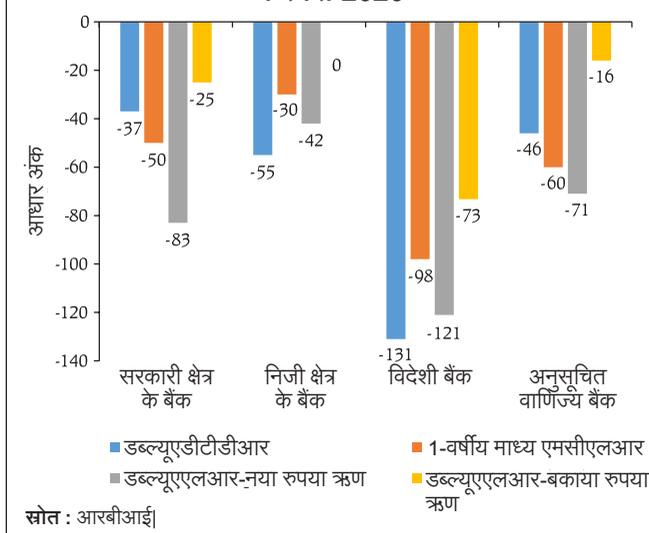
* डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूडीटीआर पर अद्यतन डाटा फरवरी 2020 से संबन्धित है। डब्ल्यूडीटीआर : भारित औसत घरेलू मियादी जमा दर। डब्ल्यूएलआर : भारित औसत उधार दर। एमसीएलआर : निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत।
स्रोत: आरबीआई।

महीनों (फरवरी-सितंबर 2019) के नाममात्र के 7 आधार अंक से अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान 39 आधार अंक का सुधार हुआ, परिणामस्वरूप 46 आधार अंकों की समग्र कमी हुई। बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में भी फरवरी से सितंबर 2019 के दौरान 2 आधार अंक की बढ़त के विपरीत अक्टूबर 2019 से 18 आधार अंक की गिरावट हुई। नया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में 71 आधार अंक (फरवरी 2019 से फरवरी 2020) की गिरावट हुई। इसमें से 31 आधार अंक की गिरावट अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान हुई।

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान बैंकों की जमाराशियों तथा उधारों पर ब्याज दरों में संचरण में सुधार पिछली दर में कटौती (फरवरी से सितंबर 2019 के दौरान 110 आधार अंक) के अवरुद्ध प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही, चयनित क्षेत्रों अर्थात खुदरा ऋण और सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए नई फ्लोटिंग दर पर ऋणों के मूल्य निर्धारण के लिए 1 अक्टूबर 2019 से बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत भी हुई।⁹

⁹ मध्यम उद्यमों के ऋण को भी 1 अप्रैल 2020 से एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है।

चार्ट IV.21: ईजिंग साइकल के दौरान बैंक समूहों में संचरण: फरवरी 2019 – फरवरी 2020

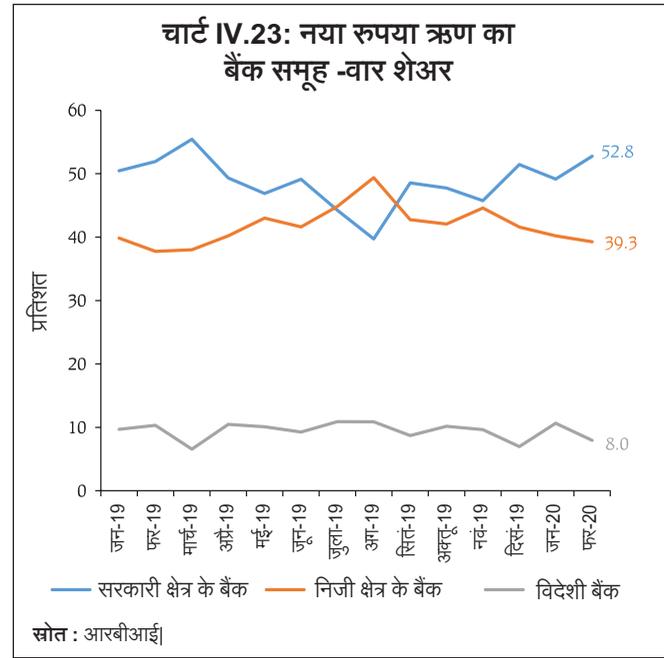
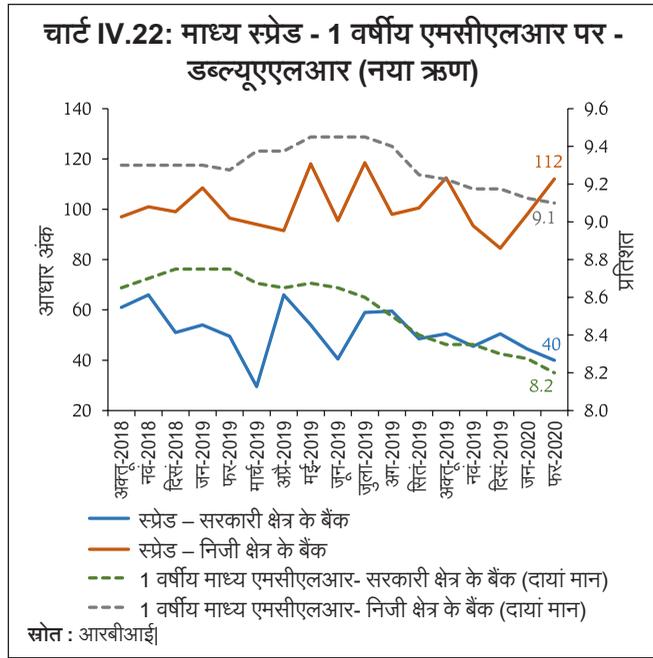


फरवरी 2019 से फरवरी 2020 के दौरान नए रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में सभी बैंक समूहों में गिरावट हुई। विदेशी बैंकों के मामले में सबसे अधिक तथा इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गिरावट आई।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा चार्ज किए गए माध्यक लाभांतर¹⁰ {1 वर्षीय निधि आधारित उधार देने की दर की माध्यक सीमांत लागत (एमसीएलआर) पर नए ऋणों पर डब्ल्यूएलआर} अधिक थी जो अन्य बातों के साथ-साथ उधारी पोर्टफोलियो में अंतर को दर्शाता है (चार्ट IV.22)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, क्रेडिट कार्ड तथा अन्य व्यक्तिगत ऋणों जैसे क्षेत्रों के संबंध में क्षेत्र-विशिष्ट की डब्ल्यूएलआर सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के समग्र डब्ल्यूएलआर की तुलना में अधिक थी। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत समग्र ऋणों में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को ऋण का हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक था।

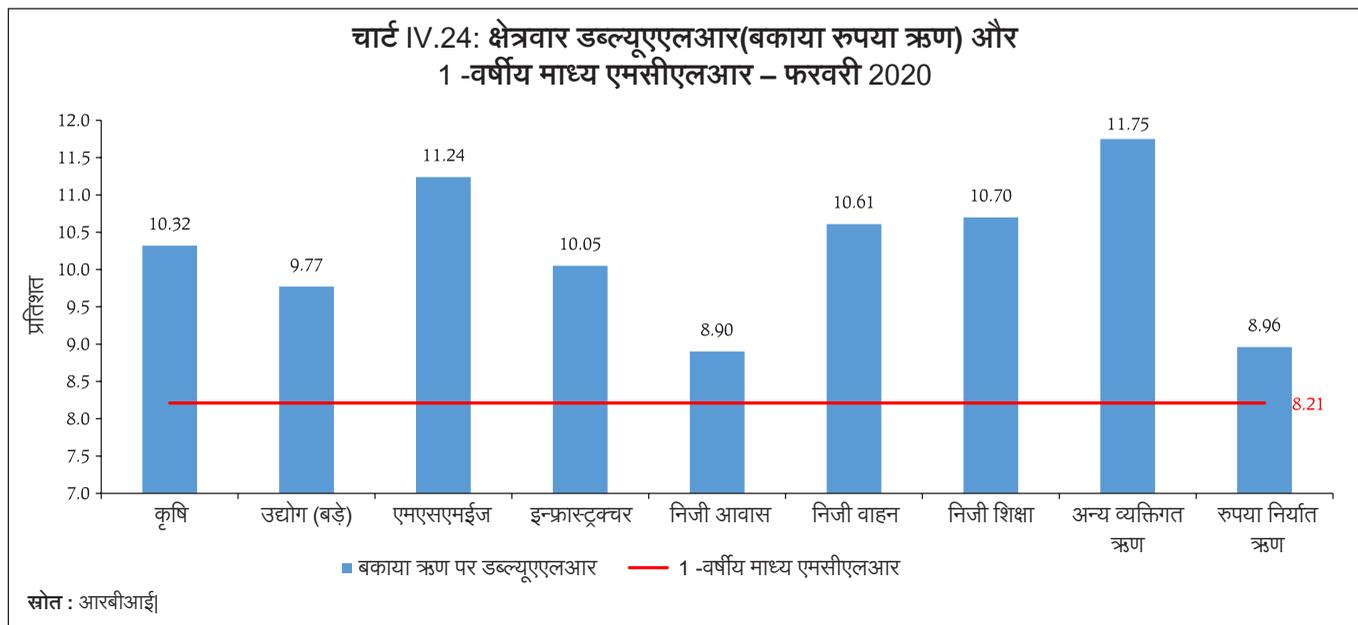
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत नए रुपया ऋणों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी अप्रैल-अगस्त 2019 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के तुलनीय थी, भले ही

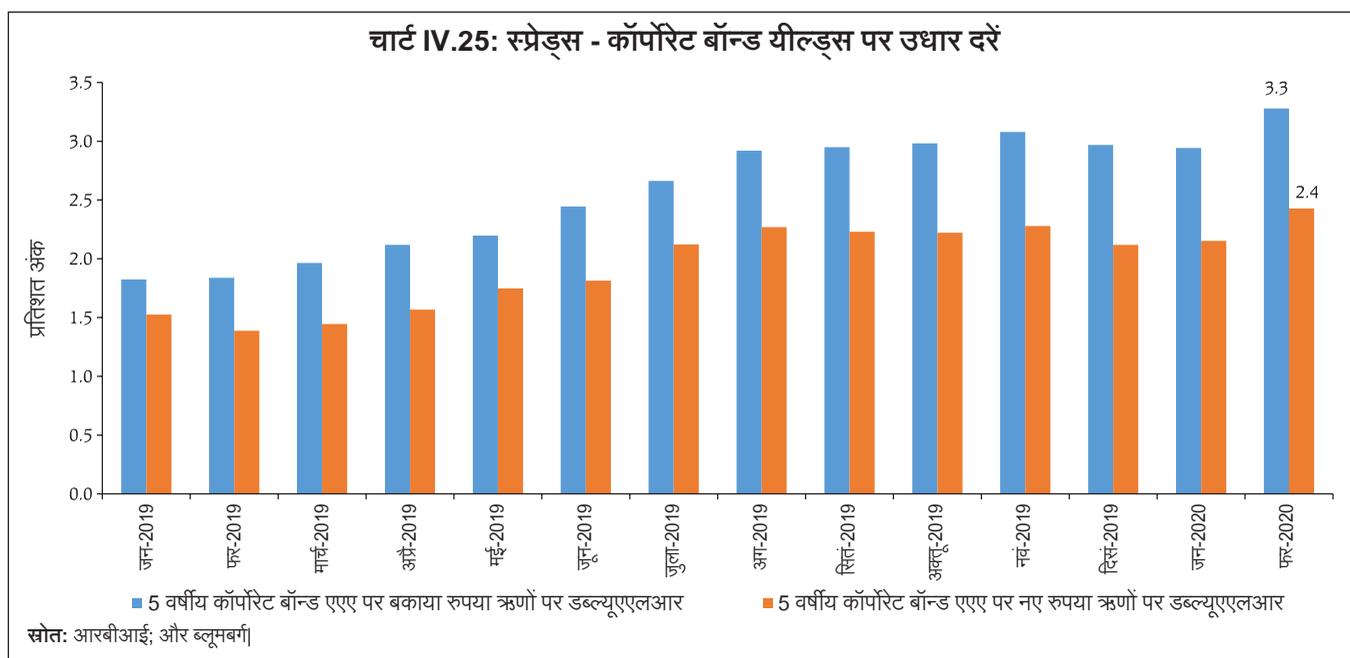
¹⁰ एक बैंक समूह का माध्यक लाभांतर उसी समूह के अंदर प्रत्येक बैंक के लाभांतर (नए रुपया ऋण पर डब्ल्यूएलआर और 1 वर्षीय एमसीएलआर के बीच अंतर) से आकलित होता है।



सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाया ऋण में काफी बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियां उच्चतर रही है तथा पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) कम रहा है। इसके बावजूद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत समग्र नए रुपया ऋणों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 39.7 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़कर अगस्त 2019 में 52.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.23)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रभारित 1 वर्षीय एमसीएलआर पर बकाया रुपया ऋणों पर लाभांतर अर्थात डब्ल्यूएलआर आवासन ऋणों के संबंध में सबसे कम थे जो चूक की कम संभावना तथा संपार्श्विक की उपलब्धता के साथ-साथ एनबीएफसी से प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाते हैं (चार्ट IV.24)। आवासन, वाहन और शिक्षा के इतर व्यक्तिगत ऋण अधिकांशतः असुरक्षित है और इसमें उच्च ऋण जोखिम शामिल रहते हैं इसलिए, 'अन्य व्यक्तिगत ऋणों' के लिए प्रभारित लाभांतर अधिकतम था।





ऋण बाजार और कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफलों में उधार दरों के बीच स्प्रेड जनवरी 2019 से तेजी से बढ़ गया है जिससे ऋण बाजार के अपेक्षाकृत कम संचरण के विपरीत कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में नीतिगत दर में कटौती का तेजी से संचरण होता है (चार्ट IV.25)।

बैंकिंग क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2019 को बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के पश्चात 62 बैंकों में से 36 बैंकों की जानकारी एकत्रित की गई थी जिन्होंने खुदरा और एमएसई क्षेत्रों के फ्लोटिंग दर वाले ऋणों के लिए बाहरी बेंचमार्क के रूप में नीतिगत रिपो दर को अपनाया (सारणी IV.4)। छह बैंकों ने अपने ऋणों को वित्तीय

बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित विभिन्न अन्य बेंचमार्क जैसे कि सीडी दर, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, मुंबई अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (मिबोर) और 3 महीने के टी-बिल से जोड़ा है। ग्यारह बैंकों ने अलग-अलग क्षेत्रों को अलग-अलग बेंचमार्कों से संबद्ध किया है।

नीतिगत रिपो दर (अर्थात रिपो दर पर माध्यक डब्ल्यूएएलआर) से जुड़े हुए नए रुपया ऋण के संबंध में माध्यक अंतराल 'अन्य व्यक्तिगत ऋणों' के लिए अधिकतम था (सारणी IV.5)। बैंक समूहों में, विभिन्न श्रेणी के ऋणों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा चार्ज किया गया माध्यक अंतराल निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कम था।

सारणी IV.4: वाणिज्यिक बैंकों के बाहरी बेंचमार्क: फरवरी 2020

बैंक समूह	नीति रिपो दर	सीडी दर	ओआई एस दर	एमआई बीओ आर	3-माह टी-बिल दर	क्षेत्र-विशिष्ट बेंचमार्क
सरकारी क्षेत्र के बैंक (15)	14	-	-	-	-	1
निजी बैंक (20)	15	1	-	-	-	4
विदेशी बैंक (27) [@]	7	-	1	1	3	6
वाणिज्यिक बैंक (62) [@]	36	1	1	1	3	11

[@] 9 बैंकों के पास खुदरा ऋण और एमएसई ऋण खंडों के लिए कोई जोखिम नहीं है।

नोट: कोष्ठक में दिये आंकड़े बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत : आरबीआई।

सारणी IV.5: पॉलिसी रेपो दर से जुड़े ऋण - मिडियन स्प्रेड (फरवरी 2020)

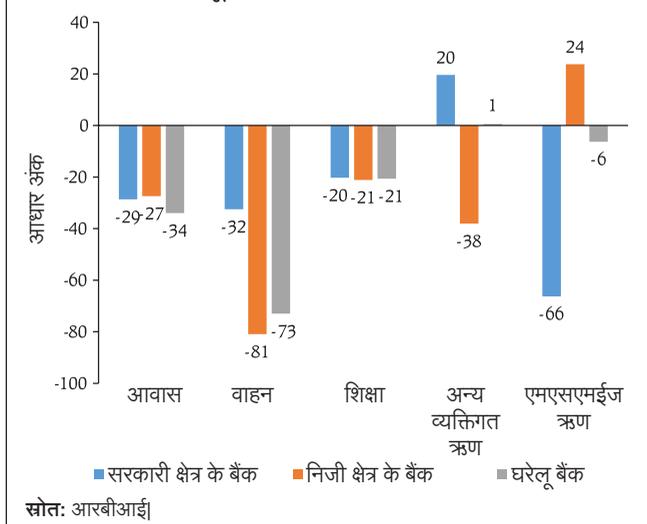
बैंक समूह	निजी ऋण				सूक्ष्म और लघु उद्यम
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य निजी ऋण	
सरकारी क्षेत्र के बैंक (15)	3.3	4.6	4.2	6.7	5.8
निजी क्षेत्र के बैंक (20)	5.3	6.2	6.8	7.1	6.4
घरेलू बैंक (35)	4.0	4.9	4.6	6.8	6.1

स्रोत: आरबीआई।

ऐसे क्षेत्र जहां नई फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा गया है उन क्षेत्रों के संबंध में स्वीकृत नए रुपया ऋणों के संचरण में सुधार के शुरुआती संकेत हैं। अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान घरेलू (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र) बैंकों के डब्ल्यूएलआर में स्वीकृत नए रुपया ऋणों के संबंध में आवासन ऋण के लिए 34 आधार अंक, वाहन ऋण के लिए 73 आधार अंक, शिक्षा ऋण के लिए 21 आधार अंक तथा लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 6 आधार अंक की गिरावट आई है (चार्ट IV.26)।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लघु बचत योजनाओं पर प्रशासित ब्याज दरों में मौद्रिक संचरण के निहितार्थ हैं। ये प्रशासित ब्याज दरें कुछ अंतराल के साथ जी-सेक पर बाजार प्रतिफलों से जुड़ी हुई है और तुलनीय परिपक्वताओं के जी-सेक प्रतिफलों के अतिरिक्त 0 से 100 आधार अंक श्रेणी के लाभांतर पर त्रैमासिक आधार पर नियत की जाती है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2020 को 2020-21 की पहली तिमाही के लिए सभी लघु बचत योजनाओं (बचत जमाराशियों को छोड़कर) पर ब्याज की दरों में 70 से 140 आधार अंक के दायरे में तेजी से कमी की है। संशोधन के बाद, 2020-21 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं

चार्ट IV.26: निजी ऋणों पर डब्ल्यूएलआर और एमएसएमईज को ऋण (अक्टूबर 2019 – फरवरी 2020)



पर ब्याज दरों को मोटे तौर पर लघु बचत पर निर्धारित सूत्र पर आधारित प्रशासित ब्याज दरों के साथ संरेखित किया जाता है (सारणी IV.6)। यह मौद्रिक संचरण को अच्छी तरह से आगे बढ़ने की पूर्व सूचना देता है।

सारणी IV.6: अल्प बचत लिखतों पर ब्याज दरें - पहली तिमाही : 2020-21

अल्प बचत योजना	परिपक्वता (वर्ष)	स्प्रेड (प्रतिशत अंक)\$	संगत परिपक्वता का औसत जी-सेक यील्ड (प्रतिशत) (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक)	फार्मूला- आधारित ब्याज दर(प्रतिशत) (तिमाही 1: 2020-21 के लिए लागू)	तिमाही 1: 2020-21 में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर(प्रतिशत)	सरकार द्वारा घोषित दर और फार्मूला- आधारित दर के बीच अंतर (आधार अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6)-(5)
जमा बचत	-	-	-	-	4.00	-
सार्वजनिक भविष्य निधि मियादी जमा	15	0.25	6.88	7.13	7.10	-3
1 वर्ष	1	0	5.15	5.15	5.50	35
2 वर्ष	2	0	5.47	5.47	5.50	3
3 वर्ष	3	0	5.78	5.78	5.50	-28
5 वर्ष	5	0.25	6.41	6.66	6.70	4
पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा खाता	5	0	5.78	5.78	5.80	2
पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना	5	0.25	6.38	6.63	6.60	-3
किसान विकास पत्र	124 माह	0	6.88	6.88	6.90	2
एनएससी VIII इश्यु	5	0.25	6.57	6.82	6.80	-2
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	6.41	7.41	7.40	-1
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	6.88	7.63	7.60	-3

\$: 16 फरवरी 2016 की भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अल्प बचत दरों के निर्धारण के लिए स्प्रेड्स।

टिप्पणी: कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग-अलग लिखतों में भिन्न होती है।

स्रोत: भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

IV.3 चलनिधि प्रबंधन और मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया

वर्ष 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन प्रक्रिया और समय-समय पर परिवर्तन, यदि कोई हो, को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है। वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान, रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि प्रबंधन परिचालनों

को 6 फरवरी, 2020 को घोषित संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अनुरूप किया गया था और COVID-19 के कारण बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजारों में चलनिधि की कमी संबंधित तनाव को दूर करने की आवश्यकता के संबंध में निर्देशित किया गया था (बॉक्स IV.2)। वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी छमाही के एक प्रमुख हिस्से के दौरान, मुख्य रूप से (i) रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा संचालन और (ii) सरकार द्वारा उच्च व्यय, जिसमें अर्थोपाय

बॉक्स IV.2: संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क

जैसा कि 6 जून, 2019 की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी, चलनिधि प्रबंधन को सरल बनाने और चलनिधि प्रबंधन के लिए टूलकिट के उद्देश्यों और टूलकिट को स्पष्ट रूप से सूचित करने के उपायों के साथ चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह की स्थापना की गई थी। समूह की रिपोर्ट को 26 सितंबर, 2019 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर हितधारकों और जनता के सदस्यों (आरबीआई, 2019) की टिप्पणियों के लिए रखा गया था। प्राप्त सुझावों के आधार पर, तत्कालीन चलनिधि प्रबंधन ढांचे को ठीक करने का निर्णय लिया गया। संशोधित रूपरेखा के प्रमुख तत्व नीचे दिए गए हैं:

- (i) चलनिधि प्रबंधन मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया बनी हुई है; भारत औसत कॉल दर (WACR) इसका परिचालन लक्ष्य बनी हुई है।
- (ii) चलनिधि प्रबंधन गलियारे को यथावत रखा गया है, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को इसकी ऊपरी सीमा (सर्वोच्च) के रूप में और फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर को स्थिर दर (न्यूनतम) के रूप में तथा गलियारे के बीच में पॉलिसी रेपो दर को रखा गया है।
- (iii) गलियारे की चौड़ाई को 50 आधार अंक पर बनाए रखा गया है - रिवर्स रेपो दर, रेपो दर से नीचे 25 आधार अंक और एमएसएफ, रेपो दर¹¹ से 25 आधार अंक से नीचे होता है।
- (iv) दैनिक फिक्स्ड रेट रेपो और चार पंद्रह-दिवसीय टर्म रेपो, जो पहले हर पखवाड़े में आयोजित किए जाते थे, वापस ले लिए गए हैं। हालाँकि, रिजर्व बैंक, अंतर्निहित और विकसित बाजार की स्थितियों के अनुसार, चलनिधि के पर्याप्त प्रावधान / अवशोषण को सुनिश्चित करेगा - मात्रात्मक सीमा द्वारा अप्रतिबंधित - नीति दर पर या उसके आस-पास।

- (v) चलनिधि प्रबंधन के साधनों में निश्चित और परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो नीलामियां, एकमुश्त खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा स्वैप और अन्य उपकरण शामिल हैं, जो समय-समय प्रयोग किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रणाली में हमेशा पर्याप्त चलनिधि रहे।
- (vi) एक परिवर्तनीय दर पर 14-दिवसीय रेपो/रिवर्स रेपो ऑपरेशन और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के साथ समायोजन करने के लिए आयोजित किया जाता है जो मामूली चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण है।
- (vii) रिजर्व रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि में बदलाव के लिए मुख्य चलनिधि संचालन को ओवरनाइट भर और / या लंबे समय तक चलने वाले ट्यूनिंग ऑपरेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- (viii) इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिनों से अधिक समय की लंबी अवधि की परिवर्तनीय दर रेपो / रिवर्स रेपो परिचालनों का संचालन करेगा।
- (ix) दैनिक आधार पर निर्धारित सीआरआरका न्यूनतम 90 प्रतिशत बनाए रखने की वर्तमान अपेक्षा जारी रहेगी¹²।
- (x) स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को ओवरनाइट चलनिधि प्रबंधन कार्यों में सीधे भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- (xi) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी; हालाँकि, रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए मार्जिन की आवश्यकता 'शून्य' रहेगी।

¹¹ यह 27 मार्च, 2020 को कॉरीडोर अससमित रूप से विस्तृत हुआ (विवरण के लिए बॉक्स IV.3 देखें)।

¹² 27 मार्च, 2020 को बाद में न्यूनतम दैनिक सीआरआर अधिशेष की अपेक्षा को घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था (विवरण के लिए बॉक्स IV.3 देखें)।

(xii) भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन ढांचे और प्रक्रियाओं पर संचार को बेहतर बनाने के लिए, निम्नलिखित उपायों को पेश किया गया था: (क) मुद्रा बाजार परिचालनों (एमएमओ) में विस्तार के संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि परिचालन पर दैनिक प्रवाह प्रभाव के साथ-साथ स्टॉक प्रभाव, दोनों दिखाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया; (ख) रिज़र्व बैंक ने एक पखवाड़े के अंतराल के

साथ पाक्षिक आधार पर बैंकिंग प्रणाली की टिकारू चलनिधि की स्थितियों का मात्रात्मक मूल्यांकन प्रकाशित करना शुरू किया; और (ग) बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के साथ आवधिक परामर्श आयोजित किया जाएगा।

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (2019), "चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट", 26 सितंबर।

अग्रिम और ओडी शामिल हैं, के कारण प्रणालीगत चलनिधि में वृद्धि हुई। रिज़र्व बैंक ने दूसरी छमाही में बढ़ती अधिशेष चलनिधि को समाप्त करने के लिए 1,96,02,726 करोड़ रुपये की विभिन्न अवधियों की परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों का आयोजन किया (14 फरवरी, 2020 से शुक्रवार को रिपोर्टिंग पर आयोजित मुख्य 14-दिवसीय टर्म रिवर्स रेपो नीलामी सहित ओवर नाइट से लेकर 63दिवसीय विभिन्न देनदारियों की परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामियों का आयोजन किया)। इसके अलावा, मौद्रिक संचरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी और मार्च के दौरान पाँच एलटीआरओ आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, वित्तीय स्थितियों पर COVID-19 से संबंधित दबाव को कम करने के लिए मार्च में एक लक्षित लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) का आयोजन किया गया था।

कोविड-19 महामारी और वैश्विक तथा घरेलू वित्तीय बाजारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर, वर्तमान के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों तथा आउटलुक को विकसित करने के लिए एमपीसी ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अपनी बैठक का आयोजन निर्धारित समय से पहले ही कर लिया। एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर रखने के लिए, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने तथा संवृद्धि को संभालने के लिए नरम रुख अख्तियार करते हुए नीतिगत दरों में 75 आधार अंको की अभूतपूर्व कटौती की। इसके साथ ही, 27 मार्च, 2020 को वित्तीय स्थितियों में तनाव को दूर करने और कोविड-19 संबंधित चलनिधि की कमी (बॉक्स IV.3) को कम करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की गई।

बॉक्स IV.3: कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चलनिधि उपाय

(I) लक्ष्यबद्ध दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ)

रिज़र्व बैंक नीतिगत रेपो दर से जुड़ी फ्लोटिंग दर पर कुल 1,00,000 करोड़ रुपये तक के लिए उपयुक्त आकार के तीन साल तक के लक्ष्यबद्ध दीर्घकालिक रेपो की नीलामी करेगा। टीएलटीआरओ के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि को 27 मार्च, 2020 तक इन बॉन्डों में अपने निवेश के उत्कृष्ट स्तर के अलावा निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में उपयोग किया जाना है।

(II) नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)

(i) 28 मार्च, 2020 से प्रारंभ पखवाड़े से बैंकों की सीआरआर अपेक्षा को उनके एनडीटीएल के 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.0 प्रतिशत कर दिया गया जिससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग 137000 करोड़ की प्रारंभिक चलनिधि उपलब्ध होगी। यह सुविधा 26 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले एक वर्ष तक उपलब्ध होगी।

(ii) 28 मार्च, 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े के पहले दिन से न्यूनतम दैनिक सीआरआर बैलेंस की आवश्यकता को 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया। यह सुविधा 26 जून, 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

(III) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

घरेलू वित्तीय बाजारों में असाधारण तीव्र उतार-चढ़ाव को देखते हुए और बैंकिंग प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए, बैंकों की ओवरनाइट एमएसएफके तहत उनके सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की सुविधा की सीमा एनडीटीएल के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक कर दी गई। यह उपाय बैंकिंग प्रणाली को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) विन्डो के तहत 4.65 प्रतिशत की कम एमएसएफ दर पर अतिरिक्त 1,37,000 करोड़ की चलनिधि प्राप्त करने की अनुमति देगी और 30 जून, 2020 तक लागू रहेगी।

(जारी)

(IV) नीतिगत दरों में कमी और नीतिगत कॉरिडोर को विस्तृत करना

- (i) एलएएफ के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.15 प्रतिशत से 75 आधार अंक घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया गया। तदनुसार, एमएसएफ दर और बैंक दर को 5.40 प्रतिशत से घटाकर 4.65 प्रतिशत कर दिया गया।
- (ii) अनवरत अतिरिक्त चलनिधि को देखते हुए, मौजूदा एलएएफ कॉरिडोर में असममित विस्तृति करते हुए इसमें 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 65 आधार अंकों कर दिया गया। तदनुसार, रिवर्स रेपो दर को 90 आधारअंकों से घटाकर 4.90 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत कर दिया गया। इस उपाय का

उद्देश्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में निष्क्रिय रूप से धन जमा करने को अपेक्षाकृत अनाकर्षक बनाना था; इसके बजाय, इन निधियों को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को उधार देने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

- (iii) इस प्रकार, रिवर्स रेपो दर पॉलिसी रेपो दर की तुलना में अब 40 आधार अंक कम है, जबकि एमएसएफ दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंकों के ऊपर बनी हुई है।

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (2020), "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य", 27 मार्च।

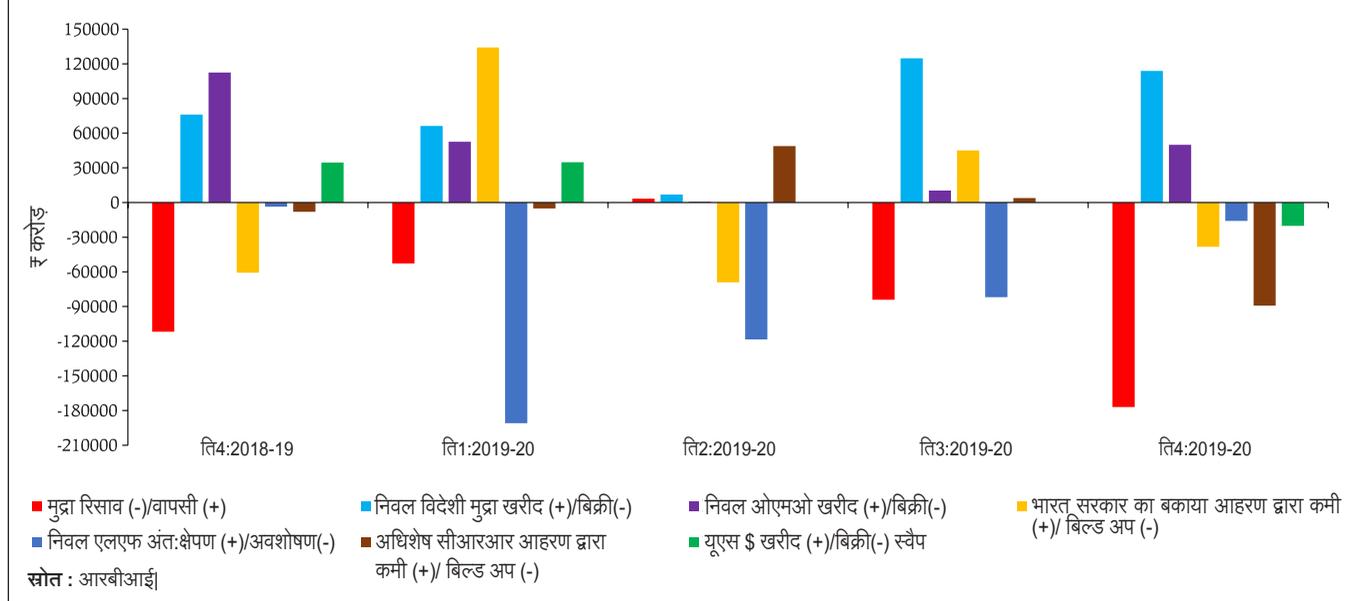
चलनिधि के चालक और प्रबंधन

वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान प्रणाली से मुद्रा का बहिर्गमन रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन और सरकारी नकदी शेष की कमी से अधिक था, जिससे बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि में वृद्धि हुई (चार्ट IV.27)। अधिशेष चलनिधि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो ऑपरेशन के माध्यम से अवशोषित किया गया था। दूसरी छमाही में 2.61 लाख करोड़ की मुद्रा परिचालन (सीआईसी) में वृद्धि वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 49,378 करोड़ की तुलना में पांच गुना से अधिक और 2018-19 की दूसरी छमाही में 2.11 लाख करोड़ से अधिक थी। परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान सीआईसी में 11.9 प्रतिशत

की वृद्धि हुई जो वर्ष 2018-19 की इसी अवधि के दौरान 11 प्रतिशत थी।

अधिशेष चलनिधि की स्थिति वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में बनी हुई थी, क्योंकि एलएएफके तहत दैनिक शुद्ध चलनिधि अवशोषण अक्टूबर में 1.99 लाख करोड़ से बढ़कर नवंबर में 2.41 लाख करोड़ और दिसंबर 2019 में 2.61 लाख करोड़ हो गई थी। अधिशेष की निरंतरता की उम्मीद के कारण रिज़र्व बैंक ने नवंबर में चार लंबी अवधि के रिवर्स रेपो नीलामियों का आयोजन किया - 21 दिवसीय दो और 42-दिवसीय और 35-दिवसीय अवधियों के एक-एक जिससे 78,934 करोड़ रुपये की चलनिधि अवशोषित हुई। तीसरी तिमाही के दौरान, रिज़र्व बैंक के

चार्ट IV.27: चलनिधि के संचालक और प्रबंधन

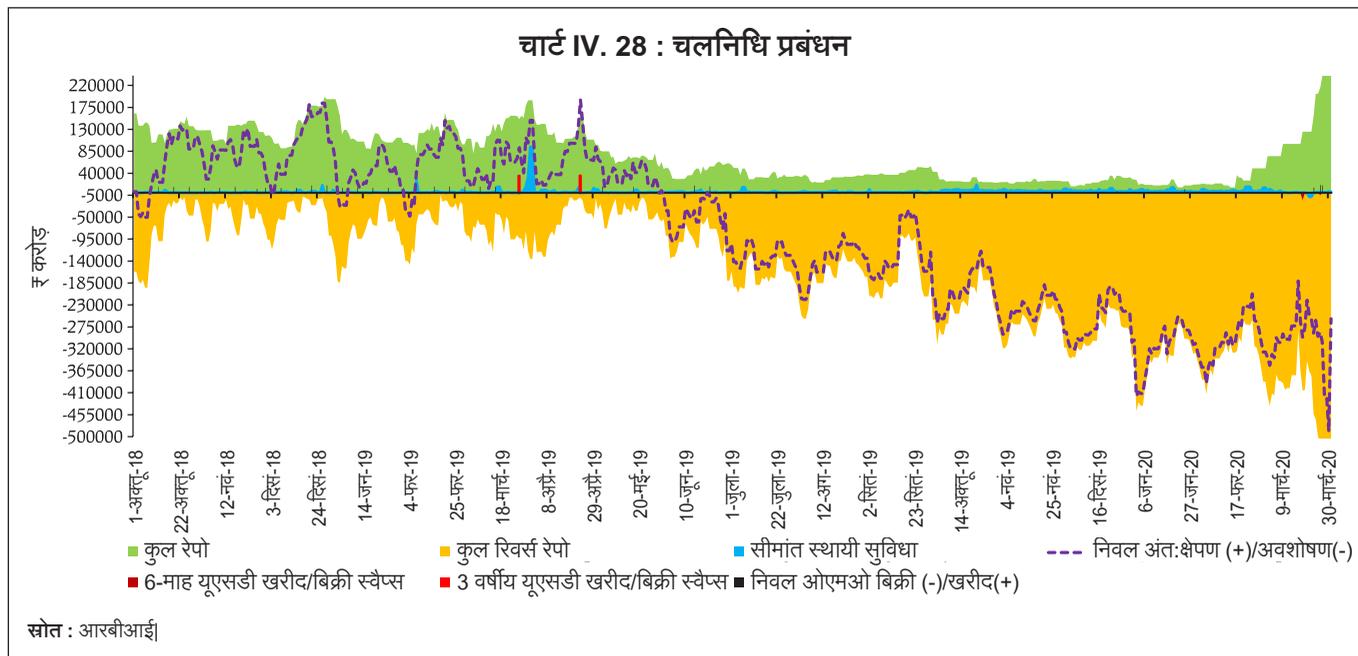


विदेशी मुद्रा संचालन (1.25 लाख करोड़) और भारत सरकार के नकद शेष (45,184 करोड़) के संवर्धित प्रणालीगत चलनिधि में गिरावट आई। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर और जनवरी (23 और 30 दिसंबर, 2019 और 6 जनवरी और 23, 2020) के दौरान चार विशेष ओएमओ का संचालन किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि ₹ 11,724 करोड़ बढ़ गई¹³।

चौथी तिमाही के दौरान जनवरी माह औसत दैनिक अधिशेष चलनिधि और भी बढ़कर ₹3.18 लाख करोड़ हो गई क्योंकि सरकार ने डब्ल्यूएमए/ओडी सुविधा का लाभ लेना जारी रखा, लेकिन फरवरी में यह कम होकर ₹2.98 लाख करोड़ हो गई, क्योंकि जैसा कि पहले चर्चा की गई है सीबीएम के निर्गमन के चलते इस महीने के दूसरे भाग में भारत सरकार का नकदी शेष धनात्मक में बदल गया था (विवरण हेतु IV.12 देखें) मार्च में, एलएफ के तहत औसतन दैनिक निवल अवशोषण ₹ 3.02 लाख करोड़ पर पहुंच गया। वैश्विक वित्तीय बाजार के अत्यधिक अस्थिर रहने के कारण निरापद स्थलों की तरफ बढ़ने के बीच अमेरिकी डॉलर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, रिज़र्व द्वारा 16 तथा 23 मार्च 2020 को 6-माह अवधि वाली यूएस डॉलर/आईएनआर बिक्री/खरीद स्वैप की दो नीलामियां

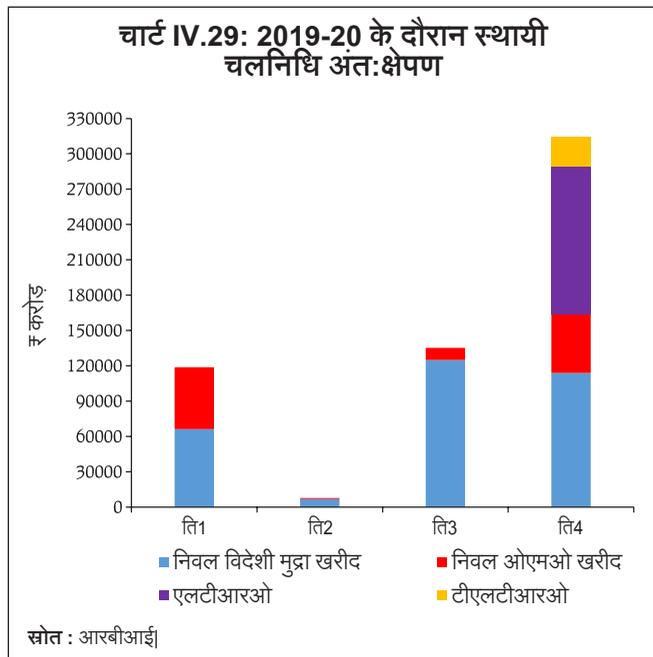
निष्पन्न की गई, जिससे संचित रूप में 2.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डॉलर चलनिधि उपलब्ध हुई (चार्ट IV.28)। इसके अलावा, प्रतिफल के दृढ़ीभूत होने तथा बाजार के कुछ प्रखंडों में स्प्रेड में विस्तार से दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति के लक्षण दृष्टिगोचर हुए (चार्ट IV.12 देखें), जिसे देखते हुए 20, 24 और 26 मार्च 2020 को खुले बाजार के तीन खरीद परिचालन निष्पादित किए गए और तदनुसार संचित रूप में ₹40,000 करोड़ की राशि अंतर्वेशित हुई।

मौद्रिक अंतरण को मजबूत बनाने तथा उत्पादक क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के प्रयोजन से, बैंक ने 17 फरवरी तथा 18 मार्च 2020 के बीच नियत रिपो दर पर (एक-वर्ष अवधि का एक तथा तीन-वर्ष अवधि के चार) पांच दीर्घावधि रिपो परिचालन (एलटीआरओ) निष्पादित किए, जिससे प्रणाली में ₹1.25 लाख करोड़ राशि की स्थायी चलनिधि अंतर्वेशित हुई और ₹ 75,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि पाइपलाइन में है। एलटीआरओ से बैंकों को प्रचलित बाजार दरों के सापेक्षतया उचित लागत पर (नियत रिपो दर) स्थायी चलनिधि उपलब्ध हुई। इसके अलावा, 27 मार्च 2020 को निष्पन्न 3-वर्षीय परिपक्वता वाली टीएलटीआरओ नीलामी से भी स्थायी चलनिधि में ₹ 25,009¹⁴ करोड़ की वृद्धि



¹³ जबकि, इन नीलामियों के जरिए ₹ 40,000 करोड़ राशि की दीर्घावधि पेपर की खरीद की गई, वहीं ₹ 28,276 करोड़ राशि की अल्पावधि प्रतिभूतियों की बिक्री भी की गई।

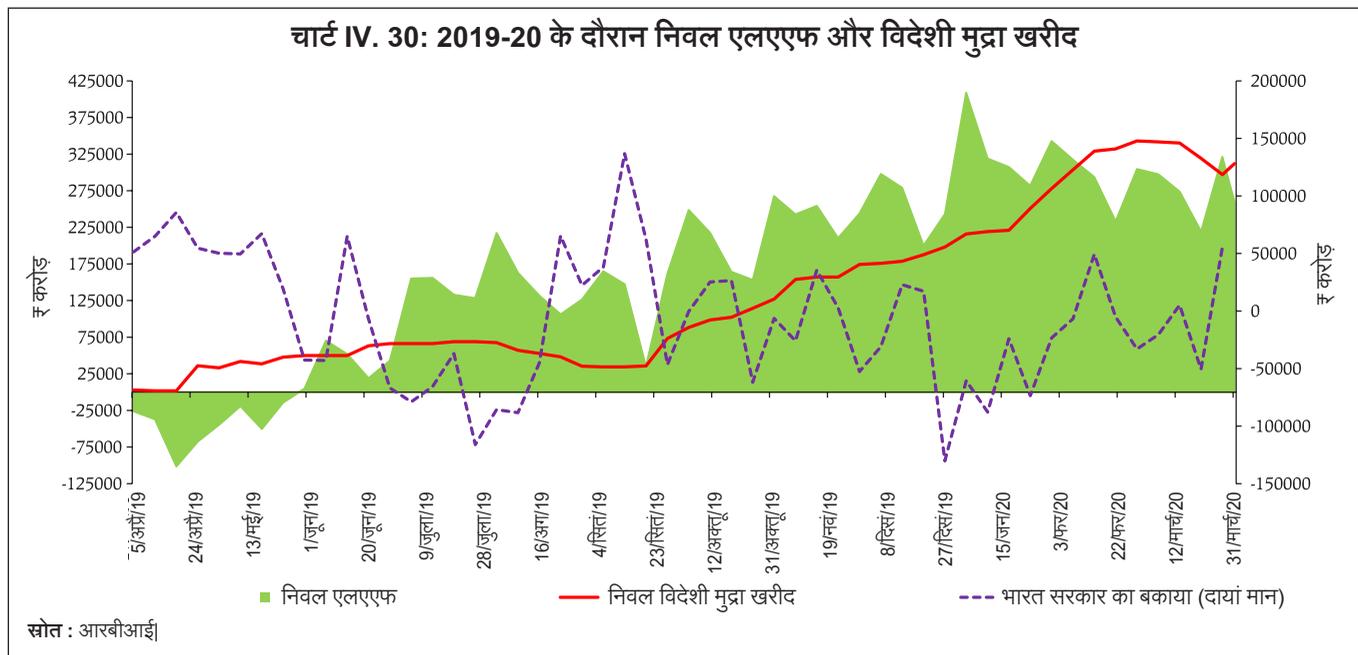
¹⁴ 3 अप्रैल को 3-वर्षीय परिपक्वता वाली एक दूसरी टीएलटीआरओ नीलामी संपादित की गई जिससे स्थायी चलनिधि में ₹ 25,016 करोड़ की वृद्धि हुई। ₹ 25,000 करोड़ की इतनी ही परिपक्वता वाली एक तीसरी नीलामी 9 अप्रैल 2020 हेतु निर्धारित है।



हुई। इस प्रकार, 2019-20 की दूसरी छमाही में ₹4,49,326 करोड़ राशि की कुल स्थायी चलनिधि (विदेशी मुद्रा खरीद, ओएमओ, एलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ सहित) अंतर्वेशित की गई, जबकि पहली छमाही में ₹ 1,26,514 करोड़ राशि अंतर्वेशित की गई थी (चार्ट IV.29)।

सारांश में, 2019-20 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रा विस्तार, रिजर्व बैंक के फोरेक्स परिचालन तथा सरकारी खर्च बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के प्रमुख चालक रहे (चार्ट IV.30)।

चलनिधि में अधिशेष की स्थिति को देखते हुए, चलनिधि का अवशोषण करने हेतु 14 फरवरी 2020 तक ऐसे परिवर्ती दर रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए सुनियोजित परिचालन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, जिनकी परिपक्वता ओवरनाइट से तीन दिवस के दायरे में थी। कोविड-19 के कारण गड़बड़ के चलते किसी फ्रिक्शनल चलनिधि आवश्यकता पर काबू पाने के लिए फाइन-ट्यूनिंग करते हुए पहले से नियत उपाय के रूप में, 23 और 24 मार्च 2020 को 16-दिवसीय परिपक्वता वाली परिवर्ती दर रिपो की दो नीलामियां निष्पादित की गई जिससे संचित रूप में ₹ 77,745 करोड़ की राशि अंतर्वेशित हुई (सारणी IV.7)। वर्ष-अंत में चलनिधि की किसी अतिरिक्त मांग को पूरा करने तथा बैंकिंग प्रणाली को अपने चलनिधि प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने के प्रयोजन से, 26 मार्च को 12-दिवसीय परिपक्वता वाली एक फाइन-ट्यूनिंग परिवर्ती दर रिपो नीलामी निष्पादित की गई, जिससे ₹11,772 करोड़¹⁵ की राशि अंतर्वेशित हुई। एक विशेष मामले के रूप में, इन नीलामियों में अन्य पात्र प्रतिभागियों सहित एसपीडी को भी भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई।



¹⁵ ₹ 25,000 करोड़ हेतु परिवर्ती दर रिपो नीलामी के जरिए दो अन्य फाइन-ट्यूनिंग परिचालन 13 मार्च तथा 31 मार्च को संपादित किए गए जिनमें से प्रत्येक क्रमशः 7-दिवस तथा 3-दिवस परिपक्वता वाले थे – जिसे बाजार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सारणी IV.7: 2019-20 की दूसरी छमाही में परिवर्तनीय दर की नीलामियों के माध्यम से फ़ाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन

	रेपो	रिवर्स रेपो							
		1-3	4	21	28-29	31	35	42	63
दिनों में परिपक्वता	12, 16								
ऑपरेशनों की संख्या	3	90	2	2	3	1	1	2	3
कुल मात्रा (₹ बिलियन)	89,517	1,85,67,948	3,21,328	28,923	47,165	12,790	25,004	30,507	65,033
औसत मात्रा (₹ बिलियन)	29,839	2,06,311	1,60,664	14,462	15,722	12,790	25,004	15,254	21,678

स्रोत : आरबीआई

IV.4 निष्कर्ष

वैश्विक गतिविधियों, भारत में संवृद्धि में सुस्त के सघनीकरण और कोविड-19 को लेकर बढ़ती चिंताओं के समक्ष घरेलू वित्तीय बाजार कमजोर बने रहे। कमजोर घरेलू संवृद्धि संभावनाओं के परिदृश्य के बावजूद, मार्च महीने के पहले भाग में भारतीय इक्विटी बाजारों ने वैश्विक इक्विटी बाजार के अनुसरण में अत्यधिक अस्थिर होने से पहले नई ऊचाइयों को छुआ। इस परिदृश्य को बढ़ी हुई अनिश्चितता तथा पूंजी बहिर्वाह से बल मिला जिससे भारतीय रुपए पर दबाव बना रहा। यह परिदृश्य अनिश्चित है और

तेजी से बॉण्ड बाजार प्रतिफलों में प्रतिबिंबित हो रहा है। ऋण संवृद्धि संयमित रहने की उम्मीद है, जो कमजोर मांग और जोखिम विमुखता को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए, संवृद्धि को फिर से बहाल करने तथा कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जहां तक आवश्यक होगा, मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख के अनुरूप चलनिधि स्थितियों का प्रबंधन संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर ही बनी रहे। ऋण बाजार को उद्वेलित करने वाले मौद्रिक नीति के बेहतर अंतरण की प्राथमिकता बनी रहेगी।

V. बाह्य परिदृश्य

प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक गतिविधियां धीमी बनी रहीं। हालांकि वर्ष 2020 के शुरुआती दौर में स्थिरीकरण के कुछ क्षणिक चिह्न दिखाई पड़े थे, लेकिन कोविड-19 के प्रसार और बहुत से देशों में इसके तेजी से फैलने से सन्निकट परिदृश्य धूमिल हो गया है। प्रमुख ईई में मुद्रास्फीति मोटे तौर पर नियंत्रित रही लेकिन खाद्य कीमतों में तेजी होने से मुख्य ईएमई में मुद्रास्फीति ने गति पकड़ ली। कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं के बीच विश्व के अधिकतम केंद्रीय बैंकों द्वारा परंपरागत और गैर-परंपरागत उपायों के माध्यम से भारी सुलभता देने के कारण मौद्रिक नीति अत्यधिक निभावकारी बनी रही। वैश्विक वित्तीय बाजार, जो 2019 की चौथी तिमाही में जोखिम रूख के आधार पर उछाल पर था, मार्च में अनियंत्रित गिरावट की ओर बढ़ा क्योंकि कोविड-19 के तीव्र रूप से फैलने के कारण पैदा हुआ बिक्री दबाव तीव्र हो गया।

2019 की दूसरी छमाही के अधिकतर हिस्से के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधियां धीमी बनी रहीं। जनवरी 2020 में, आईएमएफ ने बताया कि 2019 के लिए वैश्विक जीडीपी संवृद्धि की अनुमानित दर 2.9 प्रतिशत है, यह वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) से लेकर अब तक की सबसे कम संवृद्धि दर है। वर्ष 2020 की शुरुआत में, यूएस और चीन के बीच व्यापार-तनाव में कमी दिखाई देने और हार्ड ब्रेकिजट की संभावनाएं दिखने से स्थायीकरण के चिह्न दिखाई दिए थे। चीन के बुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया का पता चलने और 31 दिसंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को पहली रिपोर्ट करने पर इन ग्रीन शूट्स को गहरा आघात लगा और इसने दुनिया को बदल दिया। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया और 11 फरवरी, 2020 को नोवल कोरोना विषाणु को कोविड-19 का नाम दिया। 11 मार्च, 2020 को, डब्ल्यूएचओ ने इसे महामारी घोषित कर दिया - "कोरोना विषाणु के कारण पहली महामारी"। रिपोर्ट छपने हेतु जाने से पूर्व, संपूर्ण विश्व में 67000 से अधिक मौतों¹ के साथ 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित थे।

¹ महानिदेशक, डब्ल्यूएचओ की प्रारंभिक टिप्पणियां, मीडिया ब्रीफिंग, 11 मार्च 2020

² विश्व स्वास्थ्य संगठन

23 मार्च, 2020 को कोरोना विषाणु आपातकाल पर आयोजित जी-20 की मिनिस्ट्रियल कॉल में, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ ने औपचारिक रूप से सूचित किया कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर चुकी थी।

प्राप्त हुए शुरुआती आंकड़ों में, 2020 की पहली तिमाही में सिंगापुर की जीडीपी में 10.6 प्रतिशत का संकुचन हुआ। यूएस में बेरोजगारी दावे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए क्योंकि 28 मार्च, 2020 को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी बीमा दावों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 6.6 मिलियन तक पहुंच गई, ये 1967 में श्रृंखला शुरू होने से अब तक सर्वाधिक है। उत्पादन कटौती में असहमति के कारण सऊदी अरब और रूस के बीच मूल्य-युद्ध से मार्च में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट आई। वैश्विक मांग के कमजोर होने की आशंकाओं के चलते अन्य वैश्विक पण्यों की कीमतों में गिरावट देखी गई। निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश को चुनने के कारण सेफ हेवन पर भरोसे से शुरुआत में मूल्यवान धातुओं की कीमतों में उछाल आया, लेकिन निवेशकों द्वारा नकदी को प्राथमिकता देने कारण मार्च के दूसरे सप्ताह में इनमें गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के केंद्रीय बैंकों ने अत्यधिक निभावकारी नीति को अपनाते हुए इनमें से अधिकतम ने अनिर्धारित बैठकों में दर-कटौती का सहारा लिया। कठिन वित्तीय स्थितियों का सामना करने के लिए, केंद्रीय बैंकों ने कई चलनिधि उपायों और विनियामक रियायतों की भी घोषणा की। विश्व भर के राजकोषीय प्राधिकरणों ने अपने जीडीपी के 0.8 से 16.0 प्रतिशत की सीमा में प्रोत्साहन दिए हैं। प्रत्यक्ष सहयोग के अलावा, कर स्थगन और ऋण गारंटी भी उपायों में शामिल हैं।

V.1 वैश्विक आर्थिक स्थितियां

यूएस में, पिछली तिमाही के समान गति से ही 2019 की चौथी तिमाही में जीडीपी में 2.1 प्रतिशत की संवृद्धि हुई। कारोबारी निवेश और निर्यात में निरंतर कमजोरी के बीच 2019 के लिए समग्र जीडीपी संवृद्धि तीन वर्षों में अपने सबसे धीमे स्तर पर पहुंच गई (तालिका V.1)। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में, औद्योगिक उत्पादन संवृद्धि जनवरी तक लगातार पाँचवें महीने तक संकुचन के बाद फरवरी में थमी रही और जनवरी-फरवरी में मामूली सुधार

सारणी V.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (तिमाही- दर- तिमाही, वार्षिकी)

(प्रतिशत)

देश	ति4- 2018	ति1- 2019	ति2- 2019	ति3- 2019	ति4- 2019	2020 (पी)	2021 (पी)
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ							
कनाडा	1.0	1.0	3.4	1.1	0.3	1.8	1.8
यूरो क्षेत्र	1.2	1.6	0.8	1.2	0.4	1.3	1.4
जापान	2.4	2.2	2.3	0.1	-7.1	0.7	0.5
दक्षिण कोरिया	3.6	-1.6	4.0	1.6	5.2	2.2	2.7
यूके	0.8	2.4	-0.4	2.0	0.0	1.4	1.5
यूएस	1.1	3.1	2.0	2.1	2.1	2.0	1.7
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ							
ब्राज़ील	0.0	0.0	2.0	2.4	2.0	2.2	2.3
चीन*	6.5	6.4	6.2	6.0	6.0	6.0	5.8
इंडोनेशिया*	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.1
रूस *	2.7	0.5	0.9	1.7	2.1	1.9	2.0
दक्षिण अफ्रीका	1.4	-3.2	3.3	-0.8	-1.4	0.8	1.0
थाईलैंड	5.2	3.2	1.4	0.6	1.0	3.0	3.5
मेमो:	2019 (ई)		2020 (पी)			2021 (पी)	
विश्व उत्पादन	2.9		3.3			3.4	
विश्व व्यापार मात्रा	1.0		2.9			3.7	

ई: अनुमान, पी: पूर्वानुमान, *: वर्ष- दर- वर्ष संवृद्धि

स्रोत: ब्लूमबर्ग, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

के बाद मार्च में इंस्टीट्यूट फोर सप्लाय मैनेजमेंट (आईएसएम) के मैनुफैक्चरिंग पर्सेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) में संकुचन हुआ। जनवरी से खुदरा बिक्री में भी नरमी आई है। यद्यपि श्रम बाजार फरवरी में मजबूत रहा, जैसाकि यूएस की अपेक्षा की तुलना में रोजगार रिपोर्ट में बेहतर परिलक्षित होता है, 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में यूएस में बेरोजगारी दावों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या 6.6 मिलियन तक पहुंच गई, जो 1967 में श्रृंखला शुरू होने से अब तक सर्वाधिक है।

2019 की चौथी तिमाही में यूरो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि में स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों में स्पष्ट गिरावट और कमजोर उपभोक्ता मांग समग्र आर्थिक निष्पादन पर भारी पड़ी। वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के दौरान, उपभोक्ताओं का विश्वास कम होने से फ्रांस और इटली की जीडीपी संवृद्धि में संकुचन हुआ और निजी और सरकारी खर्चों में मंदी के कारण जर्मनी में यह गतिहीन रही। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में, इटली, स्पेन और अन्य यूरोपीय देशों में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैलने के कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के प्रभावित होने की

संभावना है। इसीबी ने अपने बेसलाइन सिनेरिओ एजंप्शन के अंतर्गत- कि अगले कुछ महीनों में विषाणु के प्रभावों पर काबू पा लिया जाएगा और 2020 की दूसरी छमाही में संवृद्धि सामान्य हो जाएगी -अनुमान लगाया है कि 2020 में जीडीपी संवृद्धि घटकर 0.8 प्रतिशत रहेगी।

जापानी अर्थव्यवस्था में चौथी तिमाही के दौरान तीव्र संकुचन हुआ क्योंकि अक्टूबर में बिक्री कर में वृद्धि के कारण निजी उपभोग में गिरावट आई। तूफानों की श्रृंखला और बाहरी मांग में मंदी के चलते कारखाना गतिविधियों के स्लोडाउन ने घरेलू गतिविधि पर और अधिक दबाव बनाया। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में, पूर्वी एशियाई क्षेत्रों सहित, संक्रमण की बढ़ती संख्या ने आर्थिक गतिविधि को गंभीर रूप से बाधित करने की चेतावनी दी।

तीसरी तिमाही में उछाल के बाद, यूके की जीडीपी संवृद्धि चौथी तिमाही में गतिहीन रही। विनिर्माण उत्पादन में हुई गिरावट की भरपाई सेवा और निर्माण क्षेत्रों के सकारात्मक योगदान से हुई। अक्टूबर में ब्रेकिंग की समय सीमा और दिसंबर में आम चुनाव के कारण राजनीतिक अनिश्चितता से ऐसा लगा कि अंतिम तिमाही में गतिविधि धीमी हुई है। वर्ष 2020 की पहली तिमाही में, औद्योगिक उत्पादन में संकुचन हुआ और खुदरा बिक्री मंद रही। कोविड-19 से जनित जोखिम से पहली तिमाही में आउटलुक कमजोर हो सकता है।

वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में प्रमुख ईएमई में सुस्त संवृद्धि का मुख्य कारण कोविड-19 का फैलना रहा। अचानक निम्नगामी जोखिम तीव्र हो गए (बॉक्स V.1)।

चीनी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में गति बनाए रखने के बाद 2019 की चौथी तिमाही में जीडीपी संवृद्धि की गति को बनाए रखने में कामयाबी रही, लेकिन कोविड-19 का असर केवल 2020 की पहली तिमाही में शुरू होगा। कई क्षेत्रों में लागू कामबंदी के कारण नए ऑर्डर व रोजगार कम होने से कैक्सिन्स मैनुफैक्चरिंग पीएमआई गिरकर फरवरी में 40.3 पर पहुंच गया जो अप्रैल 2004 में इसके शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे निम्न स्तर था। हालांकि, विनिर्माण गतिविधि में मामूली विस्तार के कारण यह मार्च में बढ़कर 50.1 तक पहुंच गया क्योंकि फरवरी के अवरोधों के सापेक्ष आउटपुट में मामूली रूप से सुधार हुआ। औद्योगिक उत्पादन संकुचन हुआ तथा यह तेजी से अपने 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और जनवरी-फरवरी 2020

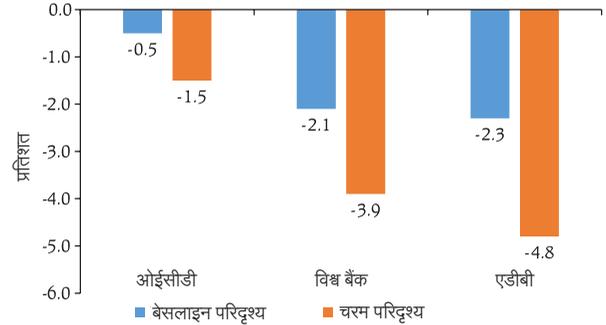
बॉक्स V.1: वैश्विक संवृद्धि पर कोविड-19 का प्रभाव

फरवरी के शुरुआती सप्ताहों में, कोविड-19 आधारित वैश्विक आउटपुट में नुकसान के अधिकांश पूर्वानुमान, विषाणु के केवल चीन में फैलने और मार्च / जून तक नियंत्रण में आ जाने पर आधारित थे। हालांकि, सीमित परिदृश्य में भी यह स्वीकार कर लिया गया था कि आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि 2003 में सार्स महामारी की तुलना में आर्थिक आकार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भूमिका दोनों ही दृष्टि से- चीन अब काफी बड़ा प्रतिभागी है (चार्ट V.1.1)।

लूनर नववर्ष की छुट्टियों को आगे बढ़ा देने, सरकार द्वारा कारखाने बंद करने और कई क्षेत्रों में यात्रा प्रतिबंधों के कारण, फरवरी में चीन की विनिर्माण / सेवा गतिविधि में तेजी से गिरावट आई। फरवरी के उत्तरार्ध में, दुनिया भर में संक्रमण और मृत्यु के मामले तेजी से सामने आने लगे, तथा चीन में वायरस के प्रसार में स्थिरता आने लगी। अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगाए गए हैं। यात्रा-प्रतिबंधों ने एयरलाइन्स, पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों के लिए संकट पैदा कर दिया है।

पण्य और वित्तीय बाजार में, कच्चे तेल की कीमतों में उत्तरोत्तर गिरावट हो रही है ; 30 मार्च 2020 को वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) में कच्चे तेल की कीमतें 20 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंच गईं। इक्विटी बाजारों को भारी नुकसान हुआ,

चार्ट V.1.2: बहुपक्षीय संस्थाओं का कोविड -19 के कारण 2020 में वैश्विक संवृद्धि पर प्रभाव का अनुमान



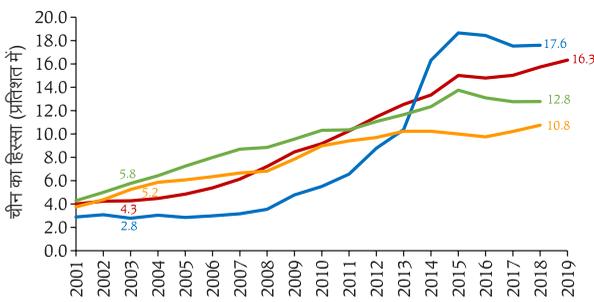
नोट: 1. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के मार्च के अनुमानों में 2020 की पहली तिमाही के दौरान चीन में कोविड-19 के अधिकतम प्रसार और अन्य क्षेत्रों में सीमित प्रसार को बेसलाइन परिदृश्य माना गया। चरम परिदृश्य के अंतर्गत ज्यादातर क्षेत्रों में कोविड-19 के और अधिक गहनता से फैलने और लंबे समय तक बने रहने पर विचार किया गया। अनुमानित प्रभाव को वैश्विक जीडीपी वृद्धि के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

2. विश्व बैंक के अप्रैल के अनुमानों को वैश्विक महामारी के बेसलाइन परिदृश्य और तीव्र वैश्विक महामारी के चरम परिदृश्य के रूप में विचार किया। अनुमानित प्रभाव को उल्लिखित मॉडल के बेंचमार्क के प्रतिशत विचलन के रूप में दर्शाया गया है।

3. एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के अप्रैल के अनुमानों में लघु अवधि के संक्रमण रोकथाम और न्यून मांग आघात के बेसलाइन परिदृश्य; और लंबे समय तक संक्रमण के रोकथाम और अधिक मांग आघात के चरम परिदृश्य पर विचार किया गया। अनुमानित प्रभाव को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

स्रोत: ओईसीडी; विश्व बैंक; और एडीबी।

चार्ट V.1.1: वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन



स्रोत: विश्व बैंक; आईएमएफ; डब्ल्यूटीआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

जबकि सेफ हेवन मांग के कारण सोना, नियत आय संपत्ति - मुख्यतः सरकारी कर्ज, अमेरिकी डॉलर में तेजी आई, लेकिन बाद में बही-लाभ और नकदी की तरफ रुझान के कारण इसमें काफी अधिक संशोधन हुआ गया (चार्ट V.4, और चार्ट V.6-8 को देखें)।

महामारी का संकट अभी भी बने रहने से वैश्विक संवृद्धि पर निम्नगामी गिरावट के अनुमानों को लगातार संशोधित किया जा रहा है। हालांकि, सर्वसम्मति यह है कि 2020 में मंदी रहेगी (चार्ट V.1.2).

महामारी और इसके परिणामों से निपटने के लिए बहुपक्षीय संस्थान, सरकारें और केंद्रीय बैंक तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं (तालिका V.1.1)

तालिका V.1.1: कोविड-19 के फैलने पर चयनित केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए प्रमुख उपाय³

केंद्रीय बैंक	उपाय
पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना	<ul style="list-style-type: none"> 3 और 4 फरवरी को 1.7 ट्रिलियन युआन चलनिधि उपलब्ध कराई गई। 17 फरवरी को वित्तीय संस्थाओं के एक वर्षीय मध्यम अवधि के 200 बिलियन युआन की ऋण सुविधा पर दर को 10 बीपीएस कम करके 3.15 प्रतिशत किया गया। 1 वर्षीय ऋण प्राइम दर को 10 बीपीएस घटाकर 4.05 प्रतिशत कर दिया गया, जो 20 फरवरी, 2020 से प्रभावी है; 5 वर्षीय एलपीआर को 5 बीपीएस घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया। चुनिदा बैंकों के लिए आरक्षित निधि अपेक्षा अनुपात में कटौती। 30 मार्च को 7-दिवसीय रिवर्स रेपो दर को 20 बीपीएस कमी कर 2.2 प्रतिशत किया गया।

(जारी)

³ 31 मार्च 2020 तक

केंद्रीय बैंक	उपाय
फेडरल रिज़र्व	<ul style="list-style-type: none"> 3 मार्च को 50 बीपीएस और 16 मार्च को 100 बीपीएस कम करके फेडरल निधि की लक्ष्य रेंज को 0-0.25 प्रतिशत किया गया। असीमित संपत्ति खरीद, संपत्ति खरीद कार्यक्रम में वाणिज्यिक बंधक समर्थित प्रतिभूतियों को शामिल किया गया। प्राथमिक ऋण दर को 0.25 प्रतिशत तक कम किया गया। बैंकों को उधार देने के लिए पूंजी और चलनिधि बफर्स का उपयोग करने की अनुमति दी गई। 26 मार्च से आरक्षित निधि अपेक्षा को घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया। अतिरिक्त रेपो परिचालन। प्राथमिक डीलर क्रेडिट सुविधा की स्थापना वाणिज्यिक-पत्र फंडिंग सुविधा की स्थापना मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड चलनिधि सुविधा की स्थापना। सावधि आस्तित्व समर्थित संपार्श्विक प्रतिभूति ऋण सुविधा की स्थापना। बड़े नियोक्ताओं को ऋण देने हेतु प्राथमिक बाजार कॉर्पोरेट क्रेडिट सुविधा और द्वितीयक बाजार कॉर्पोरेट क्रेडिट सुविधा स्थापित की गई। पांच केंद्रीय बैंकों (ईयू, यूके, जापान, कनाडा और स्विट्जरलैंड) के साथ मौजूदा डॉलर चलनिधि स्वैप लाइन व्यवस्था से लागत में कमी आई, साथ ही अक्सर और अधिक तथा दीर्घावधिक परिचालन किए गए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के केंद्रीय बैंकों के साथ अस्थायी स्वैप लाइनें स्थापित की गईं। अमेरिकी ट्रेजरी बाजार सहित, वित्तीय बाजार के सुचारु रूप से कामकाज में सहायता करने हेतु, विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकरणों (फिमा रेपो सुविधा) के लिए अस्थायी पुनर्खरीद समझौते की सुविधा स्थापित की गई।
यूरोपियन सेंट्रल बैंक	<ul style="list-style-type: none"> जून 2020 तक यूरो क्षेत्र की वित्तीय प्रणाली को तत्काल चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ)। कोविड-19 के प्रसार से सबसे अधिक प्रभावित होने वालों को बैंक ऋण देने के लिए जून 2020 से जून 2021 तक टीएलटीआरओ III के तहत अधिक अनुकूल शर्तों। 2020 तक अंत तक यूरो 120 बिलियन की अतिरिक्त निवल संपत्ति खरीदा। पिलर 2 गाइडेंस सहित, बैंकों को पूंजी और चलनिधि बफर के उपयोग की अनुमति। ग्रीक सरकार के ऋण की खरीद को शामिल करने के लिए, 750 बिलियन यूरो का महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी), जिसे लचीले तरीके से 2020 के अंत तक संचालित किया जाएगा। गैर-वित्तीय वाणिज्यिक पत्र को संपत्ति खरीद में शामिल करना। ईसीबी के पुनर्वित्त परिचालनों के लिए संपार्श्विक मानकों में नरमी की गई।
बैंक ऑफ इंग्लैंड	<ul style="list-style-type: none"> 19 मार्च को 50 बीपीएस और 15 बीपीएस के दो चरणों में बैंक दर घटकर 0.1 प्रतिशत के सबसे निम्न स्तर पर आ गई। वर्ष 2020 तक की जाने वाली £ 200 बिलियन की अतिरिक्त खरीद। लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ एक नई सावधि निधीयन योजना। 11 मार्च से प्रभावी, यूके के उधारकर्ताओं के लिए प्रति-चक्रीय पूंजी बफर दर बैंकों के एक्सपोजर के 0 प्रतिशत तक घट गई। लाभांश और अन्य संवितरण निर्गमों पर पर्यवेक्षी मार्गदर्शन। 2020 में बैंकों के वार्षिक तनाव परीक्षण को रद्द करने सहित अन्य पर्यवेक्षी और विवेकपूर्ण नीतिगत उपाय। सरकार के सहयोग से कोविड कॉर्पोरेट वित्तीय सुविधा शुरू की गई। आकस्मिक सावधि रेपो सुविधा शुरू की गई।
बैंक ऑफ जापान	<ul style="list-style-type: none"> एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले कॉर्पोरेट ऋण को संपार्श्विक स्वीकार करके 0 प्रतिशत पर ऋण प्रदान करना। वाणिज्यिक पत्र और कॉर्पोरेट बॉन्ड की अतिरिक्त 2 ट्रिलियन येन की खरीद। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और जे-आरईआईटी की खरीद की वार्षिक गति को दोगुना करना।
बैंक ऑफ कोरिया	<ul style="list-style-type: none"> 17 मार्च को बेस दर 50 बीपीएस घटकर 0.75 फीसदी हो गई। बैंक की मध्यवर्ती ऋण समर्थन सुविधा पर ब्याज दर घटकर 0.25 प्रतिशत हो गई और सुविधा पर उच्चतम सीमा 5 ट्रिलियन वोन तक बढ़ा दी गई। खुले बाजार संचालनों के लिए संपार्श्विक का विस्तार हुआ। साप्ताहिक 91-दिवसीय रेपो नीलामियों के माध्यम से असीमित चलनिधि। विदेशी मुद्रा बाजार स्थिरता नियमों में ढील दी गई।
बैंक इंडोनेशिया	<ul style="list-style-type: none"> फरवरी और मार्च प्रत्येक में नीतिगत दर में 25 बीपीएस की कमी आई, जो 19 मार्च 2020 से प्रभावी होकर 4.5 प्रतिशत हो गई। 12 महीने के कार्यकाल की दैनिक रेपो नीलामियों की शुरुआत। विदेशी मुद्रा स्वैप की नीलामी की बारंबारता में वृद्धि। रुपिया विनिमय दर की अस्थिरता में वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए तिगुने हस्तक्षेप की नीति को गहनता से लागू करना। 16 मार्च 2020 से वाणिज्यिक बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित अपेक्षा आधी होकर 4 प्रतिशत पर पहुंच गई। 1 अप्रैल, 2020 से, निर्यात-आयात गतिविधि, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों के लिए रुपया आरक्षित अपेक्षा में 50 बीपीएस की कटौती की गई। रुपिया धारण के विरुद्ध वैकल्पिक बचाव लिखत के प्रावधान हेतु विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध अंडरलाइन लेनदेनों की रेंज को बढ़ाया गया।

केंद्रीय बैंक	उपाय
रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	<ul style="list-style-type: none"> 20 मार्च से, नकद दर का लक्ष्य 25-25 बीपीएस प्रत्येक के दो चरणों में घटकर 0.25 प्रतिशत के सर्वाधिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। 3-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल के लिए निर्धारित लगभग 0.25 प्रतिशत के लक्ष्य को द्वितीयक बाजार खरीद के माध्यम से प्राप्त किया जाना। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के क्रेडिट के लिए विशेष समर्थन के साथ, बैंकिंग प्रणाली के लिए सावधि निधीयन सुविधा। विनिमय निपटान शेषों को 10 बीपीएस पर परिगणित किया जाए।
बैंक ऑफ कनाडा	<ul style="list-style-type: none"> मार्च में तीन चरणों में प्रत्येक बार 50 बीपीएस की कमी करके मुख्य दर 0.25 प्रतिशत पर पहुंच गई। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद घोषणा, प्रति सप्ताह \$ 5 बिलियन की न्यूनतम खरीद। बैंकों की स्वीकृति खरीद सुविधा का आरंभ। प्रविंशियल मुद्रा बाजार खरीद की घोषणा। स्थायी सावधि चलनिधि सुविधा की स्थापना। वाणिज्यिक पत्र खरीद कार्यक्रम की शुरुआत।

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें; और www.centralbanking.com

प्रमुख अस्तित्वगत प्रश्न है: क्या वैश्विक प्रयासों से कोविड-19 की मृत्यु दर और रुग्णता को नियंत्रित करने के साथ-साथ समष्टि आर्थिक परिणामों में रोकथाम होगी?

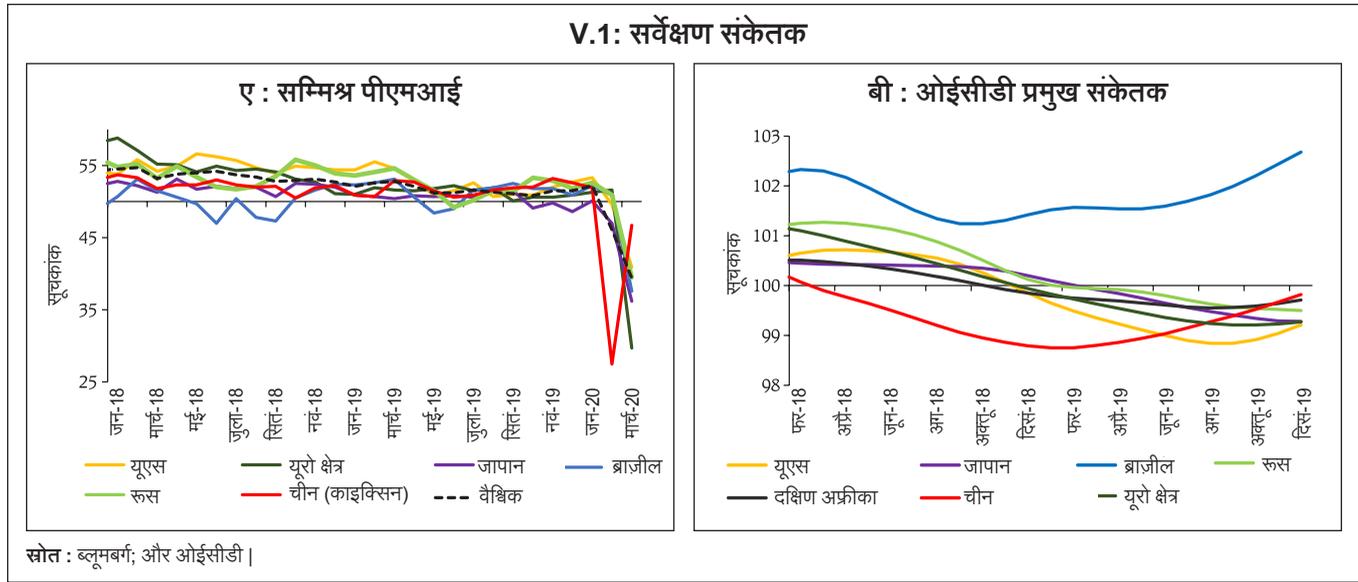
संदर्भ:
 एशियाई विकास बैंक (2020), एशियाई विकास आउटलुक 2020, अप्रैल।
 आईएमएफ(2020), <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency>.
 ओईसीडी (2020), "कोरोनावायरस: द वर्ल्ड इकोनॉमी एट रिस्क", अंतरिम आर्थिक आकलन, 2 मार्च।
 विश्व बैंक (2020), "ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19", ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट, अप्रैल।

में पहली बार खुदरा बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। वायरस नियंत्रण उपायों के रूप में पोत परिवहन प्रतिबंध लगाने और आदेशों को रद्द करने से निर्यात और आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह प्रभावित हुई। राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के रूप में व्यापक नीति सहयोग से 2020 की दूसरी छमाही में मंदी के कम होने की आशा है।

अन्य ब्रिक्स देशों के बीच, 2019 की दूसरी छमाही में रूस की आर्थिक गतिविधियां गतिशील दिखाई दीं जैसा कि उन्नत खुदरा बिक्री, मजबूत श्रम बाजार और गिरती मुद्रास्फीति में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में वृद्धि और कम ब्याज दरें 2019 की चौथी तिमाही में गतिविधि में सहयोग करती प्रतीत होती हैं। 2020 की पहली तिमाही में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से खुदरा बिक्री के बढ़ने से अभी तक अर्थव्यवस्था ने गति को बनाए रखा है, जबकि जनवरी में मंद रहने के बाद फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में सुधार हुआ है। हालांकि, सऊदी अरब के साथ तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी से बड़ा निम्नगामी जोखिम

दिखता है। निर्माण और खनन गतिविधि तथा निजी उपभोग में गिरावट के कारण वर्ष के समापन पर ब्राजील की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में रही। 2020 की पहली तिमाही के दौरान, प्राप्त आंकड़े औद्योगिक उत्पादन और खुदरा बिक्री में मंदी का संकेत देते हैं, जबकि कोविड-19 से अनिश्चितता बढ़ने पर बाहरी क्षेत्र की गतिशीलता बिगड़ने से आने वाले समय में संवृद्धि के और अधिक गिरने की संभावना है। चौथी तिमाही में दक्षिणी अफ्रीका की अर्थव्यवस्था ने पिछले दो वर्षों में दूसरी बार तकनीकी मंदी में प्रवेश किया क्योंकि बार-बार बिजली की कटौती के चलते कृषि, परिवहन और निर्माण गतिविधियों में तेजी से गिरावट आई। इसके अलावा, आपूर्ति की कमी के कारण निर्यात वृद्धि में गिरावट और कमजोर नियत निवेश तथा सरकारी खर्च ने और अधिक निम्नगामी दबाव बना दिए।

इंडोनेशिया में, आर्थिक गतिविधियों ने गति बनाए रखी: 2019 की चौथी तिमाही में जीडीपी संवृद्धि की गति तीसरी तिमाही के समान ही रही। आयात में गिरावट के कारण बाहरी क्षेत्र से धनात्मक योगदान ने कमजोर नियत निवेश और घरेलू



उपभोग की भरपाई कर दी। जबकि मजबूत आधारभूत संरचना व्यय और निभावकारी मौद्रिक नीति से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशा है, लेकिन आने वाले समय में महामारी से पैदा होने वाले निम्नगामी जोखिम गति को प्रभावित कर सकते हैं। थाइलैंड में, चौथी तिमाही में जीडीपी संवृद्धि ने वर्ष दर वर्ष के आधार पर पांच साल के निचले स्तर को छू लिया, जो कमजोर घरेलू और बाहरी मांग, सरकारी बजट में देरी और सूखे के कारण थी। पहली तिमाही का संवृद्धि आउटलुक धूमिल बना रहेगा क्योंकि कोविड-19 के कारण पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित होगा।

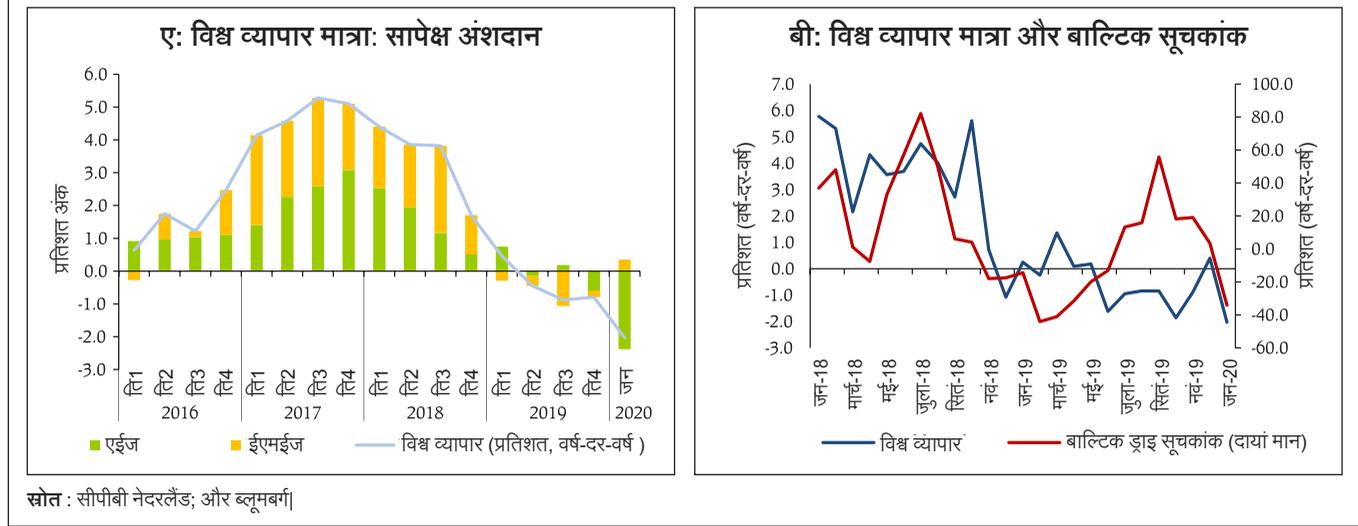
फरवरी-मार्च में वैश्विक संमिश्र पीएमआई में गिरावट आई जिसने अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य में आई उर्ध्वगामी प्रवृत्ति को उलट दिया। यह सूचकांक मजबूत कारोबारी आशाओं पर आधारित आउटपुट, नए आर्डर और तेजी से रोजगार पैदा होने के कारण जनवरी में दस महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, फरवरी से यह तेजी से गिरा, कोविड-19 की वजह से होने वाले व्यवधानों के बीच विनिर्माण और सेवा गतिविधि दोनों में काफी अधिक गिरावट के कारण मार्च में यह 133 महीने के निचले स्तर से गिरकर 39.4 तक पहुंच गया (चार्ट

V.1ए)। प्रमुख ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में, दिसंबर तक के लिए उपलब्ध संमिश्र अग्रणी संकेतक (सीएलआई) यह सुझाते थे कि 2019 के अंतिम महीनों में प्रमुख आई और ईएमई में संवृद्धि की गति मजबूत रहेगी (चार्ट V.1 बी)।

2019 की दूसरी छमाही में वैश्विक व्यापार की मंदी और गहरी हो गई क्योंकि 2019 की तीसरी तिमाही के दौरान आई की व्यापार मात्रा में हुआ थोड़ा सुधार अल्पकालिक था, 2019 की चौथी तिमाही में संकुचन दोबारा जगह बना रहा है। ईएमई ने 2019 की सभी चारों तिमाहियों में वैश्विक व्यापार को नीचे धकेला (चार्ट V.2ए)।

अग्रिम संकेतक यह बताते हैं कि कोविड-19 के कारण आपूर्ति और मांग में संकट होने से 2020 की पहली तिमाही में विश्व व्यापार वृद्धि कमजोर रहने की संभावना है। कृषि के कच्चे माल और कंटेनर लदान से संबंधित घटक सूचकांकों में संकुचन की वजह से डब्ल्यूटीओ का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर रुझान से नीचे रहा। कोयला, लौह अयस्क और अनाज जैसे अनेक प्रकार के थोक पण्यों के लिए लदान-लागत को मापने वाला बाल्टिक ड्राई सूचकांक लगातार मंदी प्रदर्शित करता रहा है (चार्ट V.2 बी)।

चार्ट V.2: विश्व व्यापार मात्रा



V.2 पण्य कीमतें और मुद्रास्फीति

2019 की चौथी तिमाही में व्यापारिक अनिश्चितताओं में कमी आने व अमेरिकी डॉलर कमजोर होने के कारण वैश्विक पण्य कीमतें काफी हद तक समर्थित रहीं। हालांकि, जनवरी की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच उत्पन्न विवाद से विश्व में पैदा प्रतिकूल स्थितियों और कोविड-19 के प्रकोप के बाद अधोगामी दबावों का सामना करना पड़ा। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच 20.5 फीसदी तक की गिरावट हुई।

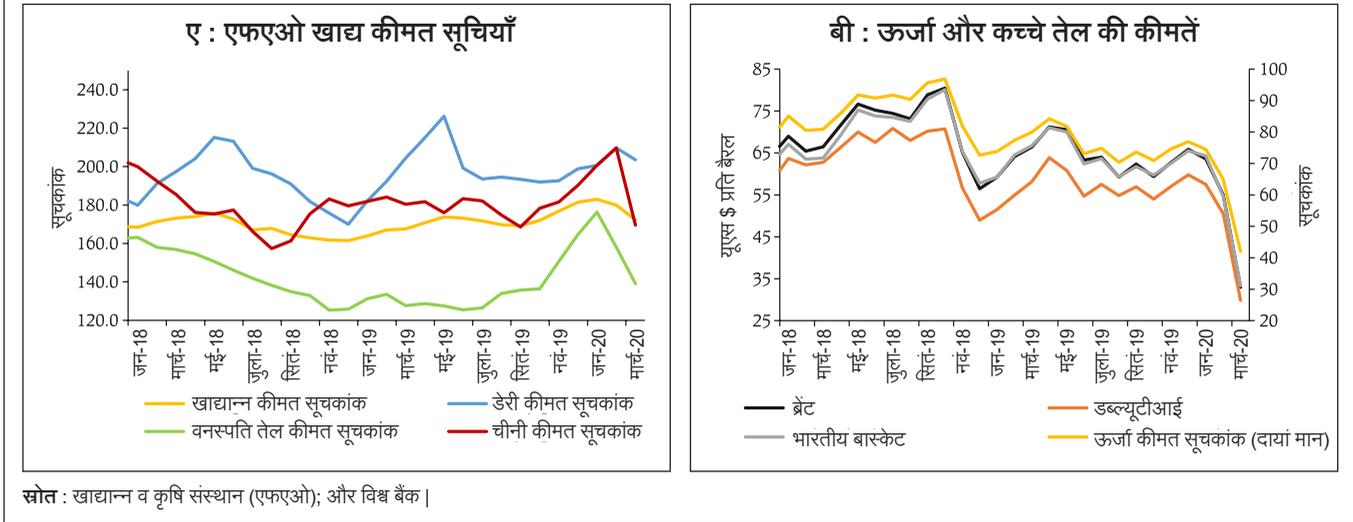
इसके विपरीत, अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के दौरान खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वैश्विक खाद्य कीमतों में मजबूती अक्टूबर 2019 से शुरू होकर दिसंबर में पाँच वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गई और तेल, चीनी और दुग्ध उत्पादों की बढ़ती कीमतों के बाद मजबूत मांग और दुनिया की आपूर्ति के दबाव के कारण जनवरी 2020 तक मजबूती बनी रही। फरवरी में वनस्पति तेल की कीमत में भारी गिरावट के कारण खाद्य मूल्य सूचकांक में गिरावट आई, जो बाद में मलेशिया से अतिरिक्त आपूर्ति पर नरम हो गया और वैश्विक मांग में गिरावट का डर बन गया। प्रमुख उत्पादकों द्वारा निर्यात की आपूर्ति को सख्त करने और मजबूत मांग के कारण चीनी और डेरी की कीमतें बढ़ी हैं। मार्च में, मुख्य रूप से वनस्पति तेल और चीनी की कीमतों में तेज गिरावट और कोविड-19 महामारी (तालिका V.3ए) के बीच मांग के संकुचन

के कारण सूचकांक में और गिरावट हुई।

जनवरी के अंत में कीमतों में गिरावट से पहले, ओपेक द्वारा विस्तारित उत्पादन कटौती के कारण 2019 की चौथी तिमाही में कच्चे तेल की कीमतें बड़े पैमाने पर समर्थित बनी रही थीं। कच्चे तेल की कीमतें अमरीका-ईरान तनाव बढ़ने के कारण 6 जनवरी, 2020 को तेज़ी से बढ़कर प्रति बैरल यूएस डॉलर- 69 हो गयी थीं, लेकिन तनाव कम होने के कारण इसमें सुधार हुआ। जनवरी के अंत तक तेल की कीमतें कोविड-19 की वजह से मांग में कमी की आशंकाओं के कारण तीव्र दबाव में आ गईं जिससे 9 मार्च, 2020 तक इसमें लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई। रूस के साथ उत्पादन में कटौती समझौते में विफल होने के बाद सऊदी अरब द्वारा आपूर्ति में वृद्धि की गई जो मूल्य युद्ध की आशंका जताता है (तालिका V.3बी)। 30 मार्च, 2020 को, डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल यूएस डॉलर 20 से नीचे फिसल गईं जिसकी प्रमुख वजह कोविड-19 है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है।

अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच, ब्लूमबर्ग के बेस मेटल इंडेक्स द्वारा मापी गई आधार धातु की कीमतों में 17.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कि विशेषकर मांग में कमी होने के कारण थी। अमेरिका और चीन के बीच चरण एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद पर अक्टूबर-दिसंबर के दौरान इन कीमतों में मजबूती ने मध्य जनवरी 2020 से मंदी की संभावनाओं को कम कर दिया। चीनी सीमाओं से बाहर निरंतर बढ़ रहे संक्रमण

चार्ट V.3 : पण्य कीमतें

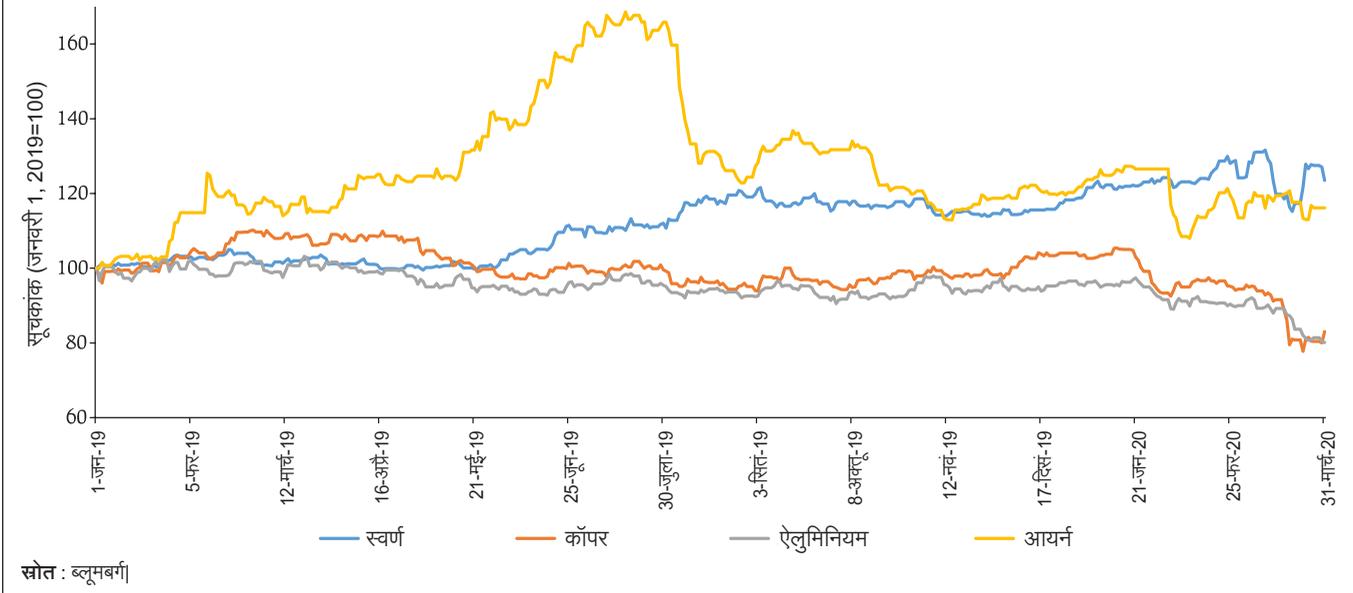


के मामलों और वैश्विक मंदी की चिंताओं ने धातु की कीमतों को कम करने के दबाव को तेज कर दिया है। (चार्ट वी.4)।

वैश्विक वृद्धि आउटलुक (बॉक्स V.2) में बढ़ी चिंताओं के बीच सुरक्षित मांग के कारण मूल्य में तेजी बने रहने की वजह से जनवरी-फरवरी में स्वर्ण की कीमतों में बढ़त बनी रही। हालांकि, मार्च के मध्य से स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि अत्यधिक उतार-चढ़ाव के बीच निवेशक अन्य बाजारों में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए नकदी की ओर बढ़े जिसके कारण बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई जिससे स्वर्ण यूएस डॉलर 1500 प्रति ट्राय औंस मार्क से नीचे आ गया।

मुद्रास्फीति मुख्य रूप से प्रमुख एईज में नियंत्रित रही, लेकिन प्रमुख ईएमईज में खाद्य की कीमतों में मजबूती रही। अक्टूबर की शुरुआत से स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के कारण अमेरिकी सीपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि कोविड-19 के व्यवधानों के बीच फरवरी में यात्रा में कमी और ईंधन की कीमतों में गिरावट के कारण इसमें मामूली नरमी आई। कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) अपस्फीतिकारी में परिवर्तन के संदर्भ में - फेड का मुख्य उपाय - मुद्रास्फीति फेड के लक्ष्य से 2 प्रतिशत नीचे रही। यूरो क्षेत्र में भी, मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे रही। हालांकि ऊर्जा और खाद्य

चार्ट V.4 : धातु कीमत सूचियाँ



बॉक्स V.2: स्वर्ण की कीमतों का संचालन कौन करता है?

एक वित्तीय संपत्ति के रूप में, स्वर्ण का आकर्षण आमतौर पर वित्तीय उथल-पुथल के समय में बढ़ जाता है। हाल ही में, कोविड-19 के कारण एक गहरी वैश्विक मंदी आने की चिंताओं ने सुरक्षित पनाह के रूप में इसकी मांग को बढ़ा दिया है। वर्ष के आधार पर, 2019 में 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ स्वर्ण की कीमतों में 11 प्रतिशत (09 मार्च, 2020 तक) की बढ़ोतरी हुई (तालिका V.2.1ए)। स्वर्ण के फ्युचर्स में भी अधिक कारोबार हुआ (तालिका V.2 1बी)। 2019 से, जोखिम-रहित संभावनाओं ने स्वर्ण के लिए समग्र मांग को मजबूत रखा, साथ ही उच्च एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इनफ्लो सुस्पष्ट रहा तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में खरीद के साथ-साथ सीओएमईएक्स नेट लॉन्ग पोजिशन में भी वृद्धि हुई। कोविड-19 के अत्यधिक जोखिम के बीच 2020 के मध्य मार्च तक स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि बनी रही, लेकिन अत्यधिक अस्थिरता और नकदी रखने के प्रति अत्यधिक वरीयता के कारण इसकी चमक भी फीकी पड़ने लगी। इसी वजह से 9 से 19 मार्च, 2020 के बीच स्वर्ण की कीमतों में 12 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, मार्च 2020 के अंत में कुछ सुधार के साथ, स्वर्ण की कीमतों में सालाना आधार पर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (31 मार्च, 2020 तक)।

अनुभवजन्य साहित्य में स्वर्ण की कीमतों के प्रमुख संचालकों में कई घटकों के समूह का अभिनिर्धारण किया गया है, यथा, तेल की कीमतें, वैश्विक चलनिधि स्थितियां, विनिमय दर, स्फीति, बॉन्ड से अर्जन, स्टॉक की कीमतें और आर्थिक नीति की अनिश्चितता

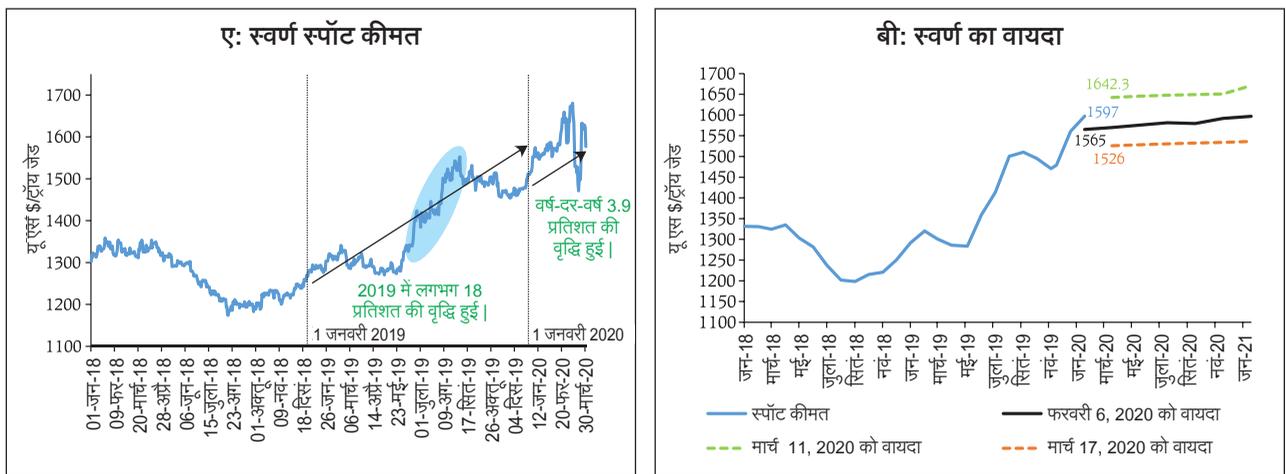
निवेशक, स्वर्ण को पोर्टफोलियो विविधीकरण का एक उपाय मानते हैं, क्योंकि यह अन्य वित्तीय लिखतों से होने वाले कीमत संबंधी जोखिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक और वित्तीय विप्लवों के समय में यह निरापद निवेश के रूप में रहता है (लेविन तथा अन्य, 2006, बुआर एन्ड लूसे, 2010; एम्स्रिख और मॅकग्राट्टे, 2013; और बिलिन तथा अन्य, 2018)।

स्वर्ण की कीमतों के डायनामिक्स को जॉन्सन की कोइन्टीग्रेसन पद्धति में जांचा गया है ताकि दीर्घकाल में इसके संबंधों का आकलन किया जा सके। स्वर्ण की कीमतों (एलजीओएलडी), यूएस सामान्य कीमत सूचकांक (एलसीपीआईयूएस) और यूएस की वास्तविक विनिमय दर (एलआरईआईआरयूएस) इस एकीकरण की एक व्यवस्था या (1) हैं और इसलिए इनके बीच दीर्घकालिक संबंध बना रह सकता है, जैसा कि कोइन्टीग्रेसन हेतु परीक्षणों से निष्पन्न होता है। दीर्घकाल के लिए अनुमानित समीकरण निम्नानुसार है:

$$LGOLD = -10.6 - 2.8 \log(LREERUS) + 1.7 LCPIUS \quad \dots(1)$$

समीकरण (1) स्वर्ण-कीमतों के अल्पावधिक डायनामिक्स को हासिल करने के लिए संवर्धित है, जबकि इसमें बहिर्जात घटकों – यथा – वैश्विक आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता (ईपीयू) सूचकांक⁴, यूएस इक्विटी बाजारों में परिवर्तनों के लिए स्टैंडर्ड एन्ड पूअर द्वारा प्राक्सी देने पर निरापदता की तरफ अंतरण (Δएलएस&पी) और ब्रेन्ट हाजिर कीमतों (Δएलओआईएल) में परिवर्तनों पर नियंत्रण रखा गया है।

चार्ट V.2.1: स्वर्ण कीमत उतार-चढ़ाव



स्रोत : ब्लूमबर्ग और विश्व बैंक।

(जारी)

⁴ डेविस स्टीवन जे. (2016), " वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता, समष्टि आर्थिक समीक्षा, अक्टूबर।

अल्पाकालिक समीकरण का अनुमान एआरसीएच प्रभावों का समायोजन करते हुए लगाया गया है, क्योंकि त्रुटियों को विषमवितरित पाया गया। स्वर्ण की कीमतों में माह के दौरान अत्यधिक उतार-चढ़ाव की अवधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले टाइम प्रतिरूपों (अक्टूबर 2008 और मई 2006) को शामिल किया गया (तालिका V.1.1)। सही ऋणात्मक संकेत वाली त्रुटि संशोधन टर्म सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यह इंगित करता है कि दीर्घकालिक संबंध के लिए स्वर्ण कीमत का प्रतिलाभ और अनुमानित प्रदर्शन सुस्थिर है, जिसे ऋणात्मक चिह्न के साथ एक लैंग पर महत्वपूर्ण पाया गया। इससे ज्ञात होता है कि यूएस डालर का मूल्यहास होने से यूएस डालर से बाह्य क्षेत्रों में स्वर्ण सस्ता हो जाएगा जिससे स्वर्ण की उच्चतर मांग होगी और यूएस डालर के परिप्रेक्ष्य में स्वर्ण की कीमतें बढ़ जाएंगी, अल्पावधि में स्वर्ण की कीमतों के साथ इसका ऋणात्मक संबंध

रहेगा, जिसका आशय यह हुआ कि यूएस में उच्चतर मुद्रास्फीति स्वर्ण की मांग को नरम और इसकी मांग को कम कर सकती है। इसे कई घटकों - यथा - केन्द्रीय बैंक की नीतियों, मंदी से पहले ही निवेशकों द्वारा नकदी रखने को प्राथमिकता और दीर्घावधिक संबंध को विचलित करने वाली अनिश्चितता - पर आरोपित किया जा सकता है। अन्य चरांक यथा - आर्थिक और राजनैतिक अनिश्चितता, स्टॉक सूचकांक और कच्चे तेल की कीमतों के अपने-अपने अनुमानित चिह्न थे और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे।

सारांश तौर पर इस अनुभवजन्य निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि अल्प अवधि में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और यूएस डालर के मूल्यहास से स्वर्ण की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ इक्विटी की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही स्वर्ण की कीमतों में गिरावट होती है। स्वर्ण की कीमतें भी आर्थिक नीति की अत्यधिक अनिश्चितता के साथ जुड़ी रहती हैं, इससे आस्तिक का निरापद निवेश लक्षण इंगित होता है।

सारणी V.1.1: सोने की कीमतों में परिवर्तन का अल्पकालिक अनुमान

	गुणांक	P- मूल्य
ईसीएम	-0.071	0.00
$\sum_{i=1}^3 \Delta LGOLD$	-0.090	0.512
$\sum_{i=1}^3 \Delta LCPIUS$	-3.13	0.004
$\sum_{i=1}^3 \Delta REERUS$	-1.217	0.001
$\Delta LOIL$	0.124	0.001
$\Delta LS\&P$	-0.222	0.014
ईपीयू	0.022	0.000

टिप्पणियाँ:

- मानकीकृत अवशिष्टों के कोरलोग्राम पर आधारित नैदानिक परीक्षण अवशिष्टों में कोई ऑटो कोरलेशन नहीं सुझाते हैं।
- मानकीकृत अवशिष्ट वर्गों के कोरलोग्राम किसी अवशिष्ट विषमता का सुझाव नहीं देते हैं।
- ARCH LM परीक्षण p- मान: 0.116

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

संदर्भ:

बाउर, डी. जी. और बी. एम. लुसी (2010), "इज गोल्ड ए हेज ऑर सेफ हेवन? स्टॉक, बॉन्ड्स और गोल्ड का विश्लेषण", वित्तीय समीक्षा, 45, 2, पीपी 217-229।

बिलगिन, एम. एच., जी गोजगोर, सी के लाऊ और एक्स शेंग (2018), "द इफैक्ट ऑफ अनशट्टेटी मेजर्स ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड", वित्तीय विश्लेषण की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, 58, पीपी.1-7, <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.03.009>

इमरिच ओ और एफ मेग्रोर्टी (2013), "शुड गोल्ड बी इंकलूडेड इन इंटूटीओनल इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो? अनुप्रयुक्त वित्तीय अर्थशास्त्र, 23, पीपी 1553-1565।

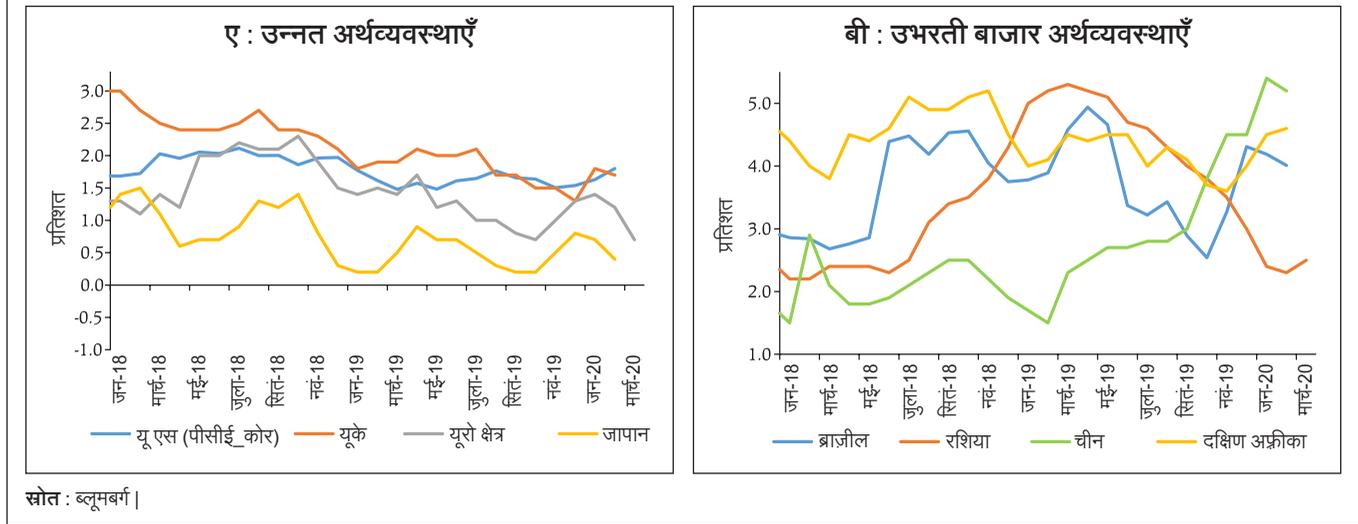
लेविन, ई जे, ए मोंटागनोली और आर ई राइट (2006), "शॉर्ट-रन एंड लॉन्ग-रन डेटरमिनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड", वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, रिसर्च स्टडी नंबर 32, <http://strathprints.strath.ac.uk/7215/1/strathprints007215.pdf>.

मुद्रास्फीति में तेजी आई, लेकिन अंतर्निहित मुद्रास्फीति के उपाय आमतौर पर मौन रहे। तथापि, मार्च में ऊर्जा की कीमतों में तेज गिरावट के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति और नरम हुई। जापान में, सीपीआई मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर बनी रही और फरवरी में खाद्य कीमतों में नरमी और ईंधन की कीमतों में गिरावट इसे और नीचे ले गई (तालिका V.5ए)।

रूस को छोड़कर प्रमुख ईएमई में मुद्रास्फीति बढ़ी। चीन में सूअर के मांस की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीतिकारी दबाव का सामना किया गया, जो जनवरी में नए साल की छुट्टी के दौरान मौसमी मांग के कारण बढ़ गया था। हालांकि, फरवरी में

गैर-खाद्य कीमतों में कुछ हद तक नरमी के कारण मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आई। नवंबर से ब्राजील में खाद्य कीमतों विशेष रूप से मांस और परिवहन कीमतों में मजबूती के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़ रही है, हालांकि फरवरी में खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में गिरावट ने कुछ राहत प्रदान की। दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से भोजन, गैर-मादक पेय और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण फरवरी में लगातार तीसरे महीने मुद्रास्फीति बढ़ी। अक्टूबर 2019 से 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे गिरने की वजह से रूस में सीपीआई मुद्रास्फीति कम हुई। बाहरी मांग में गिरावट, अत्यधिक आपूर्ति के बीच खाद्य कीमतों में

चार्ट V.5: चुनिन्दा अर्थव्यवस्थाओं में सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



गिरावट और एक साल पहले वेट दर वृद्धि से संबंधित मजबूत आधार प्रभाव ने गिरावट को तीव्र कर दिया। हालांकि, मार्च में सेवाओं और गैर-खाद्य कीमतों में मामूली वृद्धि हुई (तालिका V.5बी)।

V.3 मौद्रिक नीति का रुख

2019 में, जीएफसी के बाद से मौद्रिक नीति को दुनिया भर में सबसे अधिक समायोजनकारी बताया गया। अधिकांश एई और कुछ ईएमई ने भी अपनी नीति दर को 2019 की चौथी तिमाही में स्थिर बनाए रखा, लेकिन 2020 की पहली तिमाही में कोविड-19 के प्रकोप और उसके तेजी से प्रसार के फलस्वरूप पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों उपायों के माध्यम से व्यापक ईजिंग का सहारा लिया गया।

यूएस फेड, जिसने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 की दो क्रमिक एफओएमसी बैठकों में कोई वृद्धि नहीं की, ने 3 मार्च को 50 बीपीएस और 15 मार्च को 100 बीपीएस की कटौती करके आपातकालीन दर कटौती का सहारा लिया (चार्ट वी 6 ए)। इन तेज कटौतियों से, फेड ने फेडरल फंड्स दर की लक्ष्य सीमा को जीएफसी के दौरान के स्तर पर ला दिया। फेड ने कई अन्य उपायों की भी घोषणा की, जैसे- खरीद कार्यक्रम में वाणिज्यिक

बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों सहित बाजार के सुचारुपूर्वक कामकाज और मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रसारण को समर्थन देने के लिए आवश्यक संपत्ति की खरीद, फेडरल फंड्स दर की शीर्ष लक्ष्य सीमा के समान प्राथमिक क्रेडिट पर ब्याज दर को कम करना, बैंकों को उधार देने के लिए पूंजी और तरलता बफर्स का उपयोग करने की अनुमति देना और आरक्षित निधियों की अपेक्षा को शून्य तक कम करना आदि। संकट काल से सावधि परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूति ऋण सुविधा को पुनः शुरू करते हुए, फेड ने वाणिज्यिक पत्र, प्राथमिक व्यापारी और मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंड को वित्तीय सपोर्ट प्रदान करने के लिए समर्पित सुविधाओं की भी शुरुआत की हैं। नए कार्यक्रमों के तहत, फेड बड़े नियोक्ताओं को भी क्रेडिट संबंधी सपोर्ट प्रदान करेगा। इसके अलावा, फेड ने अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ डॉलर तरलता स्वैप लाइन का भी विस्तार किया है और विदेशी और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्राधिकारियों के लिए एक अस्थायी रेपो सुविधा स्थापित की है।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने सितंबर 2019 की बैठक में घोषित जमा दर में 10 बीपीएस की कमी के बाद से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं किया है। हालांकि, मार्च 2020 की बैठक में, ईसीबी ने अतिरिक्त € 120 बिलियन की निवल आस्ति खरीद, लंबी अवधि के अस्थायी पुनर्वित्तीयन परिचालन और जून 2020 से एक वर्ष के लिए लक्षित लंबी अवधि के पुनर्वित्तीयन परिचालनों (टीएलटीआरओ) III के लिए और अधिक अनुकूल शर्तों और

⁵ देखें <https://blogs.imf.org/2020/01/28/a-call-for-vigilance-after-a-strong-year-for-risky-assets/>, और <https://www.ft.com/content/b8709ca4-e8f8-11e9-85f4-d00e5018f061>.

परिमाण की घोषणा की। ईसीबी ने एक नए € 750 बिलियन के पेंडेमिक इमरजेंसी परचेज प्रोग्राम (पीईपीपी) की भी घोषणा की, जिसके तहत 2020 तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की सिक्योरिटीज की खरीद की जाएगी जिसमें ग्रीक सरकार के बांड सहित सभी आस्ति वर्गों और क्षेत्राधिकारों में समय के साथ खरीद प्रवाहों में लचीलापन रखा जाएगा। ईसीबी ने अपने कॉर्पोरेट क्षेत्र खरीद कार्यक्रम के लिए पात्र आस्ति के रूप में गैर-वित्तीय वाणिज्यिक पत्र को भी शामिल किया, और इसके पुनर्वित्तीयन परिचालन के लिए संपार्श्विक अपेक्षाओं को कम किया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड (BoE), जो अगस्त 2018 में बैंक दर को बढ़ाने के बाद विराम पर था, ने मार्च में 50 बीपीएस और 15 बीपीएस की दो आउट-ऑफ-टर्न दर कटौती की - जिससे बैंक दर को 0.1 फीसदी की सर्वाधिक निम्न स्थिति में ला दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2020 में £ 200 बिलियन की अतिरिक्त आस्तियों की खरीद को जल्दी ही पूरा करने की घोषणा की। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोविड-19 के नतीजों से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के प्रयोजन से समष्टि विवेकपूर्ण शिथिलताओं और अन्य प्रोत्साहनों की भी घोषणा की।

बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी), जो अक्टूबर 2019 के बाद से एक ठहराव पर था, ने मार्च 2020 में अपनी नीतिगत दर में सामूहिक रूप से 150 बीपीएस की कटौती की, जिससे कोविड -19 महामारी के दौरान कनाडाई वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान की जा सके। यह कटौती 50 बीपीएस के तीन चरणों में 0.25 प्रतिशत पर की गई। बैंक ऑफ कनाडा ने एक मात्रात्मक सुगमता कार्यक्रम शुरू करने सहित नए चलनिधि सहायता उपाय भी शुरू किए हैं।

बैंक ऑफ जापान ने मार्च 2020 में मौद्रिक सुगमता को बढ़ाने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA), जो अक्टूबर में नकदी दर को घटाकर सबसे कम रखने के पश्चात नवंबर 2019 से एक ठहराव पर था, ने मार्च में नकदी दर में दो अवसरों पर प्रत्येक 25 बीपीएस की कटौती की जिससे यह 0.25 फीसदी की नई निम्नता पर पहुंच गई। आरबीए ने प्रतिफल वक्र नियंत्रण जैसे अतिरिक्त उपाय किए जिन्हें बॉन्ड खरीद, टर्म फंडिंग सुविधा और बैंकों के विनिमय निपटान शेष के पारिश्रमिक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने मार्च में 75 बीपीएस की आपातकालीन दर कटौती की जिससे नीतिगत

दर 0.25 प्रतिशत के नए निम्न स्तर पर पहुंच गई। इसके अलावा, उसने खुले बाजार के परिचालनों के तहत खरीद और बाजार के कामकाज की सुचारुता को सपोर्ट करने के लिए अन्य उपायों की घोषणा की।

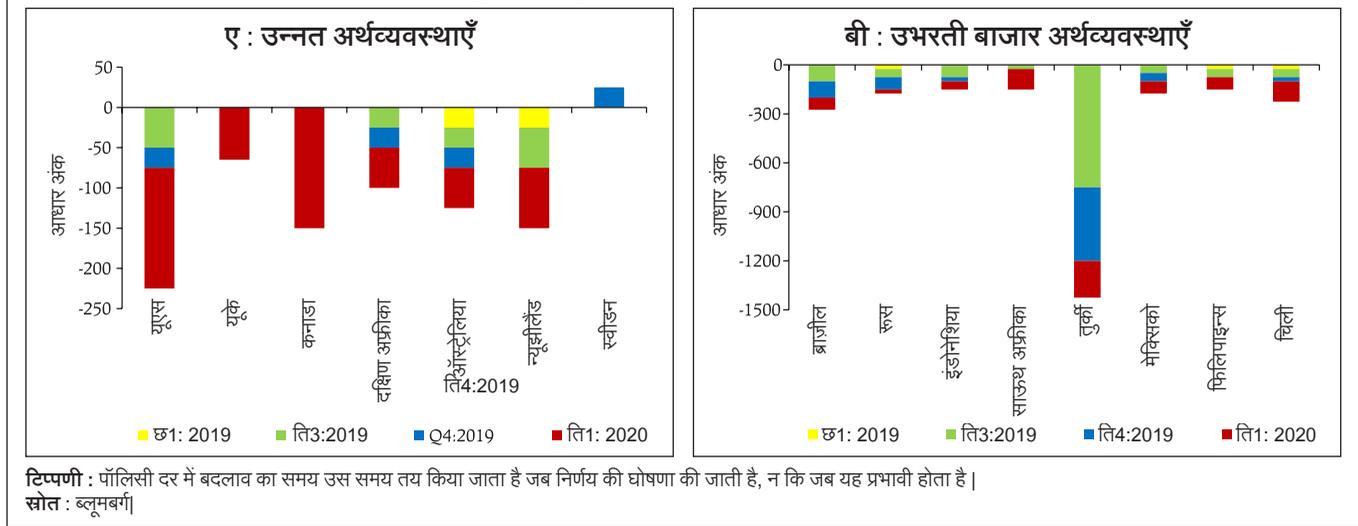
नवंबर 2019 से विराम के बाद, बैंक ऑफ कोरिया ने मार्च 2020 में 50 बीपीएस आपातकालीन दर कटौती की और आर्थिक और वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के लिए अन्य उपायों की घोषणा की।

रिक्सबैंक कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक था जिसने 2019 के दौरान दिसंबर 2019 में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी करके नीतिगत दरों को बढ़ाया, जिससे यह ऋणात्मक नीति दर क्षेत्र से बाहर हो गया। तथापि, मार्च में एक आपातकालीन मौद्रिक नीति बैठक में रिक्सबैंक ने एसईके 300 बिलियन की अतिरिक्त संपत्ति खरीदने की घोषणा की, इसके अलावा, उसने अनुकूल शर्तों और अन्य उपायों पर बैंकों को बढ़ी हुई निधि की पेशकश की।

ईएमई ने मौद्रिक सुगमता का भी मार्ग अपनाया है और अन्य तरलता सहायता उपायों की घोषणा की है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने नवंबर में एक साल के लोन प्राइम रेट (एलपीआर) में 5 बीपीएस कटौती की थी और फरवरी 2020 में 10 बीपीएस की कटौती के साथ इसका अनुसरण किया। पीबीओसी ने लूनर नव वर्ष अवकाश बढ़ाने के बाद 3 फरवरी को बाजार खुलने पर 1.2 ट्रिलियन चीनी युआन की चलनिधि बाजार में डाली। उसने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए कम लागत वाली पुनर्वित्तीयन सुविधा की भी घोषणा की। मार्च में, पीबीओसी ने बैंकों की कुछ श्रेणियों के लिए आरक्षित निधि अनुपात को कम किया और 7-दिवसीय रिवर्स रेपो दर को 20 बीपीएस से कम किया।

अन्य ब्रिक्स केंद्रीय बैंक समायोजन मोड में बने रहे। ब्राजील के केंद्रीय बैंक ने, जो प्रोत्साहनकारी मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है और अगस्त 2019 से सेलिक दर को कम कर रहा है, इस दर को 2019 की चौथी तिमाही में आगे दो और मौकों पर प्रत्येक 50 बीपीएस और इसके बाद फरवरी में 25 बीपीएस और मार्च में 50 बीपीएस घटा दिया। बैंक ने नियामक छूट और अन्य तरलता सहायता सुविधाओं की भी पेशकश की है। बैंक ऑफ रशिया, जो जून 2019 से प्रत्येक नीतिगत बैठक में अपनी नीतिगत दर को कम कर रहा था, ने अपनी अक्टूबर, दिसंबर और फरवरी की बैठकों में 25 बीपीएस की कटौती की, लेकिन मार्च की बैठक में

चार्ट V.6: चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीति दर परिवर्तन



एक ठहराव बनाए रखा। दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक, जिसने जुलाई 2019 में नीति दर में कटौती की थी और तब से एक ठहराव बनाए रखा था, ने जनवरी 2020 में रेपो दर को 25 बीपीएस और मार्च 2020 में और 100 बीपीएस कम कर दिया क्योंकि मुद्रास्फीति के मामूली बने रहने के साथ 2019 की दूसरी छमाही में मंदी में प्रवेश करने के कारण 2020 में दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था में संकुचन की उम्मीद थी (चार्ट V.6बी)।

तुर्की का केंद्रीय बैंक, जिसने जुलाई 2019 में नीतिगत समायोजन की शुरुआत की, ने नीतिगत दर में अक्टूबर 2019 से पांच अवसरों पर संचयी रूप से 675 बीपीएस की कटौती की। बैंको डे मेक्सिको, जिसने अगस्त 2019 के बाद से अपनी प्रत्येक बैठक में पॉलिसी दर में 25 बीपीएस की कटौती की क्योंकि कई तिमाहियों से संवृद्धि रुकी हुई थी फलस्वरूप, मार्च में 50 बीपीएस कटौती की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ फिलीपीन्स और बैंक इंडोनेशिया, जो सितंबर में दरों में कटौती के बाद विराम की स्थिति में थे, ने फरवरी 2020 में अपनी नीतिगत दरों में 25 बीपीएस की कटौती की और संवृद्धि को सपोर्ट करने के लिए मार्च में क्रमशः 50 बीपीएस और 25 बीपीएस की कटौती की। कोविड-19 की चिंताओं के कारण दरों में कटौती करने वाले अन्य केंद्रीय बैंकों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हैं, बैंक ऑफ थाईलैंड, बैंक नेगारा मलेशिया और सेंट्रल बैंक ऑफ चिली।

V.4 वैश्विक वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजारों ने 2019 की चौथी तिमाही में जोखिम की धारणा को कमजोर होने के लिए ऐसे अनेक कारकों को देखा, जिन्होंने बाजारों को मंद स्थिति में रखा - विशेष रूप से, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव; और ब्रेक्सिट के बारे में अनिश्चितता। अमेरिका-ईरान संघर्ष से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव के कारण जनवरी की शुरुआत में जोखिम न लेने की भावना प्रबल थी। हालांकि, शांति जल्दी बहाल हो गई लेकिन जब चीन ने 20 जनवरी को यह घोषणा की कि नॉवल कोरोना वायरस के मानव से मानव में संचरण के मामले सामने आए हैं, तो स्थिति बेहद अस्थिर हो गई, मार्च में ओपेक और रूस के बीच तेल उत्पादन कटौती पर असहमति से यह स्थिति और भी खराब हो गई। उसी सप्ताह में, उबल्यूएचओ ने कोविड -19 को महामारी के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके कारण बाजारों में उथलपुथल हो गई और दुनिया भर में वित्तपोषण की स्थिति दयनीय गई।

ई के बीच, 2019 की चौथी तिमाही में अमेरिकी इक्विटी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि अक्टूबर में यूएस फेड ने दरों में कटौती की, जबकि अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर ऐतिहासिक रूप से कम रहा। व्यापार के मोर्चे पर सकारात्मक खबर यह रही कि - प्रतिनिधि सभा ने यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौता पारित किया और अमेरिका और चीन के बीच चरण -एक समझौते की घोषणा की गई जिससे बाजारों में उछल आया। जनवरी में, ईरान

के साथ तनाव में वृद्धि ने कुछ समय के लिए इक्विटी को नीचे ला दिया था। कोविड-19 के प्रकोप के बाद एक और गिरावट हुई। चूंकि चीन ने कोविड-19 की सीमा और प्रभाव को सीमित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की, अमेरिकी इक्विटी फिर से बढ़ने लगी और फरवरी के तीसरे सप्ताह में यह सभी- समयों से उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसके तुरंत बाद, कोविड-19 के इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान में तेजी से प्रसार के साथ स्थिति बिगड़ गई और अमेरिकी सूचकांकों ने जीएफसी के बाद से अपना सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन दर्ज किया। यूएस फेड ने एक बयान जारी किया कि वह अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए तैयार है और उसने समय से पहले दर में कटौती की घोषणा की, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए बाजार में सुधार हुआ। रूस और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल के विवाद के नतीजे और कोविड -19 के महामारी घोषित होने के बाद, अमेरिकी इक्विटी बाजार में एक सप्ताह में दो दिन (9 और 12 मार्च) सर्किट ब्रेकर हुआ और 19 अक्टूबर, 1987 के ब्लैक मंडे के बाद से 12 मार्च सबसे खराब कारोबारी दिन रहा। फेड द्वारा दूसरी आपातकालीन दर कटौती के बाद, 16 मार्च को बाजार में फिर एक बार सर्किट ब्रेकर आया। मार्च के उत्तरार्ध में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कारण मामूली सुधार हुआ, जिसकी कीमत लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी।

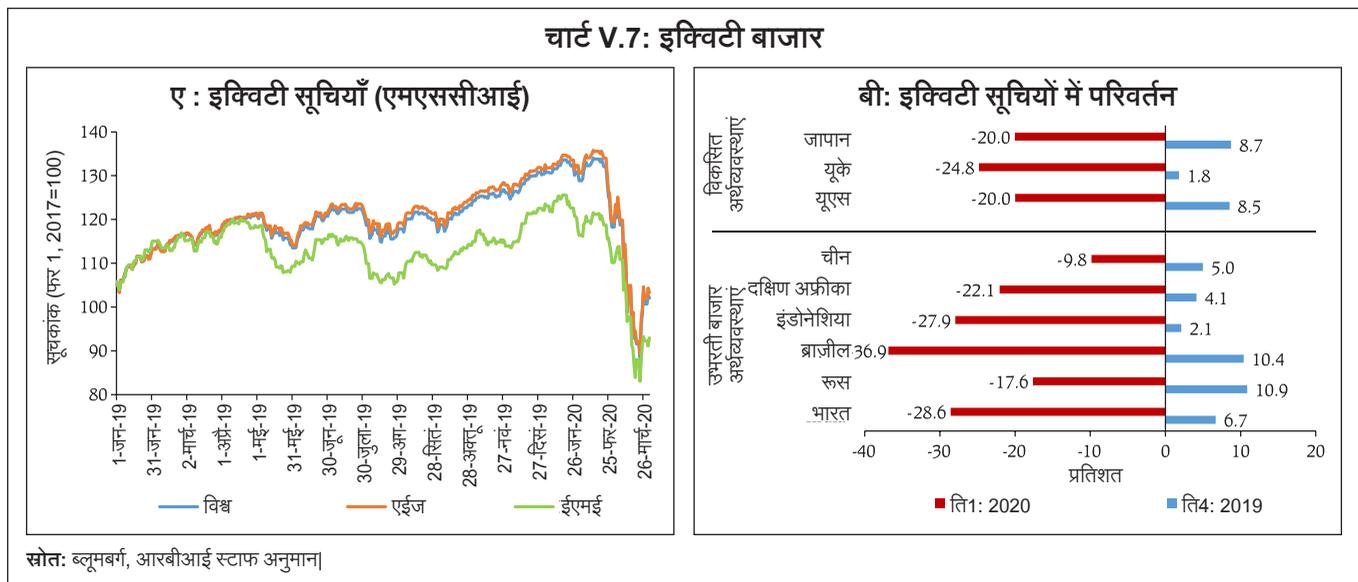
यूके और यूरो क्षेत्र में, यूके के आम चुनावों और ब्रेक्सिट के बारे में निश्चितता से इक्विटी बाजारों में दिसंबर से मजबूती हासिल

हुई। जापान में, समग्र विकास सुस्त रहने के बावजूद, अनुकूल मुद्रा संचलन के साथ उच्च लाभप्रदता की उम्मीद ने 2019 की चौथी तिमाही में स्टॉक में वृद्धि की। हालांकि, कोविड के फैलने से दुनिया भर के शेयर बाजारों की तुलना में उसके सूचकांक धड़ाम हो गए।

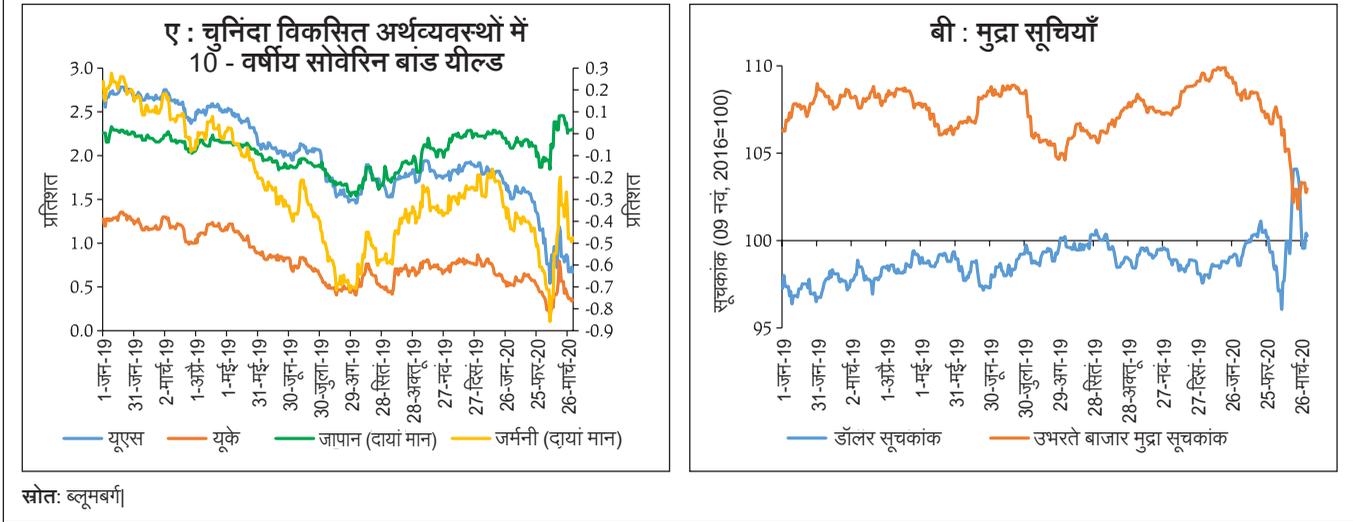
ईएमई के शेयर बाजारों ने इस पैटर्न को दिखाया। जोखिम लेने की भावनाओं से प्रेरित अधिकांश ईएमई के शेयर बाजारों में 2019 की चौथी तिमाही में अच्छा लाभ हुआ (चार्ट V.7)। 2020 की पहली तिमाही में, ईएमई शेयर बाजार मुख्य रूप से कोविड-19 के चिंताओं से प्रभावित थे, जिसमें मार्च में कच्चे तेल के मूल्य युद्ध से अतिरिक्त हेडविंड उत्पन्न हुआ। विस्तारित लूनर विराम के बाद चीनी स्टॉक 3 फरवरी को गिर गया। अन्य ईएमई बाजारों में मार्च के दूसरे सप्ताह में बार-बार ट्रेडिंग प्रतिबंध लगाए जाने से तीव्र गिरावट हुई।

वैश्विक विकास आउटलुक में सुधार और 2019 की चौथी तिमाही में व्यापार तनाव में कमी के साथ, जोखिम लेने की संभावनाओं के चलते प्रमुख एई के बीच बॉन्ड प्रतिफल मजबूत हुए। कोविड-19 के कारण प्रतिफल सेफ हेवन मांग की वजह से नीचे चले गए। अमेरिका में, फरवरी के चौथे सप्ताह में 10-वर्षीय प्रतिफल में ऐतिहासिक गिरावट हुई क्योंकि शेयर बाजार गिर गए और सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ गई, साथ ही चीन के बाहर कोविड -19 के तेजी से प्रसार और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की अमेरिकी निवासियों को बढ़ते जोखिम की

चार्ट V.7: इक्विटी बाजार



चार्ट V.8 : बांड प्रतिफल और मुद्रा उतार-चढ़ाव



चेतावनी से गुणवत्ता की तरफ भागने के लिए दृष्टांत मिला। फेड द्वारा पहली आपातकालीन दर में कटौती के बाद प्रतिफल एक प्रतिशत से कम हो गया, जो मामूली रूप से सुधार होने से पहले, 9 मार्च को सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया (सारणी V.8ए)।

इसी तरह अन्य एईज के बॉण्ड में उछाल देखा गया, जिसमें प्रतिफल यूके और यूरो क्षेत्र में नए निचले स्तर तक पहुंच गया। एईज के बीच बॉण्ड प्रतिफल 9 मार्च तक लगातार घटता-बढ़ता रहा, लेकिन इसके बाद 10 वर्षीय जापानी प्रतिफल के धनात्मक होने के कारण यह तेजी से बढ़ा। सामान्य रूप से, ईएमई में प्रतिफल 2019 की चौथी तिमाही में प्रतिफल की खोज में कमी के कारण नरम हो गए। हालांकि, फरवरी तक प्रतिफल व्यापक रूप से दायरे के अंतर्गत रहे, लेकिन मार्च में जोखिम न लेने की तीव्र भावना से स्थिति बिगड़ी और इन अर्थव्यवस्थाओं में प्रतिफल में तेजी आई।

अक्तूबर में फेड द्वारा नीतिगत दर में कमी और इस गाइडेंस के चलते कि इसमें विराम लगेगा, मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो गया। व्यापार तनाव कम होने के साथ जनवरी में डॉलर में सुधार हुआ। कोविड-19 के कारण, सुरक्षित मांग ने डॉलर इंडेक्स को और आगे बढ़ाया। हालांकि, अमेरिका में वायरस फैलने और बढ़ती मृत्यु के साथ

फेड द्वारा दर में कटौती करने से मार्च की शुरुआत में डॉलर कमजोर हुआ (चार्ट V.8बी)। उभरते बाजारों की अधिकांश मुद्राएं, जो 2019 के अंत में जोखिम लेने की धारणा के कारण मजबूत हुईं, 2020 की पहली तिमाही में सुरक्षा की ओर पलायन के कारण तेजी से कमजोर हुईं। 2019 की चौथी तिमाही में एमएससीआई उभरते बाजार के मुद्रा इंडेक्स में 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और 2020 की प्रथम तिमाही में 6.0 प्रतिशत की गिरावट आई।

V.5 निष्कर्ष

संक्षेप में, कोविड-19 ने वैश्विक विकास की संभावनाओं को जटिल बना दिया है, साथ ही निकट-अवधि आउटलुक बेहद कमजोर है। एईज में मुद्रास्फीति सौम्य बनी रही, और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट ने एक और निम्नगामी प्रवृत्ति को जन्म दिया है। हालांकि, कुछ ईएमई में मुद्रास्फीति की चिंता बनी हुई है, तथापि, कोविड-19 के कारण मुद्रास्फीति आउटलुक के संदर्भ में बहुत हद तक अनिश्चितता के बादल घिरे हुए हैं। वैश्विक वित्तीय बाजार बेहद अस्थिर हो गए हैं। मौद्रिक अधिकारियों और सरकारों द्वारा त्वरित और समन्वित कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिमों के आधिक्य को कम कर सकते हैं।

भाषण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और भावी दिशा
शक्तिकांत दास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम: चुनौतियां और भावी दिशा* शक्तिकांत दास

एसोचैम के 15वें वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। विशेषतः इसलिए क्योंकि यह एसोचैम का शताब्दी वर्ष है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और एसोचैम से जुड़े सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में, एसोचैम ने भारतीय व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को एक शक्तिशाली, सक्रिय, प्रगतिशील संगठन के रूप में बदला है। मुझे यकीन है कि उत्कृष्टता की दिशा में एसोचैम की यात्रा जारी रहेगी।

लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे देश में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और रोजगार के बड़े अवसर निर्माण करता है। एमएसएमई अतिरिक्त खेतिहर मजदूरों को अपने में समाहित करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या कम करने में सहायक है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक भी हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के पूरे इको-सिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हम सभी जानते हैं कि एमएसएमई क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इसलिए, एसोचैम द्वारा चुना गया आज के शिखर सम्मेलन का विषय -- 'एमएसएमई फंडिंग में संरचनात्मक सुधार'- अधिक सटिक और समीचीन नहीं हो सकता। आज मैं अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई के महत्व को रेखांकित करना चाहूंगा। मैं उनके सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए कुछ उपायों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं भावी दिशा के रूप में कुछ मुद्दों को भी सूचीबद्ध करूंगा।

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 मार्च 2020 को मुंबई में आयोजित 15वें एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में दिया गया भाषण।

I. अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण / अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर कुछ शोधपरक तथ्यों को मैं उजागर करना चाहूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 6.3 करोड़ इकाइयों का विशाल नेटवर्क है तथा वर्ष 2016-17¹ में सांकेतिक जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ महत्वपूर्ण योगदान है। कुल विनिर्माण उत्पादन में क्षेत्र की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत² से भी अधिक थी। शेष अर्थव्यवस्था को एमएसएमई क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले विविध लाभों का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक होने की अपेक्षा की है क्योंकि देश ₹ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था³ की महत्वाकांक्षा रखता है।

वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ अनुमानित रोजगार था। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर, तीन उप-क्षेत्रों में से प्रत्येक, अर्थात्, व्यापार, विनिर्माण और अन्य सेवाओं में कुल रोजगार का लगभग एक तिहाई रोजगार है। कुल एमएसएमई का लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है और कुल रोजगार का 45 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। दिलचस्प बात यह है कि एमएसएमई क्षेत्र⁴ में कुल उद्यमों के 97 प्रतिशत रोजगार में सूक्ष्म उद्यमों का योगदान है। यह वह समस्या है जिसे बीच की अनुपस्थिति⁵ कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि समय के साथ सूक्ष्म फर्में छोटी और मध्यम फर्मों में विकसित होने में असफल रही हैं। ऐसा लगता है कि इसने सूक्ष्म क्षेत्र को बड़े पैमाने की लागत का आनंद लेने, अचल संपत्तियों में निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

भारत के व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19⁶ में लगभग 48 प्रतिशत थी। जिसका तात्पर्य यह है कि

¹ वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई मंत्रालय 2018-19.

² सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: यू.के. सिन्हा), 25 जून, 2019.

³ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, 24 सितंबर, 2019.

⁴ वार्षिक रिपोर्ट एमएसएमई मंत्रालय 2018-19.

⁵ क्रूर, ए. ओ. (2013). दि मिसिंग मिडल. *इकोनॉमिक रिफॉर्मस इन इंडिया: चैलेंजेस, प्रोस्पेक्ट, एण्ड लेसन*, 299.

⁶ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2019.

भारतीय एमएसएमई विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं और उनके उत्पादों / सेवाओं को विदेशों में स्वीकार किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रयासों में सुधार के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को जारी रखा जाना चाहिए और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

II. एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियां

एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रमुख चुनौतियों में भौतिक बुनियादी ढांचागत बाधाएं; औपचारिक रूप न दे पाना; प्रौद्योगिकी अपनाने में सुस्ती बर्तना; क्षमता निर्माण; आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच की कड़ी; ऋण और जोखिम पूंजी तक पहुंच की कमी; और इनके साथ-साथ देरी से भुगतान की सार्वकालिक समस्या शामिल हैं। अब मैं इनमें से कुछ मुद्दों पर विस्तार से बात करता हूँ।

बुनियादी ढांचागत बाधाएं व प्रतिस्पर्धा

बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद, एमएसएमई क्लस्टर, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यम, अपर्याप्त रूप से आवश्यक समर्थन प्रणालियों से लैस हैं, जो न केवल उनके दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों को बाधित करते हैं, बल्कि उनके भविष्य की विकास की संभावनाओं को भी बाधित करते हैं। जबकि बुनियादी ढांचे की कमी कहानी का केवल एक पहलु है, मेरा मानना है कि प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए एमएसएमई को भी थोड़ा अधिक कार्य करने की जरूरत है। नई तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें अपने निषेध को छोड़ने की जरूरत है; ई-भुगतान स्वीकार करें; और इन-हाउस इन्नोवेशन को बढ़ावा दे जो उन्हें अपने व्यवसायों को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करेगा। वैश्विक व्यापार के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, व्यवसाय संचालन की सदियों पुरानी विधियों के साथ कम स्तर की प्रौद्योगिकी अपनाना, उन्हें पैमाने की संभावित अर्थव्यवस्थाओं से दूर रखती हैं। अपने छोटे आकार के कारण उत्पाद विकास, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और विपणन कार्यनीति में विशेषज्ञता का अभाव उनके आसपास के बदलते परिवेश के अनुकूल होने का दबाव बढ़ाता है। एमएसएमई की कार्यनीति, धीरे-धीरे आकार में विस्तार करने और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन संरचना पर निर्भरता कम करना होनी चाहिए। उनका उद्देश्य अंततः वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना होना चाहिए।

ऋण तक पहुंच और उसे औपचारिक रूप देना

एमएसएमई क्षेत्र के विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उचित लागत पर धन उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। हालांकि, इस क्षेत्र में ऋण वितरण हाल के समय में सुस्त रहा। कुल स्तर पर, बैंकों और एनबीएफसी से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक का कुल क्रेडिट सितंबर, 2019 के अंत तक लगभग ₹16.6 लाख करोड़ था। कुल बकाया क्रेडिट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 90 प्रतिशत है।

जैसा कि कई एमएसएमई मुख्य रूप से अनौपचारिक दायरे में कार्यरत हैं, विशेष रूप से उनके व्यवसायों के वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में, सूचना विषमता के कारण उनकी साख का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। संपार्श्विक की अनुपस्थिति में, ग्राहक के जोखिम को आंकने के लिए अक्सर उच्च परिचालन लागत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उनके छोटे पैमाने पर संचालन के कारण, एमएसएमई जोखिम पूंजी बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। वे ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आधारित हैं और जिसमें लाभार्थियों की डिजिटल पहचान और उपस्थिति होना आवश्यक है। हालांकि, जीएसटी और जेएएम ट्रिनिटी जैसे संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन के साथ, अनौपचारिक इकाइयां, हाल के वर्षों में मुख्यधारा के साथ एकीकृत हो रही हैं।

विलंबित भुगतान

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एमएसएमई बड़े उद्योगों की जरूरतों के लिए सहायक इकाई हैं। वे अक्सर विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करते हैं, जिससे उनका नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की उपलब्धता प्रभावित होती है। अधिकांश समय, ऐसी प्राप्य राशियां देरी से प्राप्त होने से उनके परिचालन चक्र बाधित होते हैं और नए ऑर्डर प्राप्त करने या मौजूदा को पूरा करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 2019 में किए गए एक प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चला है कि विनिर्माण गतिविधियों में लगे एमएसएमई में से 44 प्रतिशत एमएसएमई को विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा। समय पर भुगतान प्राप्त नहीं करने वाले लोग मुख्य रूप से मूल धातु और धातु उत्पाद, इंजीनियरिंग, निर्माण और बुनियादी ढांचे से संबंधित उद्योगों से संबंधित थे। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र में विलंबित भुगतान 27 प्रतिशत कम था। यहां परिवहन ऑपरेटर्स को

ज्यादातर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। यद्यपि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में खरीदारों द्वारा विलंबित भुगतान के मामले में जुर्माने का प्रावधान है, परंतु कमजोर सौदेबाजी क्षमता और व्यापार के खोने का डर एमएसएमई को इस प्रावधान को लागू करने से रोकता है।

III. एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति

एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक बाधाओं और कारकों को समझने के लिए, आरबीआई ने जनवरी 2019 में श्री यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा की और एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए कई सिफारिशें प्रस्तुत कीं। अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिशें विस्तृत और व्यापक रूप से विधायी परिवर्तनों; बुनियादी ढांचे का विकास; क्षमता निर्माण; तकनीकी उन्नयन; आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच की कड़ी को बेहतर करना औपचारिक स्रोतों से वित्तीय सहायता में सुधार; मजबूत जोखिम-अंकन प्रथाओं के लिए नए तकनीकी उपाय; और क्रेडिट वितरण से संबंधित हैं। जबकि समिति की कुछ सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं, अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा विचाराधीन हैं।

IV. आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

ऋण प्रवाह को बेहतर करने के उपाय

हाल ही में रिजर्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार हेतु कई उपाय किए हैं। बैंक एमएसएमई के औपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत होता है जिसमें बैंकों के ऐसे सभी ऋण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। अगस्त 2019 में, हमने एनबीएफसी क्षेत्र के माध्यम से एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों को और प्रोत्साहन दिया है। नतीजतन, ₹20 लाख प्रति उधारकर्ता तक के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अलावा) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

1 जनवरी 2019 को चूक खाते के रूप में वर्गीकृत लेकिन मानक जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई खातों के लिए आस्ति वर्गीकरण डाउनग्रेड किए बिना एक बार पुनर्गठन की योजना को

अनुमति दी गई थी। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया का वित्तीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, इस योजना को ऐसे खातों तक विस्तारित किया गया है जो मानक हैं लेकिन 1 जनवरी 2020 को चूक खाते के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं तथा जो खाते पात्र हैं उनका 31 दिसंबर 2020 तक पुनर्गठन किया जाना है। 1 जनवरी 2019 के परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत जो एमएसएमई पुनर्गठित नहीं की जा सकी तथा इसके बाद दबावग्रस्त हो गई हैं ऐसे पात्र एमएसएमई को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तक, बैंकों ने योजना के अंतर्गत 15 लाख पात्र खातों में से 6 लाख खातों का पुनर्गठन किया है। हमारे प्राथमिक सर्वेक्षण ने यह सुझाव दिया है कि एमएसएमई के बीच योजना के बारे में जागरूकता की कमी है।

हमने पिछले महीने घोषणा की है कि ऑटोमोबाइल और रिहायशी आवासों के लिए खुदरा ऋण के साथ-साथ वृद्धिशील ऋण के लिए 31 जनवरी 2020 को समाप्त होनेवाले पखवाड़े से 31 जुलाई 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक एमएसएमई को सीआरआर से छूट दी जाएगी।

अक्टूबर 2019 में एक बाह्य बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, मौद्रिक नीति संचरण में सुधार हुआ है तथा सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए नए अस्थायी दर ऋण, बाह्य बेंचमार्क से जोड़े गए। मौद्रिक नीति संचरण को और मजबूत करने की दृष्टि से 01 अप्रैल 2020 से बैंकों द्वारा मध्यम उद्यमों को प्रदत्त सभी नए अस्थायी दर ऋणों को भी बाह्य बेंचमार्क से जोड़े जाएंगे।

विलंबित भुगतान का समाधान

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, भुगतान प्राप्ति में देरी एमएसएमई की सार्वकालिक समस्याओं में से एक है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2014 में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) की शुरुआत की। टीआरडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां एमएसएमई को खरीदारों (बड़े कॉर्पोरेट्स, पीएसयू, सरकारी विभागों) से मिलनेवाली प्राप्तियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर कई फाइनेंसरों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। यह एक नीलामी-आधारित प्रणाली से किया जाता है। टीआरडीएस के दायरे को व्यापक बनाने और अधिक प्रतिभागियों को इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2016 में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों के एक्सपोजर को

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा, लाइसेंस प्राप्त तीन इकाइयां [रिसेवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), टीआरडीएस तथा मायंड सॉल्यूशंस] दो से अधिक वर्षों से इस मंच का संचालन कर रही हैं। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने हाल ही में टीआरडीएस को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इच्छुक संस्थाओं को 'ऑन टैप' प्राधिकरण की अनुमति दी है। इसलिए, आने वाले वर्षों में, प्राप्ति की डिस्काउंटिंग में नए प्रतिभागियों के प्रवेश से निश्चित ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कॉर्पोरेट्स की आवश्यकता है, जो टीआरडीएस प्लेटफॉर्म में शामिल हों और सिस्टम को अधिक कुशल बनाएं।

सरकार ने 2018 में ₹ 500 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों के लिए टीआरडीएस के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया। फरवरी 2020 तक 8211 एमएसएमई विक्रेताओं ने पंजीकरण किया, जबकि केवल 1530 खरीदार प्लेटफॉर्म पर भाग ले रहे थे। मैं एसोचैम से अपील करूंगा कि वह अपने सभी सदस्यों को टीआरडीएस प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार ने एमएसएमई के विलंबित भुगतानों की समस्या दूर करने के लिए ऐप आधारित चालान वित्तपोषण उत्पादों की घोषणा की है। यह व्यवस्था टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के लिए पूरक साबित हो सकती है और आगे विलंबित भुगतान की समस्या का भी समाधान करेगी।

V. भावी दिशा

एमएसएमई क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जरूरत है नीतियों के सही निर्धारण की और ऐसे ढांचे को सक्षम करने की जो एमएसएमई को अपनी मौजूदा समस्याओं और उद्यम को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए मार्गदर्शन और समर्थन दे। हालांकि सरकार और आरबीआई दोनों ने वित्त की पहुंच में सुधार और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपाय प्रस्तुत किए हैं, व्यक्तिगत इकाइयों के छोटे आकार और क्षेत्र के अनौपचारिक स्वरूप के चलते इस क्षेत्र द्वारा चुनौतियों का सामना करना जारी है।

बैंकों की पारंपरिक बैंक ऋण प्रणाली वित्तीय विवरणों और उधारकर्ता की संपार्श्विक पर आधारित है। जीएसटीएन, आयकर, क्रेडिट ब्यूरो, आदि सहित कई स्रोतों से डेटा की बढ़ती

उपलब्धता के कारण अब एमएसएमई ऋण प्रस्तावों का समुचित सावधानी के साथ ऑनलाइन शीघ्र मूल्यांकन करना संभव है। इसके अलावा, खाता एग्रीगेटर्स (एए) की सहायता से, उधारदाताओं के पास एक ही स्थान पर संभावित उधारकर्ता की वित्तीय जानकारी उसकी सहमति से मिल सकती है। साथ ही, फिनटेक कंपनियों के सृजन से अज्ञात डेटा स्रोतों जैसे डिजिटल लेनदेन ट्रेल्स, ई-कॉमर्स साइट के माध्यम से सृजित डेटा, आदि का उपयोग करके एमएसएमई की क्रेडिट योग्यता का आकलन करना संभव बना दिया है। कुछ उधारदाता फिनटेक कंपनियों के साथ मिलकर एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए तेजी से ऋण हामीदारी के लिए इस तरह के सरोगेट डेटा का लाभ उठाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये नए आर्किटेक्चर क्रेडिट की पहुंच का विस्तार करेंगे।

डिजिटल रूप से सक्रिय इकाइयों के लिए नए मॉडल फायदेमंद हैं, जबकि एमएसएमई इकाइयों का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक ऋण मॉडल के माध्यम से ऋण लेता है। सूक्ष्म उद्यम, उद्यम उपक्रम के शुरुआती चरण के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें प्रौद्योगिकी में कम निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे और मध्यम उद्यमों में परिवर्तित होनेवाली इकाइयों को अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है और स्थिर वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए नए बाजारों का पता लगाना है। हाल के नीतिगत प्रयास एक सक्षम वातावरण प्रदान करेंगे और एमएसएमई क्षेत्र को नए उभरते अवसरों को हासिल करने में सहायता करेंगे। मुझे यह कहना है कि एक विनियामक के रूप में, आरबीआई में हमें वित्त की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करते हुए वित्तीय स्थिरता की रक्षा करनी होगी। बैंकों और अन्य प्रतिभागियों को विवेकपूर्ण उधार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इसके अलावा, आरबीआई में हमने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के अंतर्गत कोहॉर्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया है। नवंबर 2019 में पहली बार इस तरह के कोहॉर्ट को 'रिटेल पेमेंट्स' के थीम के साथ लॉन्च किया गया था, ताकि वे बैंकिंग सेवा रहित और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्र के लिए नई भुगतान सेवा ईजाद करने और परीक्षण करने के लिए डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नवोन्मेषन में तेजी ला सके। यथा समय, हम उधार पर ध्यान केंद्रित किए गए कोहॉर्ट के लिए एक विनियामक सैंडबॉक्स का प्रस्ताव करते हैं। यह एमएसएमई ऋण के खंड में नवोन्मेषन को बढ़ावा देगा। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) संबंधी परियोजना,

बुनियादी रूप से सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच में बाधा डालने वाली सूचना विषमता का समाधान करेगी। मूल क्रेडिट सूचना के डेटाबेस के रूप में पीसीआर की कल्पना की गयी है। इस खंड में क्रेडिट गैप कम करने में रजिस्ट्री की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

इस तथ्य को देखते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह आवश्यक है कि उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए एकीकृत होना चाहिए क्योंकि यह तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त बनने का एक अवसर है। जीवीसी का हिस्सा होने से एमएसएमई गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम बनेंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक स्वीकार्यता

होगी। क्षेत्र के लिए, सूचना का अभाव, बाजारों का ज्ञान न होना और गुणवत्ता मानकों की कमी जीवीसी से जुड़ने की प्रमुख चुनौतियां हैं। इस संबंध में सभी हितधारकों के बीच सहयोग होना आवश्यक है।

मैं यह दोहराता हूं कि एसोचैम जैसे उद्योग निकायों को अपनी भूमिका के दायरे को बढ़ाकर तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के अनुरूप सर्वोत्तम व्यवसाय प्रथाओं को अपनाने में एमएसएमई की सहायता करनी चाहिए।

मैं एसोचैम को शताब्दी वर्ष के शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं।

धन्यवाद।

लेख

जलवायु परिवर्तन: समष्टि आर्थिक प्रभाव और जोखिमों को कम करने के नीतिगत विकल्प

केंद्रीय बजट 2020-21 का आकलन

जलवायु परिवर्तन: समष्टि आर्थिक प्रभाव और जोखिमों को कम करने के नीतिगत विकल्प*

यह आलेख पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डालता है और साथ ही यह जोखिम को कम करने के लिए उपलब्ध नीतिगत विकल्पों की समीक्षा भी करता है। यदि हम सन 1901 से लेकर मौसम से जुड़ी भारत की प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं पिछले दो दशकों में अत्यधिक गंभीर घटनाओं की संख्या बढ़ी है और दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में देखने पर औसत तापमान का स्तर बढ़ा है तथा वर्षा का रुख भी अधिक परिवर्तनशील हो गया है। अनुभव आश्रित निष्कर्ष यह बताते हैं भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का समष्टि आर्थिक प्रभाव, विशेष रूप से खाद्य स्फीति और वास्तविक अर्थव्यवस्था गतिविधियों कुछेक संकेत को पर काफी अधिक रही है।

भूमिका

विश्व के औसत तापमान में हुई वृद्धि के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप मौसमी चक्र में आ रहा परिवर्तन उन्नत और उभरती दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के समष्टि आर्थिक परिदृश्य के सम्मुख प्रमुख जोखिम बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी है कि 'जलवायु परिवर्तन' एक ऐसा मुद्दा है, जो हमारे समय को परिभाषित कर रहा है और हम एक निर्णायक क्षण पर खड़े हैं। हाल की अवधि में भारत भी मौसमी चक्र में बड़े परिवर्तनों का साक्षी रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) का उत्सर्जन संचयी रूप में ऊंचे स्तर पर रहा है जिसके परिणामस्वरूप औसत तापमान बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 में भारत ने 2,299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.8 प्रतिशत अधिक था¹।

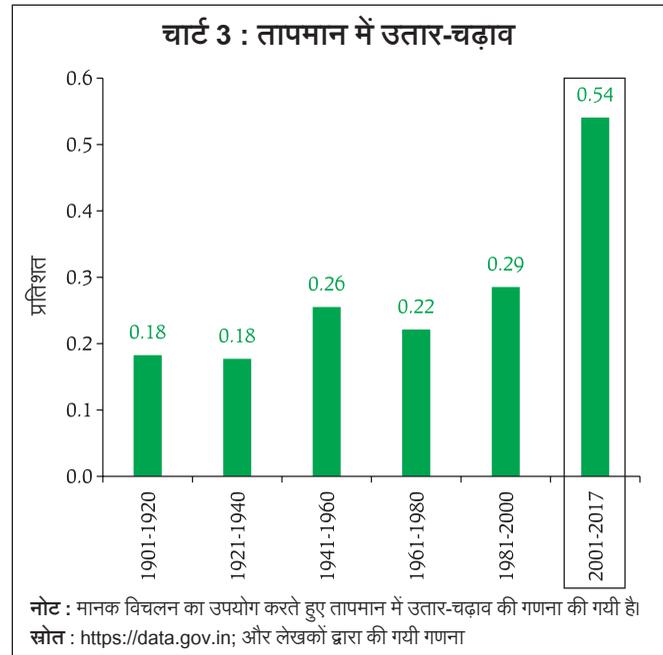
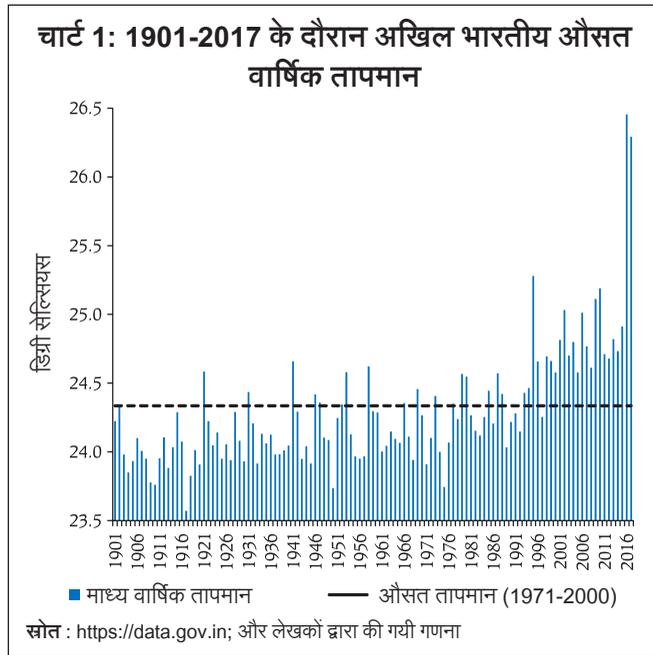
* यह आलेख अर्चना दिलीप और सुजाता कुंडू द्वारा तैयार किया गया है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्रमशः वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) तथा आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) में अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

¹ वर्ष 2018 में भारत द्वारा CO₂ के उत्सर्जन की वृद्धि दर यूएस और चीन, जो विश्व में सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश माने जाते हैं, से अधिक रही।

भारत में समृद्धि और महँगाई परिदृश्य आज भी दक्षिण पश्चिम मानसून एसडब्ल्यूएम के मौसम (जून-सितंबर) के दौरान होने वाली वर्षा मात्रा और उसके वितरण से प्रभावित होता है। पूरे वर्ष भर में देश में होने वाली वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत इन्हीं 4 महीनों के दौरान मिलता है जोकि कृषि क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कुल कृषि योग्य भूमिका 65 प्रतिशत हिस्सा अभी भी असिंचित है। वर्ष 2019 में दक्षिण पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) ने पिछले दो दशकों की सर्वाधिक बारिश प्रदान की। हालांकि, शुरुआती महीनों में काफी दिनों तक सूखे की स्थिति बने रहने के बाद जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ा, भारी या अत्यधिक बारिश हुई जिसके कारण देश के बहुत से हिस्सों में बाढ़ आ गई और फसल को नुकसान हुआ।

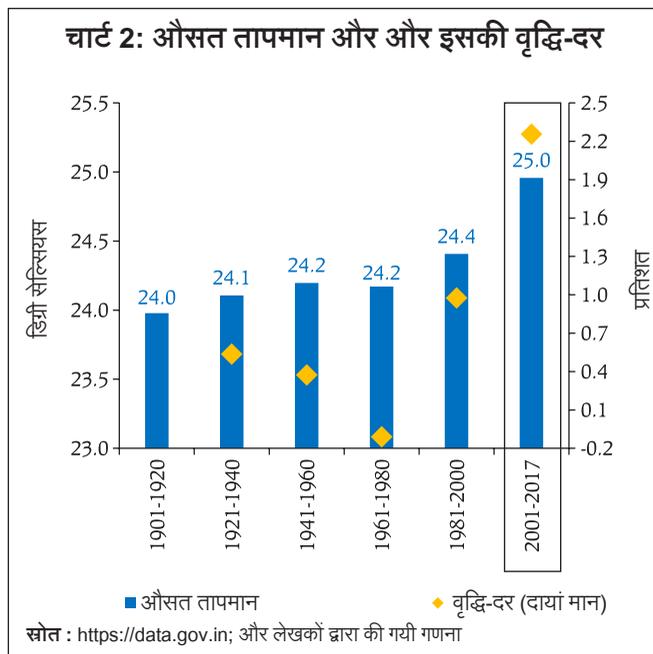
वर्षण (बारिश) के अलावा, तापमान और उसमें जारी परिवर्तन मौसम में आ रहे इस बदलाव का एक अन्य प्रमुख संकेतक है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत का मध्यमान वार्षिक तापमान काफी बढ़ गया है। अब तक, जैसा कि भारत के मौसम विभाग आईएमडी ने बताया है, वर्ष 2016 भारत का सबसे गर्म वर्ष रहा है। जहां एक ओर, पूरे विश्व में बदलती मौसमी परिस्थितियों की एक बड़ी विशेषता आवश्यकता में क्रमशः हो रही वृद्धि है, वहीं अति गंभीर/ मौसमी परिवर्तन से जुड़ी घटनाएं, जैसे वर्षा के चक्र में बदलाव आ जाना, इसका वितरण असमान हो जाना, बाढ़ बार-बार और अधिक तीव्रता से आना, बेमौसम बारिश होना, गर्म हवाएं चलना और सूखा पड़ना आदि अति गंभीर समष्टि आर्थिक जोखिम उत्पन्न करती हैं। भारत समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ग्लेशियरों के पिघलने का साक्षी भी रहा है जिसका कारण ग्लोबल वार्मिंग को माना जा सकता है। सागर के जलस्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता जाने की आशंका है।

वर्तमान में तापमान-वृद्धि की जो दर है, उसे देखते हुए अतिवृष्टि और तापमान बढ़ने से जुड़ी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ जाएगी जिससे कि आजीविका और उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है [इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी), 2018]। इस प्रकार प्रौद्योगिकी में हो रही तीव्र प्रगति तथा जनांकिकीय बदलावों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन बड़े आर्थिक उथल-पुथल लाने की क्षमता रखता है (रुडबुश, 2019)। मौसमी परिस्थितियों में होने वाले बदलावों के



की बात करें तो किसी भी 20 वर्ष के अंतराल की तुलना में 2001-17 के दौरान औसत तापमान में वृद्धि (साथ ही, तापमान में उतार-चढ़ाव) काफी अधिक रही (चार्ट 2 और 3)।

भारत में तापमान के क्रम के अंतः-वर्ष अवधिक इस प्रकार हैं कि किसी भी वर्ष के दौरान न्यूनतम तापमान आमतौर पर जनवरी-फरवरी (सर्दियों के महीनों) के दौरान होता है, जबकि अधिकतम तापमान आमतौर पर मार्च-मई (मानसून पूर्व) के दौरान देखा

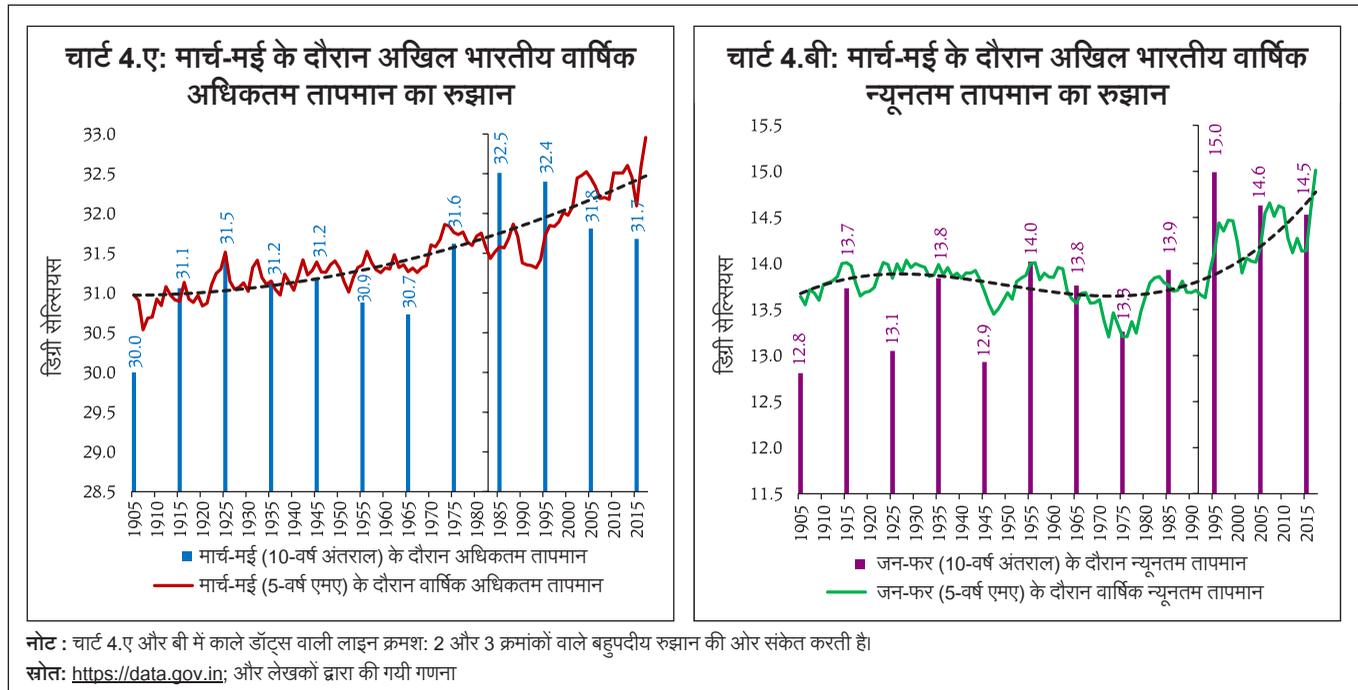


जाता है। आंकड़े बताते हैं कि साल-दर-साल इन महीनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमानों में वृद्धि हो रही है (चार्ट 4.ए और चार्ट 4.बी)। इसके अलावा, 1901 के बाद से 5 साल की चलायमान औसत (एमए), विशेष रूप से विगत 30 वर्षों की बात करें तो इस वृद्धि में ज्यादा परिवर्तन देखा गया है।

वर्षा

एसडब्ल्यूएम में अपने सामान्य पैटर्न / वितरण से होने वाले विचलन व्यापक आर्थिक परिदृश्य के सम्मुख बड़े जोखिम उत्पन्न कर देते हैं। विगत कई वर्षों में एसडब्ल्यूएम के मौसम की गतिकी में क्रमिक परिवर्तन दिखाई पड़े हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के दौरान, विलंब से हुई शुरुआत (8 जून, 2019) और जून के दौरान अत्यधिक कम बारिश वाले दौर (एलपीए से 33 प्रतिशत) के बावजूद, सीजन समाप्त होते-होते सामान्य से 10 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गयी जो कि पिछले 25 वर्षों का सर्वाधिक स्तर था (1990-2019 की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर 1994 में 12.5 प्रतिशत था) (चार्ट 5)।

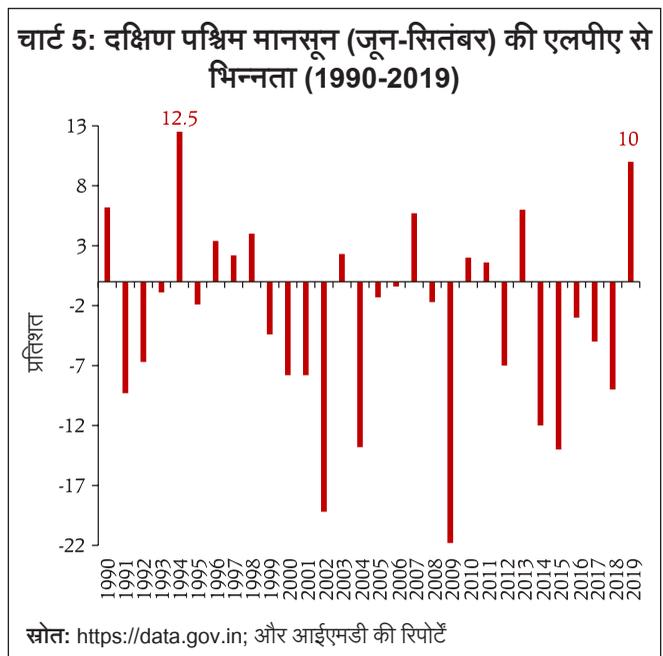
2019 में, जून में वर्षा की काफी कमी के बाद, मानसून ने जुलाई में कुछ गति प्राप्त की (चार्ट 6.ए और 6.बी)। हालांकि, अगस्त और सितंबर के दौरान वर्षा की अधिकता बहुत ज्यादा थी (चार्ट 6.सी और 6.डी)। अगस्त में, वर्षा एलपीए से 15 प्रतिशत ऊपर हुई थी, जो पिछले 23 वर्षों में सबसे अधिक थी, जबकि



सितंबर में तो, यह एलपीए से 52 प्रतिशत ऊपर थी, जो 1918 के बाद अब तक का सबसे अधिक स्तर रहा। साथ ही, यदि अगस्त और सितंबर के दौरान वर्षा की कुल मात्रा (557 मिमी) को देखें तो यह 1983 (564 मिमी) के बाद सर्वाधिक थी।

इसके अलावा, एसडब्ल्यूएम की शुरुआत और समाप्ति की तारीखें (2010 के बाद से) इसकी समयरेखा में दिखने वाले

परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं (सारणी 1)। आईएमडी के अनुसार, एसडब्ल्यूएम की शुरुआत और वापसी की सामान्य तिथियां क्रमशः 1 जून और 1 सितंबर हैं। 2010 से लेकर पांच साल तक एसडब्ल्यूएम की शुरुआत में देरी हुई थी जहां औसत देरी 5 दिनों की थी, जबकि 2019 के दौरान मानसून 7 दिनों की देरी से आया था। खास तौर पर, तबाही मचाने वाली बात यह थी कि मानसून की समाप्ति में 39 दिनों की देरी हुई, जो पिछले नौ वर्षों के बिलकुल विपरीत थी³



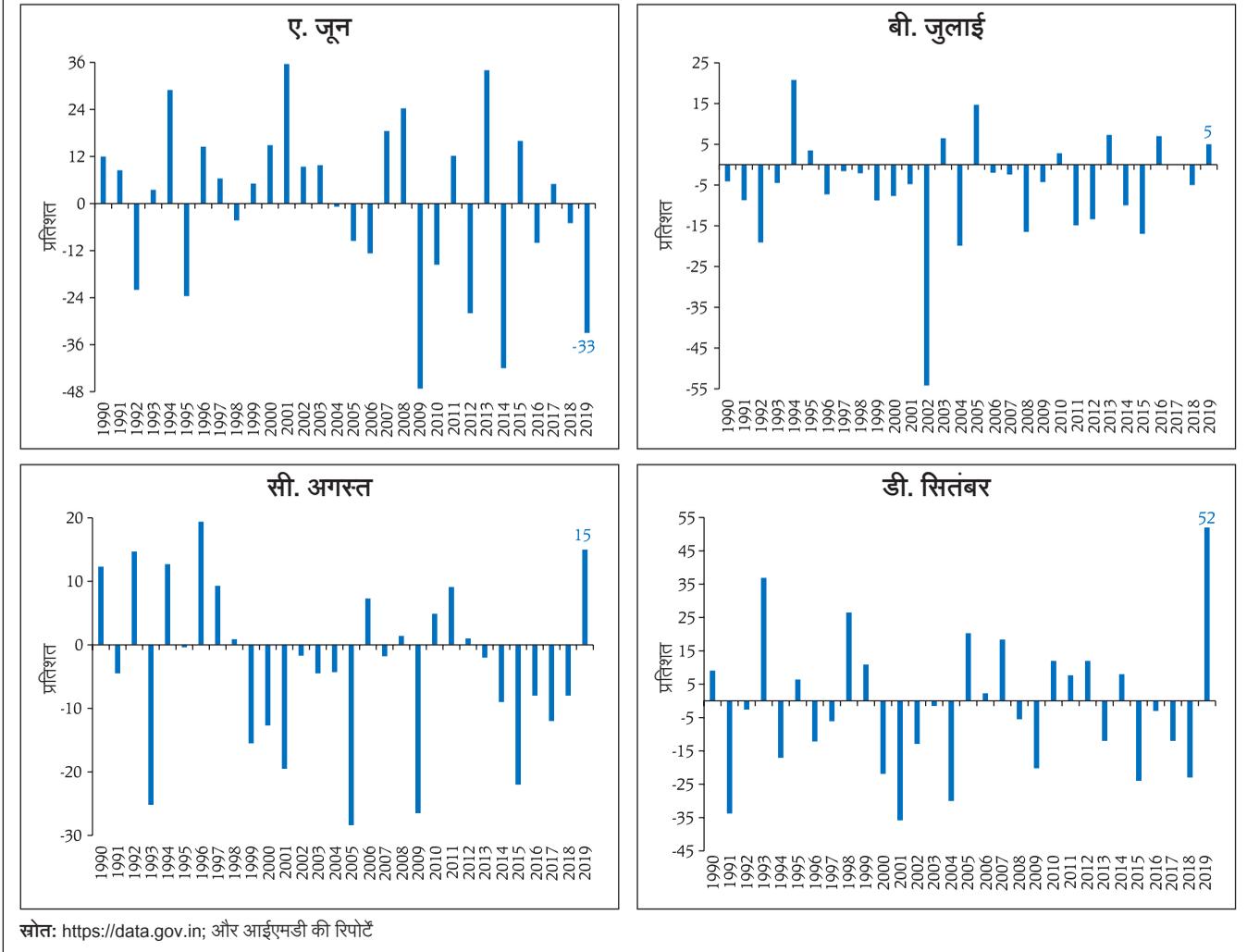
सारणी 1: दक्षिण पश्चिम मानसून का आना और इसकी वापसी की समय-सीमा (दिनों की संख्या)

वर्ष	शुरुआत में विलंब	वापसी में विलंब	पूरी तरह वापसी में लगा समय
2010	1	27	33
2011	3	23	32
2012	-4	24	25
2013	0	9	43
2014	-5	23	26
2015	-4	4	46
2016	-7	15	44
2017	2	27	15
2018	3	29	23
2019	-7	39	8

स्रोत: मानसून रिपोर्टें, आईएमडी

³ आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से पहले SWM की सबसे देरी से निकासी 1961 (1 अक्टूबर; 31 दिन) और 2007 (30 सितंबर; 30 दिन) में दर्ज की गई थी।

चार्ट 6: एलपीए से दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा का माह-वार अंतर (1990-2019)



एसडब्ल्यूएम द्वारा इसकी पूर्णतया समाप्ति में लिए गए दिनों की संख्या (आठ दिन) भी असामान्य थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 में एसडब्ल्यूएम की वापसी के साथ ही उत्तर-पूर्व मानसून का आगमन हो गया जो बिलकुल नई घटना थी।

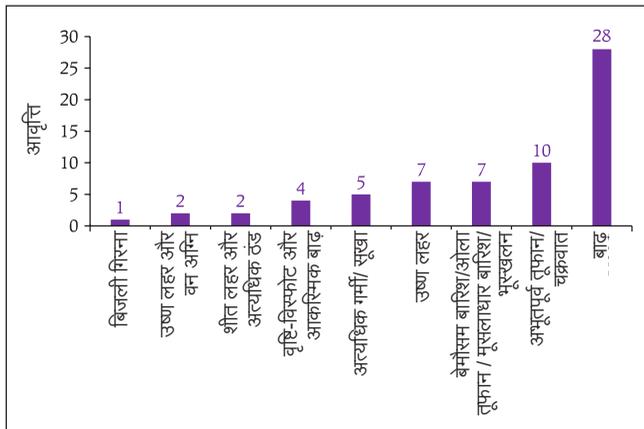
अत्यंत प्रतिकूल मौसम वाली घटनाएं

तापमान और वर्षा के पैटर्न में धीरे-धीरे बदलाव के साथ, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम वाली घटनाएं यथा अत्यधिक/बेमौसम बारिश (अक्सर बाढ़ लाने वाली), तापमान में चिंताजनक उतार-चढ़ाव (जैसे, गरम लू और शीतलहरी) और तेज हवाएँ (जैसे, तूफान) दुनिया भर में बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के साथ देखी

जा रही हैं। भारत में भी, पिछले दो दशकों के दौरान, बाढ़ें और उनके बाद आए चक्रवातों, बेमौसम बारिश और गर्म लू इस प्रकार के अत्यधिक प्रतिकूल मौसम से जुड़ी प्रमुख घटनाएं थीं (चार्ट 7. ए)। वर्ष 2008 से इन घटनाओं की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है (चार्ट 7. बी)।

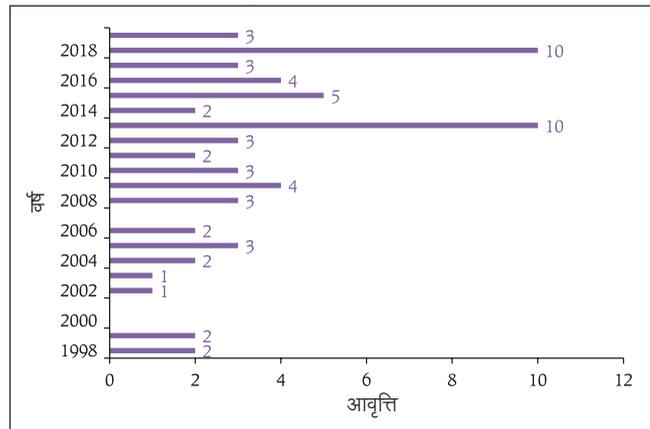
2004 के बाद से बड़े पैमाने पर बाढ़ और मूसलाधार बारिश की घटनाएं हुई हैं, जबकि 2011 के बाद से बेमौसम बारिश एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। इसके अलावा, अगर हम इन घटनाओं के क्षेत्रीय वितरण को देखें, तो यह पाते हैं कि कुछ प्रमुख कृषि आधारित राज्य (या तो खाद्यान्न उत्पादक या नकदी फसल

चार्ट 7.ए : अत्यधिक प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रकार (1998-2019)



नोट : इन घटनाओं को ऐसे राज्यों में नोट किया गया जो भौगोलिक रूप से पास-पास नहीं हैं और/अथवा लगातार आने वाले महीनों के नहीं हैं।
स्रोत : डाउन टु अर्थ (विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा सहायता-प्राप्त) : आईएमडी प्रकाशन: और लेखकों द्वारा की गयी गणना।

चार्ट 7.बी: अत्यधिक प्रतिकूल मौसमी घटनाओं की आवृत्ति (1998-2019)



उत्पादक) सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) (चार्ट 8)।

III. साहित्य की समीक्षा

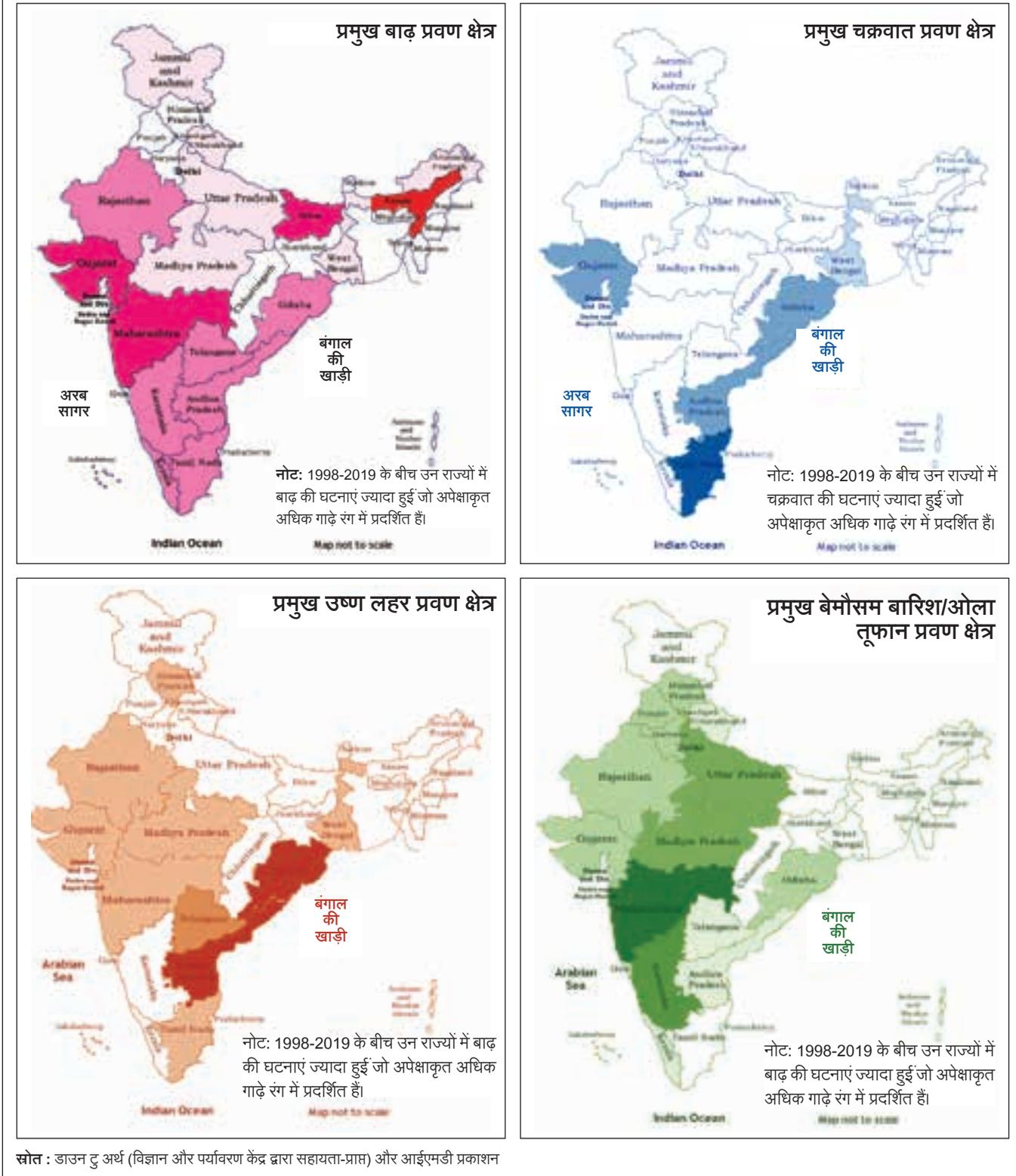
जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से संबंधित साहित्य भरा पड़ा है, चाहे विभिन्न प्रकार के जटिल मुद्दों को समावेशित करने की दृष्टि से देखें या फिर विश्लेषण की गहनता की दृष्टि से। जहाँ एक ओर विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में बहुत सारा काम किया गया है, वहीं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए साहित्य अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। नीति निर्माता और केंद्रीय बैंकर भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते आर्थिक परिणामों / जोखिमों को महसूस कर रहे हैं, तथा समष्टि आर्थिक चरों की मॉडलिंग और पूर्वानुमानों की प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है (नॉर्डहाउस, 2017; बैटन, 2018)। इस प्रकार के साहित्य से ऐसे संकेत मिलते हैं कि यदि यह प्रक्रिया अधिकांश निवेशकों को अपने निहित वित्तीय जोखिमों का मूल्यांकन करने में सहायक बन सके, तो जलवायु संबंधी प्रकटीकरणों से क्रमिक रूप से कम कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा जा सकेगा (बैटन और अन्य, 2016)।

समग्र आर्थिक स्वास्थ्य पर मौसमी परिवर्तनों के प्रभाव के संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं वे आम तौर पर कुल आर्थिक उत्पादन और कृषि पैदावार पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि उच्च तापमान का न केवल कुल आर्थिक उत्पादन के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि यह इसकी वृद्धि दर भी कम कर सकता है (डेल और अन्य,

2012; ऐसीवेडो और अन्य, 2018)। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि 1964-2007 के दौरान, सूखे और अत्यधिक गर्मी ने दुनिया भर में कृषि उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाया, और हाल के सूखों ने अनाज उत्पादन पर पहले वाले सूखों की तुलना में अधिक प्रभाव डाला (लेस्क और अन्य, 2016)।

ऐसे भी अध्ययन भी हुए हैं जो यह बताते हैं कि जीवन स्तर, पशुधन की उत्पादकता और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है (मणि और अन्य, 2018; आईपीसीसी, 2019)। तापमान से संबंधित प्रतिकूल मौसम की घटनाओं का असर वर्षा संबंधी कारकों की तुलना में कृषि उपज से जुड़ी विसंगतियों पर अधिक दिखता है; सिंचाई सुविधाएं अत्यधिक तापमान के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करती हैं लेकिन केवल आंशिक रूप से (वोगेल और अन्य, 2019)। 1960-2014 की अवधि के लिए 174 देशों के पैनल डेटासेट का उपयोग करते हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि तापमान के अपने ऐतिहासिक मानकों से लगातार विचलन से प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है (कहन और अन्य, 2019)। यह कई राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक उत्पादन, श्रम उत्पादकता और रोजगार की स्थिति पर जलवायु परिवर्तन के निरंतर नकारात्मक प्रभाव का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अमेरिका के लिए भी इसी तरह के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं (कोलासिटो और अन्य, 2018)। एक समष्टि मौसम सूचकांक का उपयोग करते हुए, जापान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वर्षा में वृद्धि से उपभोक्ता खर्च में गिरावट आएगी और

चार्ट 8 : भारत में प्रतिकूल मौसम की प्रमुख घटनाओं का क्षेत्रीय विस्तार



तापमान में वृद्धि से गर्मियों में निजी खपत में वृद्धि होगी और सर्दियों में कमी आएगी (अकुत्सु और कोइके, 2019)।

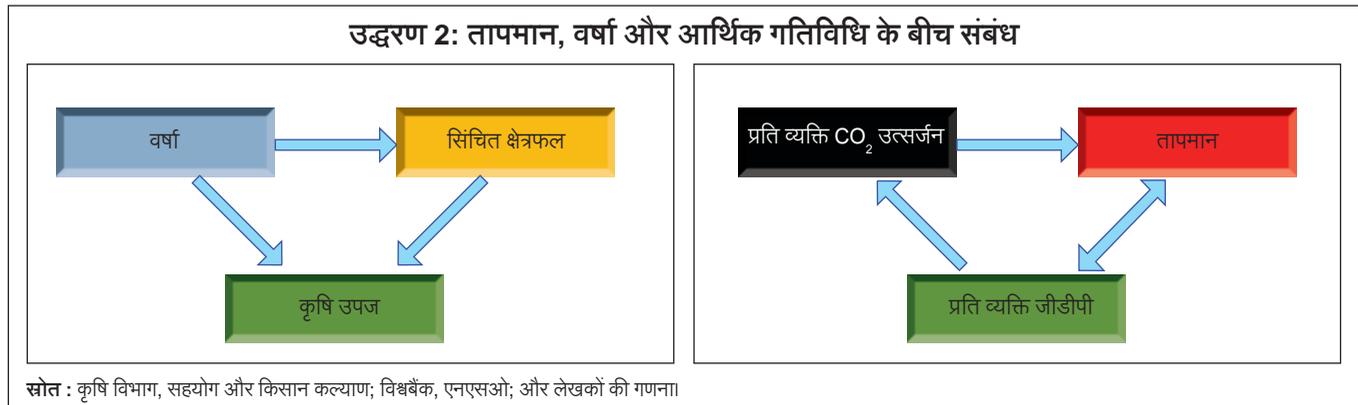
भारतीय संदर्भ में बात की जाए तो कुछ अध्ययन हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों को उजागर किया है, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र (विशेष रूप से, फसल की पैदावार) और लोगों के जीवन स्तर से जुड़े जोखिमों को। अफ्रीका को छोड़कर भारत को अमेरिका, चीन, रूस और दुनिया के अधिकांश अन्य हिस्सों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है (जोशी और पटेल, 2009)। वर्ष 1957-2000 के लिए जिला-स्तरीय पैनेल डेटासेट का उपयोग करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि किसी वर्ष के दौरान उच्च तापमान वाले दिनों में मानक विचलन में एक की वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि पैदावार और वास्तविक मजदूरी में क्रमशः 12.6 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की गिरावट आ जाती है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या की वार्षिक मृत्यु दर में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है (बर्गेस और अन्य, 2014)। कर्नाटक में विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार (जैसे धान, ज्वार, रागी और सफेद मटर) पर अत्यधिक तापमान के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला एक अन्य अध्ययन यह दर्शाता है कि फसल की पैदावार और अत्यधिक तापमान वाले दिनों की संख्या के बीच एक व्युत्क्रम रैखिक संबंध होता है, और साथ ही यह भी कि पैदावार पर तापमान का प्रभाव वर्षा के प्रभाव से अधिक होता है (मुरारी और अन्य, 2018)। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि तापमान में वृद्धि कृषि उत्पादकता को कम कर देती है, जबकि वर्षा (जब तक कि आवश्यकता से अधिक न हो जाए) इस प्रभाव को प्रायः दूर कर देती है (बिर्थल और अन्य, 2014)। अगर इस जोखिम को कम करने के लिए नीतियाँ नहीं बनायी जातीं, तो तापमान में हो रही लगातार वृद्धि के कारण वर्ष 2100 तक भारत के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है (काहन और अन्य, 2019)।

IV. भारत के लिए अनुभवजन्य विश्लेषण

भारत में CO₂ उत्सर्जन की मात्रा एक बड़ी चिंता का विषय रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि यह उत्सर्जन ही तापमान के बढ़ते स्तर के लिए मुख्य रूप से दोषी है। साथ ही, यह आम तौर पर माना जाता है कि बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप CO₂ का अधिक उत्सर्जन होता है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर, तीन सेटों में युग्म-वार ग्रेंजर-कार्य-कारण परीक्षण किए गये हैं जिनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी का डेटा, प्रति व्यक्ति CO₂ उत्सर्जन (मीट्रिक टन) और भारतीय संदर्भ में 1960-2014 की अवधि के वार्षिक औसत तापमान का उपयोग किया गया है। इसके परिणाम यह बताते हैं कि प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर मापी गयी आर्थिक गतिविधि के कारण CO₂ का उत्सर्जन होता है और CO₂ उत्सर्जन से औसत तापमान में वृद्धि होती है (संलग्न सारणी 2.ए)। इसके अलावा, ये परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि तापमान और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के बीच एक द्वि-दिशात्मक कार्य-कारण संबंध होता है। जैसा कि अपेक्षित है, वर्षा के कारण उपलब्ध सिंचित क्षेत्र (सकल सिंचित क्षेत्र) की मात्रा प्रभावित होती है, जो बदले में कृषि उपज (उत्पादन और/अथवा बोया गया क्षेत्र) को प्रभावित करती है (संलग्न सारणी 2.बी)। इन परिणामों को फ्लो चार्ट के माध्यम से भी सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है (उद्धरण 2)।

किसी भी समय विशेष पर भारतीय जलवायु की परिस्थितियों में मौजूद विविधता को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों में मौसम संकेतकों का सामान्य औसत मात्रा मौसम के बदलते चक्र की वास्तविक प्रकृति को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। इस समस्या से निपटने के लिए, मौसम सूचकांकों - तापमान सूचकांक और वर्षा सूचकांक - की गणना दीर्घावधिक औसतों से होने वाले विचलनों के भारत औसत के रूप में की जाती है। इसके

उद्धरण 2: तापमान, वर्षा और आर्थिक गतिविधि के बीच संबंध



स्रोत : कृषि विभाग, सहयोग और किसान कल्याण; विश्वबैंक, एनएसओ; और लेखकों की गणना।

अलावा, चूंकि अधिकांश आर्थिक आंकड़े पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए गए होते हैं और वे मासिक अंतराल पर उपलब्ध कराए जाते हैं, इसीलिए ये सूचकांक भी अखिल भारतीय स्तर पर मासिक रूप से तैयार किए जाते हैं।

ब्लोश और गौरियो (2015) के सिद्धांत पर चलते हुए इन सूचकांकों को तैयार करने के विविध चरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

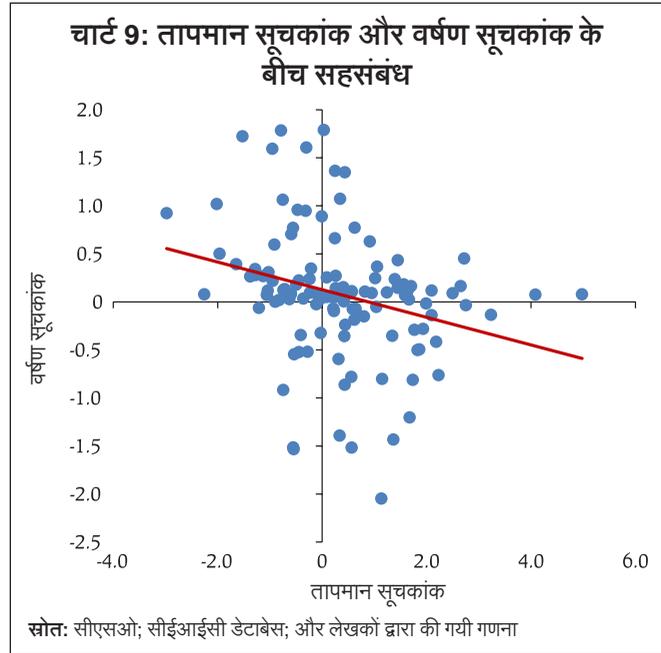
चरण 1: देश के महत्वपूर्ण मौसम केंद्रों के लिए तापमान और वर्षा के मासिक विचलनों (मासिक औसत और दीर्घकालिक सामान्य के बीच अंतर) से जुड़ा डेटा प्राप्त किया जाता है। मान लेते हैं कि विचलनों को D_i से दर्शाया गया है जहाँ i राज्य / स्थान दर्शाता है।

चरण 2: इन विचलनों को परिवर्तनशीलता के माप से सामान्यीकृत किया जाता है, जो कि मानक विचलन (σ_i) होता है। अब हम इन सामान्यीकृत विचलनों (तापमान/वर्षा विचलन और मानक विचलन का अनुपात) को इस प्रकार दर्शाते हैं \hat{D}_i ।

चरण 3: सभी राज्यों के सामान्यीकृत विचलनों को विभिन्न राज्यों की जनसंख्या (w_i) के अनुसार भारिता देते हुए उनका औसत निकाला जाता है, यह मानते हुए कि आर्थिक गतिविधि जनसंख्या से सहसंबद्ध होती है।

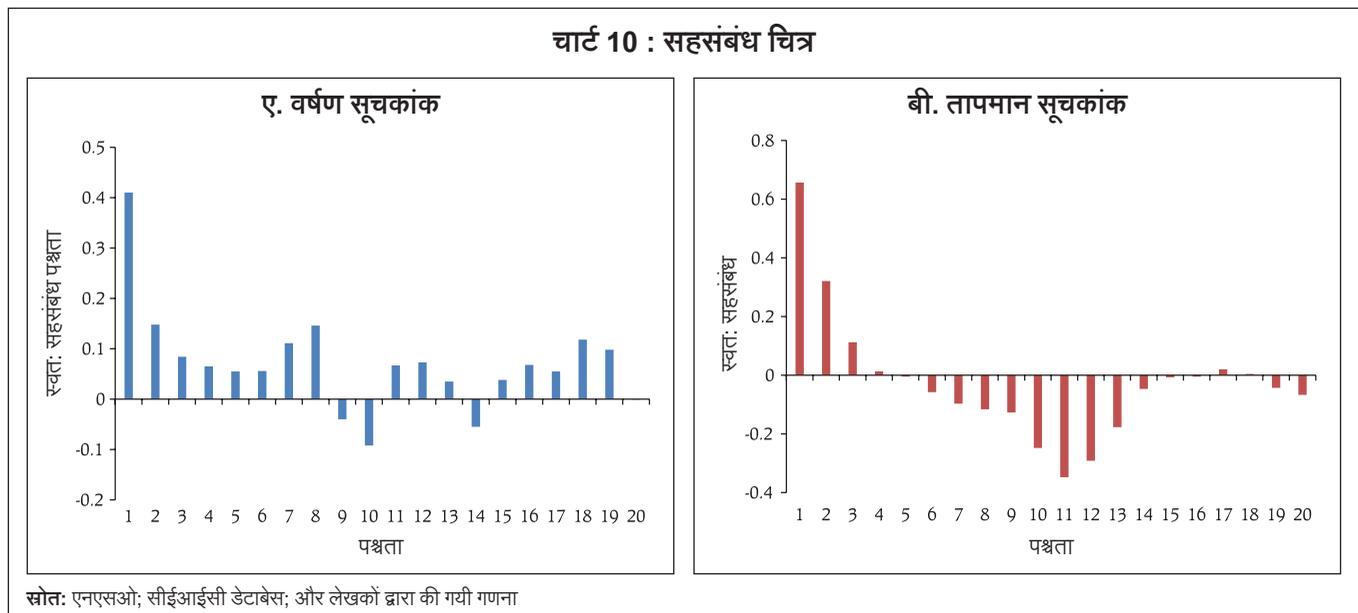
$$\bar{D} = \frac{\sum_i w_i \hat{D}_i}{\sum_i w_i}$$

चरण 4: इसके बाद, भारत की आर्थिक गतिविधि पर एसडब्ल्यूएम के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसे जून-सितंबर के औसत और मानक विचलन के साथ सामान्यीकृत किया जाता है।



जैसा कि भारतीय संदर्भ में अपेक्षित है, अक्टूबर 2009-जुलाई 2019 की अवधि के लिए तैयार किया गया वर्षा सूचकांक की तुलना में तापमान सूचकांक के प्रकीर्ण प्लॉट नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध $[(-) 0.32]$ प्रदर्शित करता है। यह इंगित करता है कि जब वर्षा में वृद्धि होती है तो तापमान घटता है (चार्ट 9)।

इसके अतिरिक्त, वर्षण और तापमान के सूचकांकों के बीच सहसंबंध चित्र यह बताते हैं कि विचलन कितने समय तक बने रहते हैं (चार्ट 10)। तापमान सूचकांक के मामले में तो यह सहसंबंध

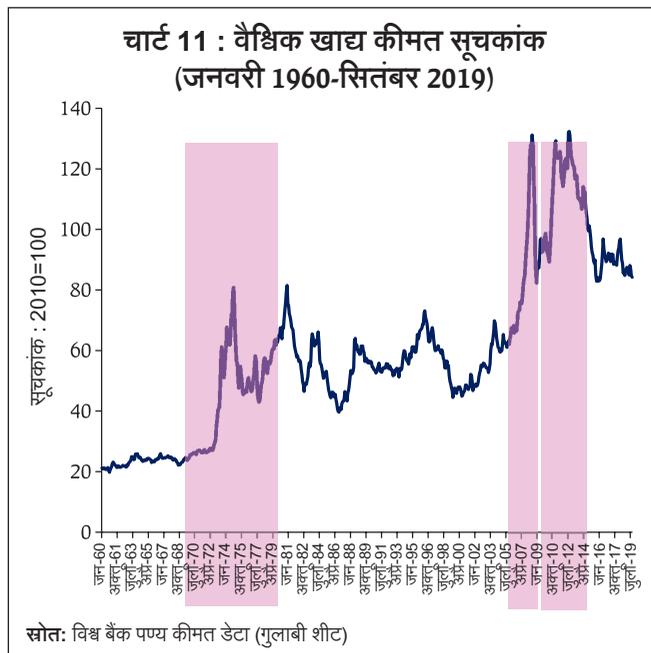


जल्दी समाप्त हो जाता है। वर्षण सूचकांक में सहसंबंध का दीर्घकाल तक बने रहना अधिक लंबे मानसून तथा एसडब्लूएम मानसून की वापसी और उत्तरी पूर्वी मानसून के आगमन के बीच के समयांतराल के कम होने का संकेत देता है।

अगले दो उप-खंडों में मँहगाई और आर्थिक गतिविधि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यहाँ, हालांकि समुद्र तल और पवन-चक्र जैसे अन्य कारक भी हैं जो बदलते जलवायु चक्र को दर्शाते हैं, तथापि इस विश्लेषण के तहत तापमान और वर्षा के प्रभाव (जैसा सूचकांकों का उपयोग करके मापा जाता है) का अध्ययन किया गया है।⁴

IV.1. मँहगाई पर असर

वैश्विक स्तर पर बात करें तो, खाद्य-वस्तुओं की कीमतों में उछाल मौसम से संबंधित घटनाओं के बाद की समयावधियों में ही आता है और इसका कारण होता है खराब मौसम से फसल की हानि / कम कृषि उत्पादन। पिछले छह दशकों के दौरान, ऐसे तीन अवसर आए जब विश्व स्तर पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई : 1970 के दशक के दौरान; 2007-08 में; और 2010-14 के दौरान, और इन सभी के मूल में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से लगे झटके तथा उनसे प्रेरित अन्य कारक जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि, व्यापार नीतियों में बदलाव और जैव ईंधन की खपत थे (चार्ट 11)।



⁴ चरम घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि के साथ, तापमान और वर्षा के प्रभावों में बदलाव की संभावना है।

भारत के मामले में, मुख्य मँहगाई⁵ साल-दर-साल गिरती गयी है और साथ ही, खाद्य मँहगाई में उल्लेखनीय गिरावट आयी है (संलग्न सारणी 3)। चूंकि समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में 46 प्रतिशत भागीदारी खाद्य समूह की है, इसलिए यह मुख्य मँहगाई के प्रक्षेपवक्र का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। मँहगाई और विभिन्न खाद्य घटकों में मौजूद इसकी अस्थिरता दोनों अलग-अलग पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। जनवरी 2012 से सितंबर 2019 के दौरान सब्जियों की मँहगाई दर उच्च (6.8 प्रतिशत) बनी रही है और साथ ही, इसकी अस्थिरता भी उल्लेखनीय रूप से अधिक (15.8 प्रतिशत) रही है। इसके अलावा, यह सीपीआई-खाद्य (भारिता: सीपीआई-खाद्य में 13.2 फीसदी) के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसका समग्र खाद्य मँहगाई दर के साथ मजबूत सकारात्मक संबंध है (सारणी 2)।

वर्षा का विचलन का सब्जियों की मँहगाई दर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से समग्र खाद्य मँहगाई दर

सारणी 2: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थ और इसके प्रमुख घटक : संक्षिप्त आंकड़े

घटक	खाद्य मँहगाई से साथ सहसंबंध	औसत मँहगाई (प्रतिशत)	मँहगाई में उतार-चढ़ाव (प्रतिशत)
अनाज और उनके उत्पाद (21.1)	0.77***	5.3	4.3
मांस और मछली (7.9)	0.81***	7.3	3.6
अंडा (0.9)	0.72***	5.9	5.4
दूध और उसके उत्पाद (14.4)	0.64***	6.4	3.9
तेल और वसा (7.8)	0.47***	4.6	4.7
फल (6.3)	0.51***	5.9	5.5
सब्जियाँ (13.2)	0.78***	6.8	15.8
दालें और उनके उत्पाद (5.2)	0.37***	5.2	16.5
चीनी और मिष्ठान (3.0)	0.17	3.0	9.8
मसाले (5.5)	0.24**	4.7	4.0
अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थ (2.7)	0.84***	4.9	2.4
बना-बनाया भोजन, नाश्ता, मिठाइयाँ आदि (12.1)	0.82***	7.5	3.3
भोजन और पेय पदार्थ	1.00	5.8	4.3

*** ** और * महत्व की दृष्टि से क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत को दर्शाते हैं।

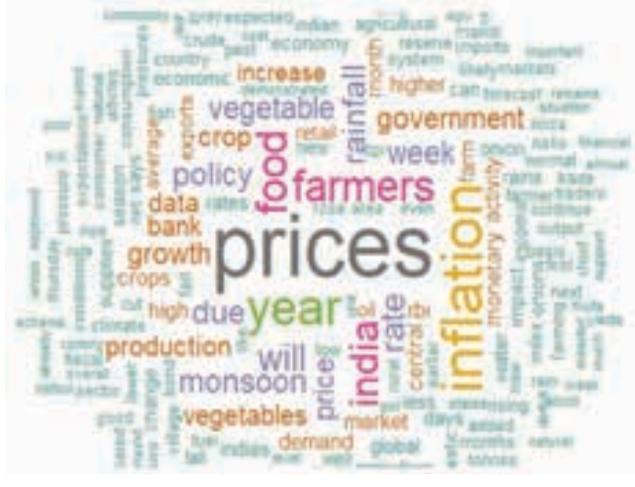
नोट: 1. कोष्ठक में दी गयी संख्याएं सीपीआई खाद्य एवं पेय पदार्थों की भारिता का संकेत करते हैं।

2. मँहगाई में उतार-चढ़ाव को मानक विचलन का प्रयोग करते हुए मापा जाता है।

स्रोत : एनएसओ; तथा लेखकों द्वारा की गयी गणना।

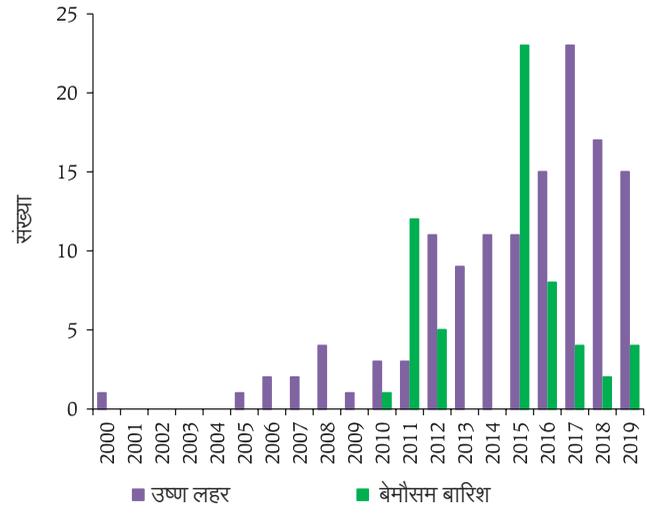
⁵ हेडलाइन मँहगाई को अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण और शहरी) में साल-दर-साल हुए परिवर्तनों से मापा जाता है।

उद्धरण 3: 2000-19 के दौरान बेमौसम बारिश, मॉनसून और भारत में खाद्य वस्तुओं/सब्जियों की कीमतें जैसे प्रमुख शब्दों पर आधारित समाचार-पत्र लेख



स्रोत: प्रोक्वेस्ट डेटाबेस; और लेखकों द्वारा की गयी गणना।

चार्ट 12: उष्ण लहर/बेमौसम बारिश और सब्जियों की कीमतों से संबंधित लेखों की संख्या



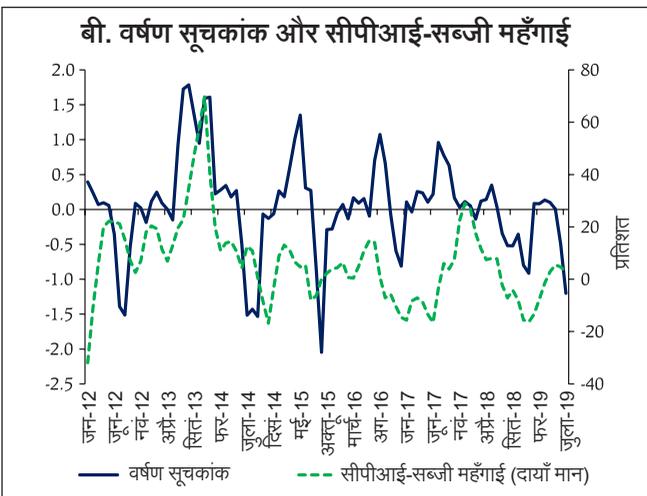
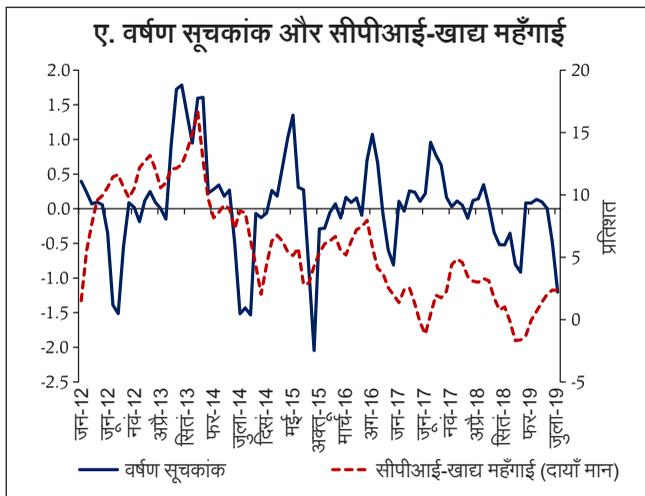
के साथ भी। समाचार पत्रों में इस प्रकार के लेखों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनमें बेमौसम बारिश और गर्म लू के थपेड़ों से खाद्य पदार्थों की कीमतें (विशेष रूप से सब्जियों की कीमतें) प्रभावित होने का जिक्र होता है (उद्धरण 3 और चार्ट 12)।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, हम सबसे पहले अखिल भारतीय वर्षण सूचकांक के साथ खाद्य मँहगाई दर और सब्जियों की मँहगाई दर के प्लॉट्स का अध्ययन करते हैं (चार्ट 13. ए और

13.बी)। वर्षण सूचकांक के साथ जहाँ जबकि खाद्य मँहगाई दर का आंशिक जुड़ाव का पता चलता है वहीं सब्जियों की मँहगाई दर का मजबूत सहसंबंध इसके साथ दिखाई पड़ता है।

वर्षण सूचकांक और खाद्य मँहगाई दर और इसके विभिन्न घटकों के बीच समकालीन सहसंबंध यह दर्शाता है कि सब्जियों की मँहगाई दर का वर्षण सूचकांक के साथ सहसंबंध 0.38 के उच्चतम स्तर पर है (सारणी 3)⁶ इसके अतिरिक्त, 12 महीने के

चार्ट 13 : अखिल भारतीय वर्षण सूचकांक और सीपीआई-खाद्य/सीपीआई-सब्जी मँहगाई



स्रोत: एनएसओ; सीआईसी डेटाबेस; और लेखकों द्वारा की गयी गणना।

⁶ हमें खाद्य मँहगाई और तापमान सूचकांक के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं देखने को मिला।

सारणी 3: खाद्य स्फीति, इसके घटकों और वर्षण सूचकांक के बीच संबंध

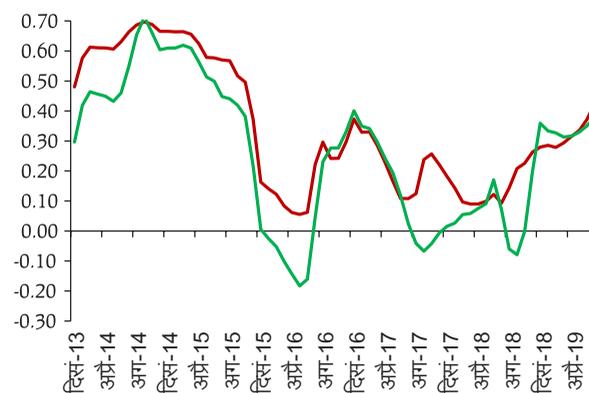
घटक	सहसंबंध गुणांक	पी-मान
अनाज और उत्पाद	0.26	0.01***
मांस और मछली	0.18	0.08*
अंडा	0.10	0.37
दूध और उत्पाद	0.02	0.82
तेल और वसा	-0.18	0.08
फल	-0.04	0.67
सब्जियां	0.38	0.00***
दालें और उत्पाद	-0.11	0.29
चीनी और कन्फेक्शनरी	0.03	0.77
मसाले	0.11	0.30
गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ	0.21	0.05**
तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि	0.16	0.13
खाद्य और पेय पदार्थ	0.25	0.02**

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; सीईआईसी डेटाबेस; और लेखकों की गणना।

परिवर्ती सहसंबंध गुणांक (जनवरी 2012 से प्रारंभ करते हुए) ऐसी समयावधियों को दर्शाते हैं जब सब्जियों (खाद्य) की मँहगाई दर और वर्षण सूचकांक के बीच सहसंबंध उच्चतम स्तर 0.70 पर पहुंच गया (चार्ट 14)।

इसके अलावा, हम क्रॉस-सहसंबंध गुणांक को देखते हैं, जो न केवल समकालीन सहसंबंध को प्रग्रहण करेगा, बल्कि अंतराल (लों) के साथ वर्षा के प्रभाव को भी दिखाएगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कुछ खाद्य घटकों में, वर्षा का प्रभाव कुछ समय अंतराल के साथ दिखाई दे सकता है, जबकि अन्य के लिए बारिश का प्रभाव कुछ महीनों तक रह सकता है। परिणामों से पता चलता है कि वर्षा का प्रभाव आमतौर पर सब्जी स्फीति के साथ-साथ समग्र खाद्य स्फीति के मामले में 5-6 महीने तक रहता है (चार्ट 15)। साथ ही, सब्जियों के मामले में, प्रभाव की सीमा कुछ अंतराल के साथ बढ़ सकती है। यह आमतौर पर ऐसा होता है क्योंकि सब्जियों की प्रकृति खराब हो जाने वाली होती है और फसलों के क्षतिग्रस्त होने और क्षेत्रों में फैले उत्पादन केंद्रों से प्रतिकूल आपूर्ति नुकसान के बाद कीमतों पर प्रभाव धीरे-धीरे परिलक्षित होता है। अनाजों के मामले में देखें तो हम वर्षण सूचकांक और मुद्रास्फीति के बीच बहुत अधिक संबंध नहीं पाते हैं, जो मुख्य रूप से अनाज के खराब नहीं होने और उपलब्ध बफर स्टॉक/अच्छी तरह से परिभाषित आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली

चार्ट 14: वर्षण सूचकांक और सीपीआई-खाद्य/सब्जी स्फीति के बीच रोलिंग सहसंबंध गुणांक

— वर्षण सूचकांक और सीपीआई-सब्जी मुद्रास्फीति

— वर्षण सूचकांक और सीपीआई-खाद्य स्फीति

स्रोत: एनएसओ; सीईआईसी डेटाबेस; और लेखकों की गणना।

की स्थिर भूमिका होने के कारण हो सकता है। किसी भी समकालीन सहसंबंध को मुख्य रूप से प्रतिकूल वर्षा पैटर्न और फसल बुवाई से संबंधित व्यापारियों के बीच बाजार की धारणाओं से प्रभावित किया जा सकता है। फलों के मामले में, वर्षण सूचकांक मुद्रास्फीति को कुछ अंतराल के साथ प्रभावित करता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अधिकांश फल मौसमी होते हैं और पूरे वर्ष में उत्पादित नहीं होते हैं। इसलिए, यदि प्रतिकूल वर्षा से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कीमतों पर प्रभाव धीरे-धीरे होता है और एक बार प्रभावित होने पर, यह कुछ अवधि तक रह सकता है।

चूँकि सब्जियों की कीमतें वर्षा में विघ्न से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, इसलिए हम सब्जियों के मूल्यों पर वर्षण सूचकांक के प्रभाव को एक अव्यवस्थित स्तर पर देखते हैं। सीपीआई-सब्जियों के भीतर, टमाटर (वजन: 9.5 प्रतिशत), प्याज (वजन: 10.7 प्रतिशत) और आलू (वजन: 16.3 प्रतिशत) मिलकर कुल हिस्सेदारी का 36 प्रतिशत हैं और इन तीन प्राथमिक सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं, जो समग्र रूप से सब्जियों की मँहगाई निर्धारित करते हैं। पुनः, क्रॉस-सहसंबंध विश्लेषण के आधार पर परिणाम दर्शाते हैं कि लगातार 4-5 महीनों के प्रभाव के साथ टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) को छोड़कर वर्षण सूचकांक में

चार्ट 15: वर्षण सूचकांक और खाद्य स्फीति के बीच क्रॉस-सहसंबंध गुणांक

खाद्य, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब	सब्जी, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब
	0	0.2490		0	0.3757
	1	0.2296		1	0.4050
	2	0.2289		2	0.4352
	3	0.2165		3	0.4162
	4	0.1758		4	0.3211
	5	0.1095		5	0.1788
	6	0.0442		6	0.0546
	7	0.0226		7	0.0121
मांस_मछली, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब	पेय, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब
	0	0.1827		0	0.2107
	1	0.1782		1	0.1535
	2	0.1290		2	0.1044
	3	0.0814		3	0.0699
	4	0.0347		4	0.0380
	5	-0.0133		5	0.0011
	6	-0.0898		6	-0.0370
अंडा, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब	फल, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब
	0	0.0949		0	-0.0448
	1	0.1024		1	-0.0259
	2	0.1085		2	0.0313
	3	0.1595		3	0.0948
	4	0.2201		4	0.1727
	5	0.2112		5	0.2458
	6	0.1271		6	0.2945
	7	0.0700		7	0.3206
	8	0.0510		8	0.3318
	9	0.0267		9	0.3503
	10	-0.0286		10	0.3506
				11	0.3189
				12	0.2897
				13	0.2602
				14	0.1910
				15	0.1135
				16	0.0404
अनाज, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब			
	0	0.2644			
	1	0.1938			
	2	0.1416			
	3	0.1147			
	4	0.1026			
	5	0.0820			
	6	0.0437			
	7	0.0166			

टिप्पणी: टूटी हुई रेखाएं 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाती हैं
 स्रोत: एनएसओ; सीईआईसी डेटाबेस; और लेखकों की गणना।

सब्जियों की महंगाई पर एक मजबूत और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाने की क्षमता है (चार्ट 16)। आलू के महंगा होने का वर्षण सूचकांक के साथ कोई खास संबंध नहीं था।⁷ इसका कारण आलू की स्टोर करने की प्रकृति और भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता हो सकता है। सब्जियों, विशेष रूप से प्याज और टमाटर की कीमत का बढ़ना, वर्ष 2019-20 में एक

प्रमुख चिंता का विषय था, इसकी वजह अक्टूबर में मानसून का देरी जाना, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में अत्यधिक/मानसून के बाद होने वाली बेमौसम बारिश के कारण हुआ फसलों को नुकसान और आपूर्ति में बाधा थी। पहले भी (विशेष रूप से, 2011, 2015, 2017 और 2018 के दौरान) ऐसे दौर देखने को मिले हैं जब बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों, खासकर प्याज और टमाटर की कीमतें प्रभावित हुई थी (आरबीआई, 2011; 2015; 2018)।

⁷ टमाटर और प्याज को छोड़कर वर्षण सूचकांक और सब्जियों के बीच क्रॉस सहसंबंध गुणांक दूसरे और तीसरे लैंग में महत्वपूर्ण पाए गए, लेकिन कम परिमाण के साथ। यह संभवतः आलू की कीमतों के अच्छे-खासे प्रभाव को दर्शाता है।

चार्ट 16: वर्षण सूचकांक और सीपीआई-सब्जी मुद्रास्फीति के बीच क्रॉस-सहसंबंध गुणांक

प्याज, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब	टमाटर, वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब	सब्जी_एक्सटॉप वर्षण सूचकांक (-i)	i	विलंब
█████	0	0.3719	█████	0	0.3514	█████	0	0.3975
█████	1	0.4187	█████	1	0.2978	█████	1	0.4538
█████	2	0.4400	█████	2	0.2522	█████	2	0.4912
█████	3	0.4041	█████	3	0.2550	█████	3	0.4345
█████	4	0.3085	█████	4	0.2005	█████	4	0.3111
█████	5	0.1793	█████	5	0.0596	█████	5	0.1795
█████	6	0.0718	█████	6	-0.0563	█████	6	0.0792

टिप्पणी: टूटी हुई रेखाएं 95 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाती हैं
 स्रोत: एनएसओ; सीआईआईसी डेटाबेस; और लेखकों की गणना।

IV.2. आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव

आर्थिक गतिविधि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, आठ उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक (जिनके लिए मासिक आधार पर डेटा उपलब्ध हैं) का उपयोग किया गया है। संकेतकों को इस तरह से चुना गया है कि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ट्रैक करते हैं। इन संकेतकों में शामिल हैं: विदेशी पर्यटक आगमन, ऑटोमोबाइल बिक्री, ट्रैक्टर बिक्री, बिजली की मांग, भारत का कुल व्यापार, क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आईआईपी-विनिर्माण खाद्य उत्पाद।

विश्लेषण के लिए, सभी चर मौसमी रूप से समायोजित किए जाते हैं। प्रत्येक संकेतक के लिए अलग-अलग समय-श्रृंखला प्रतिगमन दो मौसम सूचकांकों पर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाता है:

$$\Delta \log Y_t = \alpha + \beta P_t + \gamma T_t + \epsilon_t^8$$

जहां, Y_t आठ आर्थिक संकेतकों में से एक है जिस t समय पर मान लिया गया है। t समय पर P_t वर्षण सूचकांक है। t समय पर T_t

⁸ जिज्ञा किया गया मॉडल बहुत मजबूत नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि मौसम के सूचकांकों का आर्थिक गतिविधि के संकेतकों पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। हालांकि, चर (वेरिअस इन्फ्लेशन फैक्टर का उपयोग करके) और ऑटोकोर्रिलेशन (डर्बिन वाटसन स्टेटिस्टिक का उपयोग करके) के बीच की कोलीनियरिटी की जाँच की जाती है। अमेरिका के संदर्भ में तापमान और बर्फबारी के प्रभाव के समान विश्लेषण में निम्न आर-वर्गीय मान भी देखे गए थे (ब्लेशेक और गौरियो, 2015)।

तापमान सूचकांक है और ϵ_t अवशिष्ट है।

परिणाम से पता चलता है कि तापमान में परिवर्तन की तुलना में वर्षा का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है (सारणी 4)। वर्षण और तापमान दोनों सूचकांकों के मामले में पीएमआई के

सारणी 4: प्रतिगमन परिणाम⁹

आश्रित चर	वर्षा	तापमान	आर-वर्गीकृत
विदेशी पर्यटकों का आगमन ¹⁰	0.007 (0.205)	0.002 (0.441)	0.016
ऑटोमोबाइल की बिक्री	0.015** (0.026)	0.002 (0.624)	0.043
ट्रैक्टर की बिक्री	0.020* (0.086)	0.007 (0.234)	0.030
विद्युत ऊर्जा: मांग	0.005 (0.192)	0.005*** (0.009)	0.061
कुल व्यापार	-0.068** (0.048)	-0.045*** (0.012)	0.068
पीएमआई	-0.019*** (0.0000)	-0.005** (0.049)	0.222
आईआईपी	0.002 (0.441)	0.001 (0.429)	0.011
आईआईपी; विनिर्माण, खाद्य उत्पाद ¹¹	-0.007 (0.267)	-0.005 (0.199)	0.026

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व के स्तर को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े पी-मान को दर्शाते हैं।

⁹ यूनिट रूट परीक्षणों के परिणाम परिशिष्ट सारणी 4 में प्रस्तुत किए गए हैं।

¹⁰ वर्षण सूचकांक के पश्चायित मान ने विदेशी पर्यटकों की संख्या पर ऋणात्मक प्रभाव डाला (और यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया)। यह प्रशंसनीय है क्योंकि यात्रा वाले देश में मौसम संबंधी घटनाओं की संभावित निगरानी आगंतुकों द्वारा की जाएगी।

¹¹ वर्षण और तापमान सूचकांकों के पश्चायित मान को शामिल करने के बाद किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि तापमान और वर्षा प्रस्थान सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और विनिर्मित खाद्य उत्पादन पर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं।

लिए नकारात्मक संकेत यह दर्शाते हैं कि ज्योंही देश में गर्म बढ़ जाती है या जब अपेक्षित से अधिक बारिश होती है, तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में गिरावट आ जाती है। कुल व्यापार में भी नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि हम जानते हैं, तापमान में वृद्धि होने से बिजली की मांग बढ़ जाती है क्योंकि एयर-कंडीशनर, कूलर और रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता बढ़ जाती है। बारिश होने से ट्रैक्टर की बिक्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, बारिश में वृद्धि से ऑटोमोबाइल की बिक्री में भी तेजी आती है।

V. जलवायु परिवर्तन जोखिमों को कम करना

क्रोगस्ट्रुप और ओमान (2019) समष्टि आर्थिक और वित्तीय नीतियों पर साहित्य की व्यापक समीक्षा प्रदान करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि राजकोषीय साधन पहले सर्वोत्तम विकल्प हैं, लेकिन उपयुक्त मौद्रिक नीति लिखतों द्वारा पूरक होना चाहिए।

V.1. राजकोषीय नीति साधन

अप्रैल 2016 में, भारत ने आधिकारिक तौर पर अन्य 194 देशों के साथ 2015 के पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से ठीक नीचे रखा जाना चाहिए और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

क्रोगस्ट्रुप और ओमान (2019) के अनुसार, राजकोषीय नीति टूल्स को इनमें वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) कीमत नीतियां (कार्बन कराधान जो फर्मों और व्यक्तियों को उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करेगा; और शमन कार्यों के लिए सब्सिडी देगा); (2) खर्च और निवेश (एकमुश्त सार्वजनिक निवेश और रियायती ऋण); और (3) लोक गारंटी। आईएमएफ के राजकोषीय मॉनीटर (अक्टूबर 2019) में कार्बन कराधान के अलावा अन्य लिखतों के उपयोग पर चर्चा की गयी है, जिसमें एमिसन ट्रेडिंग सिस्टम्स¹², फीबेट्स¹³ और उत्सर्जन दर मानकों को निर्धारित

¹² फर्मों से अपेक्षित है कि वे अपने प्रत्येक टन उत्सर्जन के लिए एक अनुज्ञा रखें और सरकार कुल उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित कर सकती है।

¹³ औसत से ज्यादा उत्सर्जन पर शुल्क लगाना और उत्सर्जन दर से कम के लिए छूट।

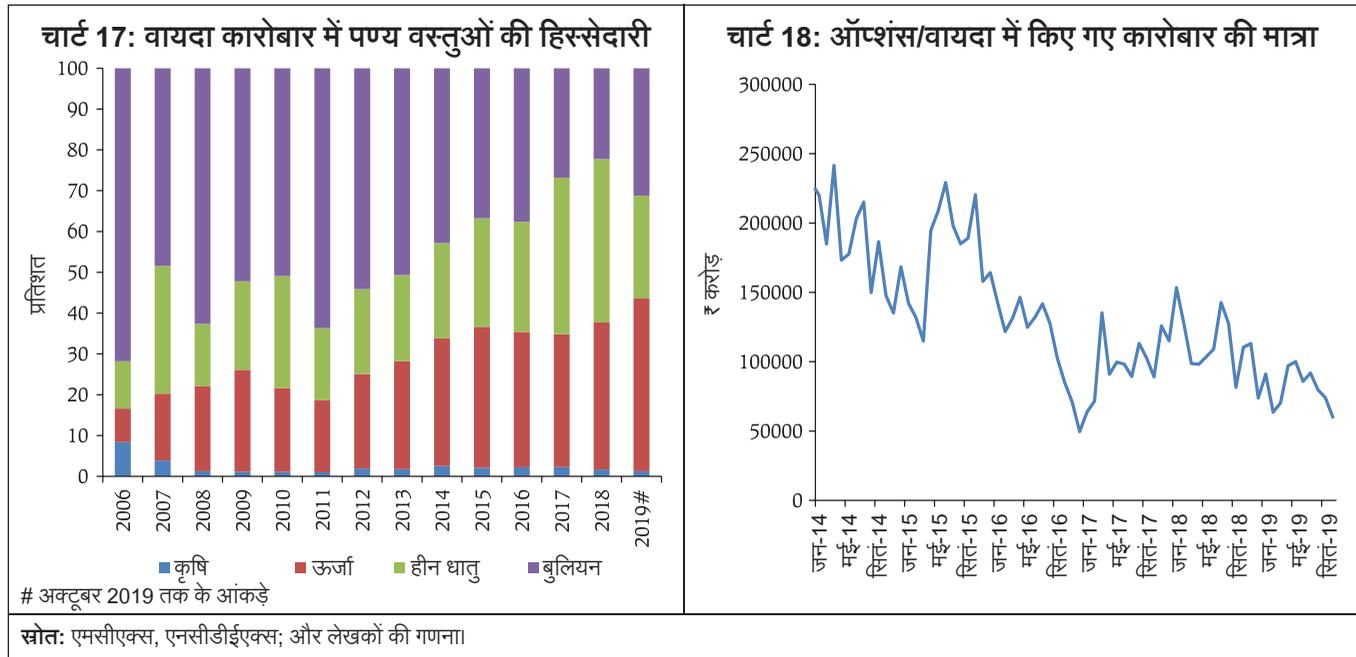
करने के लिए विनियम, या बिजली उत्पादन में नवीकरण के उपयोग के लिए न्यूनतम अपेक्षाएँ शामिल हैं। हालांकि, जागरूकता पैदा करना पहला कदम है, जो शासी निकायों की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।

V.2. कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार

वर्तमान में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) भारत में सबसे बड़ा कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है, इसके बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) है। व्यापार में शामिल वस्तुओं में धातु, बुलियन, ऊर्जा, मसाले, बागान, दालें, अनाज, पेट्रोकेमिकल, तेल और तिलहन शामिल हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि जिंस में वायदा कारोबार कम है और कुल व्यापार में हिस्सेदारी हाल के दिनों में घटी है (चार्ट 17)। इसके अलावा, एनसीडीईएक्स पर वायदा/विकल्प कारोबार किए जाने की मात्रा में तेज गिरावट आई है, जो कि सबसे बड़ा कृषि वायदा बाजार (चार्ट 18) है। अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एक विकसित कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार निरंतर कीमत निर्धारण को सक्षम करने और अनिश्चितता की स्थिति में कीमत जोखिम को कम करने के लिए एक रणनीति प्रदान करके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।

मौसम डेरिवेटिव्स को 'वित्तीय लिखतों के रूप में देखा जा सकता है, जिनके मूल्य और/या नकदी प्रवाह मौसम संबंधी घटनाओं के घटित होने पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना और मापा जा सकता है और ये वित्तीय संविदाओं के बुनियाद के तौर काम कर सकते हैं' (बैरीयू और स्कैलेट, 2009; कंसीडाइन) 2000)। मौसम डेरिवेटिव्स जो अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 1997 और 1998 में पेश किए गए थे, लोकप्रिय हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में बाजार काफी बढ़ गए हैं और उनका विस्तार काउंटर पर (ओटीसी) शेयर क्रय-विक्रय बाजारों तक हो गया है। शिकागो मर्केटाइल एक्सचेंज (सीएमई) ने मौसम संबंधी डेरिवेटिव पेश किए हैं जिसकी खरीद-बिक्री सीएमई के ग्लोबेक्स प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जा सकती है। लोकप्रिय संविदाएं फ्यूचर्स पर विकल्पों के साथ-साथ हीटिंग डिग्री डेज (एचडीडी) के आधार पर मासिक वायदा (स्वैप) संविदाएं हैं, जो यह मापती हैं कि सर्दियों में कितना हीटिंग आवश्यक है; और



कूलिंग डिग्री डेज (सीडीडी), जो मापता है कि गर्मी के महीनों में कितना ठंडा जरूरी है (श्वेनकर और टेलर, 2019)।

आमतौर पर बीमा का उपयोग कम संभावना और उच्च जोखिम वाली घटनाओं के घटित होने के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए किया जाता है। लेकिन मौसम डेरिवेटिव के मामले में, अंतर्निहित घटना को आवश्यक रूप से विनाशकारी नहीं होना चाहिए और उच्च-संभावना एवं कम जोखिम वाली घटनाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। देश में जलवायु परिवर्तन के पैटर्न को देखते हुए, मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत और उसे लोकप्रिय बनाना समय की समय की मांग बन गयी है।

मौसम डेरिवेटिव्स को पेश करने में आने वाली चुनौतियों में डिजाइन के मुद्दे, उचित मूल्य निर्धारण करने संबंधी नियमों का चुनाव और अंतर्निहित आस्तियों का चुनाव शामिल हैं। बेमौसम बारिश से होने वाले जोखिमों को कम करने में इसके महत्व और व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए वर्षा के लिए एक उपयुक्त सूचकांक का उपयोग करके पायलट रन चलाया जा सकता है।

V.3. केंद्रीय बैंकिंग टूल्स

केंद्रीय बैंकों से दो प्रकार के जोखिमों की निगरानी करने की अपेक्षा होती है: भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम (बैटन एवं

अन्य, 2016)। जहां भौतिक जोखिमों में मौसम संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले घर-परिवारों, कॉरपोरेट्स, बैंकों और बीमा कंपनियों की बैलेंस शीट की क्षति शामिल होगी, जिससे वित्तीय और समष्टि आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है, वहीं संक्रमण जोखिमों में राजकोषीय नीति संबंधी टूल्स के कार्यान्वयन के बाद के प्रभाव शामिल होंगे, जिसके कारण कार्बन-प्रधान आस्तियों का पुनः मूल्य निर्धारण करना पड़ सकता है और ऋणात्मक आपूर्ति का आघात भी लग सकता है।

जलवायु परिवर्तन पर केंद्रीय बैंक के सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जलवायु परिवर्तन को काफी चिंता का विषय बताया। आठ केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों ने 2017 में ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (एनजीएफएस) के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों नेटवर्क की स्थापना की, जो वित्तीय क्षेत्र¹⁴ में जोखिमों के विश्लेषण और प्रबंधन से संबंधित है। एनजीएफएस ने जलवायु-संबंधी कारकों को विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण में शामिल करने सहित केंद्रीय बैंकों, पर्यवेक्षकों, नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए छह सिफारिशों की है और वह एक मजबूत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत जलवायु और पर्यावरण प्रकटीकरण फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर देता है [एनजीएफएस (2019)]।

¹⁴ एनजीएफएस का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में 48 सदस्य हैं जिसमें दुनिया भर के केंद्रीय बैंक शामिल हैं।

क्रोगस्टुप और ओमान (2019), बैटन एवं अन्य, (2016), सिल्वा (2019) और केंद्रीय बैंकिंग फोकस रिपोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों की त्वरित समीक्षा उन महत्वपूर्ण उपायों को इंगित करेगी जिन्हें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाया जा सकता है:

1. ग्रीन फाइनेंस (जैसे एनजीएफएस) को लक्षित करने वाली गतिविधियों/पहलों को सहायता प्रदान करें।
2. नीति निर्माण और अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले विश्लेषणात्मक मॉडल में जलवायु जोखिमों को शामिल करें और उन क्षेत्रों को समझने के लिए वहाँ परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण करें जहां कार्रवाई की अपेक्षा हो।
3. वित्त के विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के अंतर को दूर करें।
4. अपने आरक्षित प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय बैंक कार्बन-प्रधान आस्ति जैसी ब्राउन आस्ति के बजाय हरित आस्ति में निवेश कर सकते हैं।
5. पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों में निवेश करने वाले बैंकों को अतिरिक्त/रियायती चलनिधि सहायता प्रदान करें।
6. पूंजी और संपार्श्विक नियमों को नया स्वरूप देकर बैंकों को हरित परियोजनाओं की ओर प्रेरित करना।
7. पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्रों को कम से कम एक निश्चित न्यूनतम ऋण आवंटित करने के लिए विनियमित/पर्यवेक्षित संस्थाओं (बैंकों) को प्रोत्साहित करना।

VI निष्कर्ष

जलवायु संबंधी स्थितियाँ, जिनमें दो प्रमुख संकेतक शामिल हैं - वर्षण और तापमान, भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वर्षों में, भारत ने बाकी दुनिया के अनुरूप जलवायु पैटर्न में बदलाव देखा है। जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ, जीएचजी उत्सर्जन के संचयी स्तर में वृद्धि हुई है, जिससे समय के साथ औसत तापमान में वृद्धि हुई है। खासकर वर्षा पैटर्न, विशेष रूप से एसडब्ल्यूएम के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत प्रदान करता है। इसके अलावा, पिछले दो दशकों के दौरान बाढ़/बेमौसम बारिश, लू और चक्रवात जैसे कठोर मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है और आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के कुछ प्रमुख कृषि राज्य इस तरह की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर दो अलग-अलग सूचकांकों का निर्माण किया गया - तापमान सूचकांक और वर्षण सूचकांक - और खाद्य स्फीति और आर्थिक गतिविधि संकेतकों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। परिणामों से पता चला कि मौसम की स्थिति, विशेष रूप से वर्षा, खाद्य स्फीति पथ पर मजबूत प्रभाव डालती है और यह प्रभाव कुछ महीनों तक बना रहता है। खाद्य के भीतर देखें तो, सब्जियों की कीमतें वर्षा आघात के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। परिणामों से यह भी देखने को मिला कि पीएमआई, आईआईपी, बिजली की मांग, व्यापार, पर्यटक आगमन और ट्रैक्टर एवं ऑटोमोबाइल बिक्री जैसे आर्थिक गतिविधियों के कुछ प्रमुख संकेतकों पर मौसम की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस आलेख में विभिन्न नीतिगत टूल पर भी प्रकाश डाला गया है जो जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

संदर्भ

- Acevedo, S., Mrkaic, M., Novta, N., Pugacheva, E., & Topalova, P. (2018), "The Effects of Weather Shocks on Economic Activity: What are the Channels of Impact?", *IMF Working Paper*, WP/18/144s.
- Akutsu, K., and Y. Koike (2019), "Analysis of Private Consumption using Weather Data", *Bank of Japan Review*, 2019-E-1.
- Barrieu, P., and O. Scaillet (2009), "A Primer on Weather Derivatives", *Uncertainty and Environmental Decision Making*, 155-175.
- Batten, S. (2018), "Climate Change and the Macro-Economy: A Critical Review", *Staff Working Paper No. 706*, Bank of England.
- Batten, S., R. Sowerbutts and M. Tanaka (2016), "Let's Talk About the Weather: The Impact of Climate Change on Central Banks", *Staff Working Paper No. 603*, Bank of England.
- Birthal, P.S., et al., (2014), "How Sensitive is Indian Agriculture to Climate Change?", *Indian Journal of Agricultural Economics*, 69 (4), National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.
- Bloesch, J., and F. Gourio (2015), "The Effect of Winter Weather on U.S. Economic Activity", *Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives*, 39, Number 1.
- Burgess, R., et al., (2014), "The Unequal Effects of Weather and Climate Change: Evidence from Mortality in India", available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/8958/18edb2300f50ffe45417f3c065c722dd1ba4.pdf>
- Central Banking (2019), "Central Banking Focus Report-Climate Change", in association with Amundi Asset Management.
- Colacito, R., et al., (2018), "The Impact of Higher Temperatures on Economic Growth", *Economic Brief*, Federal Reserve Bank of Richmond.
- Considine, G. (2000), "Introduction to Weather Derivatives", available at <http://www.agroinsurance.com/files/weather%20derivatives.pdf>
- Dell, M., B.F. Jones and B.A. Olken (2012), "Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence from the Last Half Century", *American Economic Journal: Macroeconomics*, 4 (3), 66-95.
- IMF (2019), "Fiscal Monitor-How to Mitigate Climate Change", October, Washington DC, USA.
- IMF (2019), "Global Financial Stability Report", October, Washington DC, USA.
- IMF (2019), "World Economic Outlook", April, Washington DC, USA.
- IMF (2019), "World Economic Outlook", October, Washington DC, USA.
- Indian Environment Portal: <http://www.indiaenvironmentportal.org.in>
- IPCC (2018), "Global Warming of 1.5°C", *Special Report*, Switzerland.
- IPCC (2019), "Climate Change and Land", *Summary for Policymakers*, Approved Draft.
- Joshi, V., and U. R. Patel (2009), "India and Climate Change Mitigation", *Smith School Working Paper Series*, Working Paper 003, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, UK.
- Kahn, M.E., et al., (2019), "Long-term Macroeconomic Effects of Climate Change: A Cross-Country Analysis", *NBER Working Paper Series*, Working Paper 26167.
- Krogstrup, S., W. Oman, (2019), "Macroeconomic and Financial Policies for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature", *IMF Working Paper*, No. 19/185.
- Lesk, C., P. Rowhani and N. Ramankutty (2016), "Influence of Extreme Weather Disasters on Global Crop Production", *Nature*, 529, 84-99.

Mani, M., *et al.*, (2018), "South Asia's Hotspots: The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards", World Bank Group, Washington DC, USA.

Murari, K., *et al.*, (2018), "Extreme Temperatures and crop Yields in Karnataka, India", *Review of Agrarian Studies*, 8 (2).

NGFS (2019), "A call for action-Climate change as a source of financial risk", available at https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/17/ngfs_first_comprehensive_report_-_17042019_0.pdf

Nordhaus, W.D. (2017), "Projections and Uncertainties about Climate Change in an Era of Minimal Climate Policies", *NBER Working Paper Series*, Working Paper 22933.

RBI (2011), "Reserve Bank of India Annual Report 2010-11", Mumbai.

RBI (2015), "Reserve Bank of India Annual Report 2014-15", Mumbai.

RBI (2018), "Reserve Bank of India Annual Report 2017-18", Mumbai.

Rudebusch, G.D. (2019), "Climate Change and the Federal Reserve", FRBSF Economic Letter.

Schlenker, W., and C. A. Taylor (2019), "Market Expectations about Climate Change", *NBER Working Paper Series*, Working Paper 25554.

Silva, L A P da (2019), "Research on Climate-related Risks and Financial Stability: An Epistemological Break?", Conference of the Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS), Paris, April.

United Nations <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/>

United Nations Framework Convention on Climate Change <https://unfccc.int/>

Vogel, E., *et al.*, (2019), "The Effects of Climate Extremes on Global Agricultural Yields", *Environmental Research Letters*, 14.

परिशिष्ट सारणी 1: जलवायु परिवर्तन और समष्टि अर्थव्यवस्था - ट्रांसमिशन चैनल और जोखिम				
आघात/प्रभाव का प्रकार		भौतिक जोखिम		संक्रमण जोखिम
		कठोर मौसम की घटनाओं से	क्रमिक ग्लोबल वार्मिंग से	
मांग	निवेश	जलवायु घटनाओं के बारे में अनिश्चितता		जलवायु नीतियों से 'निजी निवेश का बहिर्गमन'
	उपभोग	आवासीय संपत्ति के लिए बाढ़ का बढ़ा हुआ जोखिम		जलवायु नीतियों से 'निजी निवेश का बहिर्गमन'
	व्यापार	प्राकृतिक आपदाओं के कारण आयात/निर्यात प्रवाह में व्यवधान		असममितिक जलवायु नीतियों से उत्पन्न विकृतियां
	श्रम आपूर्ति	प्राकृतिक आपदाओं के कारण काम के घंटों का नुकसान	अत्यधिक गर्मी के कारण काम किए गए घंटों का नुकसान	
	ऊर्जा, भोजन और अन्य इनपुट	भोजन और अन्य इनपुट की कमी		ऊर्जा आपूर्ति का जोखिम
आपूर्ति	पूंजीगत स्टॉक	कठोर मौसम के कारण नुकसान	उत्पादक निवेश से अनुकूलन पूंजी की ओर संसाधनों का विचलन	उत्पादक निवेश से शमन गतिविधियों की ओर संसाधनों का विचलन
	प्रौद्योगिकी	नवाचार से पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापन की ओर संसाधनों का विचलन	नवाचार से अनुकूलन पूंजी की ओर संसाधनों का विचलन	नवाचार की दर और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बारे में अनिश्चितता

स्रोत: बैटन (2018)

परिशिष्ट सारणी 2.ए: पेयरवाइज ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट	
शून्य परिकल्पना	पी-मान
प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रति व्यक्ति ग्रेंजर कॉज CO_2 उत्सर्जन नहीं करता है	0.008
प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का कारण नहीं है	0.392
तापमान प्रति व्यक्ति ग्रेंजर कॉज CO_2 उत्सर्जन नहीं करता है	0.983
CO_2 उत्सर्जन प्रति व्यक्ति ग्रेंजर कॉज तापमान का कारण नहीं है	0.000
तापमान प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रेंजर कॉज नहीं करता है	0.085
प्रति व्यक्ति जीडीपी ग्रेंजर कॉज तापमान नहीं है	0.000

परिशिष्ट सारणी 2.बी: पेयरवाइज ग्रेंजर कॉजेलिटी टेस्ट	
शून्य परिकल्पना	पी-मान
कृषि उपज वर्षा का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.162
वर्षा कृषि उपज का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.000
सकल सिंचित क्षेत्र वर्षा का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.168
वर्षा सकल सिंचित क्षेत्र का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.000
सकल सिंचित क्षेत्र कृषि उपज का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.001
कृषि उपज सकल सिंचित क्षेत्र का ग्रेंजर कॉज नहीं होता है	0.481

परिशिष्ट सारणी 3: सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति और इसके प्रमुख घटक

घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रै.-सितं.)
खाद्य और पेय पदार्थ (45.86)	11.2	11.9	6.5	5.1	4.4	2.2	0.7	2.6
ईंधन और प्रकाश (6.84)	9.7	7.7	4.2	5.3	3.3	6.2	5.7	0.5
भोजन और ईंधन को छोड़कर (47.30)	9.0	7.2	5.4	4.6	4.8	4.6	5.8	3.3
सभी समूह	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.3

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सीपीआई-संयुक्त में भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

परिशिष्ट सारणी 4: यूनिट रूट टेस्ट के परिणाम

चर	औगंमेटेड डिक्ली फुलर टेस्ट स्टेटिस्टिक		फिलिप्स-पेरोन टेस्ट स्टेटिस्टिक	
	X	ΔX	X	ΔX
विदेशी पर्यटक आगमन	-0.182	-9.727***	-0.387	-29.786***
ऑटोमोबाइल बिक्री	-1.910	-13.367***	-2.287	-14.592***
ट्रैक्टर बिक्री	-3.016	-9.311***	-2.660	-16.058***
विद्युत ऊर्जा: मांग	-0.325	-15.339***	-0.323	-17.275***
कुल व्यापार	-2.093	-22.254***	-1.957	-19.867***
आईआईपी	0.333	-10.567***	0.480	-25.973***
आईआईपी: विनिर्माण, खाद्य उत्पाद	-0.089	-10.629***	-0.162	-25.561***
पीएमआई	-4.695***	-	-4.640***	-

***, ** और * क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के महत्व को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; और लेखकों की गणना।

केंद्रीय बजट 2020-21 का आकलन*

केंद्रीय बजट 2020-21 का उद्देश्य अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि उपायों के संयुक्त प्रयासों से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसे, राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए, वृद्धि के लिए प्रति-चक्रिय सहयोग प्रदान करने की जरूरत को लेकर संतुलन बनाए रखते हुए नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ा। केंद्रीय बजट 2020-21 में वृद्धि को बढ़ावा देने, कर संरचना को आसान बनाने, अनुपालन को सुलभ करने और मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से कर परिवर्तन लाया गया। बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती से भी बचा गया, जो प्रशंसनीय है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2020-21 को, वृद्धि के लिए प्रति-चक्रिय सहयोग प्रदान करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन करने की दोहरी अनिवार्यता को लेकर संतुलन बनाए रखते हुए, नाजुक स्थितियों से गुजरना पड़ा। इसने एफआरबीएम एस्केप क्लॉज के भीतर कर संग्रह में कमी को देखते हुए व्यय की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करते हुए राजकोषीय विवेक का पालन किया। यह माना जाता है कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल उन्नयन, उद्योग, वाणिज्य, निवेश, आधारभूत संरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि मुख्य रूप से गैर-कर राजस्व और विनिवेश द्वारा वित्तपोषित है। इस पृष्ठभूमि में, आलेख के बाकी हिस्सों को सात खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II में सकल राजकोषीय घाटे और अंतर्निहित राजकोषीय अंकगणित पर चर्चा की गई है, जबकि खंड III में केंद्र सरकार के वित्त के प्राप्ति पक्ष की जांच की गई है। खंड IV सरकारी खर्चों से संबंधित है और खंड V सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। खंड VI सरकार की

* कौशिकी सिंह, सक्षम सूद, राहुल अग्रवाल और अंशुमान कमिला द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के समीर रंजन बेहरा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। डेटा के लिए अर्चना वर्मा का आभार। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने विचार हैं और इन विचारों का उनकी संस्था से कोई संबंध नहीं है। सामान्य अस्वीकरण लागू होते हैं। केंद्रीय बजट 2019-20 पर पिछला लेख भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2019 बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था।

बकाया देयताओं को दर्शाता है और खंड VII केंद्र से राज्यों में संसाधन के अंतरण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड VIII में निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं। अनुबंध 1 में बजट में निर्धारित विस्तृत क्षेत्रवार उपायों को सूचीबद्ध किया गया है।

II. राजकोषीय घाटा

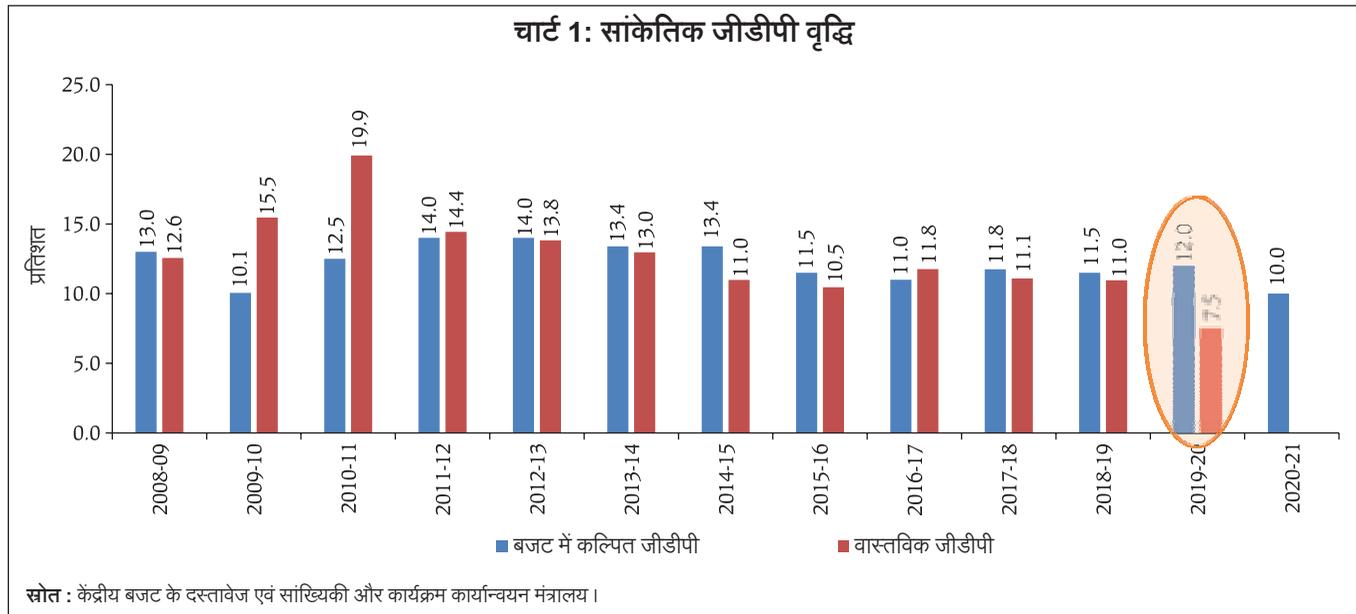
2019-20 के लिए जीडीपी के 3.3 प्रतिशत के बजटीय सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के मुकाबले, संशोधित अनुमान ने जीएफडी को जीडीपी¹ के 3.75 प्रतिशत पर रखा। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के तहत प्रावधानों को लागू करते हुए, 2020-21 के लिए उपर्युक्त के समान ही लक्ष्य से अधिक अर्थात् जीडीपी से 0.5 प्रतिशत अधिक का बजट भी किया गया है² वर्ष 2019-20 में जीएफडी के खस्ताहाल के पीछे मुख्य कारण कर राजस्व में जीडीपी की तुलना में 1.1 प्रतिशत की गिरावट का होना था, वहीं गैर-कर राजस्व ने थोड़ी राहत प्रदान की। वर्ष 2020-21 के लिए एफआरबीएम लक्ष्य से अनुमानित विचलन, राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के व्यय ट्रेजेवट्री को बनाए रखने की वजह से है, ताकि कर राजस्व को लेकर वास्तविकता के अधिक करीब स्तर का अनुमान लगाते हुए घरेलू आर्थिक गतिविधि को बढ़ाया जा सके (सारणी 1)।

केंद्रीय बजट और अंतर्निहित अंकगणित

वर्ष 2019-20 में सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर (बजटीय और संशोधित अनुमानों के बीच) में तेज गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2008-09 में देखे गए वैश्विक वित्तीय संकट की अपेक्षा कहीं ज्यादा थी (चार्ट 1)।

¹ किसी अमुक वर्ष के संदर्भ में जीडीपी के नवीनतम अनुमानों का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, हमने 2018-19 के लिए जीडीपी के पहले संशोधित अनुमानों और 2019-20 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों का उपयोग किया है, जिसके कारण इन दो वर्षों के मामले में जीडीपी की तुलना में कुछ निश्चित अनुपात केंद्रीय बजट में प्रकाशित अनुपात से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट में प्रयुक्त सांकेतिक जीडीपी (₹204.4 लाख करोड़) के पहले अग्रिम अनुमान के आधार पर, 2019-20 (आरई) के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.75 प्रतिशत है। हालांकि, दूसरे अग्रिम अनुमान (₹203.8 लाख करोड़) के आधार पर, जो बाद में जारी किए गए थे, 2019-20 (आरई) के लिए जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.76 प्रतिशत है।

² संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(2) के तहत यथा निर्दिष्ट अनुसार, सकल राजकोषीय घाटे को विशिष्ट परिस्थितियों में, अर्थात्, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि के पतन से कृषि उत्पादन और आय बुरी तरह से प्रभावित होने, अप्रत्याशित राजकोषीय प्रभाव के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, तिमाही की वास्तविक उत्पादन वृद्धि में उसकी पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों की गिरावट के आधार पर वर्ष में जीडीपी के अधिकतम डेढ़ प्रतिशत तक विचलित होने की अनुमति दी जा सकती है।
स्रोत: वित्त अधिनियम, 2018.



सारणी 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2018-19	2019-20		2020-21	2021-22	2022-23
	वास्तविक	बीई	आरई	बीई	अनुमान	
1	2	3	4	5	6	7
1. राजकोषीय घाटा	3.4	3.3	3.8	3.5	3.3	3.1
2. राजस्व घाटा	2.4	2.3	2.5	2.7	2.3	1.9
3. प्राथमिक घाटा	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.0
4. कर राजस्व	11.0	11.7	10.6	10.8	10.7	10.7
5. गैर-कर राजस्व	1.2	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5
6. राजस्व व्यय	10.6	11.6	11.5	11.7	-	-
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.6	1.7	1.8	-	-

स्रोत : केंद्रीय बजट 2020-21.

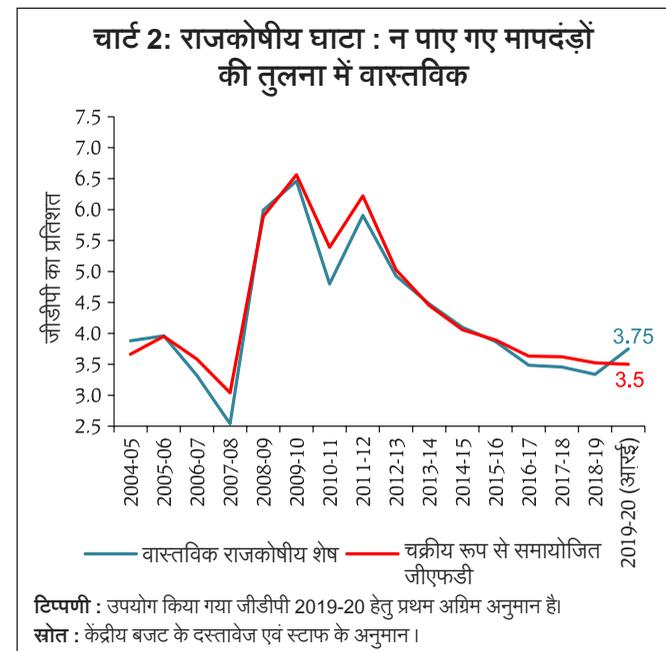
जीडीपी वृद्धि में कमी जीएफडी-जीडीपी अनुपात को दो तरीके से प्रभावित कर सकती है : (i) जब कर राजस्व कम होने लगता है ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर सक्रिय हो जाते हैं किंतु व्यय ट्रैजेक्ट्री को बनाए रखा जाता है, और इस प्रकार अंश (न्यूमरेटर) ऊपर चला जाता है; तथा (ii) जीडीपी में अनुमानित सांकेतिक वृद्धि से भी कम वृद्धि होने के चलते विभाजक (डिनामिनेटर) बजटीय की अपेक्षा कम है। इन दो प्रभावों के लिए समायोजन करने से चक्रिय रूप से समायोजित जीएफडी 3.5 प्रतिशत³ होता

³ फेडेलिनो एनलिसा, मार्क हॉर्टन, और अन्ना इवानोवा (2009), "कम्प्यूटिंग साइकिलिकली-एडजस्टेड बैलेंसेस एंड ऑटोमैटिक स्टेबलाइजर्स", तकनीकी नोट्स और मैनुअल, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विसंबरा।

है, जो 2019-20 हेतु 3.75 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से 25 आधार अंक कम है, जिनमें से 12 आधार अंक डिनामिनेटर पर निम्नतर जीडीपी वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ने से है (चार्ट 2)।

जीएफडी का वियोजन

यह संभावना है कि राजस्व घाटे की वजह से 2020-21 में जीएफडी का लगभग 76.5 प्रतिशत पहले ही खाली हो जाएगा, जो 2018-19 और 2019-20 में हुए सुधार को पूरी तरह से कम



सारणी 2: जीएफडी का वियोजन

(प्रतिशत)

	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21
	बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	आरई	बीई
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व घाटा	58.8	75.1	66.6	70.0	68.9	65.1	76.5
2. पूंजीगत परिव्यय	49.4	41.5	44.6	43.0	44.2	41.9	47.8
3. शुद्ध उधार	5.1	0.4	1.5	1.6	1.8	1.4	2.1
4. विनिवेश (घटाकर)	13.3	16.9	12.8	14.6	14.9	8.5	26.4

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

कर देगा। फिर भी, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है, और संभावना है कि इसके वित्तपोषण के लिए मुख्यतः अधिक से अधिक विनिवेश किया जाएगा (सारणी 2)।

III. प्राप्ति

2019-20 हेतु संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुसार कुल प्राप्ति, जिसमें शुद्ध कर एवं गैर-कर राजस्व के साथ-साथ गैर-कर पूंजीगत प्राप्ति आती हैं, जीडीपी का 9.5 प्रतिशत थीं, जो कम कर राजस्व (जीडीपी के 7.8 प्रतिशत के बजट अनुमानों (बीई) की अपेक्षा जीडीपी के 7.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान) प्राप्त होने की वजह से 9.9 प्रतिशत के बजटीय जीडीपी से कम है। गैर-कर राजस्व में अच्छी वृद्धि हुई और वह मामूली रूप से बीई से भी अधिक हुआ।

कर राजस्व

2020-21 में जीडीपी में सकल कर राजस्व का अनुपात बढ़कर 10.8 प्रतिशत (2019-20 में जीडीपी का 10.6 प्रतिशत) होने की उम्मीद की जाती है, जो व्यक्तिगत आय कर - मध्यम आय समूह के पक्ष में कर की दरों में समायोजन करने - एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सिवाय सभी कर श्रेणियों के लिए अधिक बजटीय उछाल की बदौलत है। विशेष रूप से, उत्पाद शुल्कों के सिवाय सभी करों के संबंध में उल्लिखित उछाल उनके रुझान के स्तरों (2011-18 के औसतों को लेकर) से भी अधिक हैं (सारणी 3)।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है वहीं 2019-20 (आरई) में उसमें 2.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (सारणी 4)। सभी आय समूहों में आय कर की दरों को युक्तिसंगत करने तथा अनुपालन को सरल बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप

सारणी 3: कर उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 से 2017-18)	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6
1. सकल कर राजस्व	1.15	0.77	1.63	0.54	1.16
2. प्रत्यक्ष कर	1.00	1.23	1.56	0.39	1.23
(i) कॉर्पोरेशन कर	0.84	1.48	1.38	-1.07	1.12
(ii) आय कर	1.20	1.19	1.83	2.49	1.38
3. अप्रत्यक्ष कर	1.37	0.27	1.72	0.70	1.08
(i) जीएसटी	-	2.87	1.25	0.71	1.24
(ii) सीमा शुल्क	0.47	-0.79	2.88	0.82	1.01
(iii) केंद्रीय उत्पाद	1.17	-0.97	2.61	0.93	0.74

टिप्पणी : '-' : लागू नहीं। कर उछाल को सांकेतिक जीडीपी में परिवर्तन की तुलना में कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है।

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट के दस्तावेजों पर आधारित स्टाफ की गणनाएं।

₹40,000 करोड़ का राजस्व त्यागना होगा। इसके अलावा, लाभांश वितरण कर के हटाए जाने से ₹25,000 करोड़ की राजस्व हानि होगी। सरकारी खजाने को होने वाली इन हानियों की भरपाई अनुपालन में बढ़ोत्तरी से कर उछाल में होने वाले संभावित लाभ से की जाती है एवं साथ ही निवेश के लिए गंतव्य स्थान के रूप में भारत को ज्यादा आकर्षक बनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स, विदेशी निवेश, विद्युत उत्पन्न करने वाली कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा किफ़ायती आवास के मामले में कर रियायतों से एक उज्ज्वल निवेश वातावरण पनपने की संभावना है (कर प्रस्तावों के विवरण के लिए अनुबंध। देखें)। इतना ही नहीं, एक सरल आय कर संरचना के होने से मध्यम वर्ग को अवश्य लाभ होगा। आय कर एवं कॉर्पोरेट कर की दरों (जैसा 2019 में पहले ही घोषणा की गई) के माध्यम से संयुक्त प्रोत्साहन जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत होता है।

सारणी 4: केंद्र सरकार का कर राजस्व

	₹ हजार करोड़				जीडीपी का प्रतिशत			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. प्रत्यक्ष कर	1136.6	1335.0	1170.0	1319.0	6.3	5.7	5.9	17.5	2.9	12.7
जिसमें से :										
i. आय कर	461.5	556.2	547.0	625.0	2.6	2.7	2.8	20.5	18.5	14.3
ii. कॉर्पोरेशन कर	663.6	766.0	610.5	681.0	3.6	3.0	3.0	15.4	-8.0	11.5
2. अप्रत्यक्ष कर	943.9	1126.2	993.4	1104.0	5.3	4.9	4.9	19.3	5.3	11.1
जिसमें से :										
i. जीएसटी	581.6	663.3	612.3	690.5	3.1	3.0	3.1	14.1	5.3	12.8
सीजीएसटी	457.5	526.0	514.0	580.0	2.5	2.5	2.6	15.0	12.3	12.8
आईजीएसटी	28.9	28.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-3.3	-	-
मुआवजा उपकर	95.1	109.3	98.3	110.5	0.5	0.5	0.5	15.0	3.4	12.4
ii. सीमा शुल्क	117.8	155.9	125.0	138.0	0.7	0.6	0.6	32.3	6.1	10.4
iii. केंद्रीय उत्पाद	232.0	300.0	248.0	267.0	1.4	1.2	1.2	29.3	6.9	7.7
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2080.5	2461.2	2163.4	2423.0	11.7	10.6	10.8	18.3	4.0	12.0

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

अप्रत्यक्ष कर

2019-20 (आरई) में अप्रत्यक्ष कर संग्रह के सभी घटकों में गिरावट होने की वजह से वह बजट अनुमानों की अपेक्षा ₹1.3 लाख करोड़ से कम रह गया। अप्रत्यक्ष कर 2020-21 में 11.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है और बजट में जीएसटी संग्रह ₹6.9 लाख करोड़ होना बताया गया है जो 12.8 प्रतिशत की वृद्धि बताता है। इस दरमियान जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने की बदौलत लगभग ₹1 लाख करोड़ का प्रोत्साहन उपलब्ध होने का अनुमान है। आगे, जीएसटी संबंधी बाधाओं को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाने से जीएसटी संग्रह और मजबूत एवं कारगर होगा। सीमा शुल्क को लेकर

विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के अंतर्गत आयात की डम्पिंग, जो घरेलू उद्योग, खासकर श्रम-प्रधान एमएसएमई एवं मेक इन इंडिया के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को काबू में करने पर जोर दिया जा रहा है।

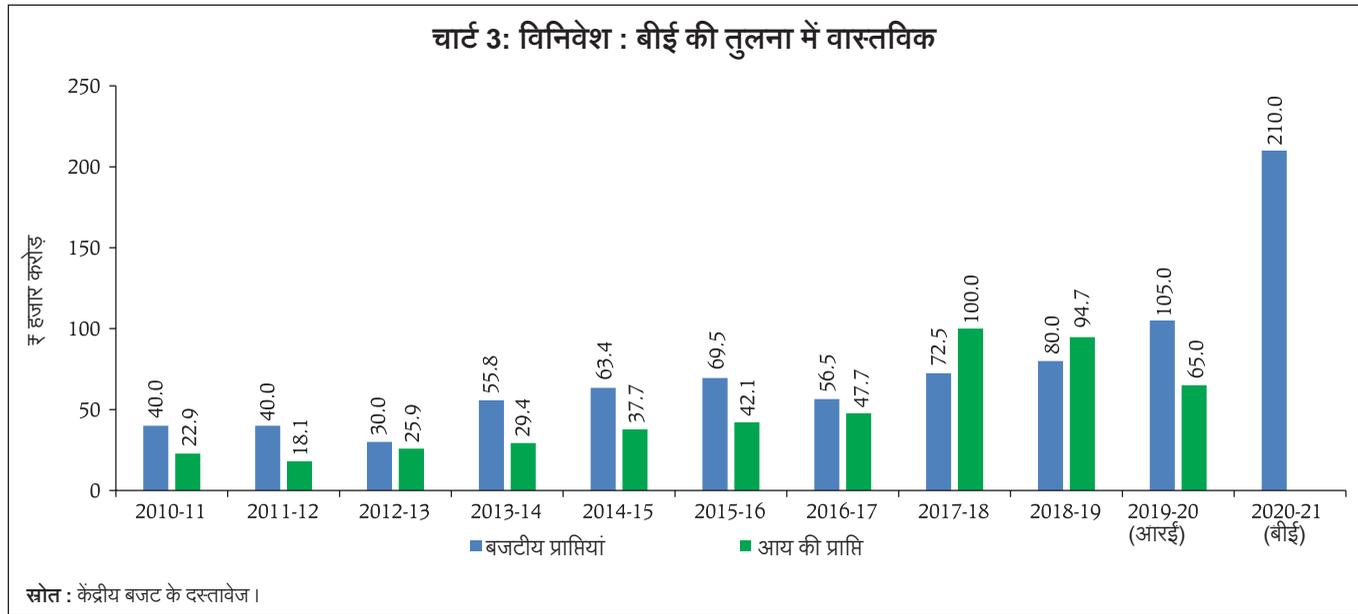
गैर कर राजस्व

गैर-कर राजस्व से प्राप्तियां 2020-21 में 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू बैंकों सहित) से होने वाले लाभांश और लाभ तथा आरबीआई से होने वाले अधिशेष अंतरण 2020-21 (बीई) में घटने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो 2019-20 (आरई) के दौरान बजटीय राशि से 22.2 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 5)।

सारणी 5: गैर-कर राजस्व

	₹ हजार करोड़				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल गैर-कर राजस्व	235.7	313.2	345.5	385.0	22.3	32.9	46.6	11.4
जिसमें से								
लाभांश और लाभ	113.4	163.5	199.9	155.4	24.1	44.2	76.2	-22.3
पीएसई से	43.1	57.5	48.3	65.7	-7.4	33.5	12.1	36.2
आरबीआई/बैंक/एफआई से	70.4	106.0	151.6	89.6	56.9	50.7	115.5	-40.9

स्रोत : विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट के दस्तावेज।



गैर-कर्ज पूंजीगत प्रामियां

विनिवेश का लक्ष्य 2020-21 (बीई) में ₹2.1 लाख करोड़ होना दर्शाया गया है जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। वर्ष 2019-20 (आरई) में, विनिवेश आय में ₹1.05 लाख करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है (चार्ट 3)। ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो, विनिवेश के संबंध में बजटीय लक्ष्यों की तुलना

में कमियां पिछले दस वर्षों में आठ बार देखने को मिली हैं, वहीं वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त, विनिवेश में एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) के बढ़ते महत्व को महसूस करना उल्लेखनीय है (बॉक्स I)। वर्ष 2020-21 (बीई) में ऋणों और अग्रियों से होने वाली वसूली 2019-20 (आरई) की बनिस्बत 9.9 प्रतिशत से घटने का उल्लेख बजट में किया गया है।

बॉक्स I: एक्सचेंज ट्रेड फंड्स (ईटीएफ) के जरिए विनिवेश

ईटीएफ प्रतिभूतियों के समूह होते हैं, जिन्हें एक्सचेंज पर व्यक्तिगत स्टॉक की तरह खरीदा-बेचा जाता है। नियमित म्यूचुअल फंडों के विपरीत, ईटीएफ को किसी भी स्टॉक की तरह पूरे दिन खरीदा और बेचा जा सकता है। ईटीएफ आम तौर पर विभिन्न आस्ति वर्गों, जैसे कि सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, पण्यों जिसमें कच्चा तेल और सोना शामिल है, यूरो या कैनेडियन डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर नज़र रखते हैं।

निवेशकों के लिए, ईटीएफ पसंदीदा निवेश अवसर हैं क्योंकि (i) वे किफ़ायती हैं (वे स्टार फंड मैनेजरों की सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं; भारत में, अधिकांश ईटीएफ अपने शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.05 से 1 प्रतिशत वार्षिक खर्च लेते हैं, जबकि सक्रिय रूप से देखरेख किए जाने वाले फंड प्रति वर्ष 2.5-3.25 प्रतिशत और ओपन-एंड इंडेक्स फंड प्रति वर्ष 0.20-2 प्रतिशत शुल्क लेते हैं) (प्रशांता और राज, 2015); (ii) वे निवेशकों को फंड मैनेजर के अधिक सुविज्ञ प्रतिभूति चयन का लाभ पहुंचाते हैं, साथ ही उन्हें विविध निवेश पोर्टफोलियो पेश किया जाता है; (iii) वे एक्सचेंजों के

माध्यम से उच्च तरलता पेश करते हैं; (iv) प्रारंभिक निवेश कम होने की वजह से, खरीद/ बिक्री के लिए वे सरल और सुविधाजनक हैं।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार अपने व्यापक विनिवेश कार्यक्रम के तहत ईटीएफ के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। इस पहल के तहत दो ईटीएफ शुरू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: (ए) सीपीएसई ईटीएफ - जो 11 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) - तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (एनटीपीसी), कोल इंडिया, इंडियन ऑयल निगम (आईओसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, एनबीसीसी इंडिया, एनएलसी इंडिया और एसजेवीएन के शेयरों को ट्रेक करता है; तथा (बी) भारत -22 ईटीएफ - जिसमें नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को), ओएनजीसी, आईओसी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आरईसी, पीएफसी, इंडियन बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, भारत

(जारी)

इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), एनटीपीसी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी), एनएलसी, एसजेवीएन शामिल हैं।

2013-14 से ईटीएफ के जरिए प्राप्त विनिवेश का विवरण इस प्रकार है:

सारणी 1.1: विनिवेश में ईटीएफ का शेयर

वित्त वर्ष	ईटीएफ			कुल विनिवेश	कुल विनिवेश में ईटीएफ का हिस्सा (प्रतिशत)
	सीपीएसई ईटीएफ	भारत 22 ईटीएफ	कुल		
1	2	3	4	5	6
2013-14	3,000	0	3,000	29,368	10.2
2014-15	0	0	0	37,737	0.0
2015-16	0	0	0	42,132	0.0
2016-17	8,500	0	8,500	47,743	17.8
2017-18	0	14,500	14,500	1,00,045	14.5
2018-19	26,350	18,730	45,080	94,727	47.6
2019-20	26,500*	4,369*	30,869*	65,000	47.5

टिप्पणी : *2019-20 के आंकड़े 24 फरवरी 2020 तक के हैं। कॉलम (5) में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट के दस्तावेज से उठाए गए हैं।

स्रोत: निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

कुल विनिवेश संग्रह में ईटीएफ मार्ग से हुई आय क हिस्सा ज्यादा है, जो सारणी 1.1 से स्पष्ट होता है। भारत सरकार की विनिवेश नीति के अनुरूप (जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा उल्लिखित है) - अर्थात्, सीपीएसई के सरकारी स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए - ईटीएफ सरकार द्वारा विनिवेश के लिए पसंदीदा वाहन के रूप में उभरे हैं।

रणनीतिक विनिवेश, विनिवेश का एक वैकल्पिक तरीका है। इसका तात्पर्य है, प्रबंधन के नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सीपीएसई में 50 प्रतिशत तक की सरकारी शेयर-धारिता के बड़े हिस्से की बिक्री या उससे भी अधिक जैसा निर्धारित किया जाए। वर्ष 2013-14 की अवधि पर्यन्त में, सरकार ने 2016-17 में ₹10,779 करोड़, 2017-18 में ₹42,469 करोड़ और 2018-19 में ₹15,914 करोड़ इस मार्ग के माध्यम से जुटाए, जो कुल विनिवेश आय का क्रमशः 22.6 प्रतिशत, 42.5 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत होता है।

संदर्भ:

प्रशांता, ए. और राज, के.के. (2015), "इंडेक्स फंड्स की तुलना में ईटीएफ: मूल्यांकन" एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस मैनेजमेंट, वॉल्यूम 20(1).

IV. व्यय का स्वरूप और प्राथमिकताएं

कुल व्यय 2020-21 में 12.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो 2019-20 (आरई) में देखी गई वृद्धि दर की अपेक्षा कम है। यह उल्लेखनीय है कि निवेश और वृद्धि को बहाल करने के दृष्टिकोण से पूंजीगत व्यय 18.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो एफआरबीएम पश्चात की अवधि (2004-05 से 2018-19) के ऐतिहासिक औसत से अधिक है (सारणी 6)। इसके विपरीत, राजस्व व्यय वृद्धि मामूली होने का अनुमान किया गया है (2004-05 से 2018-19 के सापेक्ष), जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है क्योंकि पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय की तुलना में अधिक गुणक प्रभाव होता है (आरबीआई, 2019)⁴।

सब्सिडी और ब्याज भुगतान

सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर व्यय 2019-20 (आरई) में राजस्व व्यय के 37.8 प्रतिशत तक घटने तथा 2020-21 (बीई) में और घटकर 36.9 प्रतिशत तक पहुंचने का उल्लेख बजट में

⁴ भारतीय रिजर्व बैंक (2019), "भारत के लिए आकलन योग्य राजकोषीय गुणक", बॉक्स III.1, अध्याय III - मांग और आउटपुट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल।

सारणी 6: केंद्र सरकार के व्यय

मदें	₹ हजार करोड़			वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6
1. कुल व्यय	2,315	2,699	3,042	16.6	12.7
2. राजस्व व्यय (जिसमें से)	2,007	2,350	2,630	17.0	11.9
(i) ब्याज भुगतान	583	625	708	7.3	13.3
(ii) प्रमुख सब्सिडी खाद्य	197	227	228	15.5	0.2
उर्वरक	101	109	116	7.3	6.3
पेट्रोलियम	71	80	71	13.3	-10.9
(iii) मनरेगा	25	39	41	55.3	6.1
(iv) पीएम-किसान	62	71	62	14.9	-13.4
(v) रक्षा (राजस्व)	1	54	75	-	37.9
196	206	209	5.3	1.7	
3. पूंजीगत व्यय	308	349	412	13.4	18.1

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

किया गया है, जो पिछले बीस वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है। 2019-20 में, ब्याज भुगतान बीई में ₹6.60 लाख करोड़ से घटकर आरई में ₹6.25 लाख करोड़ रह गया, जो हो सकता है वर्ष के दौरान प्रचलित कम ब्याज दर के माहौल को दर्शाता हो।

सारणी 7: प्रमुख सरकारी योजनाओं पर व्यय

मदें	₹ हजार करोड़				कुल व्यय का प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ए. केंद्र क्षेत्र की योजनाएं								
1. पीएम-किसान	1	75	54	75	2.0	2.5	-	37.9
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन	0	1	0	1	0.0	0.0	-	-
3. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4	4	4	5	0.2	0.1	7.0	10.7
4. उज्ज्वला योजना	3	3	4	1	0.1	0.0	16.4	-70.0
5. सड़क कार्य	38	46	46	49	1.7	1.6	21.4	6.3
6. सागरमाला	0	1	0	0	0.0	0.0	5.8	-22.0
7. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	2	1	1	1	0.0	0.0	-25.9	-30.0
बी. केंद्र प्रायोजित योजनाएं								
1. मनरेगा	62	60	71	62	2.6	2.0	14.9	-13.4
2. आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई)	2	7	3	6	0.1	0.2	49.0	94.0
3. पीएम कृषि संघाई योजना	8	10	8	11	0.3	0.4	-3.0	40.9
4. पीएम ग्राम सड़क योजना	15	19	14	20	0.5	0.6	-8.7	38.6
5. पीएम आवास योजना	25	26	25	28	0.9	0.9	-0.4	8.6
6. स्वच्छ भारत मिशन	15	13	10	12	0.4	0.4	-37.3	27.6
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	32	34	34	34	1.3	1.1	8.9	-0.5
8. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	31	39	38	39	1.4	1.3	22.2	4.0

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

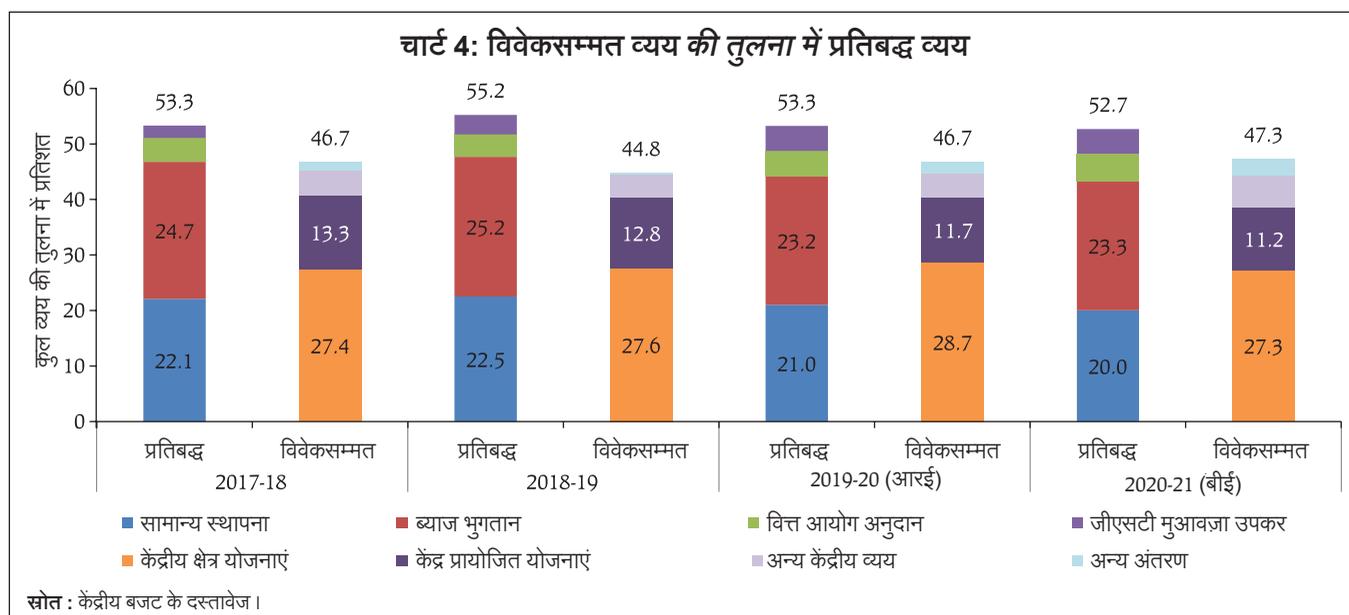
सब्सिडी पर हुआ खर्च 2019-20 (बीई) में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से घटकर 2019-20 (आरई) में जीडीपी का 1.3 प्रतिशत हो जाने तथा 2020-21 (बीई) में और घटकर 1.2 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है। हालांकि, इसे हासिल करने के लिए 2019-20 (आरई) के साथ-साथ 2020-21 (बीई) दोनों के मामले में मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी पर वर्तमान बजट व्यय को 0.9 प्रतिशत से घटाकर बजट में जीडीपी का 0.5 प्रतिशत किया गया। इस बड़ी कटौती के बावजूद, खाद्य सब्सिडी समग्र सब्सिडी बिल पर भारी है।

प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए आवंटन के संदर्भ में, बजटीय राशि 2020-21 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकिसान) के लिए समान है और 2019-20 (बीई) की तुलना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए थोड़ा अधिक है (सारणी 7)। मनरेगा और पीएमकिसान दोनों को इस तरह बनाया गया है कि वे ग्रामीण परिवारों की आय को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

विवेकसम्मत व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय

केंद्र सरकार के कुल व्यय को प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें वे खर्च आते हैं जिसे सरकार द्वारा अवश्य किया जाना होता है, जैसे, स्थापना व्यय (अर्थात्, वेतन, मजदूरी, पेंशन तथा कार्यालय खर्च), ब्याज भुगतान, वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान एवं राज्यों को जीएसटी मुआवजा और विवेकसम्मत व्यय, जिसमें सरकार कुछ विवेक के साथ काम कर सकता है, जैसे, केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं (जिसमें सभी सब्सिडी शामिल हैं), केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्यों को अंतरण (वित्त आयोग अनुदान एवं जीएसटी मुआवजा को छोड़कर) में वियोजित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कुल व्यय के आधे से ज्यादा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे काबू में करना मुश्किल होता है (चार्ट 4)। अतः, विवेकसम्मत व्यय पर ही सरकार का नियंत्रण है जिसका सहारा वह राजकोषीय समेकन⁵ के लिए ले पाता है।

⁵ गौरतलब है कि विवेकसम्मत व्यय के अंतर्गत शामिल किए गए मदों को संवैधानिक सहारा प्राप्त है, जैसे अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अतः, इसे वापस लेना मुश्किल है।



पूंजी व्यय

पूंजी व्यय में 2018-19 के दौरान 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी क्रम में पूंजी व्यय 2019-20 (आरई) में 13.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने तथा 2020-21 में 18.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का उल्लेख बजट में किया गया है। प्रमुख बुनियादी संरचनाओं के मामले में, पूंजी व्यय 22.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है, जो संचार क्षेत्र की वजह से है, जिसको लेकर 2020-21 में पांच गुना ज्यादा आवंटन किए जाने का उल्लेख

बजट में किया गया है (सारणी 8)। पूंजी व्यय पर इस कदर जोर दिया जाना राष्ट्रीय बुनियादी संरचना पाइपलाइन रिपोर्ट में रेखांकित दृष्टिपथ की तर्ज पर है, जिसमें नई बुनियादी संरचना के निर्माण तथा मौजूदा बुनियादी संरचना को अपग्रेड करने को लेकर ₹102 लाख करोड़ निवेश करने की परिकल्पना की गई है, जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में इजाफा करने एवं 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य साधने के लिए महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय बुनियादी

सारणी 8: पूंजी व्यय

	₹ हजार करोड़			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल पूंजी व्यय	308	349	412	16.9	13.4	18.1
2. रक्षा	95	110	114	5.3	15.9	3.0
3. पूंजी व्यय (रक्षा को छोड़कर)	212	239	298	23.0	12.3	25.1
(i) प्रमुख बुनियादी संरचना	138	147	179	27.7	6.1	22.4
सिंचाई	0.3	0.3	0.3	-3.4	0.0	24.0
ऊर्जा	9	5	6	92.1	-38.1	9.5
भारतीय रेल	53	68	70	21.7	28.4	3.2
सड़क और पुल	70	68	77	30.3	-2.2	13.3
नागरिक उड्डयन	4	0.03	0.03	116.5	-99.4	3.8
बंदरगाह और लाइट हाउस	0.2	0.2	0.1	3.5	36.5	-69.1
संचार	3	5	26	-43.0	83.1	450.3
(ii) उद्योग और खनीज	5	7	7	-4.1	40.6	5.0
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7	9	10	35.8	27.7	9.5
(iv) अन्य	62	76	101	15.0	21.9	34.2

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

संरचना पाइपलाइन के अंतर्गत आने वाली परियाजनाओं के लिए ₹22,050 करोड़ का विशेष प्रावधान भी किया गया है।

V. जीएफडी का वित्तपोषण

दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधार 2019-20 (आरई) में ₹7.1 लाख करोड़ होने की तुलना में 2020-21 में ₹7.8 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है। राजकोषीय घाटा बजटीय राजकोषीय घाटे की अपेक्षा अधिक होने के बावजूद, सकल और शुद्ध बाजार उधार को 2019-20 के लिए बरकरार रखा गया, क्योंकि राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के सहारे समग्र अतिरिक्त उधार आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। हाल के वर्षों में केंद्र के उधार कार्यक्रम में एनएसएसएफ का बढ़ता हिस्सा देखने को मिला है (बॉक्स II)। 2020-21 (बीई) के अनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए शुद्ध बाजार उधार जीएफडी के 68.4 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा जबकि एनएसएसएफ के जरिए वह जीएफडी के 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा की आपूर्ति करेगा (सारणी 9)।

केंद्रीय बजट 2020-21 में 2020-21 के लिए 2.7 लाख करोड़ (सकल राशि) (2019-20 (आरई) के दौरान ₹1.7 लाख करोड़) की प्रतिभूतियों को स्विट्च करने तथा ₹30,000 करोड़ की प्रतिभूतियों की पुनःखरीद का बजट किया गया है। इसमें

सारणी 9: जीएफडी की वित्तपोषण

(₹ हजार करोड़)

	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा	649 (100.0)	704 (100.0)	767 (100.0)	796 (100.0)
द्वारा वित्तपोषित				
शुद्ध बाजार उधार	423 (65.1)	473 (67.2)	473 (61.7)	545 (68.4)
शुद्ध खजाना बिल	7 (1.1)	25 (3.6)	25 (3.3)	25 (3.1)
एनएसएसएफ	125 (19.2)	130 (18.5)	240 (31.3)	240 (30.1)
बाह्य सहायता	6 (0.8)	-3 (-0.4)	5 (0.6)	5 (0.6)
राज्य भविष्य निधि	16 (2.5)	18 (2.6)	18 (2.3)	18 (2.3)
आरक्षित निधि	-18 (-2.8)	-1 (-0.1)	0 (0.0)	3 (0.4)
जमाएं और अग्रिम	66 (10.2)	14 (1.9)	33 (4.3)	36 (4.5)
नकदी शेष का आहरण	-1 (-0.2)	51 (7.3)	0 (0.0)	-53 (-6.7)
अन्य	27 (4.1)	-3 (-0.5)	-27 (-3.6)	-22 (-2.8)
ज्ञापन मद				
सकल बाजार उधार	571	710	710	780

टिप्पणी : शुद्ध बाजार उधार में केवल दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए लिए गए उधार शामिल हैं। शुद्ध खजाना बिलों में 91-दिन, 182-दिन, 364-दिन के जरिए लिए गए उधार एवं अन्य सभी खजाना बिल शामिल हैं। अन्य में प्रतिभूतियों की पुनःखरीद, प्रतिभूतियों की स्विट्चिंग, बचत बॉन्ड, राहत बॉन्ड इत्यादि शामिल हैं। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीएफडी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।
स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज ।

बॉक्स II: राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) की बढ़ती महत्ता

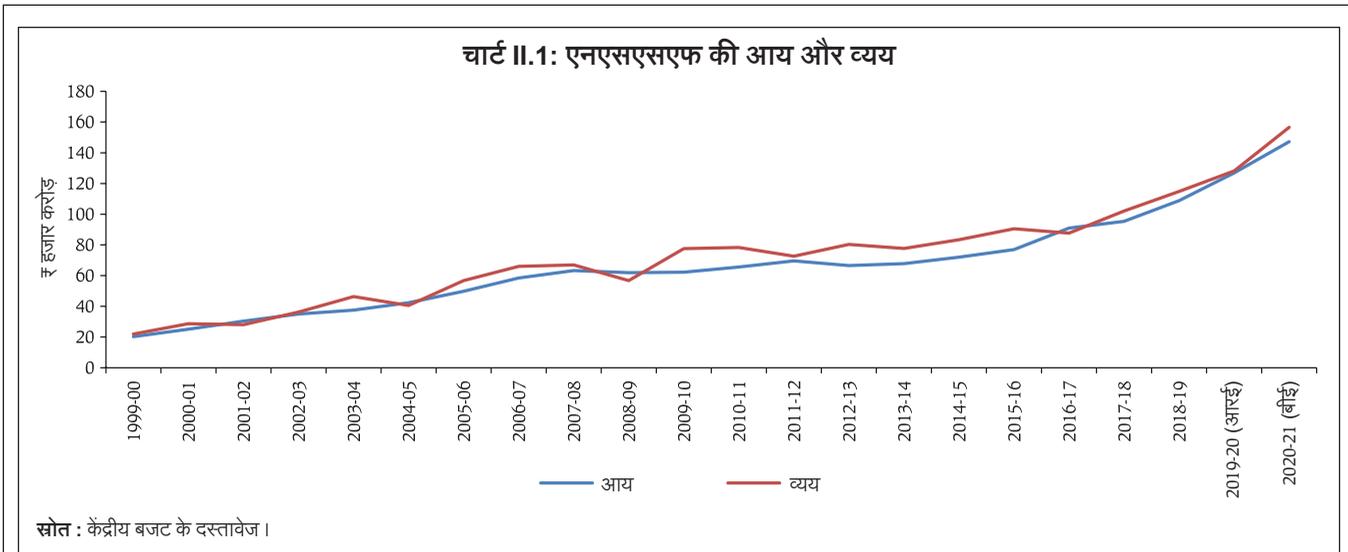
एनएसएसएफ भारत के सरकारी खाते में बनाया गया एक कोष है जिसमें वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई सभी लघु बचत योजनाओं की आय जमा होती है। एनएसएसएफ में प्राप्तिगत तीन स्रोतों, डाकघर बचत जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सरकारी भविष्य निधि से आती हैं। एनएसएसएफ में एकत्रित धनराशि का निवेश केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किया जाता है। चौदहवें वित्त आयोग (एफसी - XIV) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने एनएसएसएफ से उधार लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार, एनएसएसएफ के पास उपलब्ध अधिशेष निधि का उपयोग अन्य⁶ के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, एयर इंडिया, भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) के बीच ऋण देने के लिए किया जा रहा है।

इसलिए, एनएसएसएफ अनिवार्य रूप से एक वित्तीय मध्यस्थ है जो परिवारों के अधिशेष धन को सरकारी क्षेत्र में निवेश करता है। ऐसा करने पर, यह सरकार और पीएसयू को दिए गए ऋणों पर आय अर्जित करता है और जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करता है तथा प्रबंधन पर खर्च करता है, और इस प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर उसका परिचालन लाभ/हानि होता है। एनएसएसएफ की 1999-00 (जिस वर्ष में एनएसएसएफ को पहली बार भारत के सरकारी खाते से बाहर किया गया था) से 2018-19 तक (नवीनतम वर्ष जिसके लिए वास्तविक डेटा उपलब्ध है) की आय और व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि

(जारी)

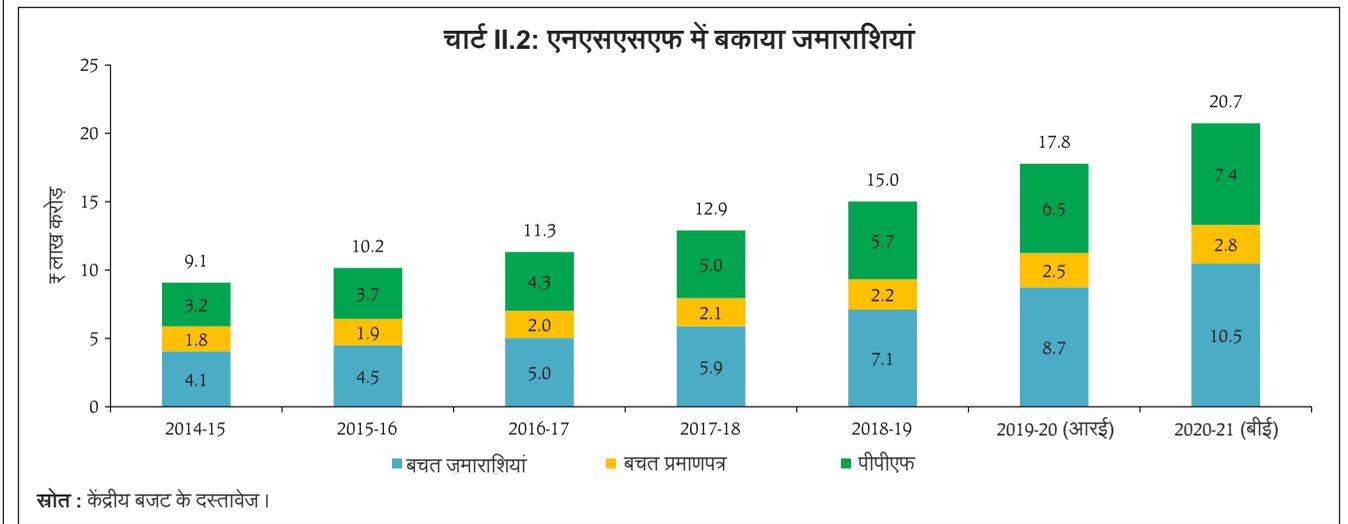
⁶ यह राष्ट्रीय लघु बचत कोष की व्यापक समीक्षा संबंधी समिति (अध्यक्ष: श्रीमती एस. गोपीनाथ) की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि एनएसएसएफ सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अवसंरचना कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है जो सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हैं।



इस बीस वर्ष की अवधि के दौरान एनएसएसएफ को केवल चार वर्षों में अधिशेष हुआ है और मार्च 2019 की समाप्ति पर उसे ₹1.13 लाख करोड़ की संचित हानी हुई, जो मार्च 2021 की समाप्ति तक बढ़कर ₹1.24 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट II.1)।

गौरतलब है कि एनएसएसएफ निर्धारित ब्याज दरों पर पैसे उधार लेता है और देता है। जहां उधार दरों को वार्षिक रूप से तय किया जाता है, वहीं जमा दरों को त्रैमासिक रूप से परखा जाता है और उसे कतिपय लघु बचत योजनाओं में थोड़े अंतर के साथ समान

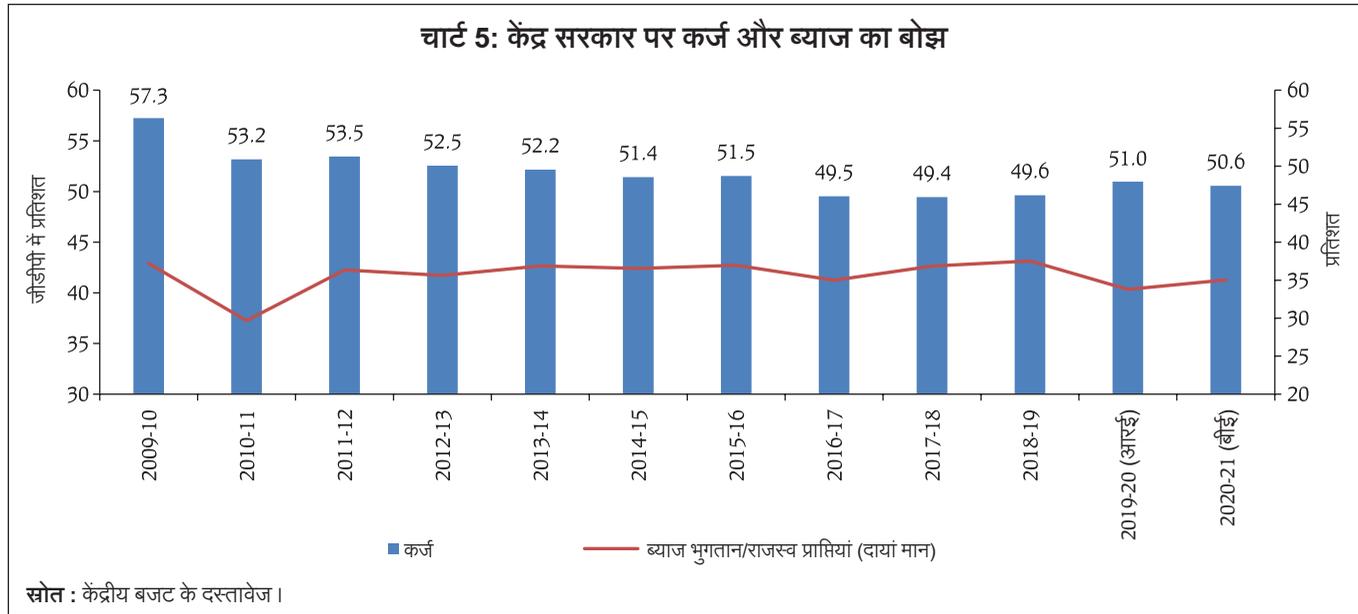
परिपक्वताओं वाली जी-सेक दरों के समरूप किया जाता है⁷। 2018-19 में एनएसएसएफ की कुल जमाराशियों में ब्याज व्यय का अनुपात 6.9 था, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए तुलनात्मक आंकड़ा 4.8 था। यह इस लघु बचत योजनाओं और बैंक जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर के बीच के अंतर के कारण ही है कि एनएसएसएफ के कुल कोष में 2014-15 से अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है और 2014-15 में ₹9.1 लाख करोड़ से दुगुना बढ़कर 2020-21 में ₹20.7 लाख करोड़ होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट II.2, अनुबंध II)।



⁷ सरकार ने 31 मार्च 2020 को 2020-21 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की घोषणा की है (<https://dea.gov.in/sites/default/files/RoI%20Q1%202020-21%20%281%29.pdf>).

₹25,000 करोड़ के शुद्ध अल्पावधि उधार और ₹2.5 लाख करोड़ के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी) के निर्गम की भी व्यवस्था की गई है। बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत

कोई आवंटन नहीं है। सरकार ने 2020-21 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) के जरिए ₹10,500 करोड़ की सकल राशि जुटाने की भी योजना बनाई है।



VI. बकाया देयताएं

केंद्र सरकार की कुल बकाया देयताएं (अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से उठाए गए उधार सहित) 2019-20 (आरई) में तेजी से बढ़कर 51.0 प्रतिशत होने तथा 2020-21 बीई में मामूली रूप से घटकर 50.6 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है (चार्ट 5)। सरकार का अनुमान है कि बकाया देयताएं 2022-23 तक कम होकर 45.5 प्रतिशत रह जाएगी⁸। गौरतलब है कि संशोधित एफआरबीएम फ्रेमवर्क के अनुसार लक्ष्य यह है कि केंद्र सरकार की बकाया देयताओं को 2024-25 तक कम करते हुए जीडीपी का 40 प्रतिशत करना है।

VII. केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधन

2019-20 (आरई) में केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधनों में गिरावट आई जो कर अंतरण में भारी कमी आने की वजह से थी

और इसकी आंशिक रूप से भरपाई के लिए अन्य अंतरणों में इजाफा किया गया। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वर्ष के दौरान सकल अंतरण में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष में कर अंतरण में गिरावट के लिए केंद्र के कर संग्रह के कम होने के साथ-साथ दूसरा मुख्य कारण संशोधित अनुमान, जिसे 2019-20 (आरई) में लगभग 30 आधार अंक तक समायोजित किया गया था, की तुलना में पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 में केंद्र के वास्तविक कर संग्रह का कम होना है। वर्ष 2020-21 में, सकल अंतरण जीडीपी का 6.2 प्रतिशत होने का उल्लेख बजट में किया गया है, जो दर्शाता है कि 2019-20 (आरई) में 5.8 प्रतिशत से काफी वृद्धि हुई है। कर अंतरण पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट (बॉक्स III) में सुझाए गए फार्मुले के अनुसार है और केंद्र से राज्यों को अंतरित संसाधनों का मुख्य आधार बना हुआ है।

बॉक्स III: पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट : एक झलक

भारत में केंद्र-राज्य राजकोषीय असंतुलन को केंद्र से राज्यों में संघीय अंतरण की एक प्रणाली के माध्यम से दुरुस्त करने की अपेक्षा की जाती है, जो मुख्य रूप से कर अंतरण और 2015-16 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण के रूप में है। वित्त आयोग (एफसी), जो अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, को कर अंतरण का अनुपात निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इस प्रकार केंद्र-राज्य के राजकोषीय संबंधों में अहम भूमिका निभाता है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर अंतरण ने इस अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, जिसका श्रेय चौदहवें वित्त आयोग (एफसी-XIV) को जाता है, भले ही सकल संसाधन अंतरण मोटे तौर पर स्थिर रहे (चार्ट III.1ए)। इस स्थिरता को हासिल करने के लिए कर अंतरण की वृद्धि पर लगाम लगाया गया जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 271 के अनुसार शेयर किए जाने योग्य कर समूह (विभाज्य समूह) की परिधि से बाहर के कर संग्रह में उपकरणों और अधिभारों पर केंद्र की निर्भरता को बढ़ाया गया (चार्ट III.1 बी)। साथ-साथ,

(जारी)

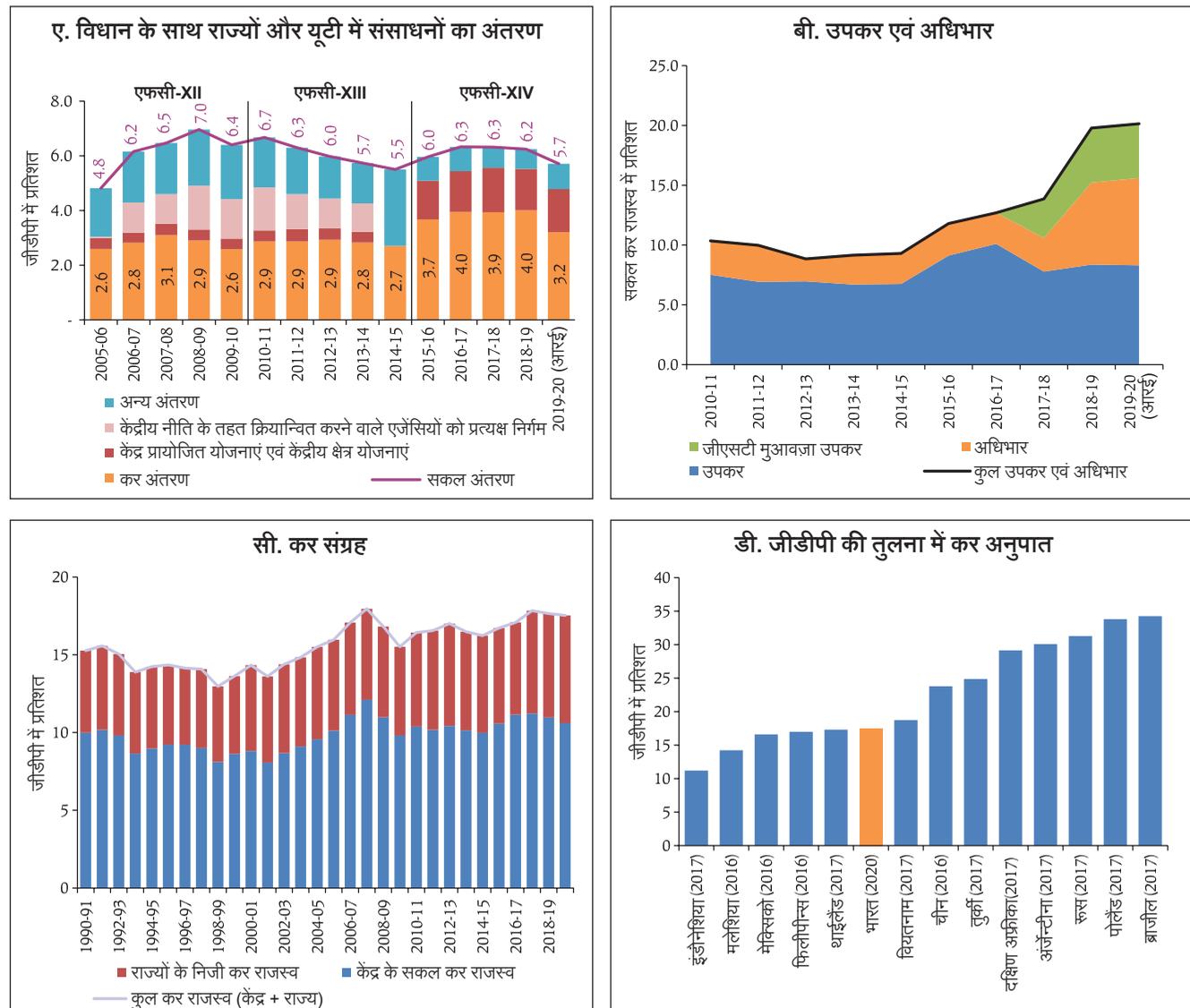
⁸ मध्यमावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण, केंद्रीय बजट 2020-21.

2001-02 से 2007-08 के बीच मजबूत वृद्धि दर्ज करने के बाद, केंद्र और राज्यों, दोनों के मामले में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर संग्रह में 2007-08 से एक ठहराव सा आ गया है (चार्ट III.1सी)। एक अन्य वास्तविकता यह है कि भारत में संघीय राजकोषीय हुकूमत को अपने समकक्ष देशों की तुलना में जीडीपी में कर की तीव्रता में कमी का सामना करना पड़ता है (चार्ट III.1डी)।

इस हालत में, पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) की अंतरिम रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को संसद के बजट सत्र में पेश की गई थी। इसकी

सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और 2020-21 के केंद्रीय बजट प्रावधानों में उल्लेख किया गया है। कर अंतरण अनुपात 2020-21 के लिए विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत होने की सिफारिश की गई है, जो एफसी-XIV के समय के अर्थात् 2015-20 के 42 प्रतिशत की तुलना में 1 प्रतिशत कम है। राज्यों की हिस्सेदारी में कमी मुख्य रूप से उस हिस्से को समाप्त करने के कारण है जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर (विभाज्य पूल का 0.8 प्रतिशत) को आवंटित किया जाता था।

चार्ट III.1: संघीय अंतरणों की गतिशीलता : तथ्यात्मक साक्ष्य



चार्ट की टिप्पणियां :

ए. वर्ष 2014-15 के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में अंतरित संसाधनों को राज्य व यूटी नीतियों की केंद्रीय सहायता में शामिल किया गया है। सी. 2019-20 में केंद्र का सकल कर राजस्व संशोधित अनुमान है। 2018-19 और 2019-20 में राज्यों के निजी कर राजस्व क्रमशः संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान हैं। स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज (विभिन्न अंक), आरबीआई की राज्य वित्त रिपोर्ट (विभिन्न अंक), संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, सरकारी राजस्व डेटासेट, 2019.

(जारी)

कर अंतरण के अलावा, एफसी ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अनुदान के रूप में राज्यों को विशिष्ट अंतरण की सिफारिश भी की है। एक के बाद एक बदलते एफसी के साथ इन अनुदानों के उद्देश्य में काफी भिन्नता आई है, हालांकि 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद से स्थानीय निकायों के लिए संघीय अंतरण को अनिवार्य करने के बाद स्थानीय निकायों में अंतरण का हिस्सा काफी बढ़ गया है। 2020-21 के लिए भी, स्थानीय निकायों को किए गए अंतरण में एफसी अनुदान का एक बड़ा हिस्सा है; आयोग ने राजस्व घाटे को कम करने के लिए अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि की भी सिफारिश की है (सारणी III.1)।

एफसी को राज्यों के बीच करों के आपसी वितरण के लिए मानदंड और सूत्र के निर्धारण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य है कि राज्यों के आय स्तरों में असमानता के कारण उनकी राजस्व जुटाने की भिन्न-भिन्न क्षमताओं का समाधान करते हुए सभी नागरिकों को न्यूनतम स्तर की सरकारी सेवाएं मिल सकें। एफसी-XV ने अलग-अलग राज्यों के मानदंडों और अंतरण हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो मुख्य रूप से 1971 से 2011 तक के जनसंख्या गणना वर्ष में हुए बदलाव के कारण हैं। जनसंख्या की गणना में परिवर्तन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टीओआर) द्वारा नियंत्रित होता है। हालांकि एफसी-XV जनसांख्यिकीय प्रदर्शन⁹ के लिए मानदंड शुरू करते हुए संदर्भ

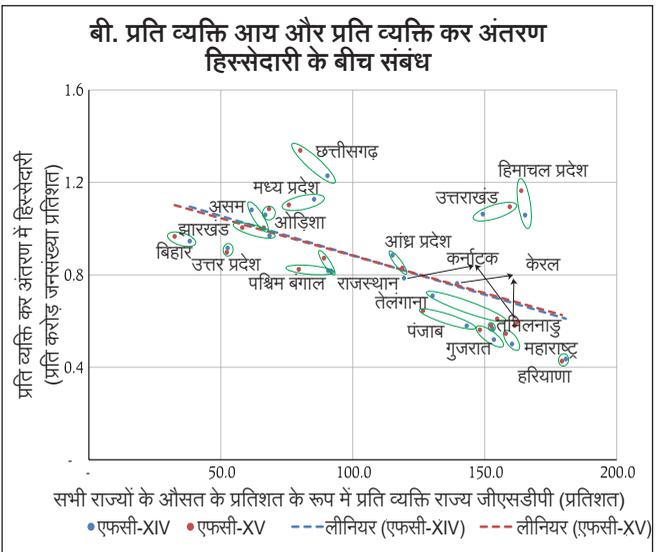
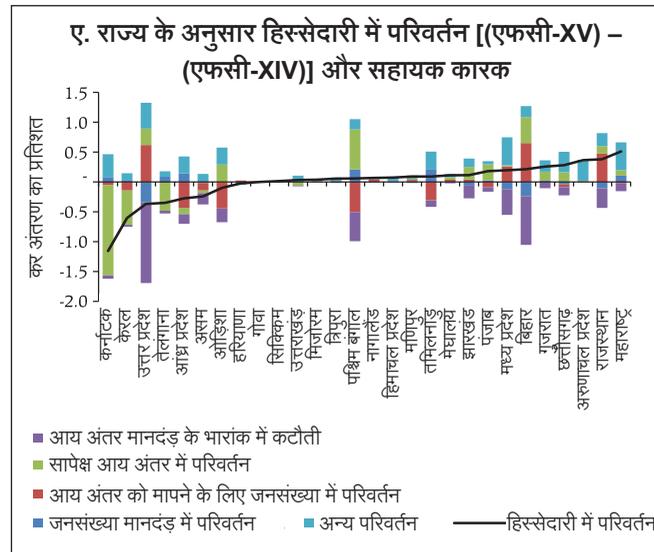
सारणी III.1: वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़)

अनुदान का नाम	केंद्रीय बजट 2020-21			एफसी-XV सिफारिश
	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2020-21
स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – ग्रामीण	35.064	58.616	69.925	60.750
स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – शहरी	14.400	25.843	30.000	29.250
राज्य आपदा राहत कोष के लिए अनुदान सहायता	9.658	10.938	20.000	22.184
अनुदान आपूर्ति के कारण अंतरण पश्चात राजस्व घाटा	34.582	28.314	30.000	74.340
विशेष अनुदान				6.764
पोषण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान				7.735
कुल वित्त आयोग अनुदान	93.704	1,23,710	1,49,925	2,01,023

जनगणना में हुए बदलाव के कारण कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के शेर में होने वाले नुकसान को संतुलित करने की कोशिश करता है, वहीं जनसंख्या को मानदंड के रूप में परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है ताकि किसी राज्य के आय अंतर को मापा जा सके और इस प्रकार उन राज्यों को नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने जनसंख्या में कम वृद्धि दर हासिल की है (चार्ट III.2ए)। आपसी वितरण को लेकर मानदंड में अन्य बदलावों में वन कवर के भारांक में वृद्धि (2.5

चार्ट III.2: अंतरित करों का आपसी वितरण



टिप्पणियाँ : 1. चार्ट ए में, जनसंख्या मानदंड में परिवर्तन संदर्भ जनगणना वर्ष में बदलाव से पड़ने वाले एवं जनसांख्यिकीय परिवर्तन मानदंड को जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मानदंड के साथ बदलने से पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। अन्य बदलावों में वन कवर के भारांक में वृद्धि से पड़ने वाले तथा कर प्रयास मानदंडों को शुरू करने से पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं।
2. चार्ट बी में, एक्स-एक्सिस के लिए, अलग-अलग राज्यों व सभी राज्यों के औसत का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी संबंधित वित्त आयोग द्वारा अपने-अपने आय अंतर मानदंडों के लिए उपयोग किए गए संदर्भ वर्षों के लिए हैं। यह विश्लेषण भारत में लंबे अरसे से क्षेत्रीय आय असमानता एवं समानता के विषय में प्रचलित अध्ययन पर आधारित है (कृष्णा, 2004; कुमार, 2005; मिश्रा और मिश्रा, 2015; बंधोपाध्याय, 2016)।

स्रोत : एफसी-XIV रिपोर्ट, एफसी-XV अंतरिम रिपोर्ट, लेखकों की गणनाएं।

(जारी)

⁹ 2011 की जनगणना एवं 1971 में राज्य की जनसंख्या के अनुसार कुल प्रजनन दर के व्युत्क्रम के उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रतिशत की दर से), कर प्रयास के लिए एक नए मानदंड की शुरुआत (2.5 प्रतिशत भार) और आय अंतर मानदंड के भारांक में 5 प्रतिशत की कटौती शामिल है। कुल मिलाकर, एफसी-XV द्वारा कर अंतरण में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी को लेकर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश एफसी-XIV द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप ही प्रगति के समान स्तर पर है (चार्ट III.2बी और अनुबंध III)।

एफसी-XV की पूरी रिपोर्ट, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए कर अंतरण और अनुदानों की सिफारिशें शामिल होंगी, 30 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत की जानी है। इसकी पूरी रिपोर्ट में, एफसी-XV स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण संपर्क, रेलवे, सांख्यिकी और पुलिस प्रशिक्षण और आवास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश करने की भी परिकल्पना करता है। इसके अलावा, आयोग छह क्षेत्रों, जैसे, कृषि सुधार; एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (एडीपी) के प्रदर्शन; बिजली क्षेत्र में सुधार; व्यापार

(निर्यात); शिक्षा; और पर्यटन को बढ़ावा देने, में राज्यों को उनके काम के प्रदर्शन के आधार पर अनुदानों की सिफारिश करने की व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन कर रहा है।

संदर्भ :

Bandopadhyay, S. (2016), "The persistence of inequality across Indian states", *CSAE Working Paper WPS/2016-26*.

Krishna, K.L. (2004), "Patterns and Determinants of Economic Growth in Indian States". *Working Paper No 144*, Indian Council of Research on International Economic Relations.

Kumar, T.R. (2005), "Tax Devolution and Regional Disparities", *Economic and Political Weekly*, Vol. 40(20).

Mishra, A. and Mishra, V. (2015), "Examining Income Convergence among Indian States: Time Series Evidence with Structural Breaks", *Discussion Paper 44/15*, Monash Business School, Department of Economics.

2019-20 (आरई) और 2020-21 (बीई) में वित्त आयोग के अनुदान में हुई वृद्धि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान में ज्यादा इजाफा करने की बंदौलत है। 2019-20 (आरई)

और 2020-21 (बीई) में केंद्र शासित प्रदेशों के अंतरण इसलिए बढ़े हैं क्योंकि भूतपूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को किए गए अंतरण को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है (सारणी 10)।

सारणी 10: केंद्र से राज्यों को सकल और शुद्ध अंतरण

	₹ हजार करोड़				जीडीपी का प्रतिशत			
	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्यों का कर अंतरण हिस्सा	673.0	761.5	656.0	784.2	3.9	4.0	3.2	3.5
ए. वर्ष के दौरान उपचित के रूप में राज्यों को कर अंतरण*	697.6	678.0	714.9	784.2	4.1	3.6	3.5	3.5
बी. गत वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0.0	24.6	-58.8	0.0	0.0	0.1	-0.3	0.0
2. वित्त आयोग अनुदान	92.2	93.7	123.7	149.9	0.5	0.5	0.6	0.7
ए. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	34.4	35.1	58.6	69.9	0.2	0.2	0.3	0.3
बी. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	12.6	14.4	25.8	30.0	0.1	0.1	0.1	0.1
सी. एसडीआरएफ के लिए अनुदान सहायता	9.4	9.7	10.9	20.0	0.1	0.1	0.1	0.1
डी. अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान	35.8	34.6	28.3	30.0	0.2	0.2	0.1	0.1
3. योजना संबंधी अंतरण	278.8	286.0	322.4	335.9	1.6	1.5	1.6	1.5
ए. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत	262.0	271.5	283.1	295.3	1.5	1.4	1.4	1.3
बी. केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत	16.0	13.6	38.2	39.5	0.1	0.1	0.2	0.2
सी. अन्य अंतरण	0.8	0.9	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
4. अंतरण के कुछ महत्वपूर्ण मदें	37.2	46.2	57.3	73.3	0.2	0.2	0.3	0.3
ए. विशेष सहायता	7.0	4.7	4.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.1
बी. एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	4.7	10.0	20.0	25.0	0.0	0.1	0.1	0.1
सी. बाह्य सहायता से परियोजना-ऋण	17.5	23.8	25.0	25.0	0.1	0.1	0.1	0.1
डी. अन्य अंतरण	8.1	7.8	8.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5. दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर को अंतरण (अक्टूबर 2019 से)	3.8	8.0	28.4	47.4	0.0	0.0	0.1	0.2
6. राज्यों और यूटी को सकल अंतरण (1 से 5)	1,085.1	1,195.4	1,188.0	1,390.7	6.3	6.3	5.8	6.2
7. ऋण और अग्रिमों की वसूली	13.1	14.4	14.2	12.5	0.1	0.1	0.1	0.1
8. राज्यों और यूटी को अंतरित शुद्ध संसाधन (6-7)	1,072.0	1,181.0	1,173.8	1,378.2	6.3	6.2	5.7	6.1

टिप्पणी :* वर्ष के दौरान उपचित के रूप में राज्यों को कर अंतरण = राज्यों को कर अंतरण - वास्तविक के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन (गत वर्ष में उपचित) + वास्तविक के अनुसार पिछले वर्ष के राज्यों के हिस्से का समायोजन उदाहरण के लिए, 2018-19 में उपचित कर = 761.5 - 24.6 + (-58.8).

कॉलम में दिए गए आंकड़ों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल में नहीं जोड़ा जा सका।

स्रोत : केंद्रीय बजट के दस्तावेज।

VIII. निष्कर्ष

यूनियन बजट 2020-21 का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि उपायों के संयोजन से सक्रिय करना है। प्रत्यक्ष कर सुधार, विशेष रूप से आयकर में छूट से मध्यम आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समाप्त करने से उद्योगों की काफी अरसे से चली आ रही मांग पूरी हो गयी तथा भारत निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बनने में इससे सहायता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर, राजकोषीय विवेक से शासित बजट, वृद्धि को बढ़ावा देने वाला और कल्याण बढ़ाने वाला है। अर्थव्यवस्था में विकास की धीमी गति के वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने

के लिए बजट में पूंजी व्यय में भी कटौती नहीं की है, जो वांछनीय है। एफआरबीएम लक्ष्यों के संबंध में, तीन क्रमिक वर्षों के लिए ऐस्क्रेप क्लॉज का उपयोग किया गया है - 2018-19 और 2019-20 में जीएसटी को यथाशीघ्र नियमित करने के लिए और 2019-20 और 2020-21 में न्यूनतम कॉरपोरेट करों के राजस्व के परिणाम जो भारत को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं और मध्यावधि में निवेश और विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगामी वर्ष के दौरान, विशेष रूप से COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास और उभरती स्थिति देश के राजकोषीय कार्यनिष्पादन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय

आरबीआई के संबंध में बजट 2020-21 में किए गए उपाय:

- निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को निक्षेप बीमा कवरेज 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता करने की अनुमति दी गई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन सुधार शुरू करने का प्रस्ताव ताकि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पारदर्शिता लाने के लिए उपाय करने के अलावा सहकारी बैंकों को मजबूत करने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम में उचित संशोधनों के माध्यम से व्यावसायिकता बढ़ाने, पूंजी तक पहुंच बनाने और आरबीआई द्वारा निगरानी में सुधार करने का प्रस्ताव।
- सरफेसी अधिनियम के अनुसार ऋण वसूली के लिए पात्र होने के लिए एनबीएफसी की सीमा को ₹500 करोड़ से घटाकर ₹100 करोड़ रुपये या मौजूदा ऋण राशि ₹1 करोड़ से ₹50 लाख रुपये तक कम करने का प्रस्ताव है।
- सरकार ने आरबीआई से एमएसएमई ऋण के पुनर्गठन की व्यवस्था (जो 31 मार्च, 2020 को बंद होना अपेक्षित है) को आगे बढ़ाने पर विचार करने के लिए सूचित किया है।
- एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना (जिसकी घोषणा पहले की गई थी) को मजबूत करने के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। एतद्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों की सरकार गारंटी देगी।

वित्तीय बाजार:

- सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां पूरी तरह से अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एफपीआई सीमा, वर्तमान में बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।

भाग I

विषय ए: महत्वाकांक्षी भारत, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर रोजगार के साथ जीवन के बेहतर मानक की अपेक्षा की गई है।

1. कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

- पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के अंतर्गत 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सोलर पंप दिया जाएगा और उनके ग्रिड से जुड़े पंपों को सौरीकृत करने के लिए 15 लाख अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीपीपी तरिके से एक कारगर मालगोदाम के निर्माण के संबंध में व्यवहार्यता गैप वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव, जो मालगोदाम विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मानदंडों का अनुपालन करता है।
- एसएचजी द्वारा संचालित ग्राम भंडारण योजना शुरू की जाएगी जिससे किसानों को अच्छी होल्डिंग क्षमता मिलेगी और उनकी लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। महिला, स्वयं सहायता समूह "धान्य लक्ष्मी" के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करेंगे।
- ई-एनडब्ल्यूआर (निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद) का ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के साथ एकीकरण।
- खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं के लिए भारतीय रेल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्रमशः "किसान रेल" और "कृषि उड़ान" राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला शुरू की जाएगी। एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे।
- बागवानी क्षेत्र में, बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, उन राज्यों को समर्थन देने का प्रस्ताव है जो क्लस्टर आधार को अपनाते हुए "एक उत्पाद एक जिले" पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणालियों का विस्तार प्रस्तावित है और जैविक उत्पादों पर राष्ट्रीय पोर्टल को बड़ावा दिया जाएगा।
- 2020-21 के लिए ₹15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शैवाल और समुद्री खरपतवार और केज कल्चर के बढ़ने के अलावा 2022-23 तक मछली उत्पादन का 200 लाख टन का लक्ष्य है।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- 'सागर मित्र' के माध्यम से मत्स्य पालन में युवाओं को शामिल करने और 500 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निर्माण के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव।

2. कल्याण, जल और स्वच्छता:

- पीपीपी तरिके से अस्पतालों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता गैप वित्तपोषण प्रदान करने का प्रस्ताव, महत्वाकांक्षी जिलों से शुरू होता है, जिनके पास पीएमजेवाई (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत कोई पैनल अस्पताल नहीं है।
- 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का विस्तार।
- ओडीएफ आचरण को बनाए रखने और जनसंख्या के सभी वर्गों में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्धता।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ लिक्विड और ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रीत करना।
- जल जीवन मिशन (पानी के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों को बढ़ाना) के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने वाले दस लाख से अधिक शहरों पर जोर दिया गया है।

3. शिक्षा और कौशल

- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी।
- बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और एफडीआई जुटाने में सक्षम बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे ताकि मुर्त और मानव पूंजी में वृद्धि के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके।
- युवाओं की रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए मार्च 2021 तक करीब 150 उच्च शिक्षण संस्थान अप्रेंटिसशिप-निहित कोर्स शुरू कर देंगे।
- यूएलबी द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटरशिप के अवसर।

- नैशनल इंस्टिट्यूशनल रेकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के पहले 100 रैंकों के संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर के पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत।
- भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में इंड-सैट का आयोजन किया जाएगा। इसका उपयोग भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को बेंचमार्क करने के लिए किया जाएगा।
- पीपीपी तरिके से मौजूदा जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अटैच करने का प्रस्ताव है।
- स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालयों द्वारा वैश्विक मानकों के समतुल्य पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष ब्रीज पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे, ताकि भारतीय शिक्षकों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों को विदेशों में रोजगार हासिल करने में सुविधा मिल सके।

विषय बी: आर्थिक विकास

1. उद्योग, वाणिज्य और निवेश

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 2020-21 से 2023-24 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- उच्चनिर्यात ऋणवितरण के लिए एनआईआरविआईके योजना शुरू की जाएगी जिसमें उच्च बीमा कवरेज, छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कटौती और दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया का प्रावधान है।
- एक निवेश क्लियरेंस सेल की स्थापना करना, एक पोर्टल के माध्यम से काम करना, पूर्व-निवेश सलाहकार, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा सहित अंत तक सुविधा और सहायता प्रदान करना।
- पीपीपी तरिके से आधार पर राज्यों के सहयोग से 5 नए स्मार्ट शहरों का विकास।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- एमएसएमई के अवसरों को अधिकतम करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर टर्नओवर को ₹3 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर जोर दिया गया।

2. बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए योजना तैयार करने की सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट बनाने और रोजगार, कौशल का सृजन और एमएसएमई को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति शुरू की जाएगी।
- सड़कें: राजमार्गों का त्वरित विकास किया जाएगा, जिसमें पहुंच नियंत्रण राजमार्गों का स्केलिंग करना, आर्थिक मार्ग, कार्यनीतिक राजमार्गों को बढ़ाना शामिल है।
- रेल: चार स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी मोड के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन। रेल पटरियों के साथ रेलवे भूमि में बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण। 148 किलोमीटर लंबी बंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना केंद्र सरकार की 20 प्रतिशत इक्विटी के साथ शुरू की जाएगी।
- बंदरगाह: सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कॉर्पोराइज करने और बाद में स्टॉक एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग पर विचार करेगी।
- वायु: उड़ान (उडे देश का आम नागरिक/क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) के अंतर्गत 100 और हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

- पावर: प्रीपेड स्मार्ट मीटर द्वारा पारंपरिक ऊर्जा मीटर को बदलने के प्रयास।
- गैस ग्रिड: 16,200 किमी से 27,000 किमी तक राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार

3. नई अर्थव्यवस्था

- देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाने में निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए एक नीति जल्द ही शुरू की जा सकती है, ताकि मूल्य श्रृंखला के हर कदम में डेटा का सामंजस्य हो सके।
- भारतनेट के माध्यम से फाइबर टू दि होम (एफटीटीएच) कनेक्शन इस वर्ष 1,00,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ देगा।
- ₹8,000 करोड़ रुपये के व्यय के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव किया गया है।
- नए और उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद समूह स्थापित किए जाएंगे।
- आरंभिक जीवन निधि पर विशेष जोर, आरंभिक अवस्था के विकास के लिए बीज कोष सहित, प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप के विकास पर विशेष जोर।

विषय सी: समाज की परवाह

1. महिला एवं बाल, समाज कल्याण

- सीवर प्रणालियों या सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई को समाप्त करने के लिए पहचानी गई उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श और वित्तीय सहायता।
- मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने और पोषण के स्तर में सुधार के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त किया जाना है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन के लाभ के लिए क्रमशः ₹85,000 करोड़ रुपये, ₹53,700 करोड़ रुपये और ₹9,500 करोड़ रुपये का आबंटन।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

2. संस्कृति और पर्यटन

- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा होगा।
- 5 पुरातत्व स्थलों को ऑन-साइट संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी।
- पर्यटकों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा संग्रहालयों (जैसे कोलकाता का भारतीय संग्रहालय) को फिर से चालू करने और नए संग्रहालयों (जैसे लोथल में समुद्री संग्रहालय) की स्थापना करने की घोषणा की गई।

3. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हवा के लिए योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित योजना।
- पुराने और उच्च कार्बन उत्सर्जक बिजली संयंत्रों के लिए, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उन्हें चलाने वाली उपयोगिताओं को बंद करने की सलाह दी जाएगी, यदि उनका उत्सर्जन पूर्व-निर्धारित मानदंडों से ऊपर है। इस प्रकार खाली की गई जमीन का दूसरा उपयोग किया जा सकता है।

गवर्नेंस और वित्तीय क्षेत्र ऐसे दो स्तंभ हैं जो ऊपरयुक्त तीनों विषयों की देखरेख करेंगे।

गवर्नेंस

- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारे नागरिक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त हों करदाता चार्टर को कानून में शामिल करने का प्रस्ताव है।
- कंपनी अधिनियम के मामले में, कतिपय संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जो सिविल स्वरूप के अधिनियमों के लिए आपराधिक दायित्व में सुधार करेगा।
- अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिले में,

विशेषकर वांछित जिलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा।

- आधिकारिक सांख्यिकी पर प्रस्तावित नई राष्ट्रीय नीति भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए एआई सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।
- वर्ष 2022 में जी 20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी की तैयारी शुरू करने के लिए ₹100 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।
- चयनित क्षेत्रों की फर्मों को सिडबी और एक्विजम बैंक द्वारा ₹100 करोड़ रुपये की योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान और विकास, व्यापार कार्यनीति के लिए प्रारंभिक सहयोग किया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वांगीण विकास को समर्थन देने के लिए क्रमशः ₹30,757 करोड़ रुपये और ₹5,958 करोड़ रुपये की रकम।

वित्तीय क्षेत्र

- स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से निजी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों को आईडीबीआई बैंक में सरकार की बैलेंस होल्डिंग बेचने का प्रस्ताव।
- पीएफआरडीआई से सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने का प्रस्ताव।
- एमएसएमई उद्यमियों के लिए गौण ऋण प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जो अर्ध-इक्विटी के रूप में गिना जाता है और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) द्वारा गारंटीकृत किया जाता है।
- सरकारी प्रतिभूतियों तक खुदरा पहुंच की अनुमति देने के लिए मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के साथ नए डेट-ईटीएफ को लॉन्च करने का प्रस्ताव।
- फैक्टर रेगुलेशन एक्ट 2011 में प्रस्तावित संशोधन ताकि एनबीएफसी ट्रेड रेसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीरईडीएस) के माध्यम से एमएसएमई को चालान वित्तपोषण का विस्तार कर सके।

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (जारी)

- विनियामक की स्वीकृति के साथ, GIFT सिटी, GIFT-IFSC में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करेगा, जो वैश्विक बाजार सहभागियों को व्यापार के लिए एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में होगा।
- सरकार ने एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव किया है।

भाग II: कर प्रस्ताव**ए. प्रत्यक्ष कर**

- सरलिकृत और नयी आयकर व्यवस्था। करदाताओं के लिए नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है तथा इससे महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
- डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को समाप्त कर दिया गया है और इसके अंतर्गत लाभांश कराधान की पारंपरिक प्रणाली अपनायी गयी है, जिससे कंपनियों को डीडीटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभांश केवल प्राप्तकर्ताओं से लागू दर पर लिया जाएगा।
- बिजली उत्पादन में लगी नई घरेलू कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर की सुविधा दी गई है।
- उपरोक्त क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशी सरकारों और अन्य विदेशी निवेशों के सरकारी धन कोष द्वारा बुनियादी ढांचे और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में निवेश के संबंध में ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ आय पर 100 प्रतिशत की कर रियायत।
- उनके लाभ में वृद्धि के 100 प्रतिशत (₹25 करोड़ से ₹100 करोड़ तक टर्नओवर की सीमा में वृद्धि) के माध्यम से स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ, कटौती के दावे के लिए पात्रता की अवधि 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर विचार हो रहा है- वृद्धि के इंजन के रूप में। इसके अलावा, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) पर कर, स्टार्ट-अप कर्मचारियों

को पांच साल या जब तक वे कंपनी छोड़ देते हैं या जब वे अपने शेयर बेचते हैं, जो भी पहले होता है, तब तक दिया जाएगा।

- सहकारिता के लिए रियायती कर दर - सहकारी समितियों से 22 प्रतिशत के उपर 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर लगाया जाएगा जिसमें मौजूदा 30 प्रतिशत दर के साथ-साथ उपकर और अधिभार में कोई छूट/कटौती नहीं की जाएगी। सहकारी समितियों को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से भी छूट दी गई है।
- किफायती आवास को और प्रोत्साहित करने के लिए, कर लाभों से संबंधित समय सीमा का विस्तार (किफायती घर की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर प्रदत्त ब्याज के लिए ₹1,50,000 तक की अतिरिक्त कटौती) किफायती आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए ' सभी के लिए आवास '

बी. अप्रत्यक्ष कर

- उन वस्तुओं के आयात को सीमित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो हमारे एमएसएमई द्वारा बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादित किए जा रहे हैं। तदनुसार जूते-चप्पल और फर्नीचर जैसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। मेक इन इंडिया पहल के तहत सावधानीपूर्वक कल्पित चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइलों के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

सी. कर प्रबंधन

- छोटे खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एमएसएमई के ऑडिट (लेखाकार द्वारा) के लिए टर्नओवर सीमा मौजूदा ₹1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गई। कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ी हुई सीमा केवल उन व्यवसायों पर लागू होती है जो

अनुलग्नक I: बजट की मुख्य बातें: उपाय (समाप्त)

अपने लेनदेन का 5 प्रतिशत से भी कम नकदी में कारोबार करते हैं।

- आसान कर अनुपालन के लिए सभी धर्मादाय संस्थानों को विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी करना।
- मानव रहित आकलन के विस्तार में मानव रहित अपील को सक्षम बनाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन।
- एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए योजना बनायी जाए जिसके अंतर्गत विस्तृत आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता के बगैर आधार की बुनियाद पर पैन को तुरंत ऑनलाइन आबंटित किया जाएगा।
- चिकित्सा उपकरणों के आयात पर स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा। इस आय का उपयोग वांछित जिलों

में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए किया जाना है।

- आयकर विभाग की वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 'करदाताओं के चार्टर' को अपनाने के लिए सीबीडीटी को अनिवार्य करना
- प्रत्यक्ष करों में मुकदमों को कम करने के लिए कोई विवाद नहीं बल्कि विश्वास योजना नहीं- विवाद से विश्वास।
- सरलीकृत जीएसटी रिटर्न 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित होगी। उपभोक्ता चालान के लिए डायनेमिक क्यूआर-कोड प्रस्तावित है। ग्राहकों को चालान लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद इनाम दिया जाएगा।

अनुबंध II

एनएसएसएफ से संबंधित वार्षिक धन प्रवाह (₹ करोड़)				
वर्ष	प्राप्तियां	वितरण	निवल उपचय	बकाया
1	2	3	4 (2-3)	5
2015-16	4,45,974	3,39,036	1,06,938	10,15,225
2016-17	5,16,000	3,98,734	1,17,266	11,32,490
2017-18	5,92,710	4,35,596	1,57,114	12,89,604
2018-19	6,80,021	4,68,018	2,12,004	15,01,608
2019-20 आरई	8,28,520	5,51,932	2,76,588	17,78,196
2020-21 बीई	8,69,946	5,74,009	2,95,936	20,74,132

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज

अनुबंध III: राज्यों के बीच करों के आपसी वितरण के मानदंड

मानदंड	एफसी-XIV		एफसी-XV	
	भारांक	फॉर्मूला (राज्य i का शेयर)	भारांक	फॉर्मूला (राज्य i का शेयर)
जनसंख्या 1971	17.5	$POP_{i1971} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 1971$		
जनसंख्या 2011	10	$POP_{i2011} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 2011$	15	$POP_{i2011} / \sum_{j=1}^{29} POP_j 2011$
जनसांख्यिकीय कार्यनिष्पादन			12.5	$DP_i / \sum_{j=1}^{28} DP_j$ [$DP_i = POP_{i1971} / TFR_i$]
वन और पारिस्थितिकी	7.5	$F_i / \sum_{j=1}^{29} F_j$ $F_i = \text{very dense forest} +$ $\text{moderately dense forest}$	10	$F_i / \sum_{j=1}^{28} F_j$ $F_i = \text{very dense forest} +$ $\text{moderately dense forest}$
आय अंतर	50	$D_i / \sum_{j=1}^{29} D_j$ $D_i = \text{distance in per capita}$ $\text{income of } i\text{th state from third}$ $\text{highest state} * POP_{i1971}$	45	$D_i / \sum_{j=1}^{28} D_j$ $D_i = \text{distance in per capita}$ $\text{income of } i\text{th state from third}$ $\text{highest state} * POP_{i2011}$
क्षेत्र	15	$Area_i / \sum_{j=1}^{29} Area_j$	15	$Area_i / \sum_{j=1}^{28} Area_j$
कर प्रयास			2.5	$TE_i / \sum_{j=1}^{28} TE_j$ [$TE = \text{tax ratio} * \text{Population}$]
कुल	100		100	

स्रोत: एफसी-IV रिपोर्ट, एफसी-XV अंतरिम रिपोर्ट

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	151
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	152
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	153
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	154
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	155
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	155
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	156
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	157
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	158
9	कुल चलनिधि राशियां	158
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	159
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	159
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	160
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	160
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	161
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	162
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	163
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	164
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	165
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	165
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	165
21	थोक मूल्य सूचकांक	166
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	170
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	170
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	171
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	171
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	172
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	173
28	वाणिज्यिक पत्र	173
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	173
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	174

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
बाह्य क्षेत्र		
31	विदेशी व्यापार	175
32	विदेशी मुद्रा भंडार	175
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	175
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	176
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	176
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	177
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	177
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	178
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	179
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	180
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	181
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	182
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ		
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	183
अवसरिक श्रृंखला		
44	लघु बचत	185
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	186
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	187
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	188
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	189
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	190

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2018-19		2019-20	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.0	6.1	5.6	4.8	4.5
1.1.1 कृषि	2.4	2.5	2.0	3.1	3.5
1.1.2 उद्योग	4.5	4.7	4.4	0.1	0.1
1.1.3 सेवाएं	7.5	7.2	7.3	6.8	6.4
1.1क अंतिम खपत व्यय	7.6	9.1	7.0	7.0	6.7
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	9.8	11.5	11.4	-4.1	-5.2
	2018-19	2019		2020	
		जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.8	1.6	0.2	2.0	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	9.6	10.0	9.9	9.0
2.1.2 ऋण	13.3	14.8	14.7	7.2	6.1
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	14.7	14.6	7.1	6.1
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	-0.1	-1.2	11.2	10.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	16.2	16.5	12.3	11.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	10.4	10.8	11.2	10.2
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.25	19.25	18.25	18.25
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.7	4.7	4.7	4.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	78.0	78.1	75.8	75.8
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	127.7	123.5	44.4	44.3
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	27.9	27.6	28.0	28.3
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	4.4	3.6	46.9	51.8
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.25	5.15	5.15
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.25	6.00	4.90	4.90
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.75	6.50	5.40	5.40
4.4 बैंक दर	6.50	6.75	6.50	5.40	5.40
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.95/9.45	8.95/9.45	8.45/9.40	8.45/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	8.15/8.55	8.15/8.55	7.50/7.95	7.50/7.90
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.50	6.25/7.50	6.10/6.40	6.00/6.40
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.43	6.29	4.94	4.96
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.56	6.40	5.13	5.08
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.69	6.48	5.24	5.18
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	6.78	6.55	5.29	5.16
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.30	7.41	6.86	6.65
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	71.11	71.22	71.51	72.19
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	80.50	80.75	78.82	79.44
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरिकी डॉलर					
1-माह (%)	6.07	4.05	4.13	3.52	3.82
3-माह (%)	4.80	4.22	4.38	4.25	3.93
6-माह (%)	4.16	4.11	4.16	4.21	3.91
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	2.0	2.6	7.6	6.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	6.6	7.0	7.5	6.8
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	2.8	2.9	3.1	2.3
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	3.0	4.8	10.0	6.7
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	1.8	1.7	3.4	3.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	2.8	2.3	0.3	0.4
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	1.9	-3.4	-0.7	2.5
7.2 निर्यात	8.7	3.9	3.2	-1.6	2.9

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से सदर्थ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2019	2020				
		मार्च	फरवरी 28	मार्च 6	मार्च 13	मार्च 20	मार्च 27
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2113764	2321924	2347848	2373668	2383278	2412993
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	11	13	14	13	11	10
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2113775	2321937	2347862	2373681	2383289	2413003
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	79481	100833	103496	98308	93661	103439
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2033559	2220225	2243498	2274517	2288781	2308718
1.2.3 रुपया सिक्का	846	735	879	868	856	847	846
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	806012	990618	1028839	1011050	1027741	1187409
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	101	101	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	43	42	42	42	42	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	565707	550033	570358	551020	591163	536186
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	4197	6739	6843	6781	6901	7603
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	3494	3132	3151	3046	3165	3445
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	32036	31600	31701	31982	32110	32641
2.1.1.8 अन्य	605100	199734	398150	414318	414615	391944	605100
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	700	822	2325	3463	2315	2291
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1087686	1219283	1347892	1314453	1300857	1350333
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	1893698	2209901	2376731	2325503	2328598	2537742
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	11	13	14	13	11	10
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	646640	1022250	1108603	1061825	1020444	1006357
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	—	5081	32976	20553	—	50477
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	10	2882	7239	6154	2339	1967
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	180688	54186	84559	105035	175754	285623
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	10064	13463	1815	1815	1815	2385	10064
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	700	10336	9090	2269	2301	2300
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	1042951	923080	983802	998435	998469	999964	1042951
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	129106	129535	134000	129370	125400	137993
2.2.6.1 सोना	127644	87169	120566	125071	119743	115577	127644

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)	
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय			
												1
फर. 1, 2020	1505	21197	-	-	4765	-	-	-	-	-	-	-14927
फर. 2, 2020	-	16	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-16
फर. 3, 2020	3099	72443	-	210011	4666	-	-	-	-	-	-	-274689
फर. 4, 2020	3309	72421	5020	175010	3750	-	-	-	-	-	-	-235352
फर. 5, 2020	2939	42280	-	190013	2802	-	-	-	-	-	-	-226552
फर. 6, 2020	2934	54744	-	190027	4290	-	-	-	-	-	-	-237547
फर. 7, 2020	2944	68933	6000	140016	3200	-	-	-	-	-	-	-196805
फर. 8, 2020	-	20	-	-	200	-	-	-	-	-	-	180
फर. 9, 2020	-	674	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-524
फर. 10, 2020	3080	59552	-	140026	4280	-	-	-	-	-	-	-192218
फर. 11, 2020	2150	43473	-	150020	1530	274	-	-	-	-	-	-189539
फर. 12, 2020	2135	55624	-	120016	4080	-	-	-	-	-	-	-169425
फर. 13, 2020	1895	69683	-	140016	3310	-	-	-	-	-	-	-204494
फर. 14, 2020	-	77970	-	112429	4426	-	-	-	-	-	-	-185973
फर. 15, 2020	-	18615	-	-	860	-	-	-	-	-	-	-17755
फर. 16, 2020	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13
फर. 17, 2020	-	92753	-	-	2950	317	-	-	-	25035	-	-64451
फर. 18, 2020	-	64590	-	-	2715	-190	-	-	-	-	-	-62065
फर. 19, 2020	-	11331	-	-	1255	-	-	-	-	-	-	-10076
फर. 20, 2020	-	39983	-	-	4065	190	-	-	-	-	-	-35728
फर. 21, 2020	-	10582	-	-	8109	-	-	-	-	-	-	-2473
फर. 22, 2020	-	30	-	-	60	-	-	-	-	-	-	30
फर. 23, 2020	-	1822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1822
फर. 24, 2020	-	59168	-	-	3177	-	-	-	-	25021	-	-30970
फर. 25, 2020	-	136776	-	-	3300	-	-	-	-	-	-	-133476
फर. 26, 2020	-	140443	-	-	3080	-432	-	-	-	-	-	-137795
फर. 27, 2020	-	156264	-	-	4534	-217	-	-	-	-	-	-151947
फर. 28, 2020	-	131050	-	162725	4130	-	-	-	-	-	-	-289645
फर. 29, 2020	-	28429	-	-	6467	-	-	-	-	-	-	-21962

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2018-19	2019	2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	-15377	825	10266	9144
1.1 क्रय (+)	40804	2086	11486	10604
1.2 विक्रय (-)	56181	1261	1220	1460
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	5404	72793	64883
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	-15377	-24785	40007	49151
(करोड़ ₹)	-111945	-176910	278096	342979
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	-13774	-4372	-1215	-2295

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2019	2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	233	400	0
1.2 विक्रय (-)	13935	233	400	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	0	-300	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	29 फरवरी 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1854	0	1854
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	519	0	519
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	7057	1705	5352
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10020	-10020
कुल (1+2+3+4)	9430	11725	-2295

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2019				2020		
		मार्च 29	अक्तूबर 25	नवंबर 22	दिसंबर 20	जनवरी 31	फरवरी 28	मार्च 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	12882	4373	3231	3856	2340	4130	1262
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	2800	2800	2800	2800	2800	10000
3.2 बकाया	4782	2678	1884	1604	1615	1872	1815	4782
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	15560	6257	4835	5471	4212	5945	6044

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2019	2020		
			फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052209	2029451	2218775	2257855	2255426
1.1 संचलन में नोट	2110883	2079892	2284695	2320416	2321924
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	25080	25537	25537	25572
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84561	76265	92199	88840	92812
2 जनता की जमाराशियां	1658254	1427467	1588103	1514641	1613427
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626512	1401265	1554247	1481214	1578869
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	26202	33856	33427	34558
3 एम₁ (1 + 2)	3710464	3456918	3806879	3772496	3868854
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	134863	141786	141786	141786
5 एम₂ (3 + 4)	3851063	3591781	3948665	3914282	4010640
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11721603	11482901	12611745	12587868	12590123
7 एम₃ (3 + 6)	15432067	14939818	16418624	16360364	16458977
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	357952	409246	409246	409246
9 एम₄ (7 + 8)	15799354	15297770	16827870	16769610	16868223

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019	2020		
			फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4433410	5014594	5004051	4983904
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	873047	1057037	997547	990539
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	875548	1057180	997690	990681
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	871456	1055970	989289	987799
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	4092	1210	8401	2882
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	127735	2501	143	143	142
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	2459	101	101	100
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3586539	3560363	3957557	4006504	3993365
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	10382719	10038752	10756819	10695015	10759445
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	8068	6380	4110	3779
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10367356	10030684	10750439	10690905	10755666
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9771722	9440366	10105180	10042583	10104866
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	581722	632356	632404	633477
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9703	8596	12903	15918	17323
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3070841	2964287	3559574	3604871	3681669
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2835016	3351074	3396371	3473169
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2835241	3351293	3396590	3473388
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	225	219	219	219
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	129271	208500	208500	208500
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25823	26280	26280	26315
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2435870	2522454	2938643	2969853	2992356
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1146678	1158386	1152770	1214879
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1377075	1375776	1780257	1817083	1777477
एम₃ (1+2+3+4-5)	15432067	14939818	16418624	16360364	16458977

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
			फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710464	3456918	3806879	3772496	3868854
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	8911512	8554285	9402185	9357114	9454268
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	15646602	15145553	16552195	16492262	16589311
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052209	2029451	2218775	2257855	2255426
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13184397	12728747	13988261	13891476	13990902
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626512	1401265	1554247	1481214	1578869
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11557885	11327482	12434014	12410262	12412032
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5201048	5097367	5595306	5584618	5585414
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	217306	176959	181741	181028
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356837	6230115	6838708	6825644	6826618
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	26202	33856	33427	34558
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	378254	361153	311303	309504	308425
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15659336	15342465	16647197	16578426	16620023
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4433410	5014594	5004051	4983904
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	873047	1057037	997547	990539
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3586539	3560363	3957557	4006504	3993365
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11270846	10909055	11632603	11574375	11636120
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	8068	6380	4110	3779
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11255483	10900987	11626223	11570265	11632341
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	858172	865080	866242	866695
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25823	26280	26280	26315
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2755358	3307262	3341921	3438198
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2835016	3351074	3396371	3473169
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-79658	-43812	-54450	-34971
2.4 पूंजी खाता	2346743	2387793	2497037	2497836	2545604
2.5 अन्य मदें (निवल)	493605	590301	931507	956529	949621

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2019		2020	
		फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	15646602	15145553	16203315	16552195	16589311
2 डाकघर जमाराशियां	367287	357952	409246	409246	409246
3 एल₁ (1 + 2)	16013889	15503505	16612561	16961441	16998557
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	54287	56400	57964
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	3078	2976	2851
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	46887	49631	51556
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	4322	3793	3557
5 एल₂ (3 + 4)	16016821	15506437	16666848	17017841	17056522
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	31905
7 एल₃ (5 + 6)	16048726	..	16698753

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14	फरवरी 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2105715	2310975	2346696	2348239
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	526238	592254	597724	591504
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	558496	491843	550704	556182	550033
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	26202	33856	33427	34558
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2658155	2937085	2977847	2974301
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	943994	718117	707966	689696
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	801951	873047	1057037	997547	990539
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	868997	1055869	989188	987699
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	73545	6817	5081
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	870671	981706	981772	981839
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	870671	981706	981772	981839
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	785	719	700	879
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	127693	2459	101	101	100
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	4050	1168	8359	2840
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	62879	-345300	-293691	-304622
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	62879	-345300	-293691	-304622
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	8068	6380	4110	3779
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	1794	1872	2146	1815
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25823	26280	26280	26315
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2835016	3351074	3396371	3473169
2.3.1 सोना	159585	161705	206919	207871	221399
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2673328	3144172	3188517	3251787
2.4 पूंजी खाता	970265	1052936	1010660	1003528	1047453
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	93742	147726	149242	167426

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2019		2020			
		मार्च 1	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21	फरवरी 28
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2665502	2937085	2944049	2977847	2977471	2974301
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2106053	2310975	2337525	2346696	2357702	2348239
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	601969	531841	592254	573077	597724	586330	591504
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	27608	33856	33447	33427	33439	34558
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	801951	914062	1057037	1015557	997547	934452	990539
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	18846	-345300	-319642	-293691	-233023	-304622
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	7869	6380	6380	4110	4427	3779
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2845742	3351074	3369143	3396371	3408531	3473169
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25841	26280	26280	26280	26280	26315
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1146858	1158386	1153669	1152770	1163196	1214879

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2019		2020	
		फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14	फरवरी 28
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12410053	11964048	13146270	13048689	13148127
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511287	1287716	1436076	1363045	1459926
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10898766	10676332	11710195	11685644	11688201
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4904445	4804349	5269588	5258540	5259691
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	217306	176959	181741	181028
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5994321	5871983	6440607	6427104	6428511
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	378254	361153	311303	309504	308425
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14032206	13656825	14707970	14702800	14751128
2.1.1 सरकार को ऋण	3379001	3353658	3730741	3781730	3769059
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10653205	10303167	10977229	10921070	10982069
2.1.2.1 बैंक ऋण	9771722	9440366	10105180	10042583	10104866
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9730112	9378626	10026280	9969259	10039270
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	12395	10967	13381	10242
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2055	1197	4965	7826	9227
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	849209	856117	857279	857733
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-79658	-43812	-54450	-34971
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	209924	242206	231596	250745
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	155418	177731	177606	178091
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	134164	108287	108440	107625
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538104	495597	977850	928470	937016
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	491843	550704	556182	550033
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74877	66633	81846	78597	82361
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	62879	-345300	-293691	-304622
2.4 पूंजी खाता	1352307	1310686	1462206	1470137	1473980
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	382835	436879	722229	748490	722640
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	398120	382532	435464	446706	476507
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-47846	-52455	54049	59841	72117

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 29, 2019 की स्थिति	2019		2020	
		फरवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 14	फरवरी 28
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3354855	3735514	3789557	3778286
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	96474	94533	95824	99608
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11582	12172	13736	13690
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	72073	67153	66482	66287
3.3 अन्य	6379	6206	5558	5769	5766
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	119458	128910	123720	119187
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	253407	230608	227140	223145
4.3 अन्य	170047	139359	191035	191213	196377
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	56962	42463	49038	47629
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	93653	79815	83567	85261

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2018-19	2019	2020		2018-19	2019	2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी		फरवरी	जनवरी	फरवरी
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	222	219	219	147	148	142	142
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	276350	255093	279961	328972	271426	250568	274771	323775
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	160954	199889	233067	176828	156578	194935	228063
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	85131	66900	82676	79459	85065	66868	82635
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	9007	13172	13229	15139	8925	12968	13078
2 अन्य के प्रति देयताएं	13835976	13293386	14598202	14638332	13495672	12963744	14179034	14218776
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	12409475	13726481	13728836	12573772	12093293	13324001	13326218
2.1.1 मांग	1542554	1294188	1463589	1493527	1511287	1265310	1431011	1459926
2.1.2 मीयादी	11359025	11115286	12262891	12235309	11062484	10827984	11892990	11866292
2.2 उधार	381864	368985	315590	312624	378254	364724	311303	308425
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	514926	556132	596871	543646	505726	543730	584132
3 रिजर्व बैंक से उधार	180688	147395	16915	54186	180688	147395	16915	54186
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	180688	147395	16915	54186	180688	147395	16915	54186
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	657555	588437	650927	650830	640584	574417	632549	632394
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	72783	84191	84805	74877	71081	81845	82361
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	581001	515654	566736	566024	565707	503336	550704	550033
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	372670	370684	290256	320156	327814	318085	231623	261901
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	238124	178084	192006	223048	217043	151373	165994
5.1.1 चालू खाते में	17216	13973	24273	35928	13329	11236	21376	33287
5.1.2 अन्य खातों में	228663	224150	153811	156077	209719	205807	129997	132706
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	54887	37079	36790	32252	31210	20180	18239
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	34858	32315	34050	29635	30546	24959	27488
5.4 अन्य आस्तियां	46793	42816	42777	57311	42879	39286	35111	50180
6 निवेश	3475607	3436578	3849568	3890053	3381056	3342703	3735514	3778286
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3430053	3838797	3874670	3379001	3341633	3730741	3769059
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6525	10771	15383	2055	1070	4773	9227
7 बैंक ऋण	10047125	9729542	10431745	10433183	9771722	9449740	10105176	10104866
7क खाद्यान्न ऋण	64636	82341	108222	94717	41610	59314	78899	65596
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	9494882	10214455	10212972	9521994	9220045	9891378	9887932
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	24082	25518	26051	26223	22613	24595	25463
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	148922	136629	141937	158296	146336	135171	140341
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	23122	23000	21734	24588	22798	22422	21239
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	38534	32142	30489	40622	37949	31611	29892

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			फरवरी 15	जनवरी 31		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	8674893	8368057	8978800	8980095	3.5	7.3
1.1 खाद्यान्न ऋण	41474	61535	78664	65384	57.7	6.3
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8633419	8306522	8900136	8914711	3.3	7.3
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1111300	1092771	1153386	1155990	4.0	5.8
1.2.2 उद्योग	2885778	2774257	2817525	2792812	-3.2	0.7
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	372659	373050	371333	-1.1	-0.4
1.2.2.2 मझौले	106395	103444	106813	107502	1.0	3.9
1.2.2.3 बड़े	2403878	2298154	2337662	2313977	-3.7	0.7
1.2.3 सेवाएं	2415609	2276196	2431975	2433858	0.8	6.9
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	134940	141293	142127	2.6	5.3
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	19177	18775	19205	3.6	0.1
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	38636	45394	45184	15.8	16.9
1.2.3.4 नौवहन	7748	7400	6682	6527	-15.8	-11.8
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	178078	172686	172907	0.8	-2.9
1.2.3.6 व्यापार	528158	504664	519547	538608	2.0	6.7
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	224291	237341	254833	1.7	13.6
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	280372	282206	283775	2.2	1.2
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	198755	227266	228826	13.1	15.1
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	641208	575401	737198	703667	9.7	22.3
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	619146	563134	576807	-13.7	-6.8
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2220732	2163298	2497250	2532051	14.0	17.0
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	4528	6453	6495	3.1	43.4
1.2.4.2 आवास	1160111	1134906	1316481	1328991	14.6	17.1
1.2.4.3 मीयादी जमा राशि की जमानत पर अग्रिम	82873	70600	67240	75469	-8.9	6.9
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	5862	5185	5183	-17.3	-11.6
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	83401	110864	110946	25.7	33.0
1.2.4.6 शिक्षा	67988	68891	67038	66563	-2.1	-3.4
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	200470	220240	221129	9.4	10.3
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	594640	703749	717275	18.2	20.6
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2739021	2682926	2772197	2690428	-1.8	0.3
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1086322	1142576	1145063	3.6	5.4
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	1026613	1100615	1095182	2.6	6.7
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	372659	373050	371333	-1.1	-0.4
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	653954	727566	723849	4.7	10.7
1.2अ.3 आवास	432703	433224	461089	460496	6.4	6.3
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	24294	36176	36477	51.4	50.1
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	56297	53101	52692	-2.3	-6.4
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	389	413	115	-71.0	-70.4
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	614877	715057	701304	5.8	14.1
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	16506	13503	14325	-8.0	-13.2

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			फरवरी 15	जनवरी 31		
	1	2	3	4	2019-20	2020
1 उद्योग	2885778	2774257	2817525	2792812	-3.2	0.7
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41752	41513	41886	41600	-0.4	0.2
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157058	154724	150279	149851	-4.6	-3.1
1.2.1 चीनी	29705	28365	26288	26623	-10.4	-6.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	21437	20745	19461	-8.8	-9.2
1.2.3 चाय	4966	4988	5438	5290	6.5	6.1
1.2.4 अन्य	101044	99934	97808	98476	-2.5	-1.5
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14662	14586	14991	15063	2.7	3.3
1.4 वस्त्र	203549	201291	190108	188067	-7.6	-6.6
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	96331	87850	86276	-11.7	-10.4
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	2146	2198	2117	-0.1	-1.4
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26748	26565	26017	25822	-3.5	-2.8
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	76249	74043	73852	-4.0	-3.1
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11071	10972	10882	10720	-3.2	-2.3
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11968	11759	12205	12102	1.1	2.9
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30319	30202	31085	30607	0.9	1.3
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	63136	55691	55622	58679	-7.1	5.4
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191484	182988	183048	184239	-3.8	0.7
1.9.1 उर्वरक	40043	28262	34535	37028	-7.5	31.0
1.9.2 औषधि और दवाइयां	50500	50742	52072	50685	0.4	-0.1
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	50913	40697	40188	-14.0	-21.1
1.9.4 अन्य	54224	53071	55744	56339	3.9	6.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45803	45221	49254	48752	6.4	7.8
1.11 कांच और कांच के सामान	9887	9976	8678	8494	-14.1	-14.9
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55683	55041	57715	56634	1.7	2.9
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371564	370686	335104	333597	-10.2	-10.0
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	285119	252173	250942	-11.3	-12.0
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	85567	82931	82655	-6.8	-3.4
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168621	163229	157586	155428	-7.8	-4.8
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	37856	37520	33594	32900	-13.1	-12.3
1.14.2 अन्य	130765	125709	123992	122528	-6.3	-2.5
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79859	79885	79793	79111	-0.9	-1.0
1.16 रत्न और आभूषण	72014	71051	59841	59147	-17.9	-16.8
1.17 निर्माण	99473	95900	105113	103972	4.5	8.4
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1055921	986557	1036852	1018749	-3.5	3.3
1.18.1 पावर	568966	554411	559305	538993	-5.3	-2.8
1.18.2 दूरसंचार	115585	91490	136080	141171	22.1	54.3
1.18.3 सड़क	186852	189183	192232	186148	-0.4	-1.6
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	151473	149235	152437	-17.4	0.6
1.19 अन्य उद्योग	201954	192985	237483	238000	17.8	23.3

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2019					2020		
		जनवरी, 25	नवंबर, 29	दिसंबर, 06	दिसंबर, 20	दिसंबर, 27	जनवरी, 03	जनवरी, 17	जनवरी, 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	31	31	30	30	30	30	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	55265.2	66211.7	122809.6	123291.7	123179.7	123700.8	124215.1	122402.4
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	17411.0	18712.1	23045.1	24293.2	23483.5	24516.6	23862.0	22274.8
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	4871.2	5353.2	4226.5	3973.9	4316.8	4705.0	4426.1	4194.1
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	9022.5	10206.8	12582.4	13224.2	13180.2	13478.7	12911.9	11625.8
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	869.9	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	40.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2647.4	3152.0	6236.2	7070.1	5986.4	6332.8	6524.0	6414.9
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	88354.4	113699.8	160651.0	162694.5	162534.0	164398.3	166685.2	166326.7
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	40850.1	56770.2	48880.0	51079.3	50938.9	52339.1	53874.8	54063.3
2.2.1.2 अन्य	52194.8	46242.6	56004.9	110227.2	110067.5	109999.5	110222.0	111303.1	110776.7
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.6	0.0	632.9	673.0	743.7	958.2	629.9	629.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	1261.1	924.7	910.8	874.7	851.9	878.9	877.4	856.7
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	51231.5	46823.1	46786.6	47670.2	48445.0	47721.8	46896.8	47300.4
4.1 मांग	16826.7	16883.7	13300.6	14149.6	14121.3	14382.0	14077.8	13830.6	13669.2
4.2 मीयादी	33548.7	34347.8	33522.5	32636.9	33548.9	34063.0	33644.0	33066.2	33631.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	4639.3	6016.7	6813.0	9236.7	8941.9	9369.9	9277.5	9090.9
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	293.9	309.6	856.6	770.4	712.5	709.1	727.2	756.6
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4345.3	5707.1	5956.3	8466.3	8229.5	8660.9	8550.3	8334.2
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	846.9	747.1	1185.1	814.3	677.7	860.5	1050.5	1030.4
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	31296.2	32995.3	48688.4	49795.3	49891.9	50062.6	49368.8	49622.6
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	17404.1	20120.9	22024.8	23287.8	25021.1	22950.8	21965.6	19796.7
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	57951.4	63661.0	98678.5	98692.2	100148.6	107241.7	101523.2	104233.2
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	57948.4	63659.3	98678.0	98691.7	100148.1	107241.2	101522.7	104232.7
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	81270.1	80806.6	77427.8	77825.3	77214.1	70604.2	78326.2	78091.6
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	3.0	1.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	27.2

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	फरवरी '19	जनवरी '20	फरवरी '20	फरवरी '19	जनवरी '20	फरवरी '20	फरवरी '19	जनवरी '20	फरवरी '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	137.2	153.0	149.8	138.0	154.4	151.7	137.5	153.5	150.5
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	136.8	143.7	144.2	139.4	145.6	146.2	137.6	144.3	144.8
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	153.0	167.3	167.4	150.1	167.6	167.6	152.0	167.4	167.5
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	139.1	153.5	150.9	145.3	157.0	153.1	141.5	154.9	151.8
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	142.5	150.5	150.9	141.7	149.3	150.7	142.2	150.1	150.8
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	124.1	132.0	133.7	118.4	126.3	127.3	122.0	129.9	131.3
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	135.8	142.2	140.7	137.0	144.4	143.1	136.4	143.2	141.8
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	128.7	191.5	165.1	131.6	207.8	181.7	129.7	197.0	170.7
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	121.5	141.1	141.8	119.9	139.1	139.6	121.0	140.4	141.1
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	108.3	113.8	113.1	110.4	114.8	114.6	109.0	114.1	113.6
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	139.2	151.6	152.8	140.8	149.5	150.4	139.7	150.9	152.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	137.4	139.7	140.1	128.3	131.1	131.5	133.6	136.1	136.5
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	156.2	158.7	159.2	153.5	158.5	159.0	154.9	158.6	159.1
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	162.8	168.6	169.4	164.9	170.8	172.0	163.4	169.2	170.1
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	149.9	152.1	152.3	141.4	144.9	145.2	146.5	149.2	149.5
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	150.5	152.8	153.0	143.3	147.0	147.3	147.7	150.5	150.8
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	146.1	147.4	147.5	130.8	133.2	133.5	139.7	141.5	141.7
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	148.5	153.9	154.8	148.5	153.9	154.8
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	145.3	150.4	152.2	127.1	135.1	138.9	138.4	144.6	147.2
6 विविध	138.6	131.1	134.9	142.2	148.1	148.4	132.4	138.4	138.4	137.4	143.4	143.6
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	150.1	151.7	151.8	136.6	140.1	140.4	143.7	146.2	146.4
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	149.9	155.7	156.2	138.5	143.8	144.4	145.6	151.2	151.7
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	129.2	136.3	136.0	119.2	126.1	125.2	123.9	130.9	130.3
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	143.4	150.1	150.4	132.2	137.2	137.7	137.1	142.8	143.2
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	155.5	161.7	161.9	146.6	152.1	152.2	150.3	156.1	156.2
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	134.9	142.5	143.3	133.0	142.1	143.5	134.1	142.3	143.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	141.0	151.9	150.4	138.6	148.2	147.7	139.9	150.2	149.1

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2020		
				फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	307	330	328
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	917	1016	1010
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	925	1021	1016

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2020	
		फरवरी	जनवरी
	1	2	3
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31193	33217	39984
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38404	40059	46498

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019		2020	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी (अ)	फरवरी (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	119.8	119.5	123.0	122.9	122.2
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	134.1	148.9	147.2	143.1
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	143.7	162.6	160.8	154.9
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	146.7	153.8	163.5	164.9	163.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	136.1	195.6	183.6	158.2
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	142.9	148.5	148.7	149.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	143.8	149.2	152.2	153.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	127.7	154.1	156.9	150.0
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	147.7	143.5	143.5	142.7
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	123.2	134.0	132.1	131.6
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	125.0	123.7	124.3	124.4
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	146.9	152.9	157.1	153.7
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	102.0	105.4	105.8	105.1
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	189.3	348.3	280.7	294.6
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	144.0	147.6	142.6	147.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	133.0	137.5	133.0	137.5
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	182.4	182.6	176.4	182.6
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	88.2	88.2	88.3	87.0
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	100.5	103.2	102.7	103.9
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.6	126.5	126.5	126.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	133.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	91.4	91.3	93.5	92.4
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	108.2	117.9	110.0	117.9
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	118.2	118.0	118.5	118.7
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	128.7	137.0	138.2	136.9
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	134.3	135.8	135.9	136.7
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	132.3	136.6	134.3	135.7
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.1	115.0	114.9	114.9
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	115.5	126.4	131.1	129.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	134.4	149.5	151.2	151.2
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	144.2	147.5	146.6	146.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	129.9	133.7	134.2	133.4
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	130.7	134.6	135.7	136.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	111.7	119.3	119.8	119.1
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	127.0	128.0	126.1	125.9
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	142.6	123.4	131.7	130.5
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	128.3	138.5	130.1	126.1
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	125.1	135.7	135.9	137.5
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	126.9	129.1	129.6	129.9
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	154.6	159.7	164.5	155.9
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	160.5	175.7	174.6	170.0
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	121.7	123.7	124.0	124.1
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	114.0	118.6	118.5	119.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	122.1	125.8	125.7	126.6
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	132.7	129.5	131.0	129.1
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	152.5	151.0	151.0	154.2
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	152.5	151.0	151.0	154.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019		2020	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी (अ)	फरवरी (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	119.2	116.0	116.4	116.7
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	111.2	105.1	105.6	105.7
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	129.7	129.3	129.5	130.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	112.3	114.8	114.7	113.9
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	134.2	135.5	135.1	133.6
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	137.7	145.8	147.2	146.0
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	118.0	116.0	116.0	116.7
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	137.5	139.2	138.0	137.8
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	138.3	140.2	138.6	138.1
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	135.5	136.7	136.4	136.9
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	119.5	118.4	118.3	117.8
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.0	103.3	104.6	103.0	102.8
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	133.0	135.9	137.1	137.6
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	123.5	123.5	120.4	120.7	119.9
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.5	136.2	133.0	133.1	132.7
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	127.6	120.5	119.8	120.1
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.3	139.6	135.7	136.2	135.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	158.7	157.0	177.8	178.0	178.0
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	124.9	121.2	120.7	121.5
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	124.1	118.9	119.1	120.0
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	129.3	131.0	122.7	122.6	123.4
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	116.4	112.1	112.7	113.8
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	121.1	120.0	119.9	120.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	146.0	151.2	151.5	151.5
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	146.0	151.2	151.5	151.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	119.7	116.2	116.3	116.0
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	125.8	116.8	116.8	117.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	123.0	123.9	123.2	122.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	114.7	109.0	110.8	109.2
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	120.2	123.5	121.8	121.5	121.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	114.5	113.9	114.3	113.2
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	119.1	118.7	119.1	118.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	116.0	113.6	113.1	113.3
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	103.0	96.1	95.6	95.5
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	126.0	127.8	127.8	130.3
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	126.0	127.8	127.8	130.3
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	109.6	108.2	107.9	107.7
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.6	98.3	98.7	98.7
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	91.8	93.9	93.8	94.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	117.3	115.2	114.6	114.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	117.5	115.5	115.5	116.3
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	125.9	125.1	126.0	125.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	111.1	106.9	107.6	108.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	98.7	103.7	102.1	103.3
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	114.4	113.3	114.8	114.7
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	117.6	118.0	117.8	119.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019		2020	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी (अ)	फरवरी (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	121.9	122.2	122.7	123.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	118.5	119.1	118.5	117.9
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	119.3	80.6	78.1	78.1
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	111.0	103.6	105.8	107.0
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	108.9	96.6	102.1	104.3
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.8	113.6	102.8	107.8	109.7
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	98.2	93.7	96.0	96.1
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	110.2	109.9	102.4	104.3	105.6
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	119.6	115.0	103.4	106.5	109.5
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	111.6	99.5	100.0	102.0
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	112.4	98.5	98.6	104.0
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	128.6	126.5	126.4	127.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	110.2	105.8	107.0	105.7
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	113.3	113.4	113.4	112.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	141.0	149.7	147.1	146.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	116.1	115.2	115.4	114.6
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	114.2	112.8	113.6	112.9
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	123.1	124.9	124.2	123.0
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	105.9	104.8	106.3	106.3	107.7
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	103.3	99.8	99.3	98.0
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.9	100.5	100.6	100.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	125.8	123.7	124.4	123.5
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	111.3	109.9	109.7	109.5
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	98.5	97.8	97.7	98.9
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.0	135.0	135.0	135.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.6	118.9	116.8	115.0
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	102.4	96.7	96.9	96.5
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	108.9	111.1	111.9	110.6
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	136.6	139.7	140.5	140.9
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	106.6	101.4	101.4	104.7
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.5	110.9	112.0	112.0
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	112.0	110.8	110.8	110.7
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	108.6	108.2	108.4	108.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	116.5	116.0	116.7	115.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	124.6	109.2	108.0	107.6
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.3	109.8	110.2	109.4
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	109.3	110.3	111.3	111.7
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	120.7	120.4	118.3	118.2
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	110.2	108.5	108.1	108.9
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	111.9	113.0	113.0	113.4
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	103.3	105.5	105.2	105.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	119.1	120.1	120.1	119.6
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.9	111.2	111.5	111.7
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	110.5	109.7	108.0	111.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	78.2	78.0	80.6	80.9	81.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	111.6	111.9	111.7	112.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2019		2020	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी (अ)	फरवरी (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	128.9	129.0	128.4	128.4
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	118.5	121.1	121.1	121.4
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	104.6	109.0	108.2	109.5
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	77.0	74.8	75.2	75.0
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	123.4	125.6	126.3	128.6
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	118.1	117.2	119.3	117.7
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	125.2	126.2	126.7	126.9
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	65.4	65.4	65.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	113.2	115.3	115.1	114.8
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	113.6	115.0	115.0	114.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	112.8	115.6	115.3	114.8
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	112.9	118.4	118.7	120.5
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	105.2	106.6	106.6	106.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	107.9	114.7	115.2	117.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	129.7	130.5	128.2	128.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	124.1	127.0	127.4	127.5
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	128.7	130.3	129.7	128.2
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	128.7	130.3	129.7	128.2
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	106.4	114.4	113.1	117.0
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	103.2	111.6	110.3	114.4
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	177.0	172.7	177.2	175.1
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	126.2	131.4	131.7	131.3
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	132.6	138.2	134.6	135.5
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.9	162.5	162.9	163.2
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	138.1	153.0	152.3	148.2

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2017-18	2018-19	अप्रैल-जनवरी		जनवरी	
				2019	2020	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	129.0	129.6	134.4	137.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	104.9	107.9	104.9	106.0	119.1	124.3
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	130.4	130.8	135.5	137.6
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	158.5	160.0	150.9	155.6
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	125.2	125.8	131.0	133.4
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	107.5	95.1	107.1	102.5
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	124.2	138.0	127.0	147.1
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	140.4	136.8	147.2	143.9
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	130.8	122.7	128.7	123.6
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	143.5	146.8	159.2	158.7

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-फरवरी			
	2019-20 (संशोधित अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	संशोधित अनुमानों का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1850101	1377777	1265678	74.5	73.2
1.1 कर राजस्व (निवल)	1504587	1114636	1093923	74.1	73.7
1.2 करेतर राजस्व	345514	263141	171755	76.2	70.0
2 पूंजीगत प्राप्तियां	81605	51092	71662	62.6	76.9
2.1 ऋण की वसूली	16605	15849	15042	95.4	114.3
2.2 अन्य प्राप्तियां	65000	35243	56620	54.2	70.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1931706	1428869	1337340	74.0	73.4
4 राजस्व व्यय	2349645	2160701	1915303	92.0	89.5
4.1 ब्याज भुगतान	625105	512984	501160	82.1	85.3
5 पूंजी व्यय	348907	304653	273536	87.3	86.4
6 कुल व्यय (4+5)	2698552	2465354	2188839	91.4	89.1
7 राजस्व घाटा (4-1)	499544	782924	649625	156.7	158.1
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	766846	1036485	851499	135.2	134.2
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	141741	523501	350339	369.3	748.1

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2019		2020				
		मार्च 1	जनवरी 24	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21	फरवरी 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	24508	6106	7116	6634	7633	9067	11205
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	11010	12681	12593	11146	9997	7688	10259
1.3 राज्य सरकारें	26999	39293	46206	40201	32977	32492	24532	18532
1.4 अन्य	27747	40860	96286	90368	87430	82427	77157	66467
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	36418	73785	73542	74602	77063	74068	71102
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	41243	26534	27297	29134	30773	34725	36667
2.3 राज्य सरकारें	28036	29573	7151	7155	7155	18640	18600	18600
2.4 अन्य	18567	15591	19176	19654	17737	14604	14636	15656
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	49736	55090	55279	54682	54958	54458	52590
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	71165	53981	55714	55823	57385	58577	61612
3.3 राज्य सरकारें	18892	18937	22369	22369	11869	11869	11870	11870
3.4 अन्य	62393	64718	66858	65783	66235	63982	63606	62394
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	161494	138311	141449	105994	89685	160993	179421
4.4 अन्य	252	417	464	382	205	320	209	281
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	443052	486223	477071	455424	461822	448983	436955

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जनवरी 29	4000	61	11114	7	27	3993	7	4000	98.74	5.1266
फरवरी 5	4000	69	17187	1408	26	3992	1408	5400	98.74	5.1241
फरवरी 12	4000	81	27124	712	10	3988	712	4700	98.75	5.0949
फरवरी 18	4000	93	22466	2034	20	3998	2034	6031	98.76	5.0566
फरवरी 26	4000	68	9041	2258	51	3982	2258	6240	98.75	5.0793
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जनवरी 29	6000	82	16002	7	61	5993	7	6000	97.45	5.2396
फरवरी 5	6000	65	21886	5	23	5995	5	6000	97.45	5.2398
फरवरी 12	6000	71	21652	11503	23	5997	11503	17500	97.47	5.1997
फरवरी 18	6000	63	16816	0	28	6000	0	6000	97.49	5.1695
फरवरी 26	5000	66	9854	25	48	4975	25	5000	97.48	5.1845
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2019-20										
जनवरी 29	3000	67	9308	0	35	3000	0	3000	94.99	5.2890
फरवरी 5	3000	61	9648	12	35	2988	12	3000	94.96	5.3221
फरवरी 12	3000	84	16401	10	5	2990	10	3000	95.03	5.2397
फरवरी 18	3000	68	10519	0	20	3000	0	3000	95.07	5.1999
फरवरी 26	3000	98	15958	0	11	3000	0	3000	95.10	5.1649

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
फरवरी	1, 2020	4.25-5.25	4.90
फरवरी	3, 2020	3.70-5.25	4.93
फरवरी	4, 2020	3.70-5.25	4.98
फरवरी	5, 2020	3.70-5.40	4.93
फरवरी	6, 2020	3.70-5.25	4.99
फरवरी	7, 2020	3.60-5.25	5.03
फरवरी	10, 2020	3.70-5.30	5.02
फरवरी	11, 2020	3.70-5.25	5.00
फरवरी	12, 2020	3.70-5.25	4.92
फरवरी	13, 2020	3.70-5.25	4.95
फरवरी	14, 2020	3.50-5.25	5.01
फरवरी	15, 2020	4.25-5.05	4.81
फरवरी	17, 2020	3.70-5.25	4.93
फरवरी	18, 2020	3.70-5.25	4.95
फरवरी	20, 2020	3.70-5.25	5.05
फरवरी	24, 2020	3.70-5.25	5.03
फरवरी	25, 2020	3.70-5.25	4.94
फरवरी	26, 2020	3.70-5.25	4.93
फरवरी	27, 2020	3.70-5.25	4.90
फरवरी	28, 2020	3.70-5.25	4.98
फरवरी	29, 2020	4.05-5.25	5.06
मार्च	2, 2020	3.60-5.25	4.95
मार्च	3, 2020	3.60-5.25	4.91
मार्च	4, 2020	3.60-5.25	4.95
मार्च	5, 2020	3.70-5.25	4.93
मार्च	6, 2020	3.70-5.20	4.94
मार्च	7, 2020	4.05-5.10	4.83
मार्च	9, 2020	3.70-5.20	4.96
मार्च	11, 2020	3.70-5.15	4.95
मार्च	12, 2020	3.70-5.15	4.93
मार्च	13, 2020	3.50-5.20	4.96

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019	2020			
	फरवरी 15	जनवरी 17	जनवरी 31	फरवरी 14	फरवरी 28
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	200250.80	181344.00	181309.00	186042.00	185932.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	33384.18	7692.49	16507.91	18874.41	16537.00
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.44-8.90	5.10-6.86	5.20-7.50	5.22-7.16	5.22-6.76

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019	2020			
	फरवरी 28	जनवरी 15	जनवरी 31	फरवरी 15	फरवरी 29
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	520811.05	434895.30	421988.85	435803.25	400200.25
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	90081.20	37801.80	72673.75	84356.40	56287.50
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.36-11.74	4.75-14.29	5.12-13.05	5.11-12.53	5.11-13.45

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2019	2020					
		मार्च 1	जनवरी 24	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21	फरवरी 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	41140	16270	14691	22212	19869	28262	27447
2 नोटिस मुद्रा	4930	9366	805	8821	870	10944	1051	8014
3 मीयादी मुद्रा	740	969	511	964	895	798	742	973
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	329012	325737	362137	283432	308513	259355	360008
5 बाजार रिपो	200970	228157	201848	249932	227651	299777	221702	297486
6 कापॉरेट बांड में रिपो		1940	1554	3235	4886	1818	1210	80
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	81741	56489	72057	69523	66967	59151	83533
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	56365	61839	60694	119431	109426	133831	117379
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	4402	4644	4535	6911	5512	6413	6094
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	2277	2059	2049	2077	3071	6176	2315
10.2 182-दिवसीय	1450	771	1267	1705	2128	1564	1608	863
10.3 364-दिवसीय	1620	768	1018	597	1323	1182	1815	840
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400	5603	3206	2179	17260	3010	2687	4596
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	70186	74033	71760	149132	123765	152530	132087
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	2624	2594	37	128	19	267	211

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रै.-फर.)		2019-20 (अप्रै.-फर.)*		फरवरी 2019		फरवरी 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	16754	120	16603	65	64536	6	53	2	14
1ए प्रीमियम	124	16085	115	15961	63	42888	4	33	2	10
1.1 पब्लिक	119	14605	111	14479	53	9851	5	27	2	14
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	107	14021	51	9425	3	16	2	10
1.2 राइट्स	10	2149	9	2124	12	54685	1	26	—	—
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	8	1940	12	33463	1	18	—	—
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	25	36680	22	33844	32	14659	2	1286	2	498
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	22	33844	32	14659	2	1286	2	498
3.1.1 पब्लिक	25	36680	22	33844	32	14659	2	1286	2	498
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3)	154	53433	142	50447	97	79195	8	1340	4	512
4.1 पब्लिक	144	51284	133	48323	85	24510	7	1313	4	512
4.2 राइट्स	10	2149	9	2124	12	54685	1	26	—	—

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2019				2020	
			फरवरी	अक्तूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2307726	191345	186934	185483	194919	185219	197646
	मिलियन अमरिकी डॉलर	330078	26866	26314	25959	27379	25972	27647
1.1 तेल	करोड ₹	325929	21960	25061	28669	27711	23555	24265
	मिलियन अमरिकी डॉलर	46554	3083	3528	4012	3892	3303	3394
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1981797	169385	161873	156814	167208	161664	173382
	मिलियन अमरिकी डॉलर	283525	23783	22786	21947	23487	22669	24253
2 आयात	करोड ₹	3594675	260603	269507	275336	282124	293440	268064
	मिलियन अमरिकी डॉलर	514078	36590	37938	38535	39628	41148	37497
2.1 तेल	करोड ₹	986275	67048	68763	79090	76110	92503	76894
	मिलियन अमरिकी डॉलर	140921	9414	9680	11069	10691	12971	10756
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2608400	193555	200744	196246	206014	200938	191170
	मिलियन अमरिकी डॉलर	373158	27176	28258	27466	28938	28177	26741
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1286948	-69258	-82573	-89854	-87205	-108221	-70418
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-184000	-9724	-11624	-12575	-12249	-15175	-9850
3.1 तेल	करोड ₹	-660346	-45088	-43702	-50421	-48399	-68948	-52629
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-94367	-6331	-6152	-7057	-6798	-9668	-7362
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-626602	-24170	-38870	-39433	-38806	-39274	-17788
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-89633	-3394	-5472	-5519	-5451	-5507	-2488

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019	2020					
		मार्च 15	फरवरी 7	फरवरी 14	फरवरी 21	फरवरी 28	मार्च 6	मार्च 13
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	2812180	3378130	3398212	3410238	3475030	3592435	3565980
	मिलियन अमरिकी डॉलर	405638	473001	476092	476122	481540	487237	481892
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	2614690	3136686	3154503	3161973	3217272	3326272	3310406
	मिलियन अमरिकी डॉलर	377774	439186	441949	441458	445823	451135	447358
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	166650	205541	207871	212456	221398	228567	218050
	मिलियन अमरिकी डॉलर	23408	28779	29123	29662	30680	31000	29467
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	1046	1045	1045	1045	1045	1045
	करोड ₹	10110	10259	10207	10216	10331	10666	10722
	मिलियन अमरिकी डॉलर	1461	1436	1430	1426	1432	1447	1449
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	20730	25644	25631	25593	26028	26931	26801
	मिलियन अमरिकी डॉलर	2995	3599	3590	3575	3606	3656	3618

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2019	2020		2018-19	2019-20
		फरवरी	जनवरी	फरवरी	अप्रैल-फरवरी	अप्रैल-फरवरी
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130423	125599	133565	132502	8269	6697
1.1 एफसीएनआर (बी)	23170	21623	24408	24233	-402	1063
1.2 एनआर (ई) आरए	92017	89183	92838	92049	6795	3972
1.3 एनआरओ	15236	14792	16319	16220	1876	1661

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2019	2020	
		अप्रैल-फरवरी	अप्रैल-फरवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)						
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	30712	29923	40625	1949	5668	2873
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	43302	40063	52090	2503	6742	4533
1.1.1.1.1 ईक्विटी	62001	56871	69908	4394	8494	6285
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	45055	41393	46864	2926	5631	3422
1.1.1.1.1.1.1 भारतीय रिजर्व बैंक	2429	2152	3077	22	24	26
1.1.1.1.1.1.2 शेयरों की अधिप्राप्ति	36315	33787	36361	2490	4751	3149
1.1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	5622	4826	6262	353	795	186
1.1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	689	628	1165	61	61	61
1.1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	13672	12455	12836	1217	1217	1217
1.1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3274	3023	10209	251	1646	1646
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18699	16809	17818	1890	1752	1752
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	18452	16573	17645	1879	1748	1748
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	235	173	12	4	4
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12590	10140	11465	554	1074	1660
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7201	6235	5916	458	810	501
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3032	2780	2869	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5202	3572	4891	242	223	1118
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	2845	2447	2210	398	212	212
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-9241	15954	1175	-227	1033
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1820	1820	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2225	-11525	16300	1852	-127	1133
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-464	346	678	100	100
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30094	20682	56579	3124	5441	3906

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	2018-19	2019		2020	
		फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13787.58	1046.51	1563.72	1804.50	1686.70
1.1 जमाराशियां	455.94	33.23	42.38	55.94	50.17
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.53	4.56	4.85	6.67	7.59
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.90	24.55	27.57	26.20	29.68
1.4 उपहार	1370.24	103.65	150.90	158.44	196.77
1.5 दान	8.67	0.58	0.89	1.10	1.16
1.6 यात्रा	4803.81	366.36	620.32	712.56	539.74
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2800.88	199.84	276.74	310.83	342.58
1.8 चिकित्सा उपचार	28.59	1.63	2.68	2.59	4.02
1.9 विदेश में शिक्षा	3569.87	296.71	420.45	510.26	496.87
1.10 अन्य	242.15	15.40	16.93	19.90	18.10

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2019	2020	
			मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	73.64	72.87	71.22
1.2 रीर	119.71	114.01	115.25	119.20	116.51
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	75.22	73.91	72.09
2.2 रीर	121.94	116.32	117.63	122.13	119.12
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	63.88	63.37	60.81
1.2 रीर	129.19	121.70	123.30	126.38	121.39
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	94.06	93.32	89.55
2.2 रीर	100.00	94.20	95.44	97.83	93.97

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2018-19	2019	2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	88	110	84
1.2 राशि	28387	2812	5869	1159
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	-	4	7
2.2 राशि	13537	-	2532	3017
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1020	88	114	91
3.2 राशि	41924	2812	8401	4175
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	5.80	7.10	8.66
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	1.56	1.24	2.01
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	1.20-10.50	0.00-11.10	0.00-11.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	285511	289806	-4296	314908	293307	21601
1 चालू खाता (1.1+1.2)	162792	180544	-17752	162579	163995	-1417
1.1 पण्य	83082	132363	-49281	81232	115856	-34625
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	79710	48181	31529	81347	48139	33208
1.2.1 सेवाएं	55075	33397	21678	55158	33278	21880
1.2.1.1 यात्रा	7372	4865	2508	8545	5569	2977
1.2.1.2 परिवहन	4807	5231	-424	5448	6411	-963
1.2.1.3 बीमा	689	419	271	617	549	67
1.2.1.4 जीएनआईई	144	289	-145	157	218	-62
1.2.1.5 विविध	42062	22594	19469	40391	20531	19860
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	21148	1254	19895	23760	2305	21455
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9978	10135	-156	11889	12027	-138
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1324	992	332	1183	550	633
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	673	284	390	757	308	449
1.2.2 अंतरण	18976	1552	17424	20627	1935	18693
1.2.2.1 आधिकारिक	102	237	-134	50	290	-240
1.2.2.2 निजी	18874	1316	17558	20577	1645	18932
1.2.3 आय	5658	13231	-7573	5562	12926	-7364
1.2.3.1 निवेश आय	4295	12639	-8344	4122	12232	-8110
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1363	592	771	1440	694	746
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	122719	108948	13770	151666	129312	22355
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	73237	68038	5199	94408	76606	17802
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16130	8820	7309	19713	9740	9973
2.1.1.1 भारत में	15505	5139	10366	19085	5856	13229
2.1.1.1.1 इक्विटी	11002	5101	5901	11033	5747	5286
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3450		3450	3590		3590
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1052	38	1014	4462	109	4354
2.1.1.2 विदेश में	625	3681	-3056	628	3884	-3256
2.1.1.2.1 इक्विटी	625	1817	-1192	628	1804	-1176
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	788	-788
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1106	-1106	0	1293	-1293
2.1.2 संविभाग निवेश	57107	59218	-2111	74695	66866	7829
2.1.2.1 भारत में	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
2.1.2.1.1 एफआईआई	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	45530	47949	-2419	56356	50342	6014
2.1.2.1.1.2 ऋण	11203	10972	231	15405	13285	2119
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	374	297	77	2934	3239	-304
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	20492	17554	2938	23041	19910	3131
2.2.1 बाह्य सहायता	2960	1278	1682	2511	1243	1268
2.2.1.1 भारत द्वारा	11	29	-18	2	28	-26
2.2.1.2 भारत को	2949	1249	1700	2509	1215	1294
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	10468	8466	2002	11007	7774	3233
2.2.2.1 भारत द्वारा	3337	3346	-9	2692	2687	5
2.2.2.2 भारत को	7131	5120	2011	8315	5087	3228
2.2.3 भारत को अल्पावधि	7064	7809	-745	9523	10893	-1370
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	4433	7809	-3377	9523	10129	-606
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	2631	0	2631	0	764	-764
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21193	16279	4913	21012	23336	-2324
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21193	16095	5098	21012	23279	-2266
2.3.1.1 आस्तियां	5964	1763	4202	5753	7260	-1507
2.3.1.2 देयताएं	15228	14332	896	15259	16019	-760
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13298	13159	139	14407	13579	828
2.3.2 अन्य	0	185	-185	0	58	-58
2.4 रुपया ऋण चुकौती		0	0		0	0
2.5 अन्य पूंजी	7797	7077	720	13205	9460	3745
3 भूल-चूक		314	-314	663		663
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	4296	0	4296	0	21601	-21601
4.1 आईएमएफ	0	0	0			
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	4296	0	4296	0	21601	-21601

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आंशिकरूप से संशोधित

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2057747	2088707	-30960	2243026	2089165	153861
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1173282	1301224	-127943	1158014	1168105	-10091
1.1 पण्य	598791	953970	-355179	578595	825220	-246625
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	574491	347254	227236	579419	342885	236534
1.2.1 सेवाएं	396941	240704	156237	392878	237033	155845
1.2.1.1 यात्रा	53135	35060	18075	60866	39664	21202
1.2.1.2 परिवहन	34647	37704	-3057	38802	45662	-6860
1.2.1.3 बीमा	4967	3016	1950	4395	3914	481
1.2.1.4 जीएनआईई	1039	2086	-1047	1116	1555	-438
1.2.1.5 विविध	303153	162837	140316	287699	146238	141461
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	152422	9037	143385	169238	16420	152819
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	71917	73043	-1126	84680	85666	-986
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9541	7149	2392	8427	3917	4510
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4854	2046	2808	5390	2194	3196
1.2.2 अंतरण	136768	11188	125580	146924	13780	133143
1.2.2.1 आधिकारिक	738	1705	-967	358	2066	-1708
1.2.2.2 निजी	136030	9483	126547	146566	11714	134852
1.2.3 आय	40781	95362	-54581	39617	92072	-52455
1.2.3.1 निवेश आय	30957	91096	-60139	29362	87129	-57766
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9824	4266	5558	10255	4943	5312
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	884465	785218	99247	1080286	921060	159227
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	527835	490368	37468	672447	545645	126802
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	116250	63571	52680	140410	69373	71037
2.1.1.1 भारत में	111745	37038	74707	135938	41710	94229
2.1.1.1.1 इक्विटी	79294	36764	42530	78585	40936	37649
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	24868	0	24868	25569		25569
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	7583	274	7309	31784	774	31011
2.1.1.2 विदेश में	4505	26532	-22027	4472	27664	-23192
2.1.1.2.1 इक्विटी	4505	13097	-8592	4472	12846	-8375
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5464	-5464		5611	-5611
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	7971	-7971	0	9207	-9207
2.1.2 संविभाग निवेश	411585	426797	-15212	532037	476272	55765
2.1.2.1 भारत में	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
2.1.2.1.1 एफआईआई	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	328145	345579	-17434	401412	358574	42838
2.1.2.1.1.2 ऋण	80746	79080	1666	109725	94630	15095
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2695	2139	556	20901	23068	-2168
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	147693	126518	21175	164114	141812	22303
2.2.1 बाह्य सहायता	21334	9213	12121	17887	8856	9031
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	14	201	-187
2.2.1.2 भारत को	21253	9004	12249	17873	8655	9218
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	75446	61020	14425	78398	55370	23028
2.2.2.1 भारत द्वारा	24052	24119	-67	19175	19136	39
2.2.2.2 भारत को	51394	36901	14493	59224	36234	22990
2.2.3 भारत को अल्पावधि	50913	56284	-5372	67829	77586	-9757
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	31949	56284	-24335	67829	72147	-4318
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	18964	0	18964	0	5439	-5439
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	152740	117328	35412	149666	166220	-16553
2.3.1 वाणिज्य बैंक	152740	115997	36743	149666	165808	-16142
2.3.1.1 अस्तित्वां	42987	12706	30281	40978	51709	-10731
2.3.1.2 देयताएं	109753	103292	6461	108688	114099	-5411
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	95839	94838	1001	102621	96723	5898
2.3.2 अन्य	0	1331	-1331	0	411	-411
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	56197	51005	5192	94059	67383	26675
3 भूल-चूक	0	2264	-2264	4725	0	4725
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	30960	0	30960	0	153861	-153861
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0		
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	30960	0	30960	0	153861	-153861

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आशिकरूप से संशोधित

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	162786	180523	-17738	162576	163968	-1391
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	138157	165760	-27603	136389	149134	-12745
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	83082	132363	-49281	81232	115856	-34625
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82438	125275	-42837	80294	108605	-28311
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	643	0	643	938		938
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		7087	-7087		7252	-7252
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	55075	33397	21678	55158	33278	21880
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	99	13	87	76	9	67
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	64	376	-313	64	207	-143
1.अ.ख.3 परिवहन	4807	5231	-424	5448	6411	-963
1.अ.ख.4 यात्रा	7372	4865	2508	8545	5569	2977
1.अ.ख.5 निर्माण	865	618	247	734	570	164
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	689	419	271	617	549	67
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1324	992	332	1183	550	633
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	182	2173	-1990	184	2197	-2013
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	21907	1629	20278	24592	2712	21880
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9978	10135	-156	11889	12027	-138
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	459	583	-124	535	757	-222
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	144	289	-145	157	218	-62
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	7183	6075	1108	1134	1502	-367
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5658	13231	-7573	5562	12926	-7364
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1363	592	771	1440	694	746
1.आ.2 निवेश आय	3438	12472	-9035	3312	12078	-8767
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1668	6495	-4827	1369	5760	-4391
1.आ.2.2 सविभाग निवेश	35	2311	-2277	28	2435	-2408
1.आ.2.3 अन्य निवेश	204	3653	-3449	138	3871	-3733
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1531	14	1517	1777	12	1764
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	857	167	690	811	154	657
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18970	1532	17438	20625	1907	18718
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18874	1316	17558	20577	1645	18932
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	18200	987	17213	19862	1189	18673
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	674	329	345	715	455	260
1.इ.2 सामान्य सरकार	96	216	-120	48	262	-214
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	71	147	-76	108	258	-150
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	42	-36	19	108	-89
2.2 पूंजी अंतरण	66	106	-40	89	150	-61
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	126950	108822	18128	151560	150683	878
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	16130	8820	7309	19713	9740	9973
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15505	5139	10366	19085	5856	13229
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14452	5101	9351	14623	5747	8875
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11002	5101	5901	11033	5747	5286
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3450		3450	3590		3590
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1052	38	1014	4462	109	4354
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1052	38	1014	4462	109	4354
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	625	3681	-3056	628	3884	-3256
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	625	2575	-1950	628	2591	-1963
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	625	1817	-1192	628	1804	-1176
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		788	-788
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1106	-1106	0	1293	-1293
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1106	-1106		1293	-1293
3.2 सविभाग निवेश	57107	59218	-2111	74695	66866	7829
3.2अ भारत में सविभाग निवेश	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	45530	47949	-2419	56356	50342	6014
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	11203	10972	231	15405	13285	2119
3.2आ. भारत द्वारा सविभाग निवेश	374	297	77	2934	3239	-304
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5859	5362	497	7328	7194	134
3.4 अन्य निवेश	43559	35422	8137	49825	45282	4542
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13298	13343	-46	14407	13637	770
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	185	-185	0	58	-58
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13298	13159	139	14407	13579	828
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	21323	12681	8642	20123	18716	1407
3.4.3अ भारत को ऋण	17975	9305	8670	17429	16001	1428
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	3348	3376	-27	2694	2715	-21
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	29	207	-179	190	660	-469
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	7064	7809	-745	9523	10893	-1370
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	1845	1381	464	5581	1377	4205
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार						0
3.5 आरक्षित आस्तियां	4296	0	4296	0	21601	-21601
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.						0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.						0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	4296	0	4296	0	21601	-21601
4. कुल आस्तियां / देयताएं	126950	108822	18128	151560	150683	878
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	66869	61491	5378	82059	69772	12287
4.2 ऋण लिखत	53940	45950	7991	63920	57933	5988
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	6141	1381	4759	5581	22978	-17396
5. निवल भूल-चूक		314	-314	663		663

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आंशिकरूप से संशोधित

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1173236	1301076	-127839	1157998	1167908	-9910
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	995732	1194674	-198942	971473	1062253	-90780
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	598791	953970	-355179	578595	825220	-246625
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	594154	902892	-308738	571916	773569	-201652
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4637	0	4637	6679	0	6679
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	51078	-51078	0	51652	-51652
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	396941	240704	156237	392878	237033	155845
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	716	91	626	543	63	480
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	460	2713	-2254	456	1477	-1021
1.अ.ख.3 परिवहन	34647	37704	-3057	38802	45662	-6860
1.अ.ख.4 यात्रा	53135	35060	18075	60866	39664	21202
1.अ.ख.5 निर्माण	6235	4455	1781	5227	4057	1170
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4967	3016	1950	4395	3914	481
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9541	7149	2392	8427	3917	4510
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1314	15658	-14344	1312	15650	-14338
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	157892	11741	146151	175162	19318	155844
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	71917	73043	-1126	84680	85666	-986
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3311	4203	-892	3813	5395	-1582
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1039	2086	-1047	1116	1555	-438
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	51768	43785	7982	8079	10696	-2617
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	40781	95362	-54581	39617	92072	-52455
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9824	4266	5558	10255	4943	5312
1.आ.2 निवेश आय	24777	89892	-65115	23588	86031	-62443
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12022	46809	-34787	9753	41027	-31274
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	250	16658	-16408	199	17347	-17148
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1471	26327	-24857	982	27570	-26588
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	11034	97	10936	12655	88	12567
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	6180	1204	4976	5774	1097	4677
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	136723	11039	125684	146908	13584	133324
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	136030	9483	126547	146566	11714	134852
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	131173	7113	124060	141473	8471	133002
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4857	2370	2487	5093	3243	1850
1.इ.2 सामान्य सरकार	693	1556	-864	342	1869	-1527
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	512	1063	-550	770	1837	-1068
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	39	299	-260	132	768	-636
2.2 पूँजी अंतरण	473	763	-290	637	1069	-432
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	914958	784305	130653	1079533	1073281	6253
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	116250	63571	52680	140410	69373	71037
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	111745	37038	74707	135938	41710	94229
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	104162	36764	67398	104154	40936	63218
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	79294	36764	42530	78585	40936	37649
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	24868	0	24868	25569	0	25569
3.1.अ.2 ऋण लिखत	7583	274	7309	31784	774	31011
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	7583	274	7309	31784	774	31011
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4505	26532	-22027	4472	27664	-23192
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4505	18561	-14056	4472	18457	-13985
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4505	13097	-8592	4472	12846	-8375
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5464	-5464	0	5611	-5611
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	7971	-7971	0	9207	-9207
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	7971	-7971	0	9207	-9207
3.2 संविभाग निवेश	411585	426797	-15212	532037	476272	55765
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	328145	345579	-17434	401412	358574	42838
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	80746	79080	1666	109725	94630	15095
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2695	2139	556	20901	23068	-2168
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	42225	38642	3583	52196	51239	957
3.4 अन्य निवेश	313938	255295	58642	354890	322535	32355
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	95839	96169	-330	102621	97135	5486
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	1331	-1331	0	411	-411
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	95839	94838	1001	102621	96723	5898
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	153680	91392	62288	143331	133310	10020
3.4.3.अ भारत को ऋण	129547	67064	62483	124142	113973	10168
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	24133	24328	-195	19189	19337	-148
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	207	1494	-1287	1355	4699	-3344
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	50913	56284	-5372	67829	77586	-9757
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	13298	9955	3343	39755	9805	29949
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	30960	0	30960	0	153861	-153861
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	30960	0	30960	0	153861	-153861
4. कुल आस्तियां / देयताएं	914958	784305	130653	1079533	1073281	6253
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	481939	443179	38761	584489	496972	87516
4.2 ऋण लिखत	388761	331171	57590	455289	412642	42648
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	44258	9955	34302	39755	163666	-123912
5. निवल भूल-चूक	0	2264	-2264	4725	0	4725

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आशिकरूप से संशोधित

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			दिसंबर		सितंबर		दिसंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399229	166594	386172	175438	417137	178694	426928
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	109875	369544	114340	398819	116303	404393
1.2 अन्य पूंजी	58841	17124	56719	16628	61099	18318	62392	22536
2 संविभाग निवेश	4699	260313	2666	245842	4541	260001	4845	266707
2.1 इक्विटी	590	147479	1386	138091	2344	144039	2619	148859
2.2 ऋण	4109	112834	1280	107752	2197	115962	2226	117848
3 अन्य निवेश	54538	419092	41550	401165	55406	428901	54006	430301
3.1 व्यापार ऋण	924	105192	252	103657	1707	106581	2286	105214
3.2 ऋण	9884	167924	6553	160322	7895	174838	6183	177286
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	17211	125997	27563	133105	27099	133331
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	17534	11190	18240	14378	18438	14469
4 रिज़र्व्स	412871		395591		433707		459863	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078634	606401	1033179	669092	1106039	697409	1123937
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436563		-426779		-436947		-426528

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2019	2020		विव 2018-19	2019	2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी		फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)			3.01	2.80			12826782	10821111
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)			1.09	1.17			8442926	6868007
1.1.1 आउटराइट			0.66	0.82			957188	1209395
1.1.2 रेपो			0.21	0.19			2999019	2604693
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो			0.22	0.16			4486719	3053919
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन			1.88	1.59			4083916	3603514
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @			0.05	0.04			299940	349590
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)			137.29	133.16			9880821	8990097
1.1 ग्राहक लेनदेन			135.09	131.07			8558049	7718135
1.2 इंटरबैंक लेनदेन			2.20	2.08			1322772	1271962
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)			21194.27	20409.50			2454422	2396212
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @			0.76	0.74			37	40
2.2 एपीबीएस \$			1511.41	1400.59			9427	8889
2.3 ईसीएस जमा			0.09	0.00			43	
2.4 आईएमपीएस			2595.26	2477.98			216811	214566
2.5 एनएसीएच जमा \$			1431.01	789.68			82398	79707
2.6 एनईएफटी			2605.55	2483.57			1929464	1870494
2.7 यूपीआई @			13050.19	13256.93			216243	222517
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@			0.78	0.70			14	12
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)			812.33	827.05			73506	73479
3.1 भीम आधार पे @			9.36	9.67			141	149
3.2 ईसीएस नामे			0.00	0.00				
3.3 एनएसीएच नामे \$			777.36	789.31			73316	73277
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @			25.61	28.07			49	53
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)			6654.46	6264.71			151147	142375
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)			2017.27	1882.94			66573	62148
4.1.1 पीओएस आधारित \$			1160.35	1072.50			35124	33446
4.1.2 अन्य \$			856.92	810.44			31449	28701
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)			4637.19	4381.77			84575	80227
4.2.1 पीओएस आधारित \$			2587.38	2455.92			38907	36258
4.2.2 अन्य \$			2049.81	1925.85			45667	43968
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)			5237.05	5026.37			18286	17296
5.1 वालेट			3876.23	3782.82			15408	14461
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)			1360.82	1243.55			2878	2836
5.2.1 पीओएस आधारित \$			128.35	115.30			997	1116
5.2.2 अन्य \$			1232.47	1128.25			1880	1719
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)			887.17	884.95			662399	659458
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)			886.39	884.58			661741	659157
6.2 अन्य			0.78	0.37			658	301
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)			34785.27	33412.57			3359760	3288820
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			34922.56	33545.73			13240581	12278916
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			34035.39	32660.78			12578182	11619458

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2019	2020		विव 2018-19	2019	2020	
			फरवरी	जनवरी			फरवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	-	14402.70	14284.28	-	-	521368	525845
1.1 इंटर-बैंक \$	-	-	1304.45	1304.52	-	-	107648	108332
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	13098.24	12979.75	-	-	413720	417513
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	2749.95	2837.88	-	-	3162106	2881819
2.1 इंटर-बैंक @	-	-	612.52	630.85	-	-	1641898	1313016
2.2 इंटर-बैंक @	-	-	2137.43	2207.03	-	-	1520208	1568803
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकाली (3.1 से 3.3)	-	-	6568.95	6203.24	-	-	298514	286006
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	8.53	7.97	-	-	399	379
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	6531.99	6167.30	-	-	297116	284652
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	28.43	27.96	-	-	999	974
4 पीओएस पर नकद निकाली \$ (4.1 से 4.2)	-	-	102.47	65.97	-	-	177	194
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	92.41	59.42	-	-	163	132
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	10.06	6.55	-	-	14	63
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकाली @	-	-	400.77	386.44	-	-	11109	11201
5.1 एईपीएस @	-	-	400.77	386.44	-	-	11109	11201

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	विव 2018-19	2019		2020	
		फरवरी	जनवरी	फरवरी	फरवरी
	1	2	3	4	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना					
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	-	8725.30	8801.81	
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	561.20	571.58	
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	8164.10	8230.23	
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	17574.74	18000.38	
2.1 वॉलेट @	-	-	16575.31	16809.60	
2.2 कार्ड @	-	-	999.43	1190.78	
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	2.33	2.34	
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	2.10	2.11	
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	0.23	0.23	
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	2.56	2.64	
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	49.47	51.00	
6 भारत क्यूआर @	-	-	17.79	18.96	

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रैन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

3. केवल धरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2018	2019		
			नवंबर	सितंबर	अक्तूबर	नवंबर
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	8671	-432	9717	14106
	बकाया	918459	870336	974938	985145	999208
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7262	-2412	7874	10876
	बकाया	618418	584853	662945	670819	681695
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	1650	-9655	1704	1881
	बकाया	140247	127270	143422	145126	147007
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	38	-19	-12	80
	बकाया	3107	2947	2947	2935	3015
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	-2	-2	-5	823
	बकाया	10	-11	-9	-14	809
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	938	1246	1086	1584
	बकाया	192658	188723	199037	200123	201707
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1197	1521	1408	1706
	बकाया	55708	50840	64280	65688	67394
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2089	3229	2606	3625
	बकाया	124292	114411	142095	144701	148326
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	66578	81128	82377	84270
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5478	6451	6531	6637
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6792	7155	7193	7262
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	35563	47361	48600	50157
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	1352	1268	1087	1177
	बकाया	102401	100689	111177	112264	113441
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	0	0	0	0
	बकाया	-26	-37	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1223	2230	1634	2580
	बकाया	221517	214368	232925	235049	237586
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	962	1304	905	1717
	बकाया	98492	91250	105156	106061	107778
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	0	-53	-1	0
	बकाया	263	283	-288	-289	-289
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1669	-1135	-822	-1090
	बकाया	19303	26391	9665	8843	7753
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	1915	2120	1552	1953
	बकाया	93630	84895	107743	109295	111248
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	15	-6	0	0
	बकाया	2	-81	-179	-179	-179
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	0	0	0	0
	बकाया	-80	-81	-82	-82	-82
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11711	10910	11400	11357
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	186	-250	209	650
	बकाया	78524	71115	79068	79277	79927

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल रसीदें हैं, अर्थात् सकल रसीद माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	5758103	5921026	6072243	6314426	6512659
1. वाणिज्य बैंक	40.51	40.28	39.05	39.66	39.05
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.33	0.31	0.36	0.42	0.39
3. बीमाकृत कंपनियां	24.57	24.34	24.88	24.86	24.90
4. म्यूच्युअल फंड	0.64	0.35	0.64	0.77	1.53
5. सहकारी बैंक	2.38	2.29	2.17	2.01	1.97
6. वित्तीय संस्थाएं	1.01	1.05	1.05	1.15	1.14
7. कॉरपोरेट	1.05	0.97	0.99	0.92	0.84
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.60	3.22	3.27	3.31	3.33
9. भविष्य निधियां	5.54	5.47	5.35	4.87	4.93
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	13.81	15.27	15.67	14.99	14.72
11. अन्य	6.55	6.46	6.57	7.05	7.23
11.1 राज्य सरकार	1.97	2.00	2.02	1.99	1.97

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2669393	2777229	2826935	2905169	3047353
1. वाणिज्य बैंक	34.00	33.87	32.57	32.53	32.46
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.60	0.58	0.81	0.72	0.64
3. बीमाकृत कंपनियां	33.90	33.04	33.94	33.39	32.50
4. म्यूच्युअल फंड	1.23	1.20	1.24	1.12	1.20
5. सहकारी बैंक	4.67	4.55	4.65	4.24	4.16
6. वित्तीय संस्थाएं	0.37	0.42	0.44	0.33	0.31
7. कॉरपोरेट	0.22	0.29	0.32	0.28	0.31
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.09	0.09	0.08	0.05	0.04
9. भविष्य निधियां	21.29	22.15	21.88	22.36	23.66
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.64	3.81	4.08	4.98	4.73
11.1 राज्य सरकार	0.07	0.11	0.14	0.16	0.17

श्रेणी	खजाना बिल				
	2018	2019			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	529826	412704	524618	538041	514588
1. वाणिज्य बैंक	53.76	57.56	53.60	50.81	45.19
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.06	2.68	1.85	1.92	2.07
3. बीमाकृत कंपनियां	4.74	6.61	5.13	5.55	5.76
4. म्यूच्युअल फंड	5.65	2.78	13.00	14.08	20.42
5. सहकारी बैंक	1.21	2.48	2.54	2.55	2.07
6. वित्तीय संस्थाएं	1.88	2.49	2.14	1.82	2.12
7. कॉरपोरेट	1.86	2.23	1.67	1.57	1.66
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.02	0.08	0.07	0.01	0.01
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	28.81	23.10	19.99	21.70	20.70
11.1 राज्य सरकार	24.04	17.91	15.59	17.91	16.36

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	1	2	3	4	(सं.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4515946	5516932	6071777
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4528422	5364245	6003162
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	997097	1174823	1247962
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1490	26	871	19	73	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	94	5	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	546	26	76	4
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	312	26	796	22	1017	8
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	81	24	120	14	46	6
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	420	29	124	6	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	225	14	621	12	131	5
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1282	23	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	564	29	215	9	-	-
29	पश्चिम बंगाल	792	13	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7973	784	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1300	1	--	-
3	असम	4233	50	--	1000
4	बिहार	7618	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4253	--	1	5500
6	गोवा	572	288	--	-
7	गुजरात	13122	462	--	-
8	हरियाणा	2004	1153	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	--	--	--	-
12	कर्नाटक	4064	--	--	7500
13	केरल	2065	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	882	--	-
15	महाराष्ट्र	39544	413	--	-
16	मणिपुर	364	96	--	-
17	मेघालय	640	29	9	-
18	मिज़ोरम	530	38	--	-
19	नगालैंड	1575	32	--	-
20	उड़ीसा	12872	1398	81	23670
21	पुदुचेरी	281	--	--	900
22	पंजाब	232	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6379	--	40	8632
25	तेलंगाना	5454	1188	--	-
26	त्रिपुरा	317	5	--	-
27	उत्तराखंड	--	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3029	76	--	-
29	पश्चिम बंगाल	10616	512	214	-
	कुल	129037	7407	661	49002

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	दिसंबर		जनवरी		फरवरी		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	513	222	5000	4708	3928	3345	37895	29730
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	-	-79	87	87	559	480
3	असम	7760	6797	10595	8089	1900	1900	1500	1500	1000	-910	10100	8190
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	-	-607	4000	4000	1959	1959	20601	17601
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	2000	2000	2000	2000	-	-	6000	5300
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	300	200	381	381	175	175	2256	1756
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	2500	1500	8000	6500	2500	1700	33400	23100
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	2000	1000	2500	2500	1500	1100	20501	17201
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	-	-900	1500	1200	1500	1500	5000	3800
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	309	309	600	600	600	57	6192	5110
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	500	500	-	-	1000	1000	3000	1156
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	7700	7700	7000	7000	6000	6000	42100	37350
13	केरल	20500	16203	19500	14784	-	-500	920	920	1000	-480	16602	11146
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	2000	440	3000	1447	3000	3000	15000	10327
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	3000	3000	6000	5000	11998	9498	43498	29998
16	मणिपुर	525	278	970	667	-	-	-	-	400	86	1203	700
17	मेघालय	1116	920	1122	863	295	295	-	-50	150	150	895	621
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	92	92	-	-	90	90	540	439
19	नगालैंड	1135	766	822	355	250	150	-	-	150	22	800	223
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	-	-	500	500	1000	1000	5500	5500
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	200	-300	100	100	100	100	800	300
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	2035	1570	2800	2600	1300	1300	23955	15070
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	1000	-	3750	2750	2500	2326	32582	22326
24	सिक्किम	995	745	1088	795	-	-	142	142	-	-188	593	405
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	8000	6000	8000	6000	5500	5500	58890	47690
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	1324	1116	3000	2792	2000	1583	28124	22289
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	-	-100	400	400	470	370	2550	2200
28	उत्तराखंड	41600	37178	46000	33307	5500	3922	7500	7500	7750	4679	49750	34819
29	उत्तरप्रदेश	6660	5830	6300	5289	750	750	-	-	750	750	3100	2500
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	5000	4000	6000	6000	7250	6450	46260	30150
	कुल	419100	340281	478323	348643	47168	34258	74593	66411	65657	52250	518246	387478

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहाँ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं आरआरबी को छोड़कर हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनपुगी सस्थांओ/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आँकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आँकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के मार्च 2405 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के जनवरी अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रि-पक्ष रेपो का परिचालन 05 दिसंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: जनवरी 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेयन, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शि कायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।